

UL N 342.54

BHA



122049
BSNAA

राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी
al Academy of Administration

मुसोरी
MUSSOORIE

पुस्तकालय
LIBRARY

अवधि संख्या
Accession No.

45092 122049

वर्ग संख्या

GLH

Class No.

342.54

पुस्तक संख्या

Book No.

BHA

भारत

भारत का विधान

मंत्री हिन्दुस्तानी कलचर सोसाइटी

48, बाई का बाग़ इलाहाबाद

पहली बार 3000] सन् 1950 ई० [कीमत 10.00

मुद्रक—

श्री अशर्फी राय शर्मा

अशोक प्रेस, महेन्द्र, पटना

पहल बात

छब्बीस नवम्बर सन् 1949 को विधान सभा ने भारत के विधान को अपना कर भारत की दफ्तरी भाषा के सबाल का फ़ैसला कर दिया और देश भर ने शान्ति का सांस लिया। भारत की दफ्तरी भाषा (official language) का नाम हिन्दी रखा गया। वह हिन्दी क्या होगी इसकी तक़दील दफ़ा 343 और 351 में खोल कर कर दी गई। वह दोनों दफ़ा यह हैं :—

“343—(1)यूनियन की दफ्तरी भाषा देवनागरी लिखावट में हिन्दी होगी।

“यूनियन के दफ्तरी मतलबों के लिखे हिन्दसों का जो रूप काम में लाया जायगा वह हिन्दुस्तानी हिन्दसों का अन्तरक्रौमी रूप होगा।

x x x x x”

“351—यूनियन का फ़रज़ होगा कि हिन्दी भाषा के फैलाव को बढ़ाए, और उसका इस तरह विकास करे कि वह भारत की मिली जुली कलचर के सब अंगों को जाहिर करने का साधन बन सके, और, उसकी आत्मा को छेड़े बिना, जो जो रूप, जो शैली और जो मुहाबिरे हिन्दुस्तानी में और आठवीं पट्टी में दर्ज भारत की दूसरी भाषाओं में काम में आते हैं उनको उसमें रचा पचा कर, और, जहां कहीं ज़रूरी या चाहनी हो, उसकी शब्दावली के लिये पहले संस्कृत से और फिर दूसरी भाषाओं से शब्द लेकर, उसे माला-माला करे।”

आठवीं पट्टी में दर्ज भाषाएं यह हैं:—1. आसामी, 2. बंगला, 3. गुजराती, 4. हिन्दी, 5. कन्नड़, 6. कश्मीरी, 7. मलयालम, 8. मराठी, 9. उड़िया, 10. बंजाबी, 11. संस्कृत, 12. तामिल, 13. तेलगू, 14. उर्दू.

इस तरह जिस हिन्दी की विधान में व्याख्या की गई है उसमें और उस भाषा में कोई फ़रक नहीं रह जाता जो भारत के बहुत बड़े भाग की

जनबोली है, जो पेशावर से आसाम तक और हिमालय से रासकुमारी तक बोली या समझी जाती है, और जिसे देसी और बिदेसी दोनों ने सैकड़ों बरस पहले हिन्दुस्तान की बोली जानकर हिन्दुस्तानी नाम दिया था. यही एक ऐसी भाषा रही है जो सच्चे मानी में भारत की मिलीजुली कलचर के सब अंगों को जाहिर करती है और अपनी आत्मा को नुकसान पहुँचाए बिना भारत की दूसरी भाषाओं के ही नहीं बाहर की भाषाओं के भी शब्द, शैलियाँ और मुहाविरों को अपने अन्दर समा कर अपने आपको मालामाल करने की सकत रखती है. हमारे देश की इसी भाषा को विधान ने हिन्दी नाम दिया है. जिन लोगों को भारत की इस मिलीजुली कलचर से प्रेम है और जो भारत को एक शक्तिशाली और गठा हुआ देश बनाना चाहते हैं उन्होंने विधान की इस दफा का खुले दिल से स्वागत किया. पर विधान का जो हिन्दी अनुवाद सरकार की तरफ से निकला है वह न तो विधान की ऊपर लिखी दफाओं को निभाता मालूम होता है और न बहुत से पत्रकारों और समझदारों की नज़र चढ़ पाया है. जनता को उसके समझ में न आने की शिकायत तो है ही. उस अनुवाद की आत्मा हिन्दी है यह कहना कठिन है. फिर हिन्दुस्तानी या किसी दूसरी देसी भाषा के रूप, शैली और मुहाविरों उसमें कैसे निभते. गुजराती, कन्नड़, उर्दू वगैरा में से किसी एक दो के इक्का तुक्का शब्द लेकर विधान की दफा के अन्तर भले ही निभाए गए हों रुह नहीं निभाई गई. अनुवाद करने वालों ने संस्कृत का इतना अधिक सहारा लिया है कि बेचारी हिन्दी तो दब कर रह गई.

संसार की भाषाओं के इतिहास से पता चलता है कि जब तक कोई भाषा किसी प्राचीन भाषा की शब्दावली के बोझ से दबी रहती है तब तक वह कभी तरक्की नहीं कर पाती. मिसाल के लिये जब तक अंगरेज़ी भाषा लातीनी, यूनानी जैसी पुरानी भाषाओं के बोझ से दबी रही, वह तरक्की न कर सकी. जब शेक्सपियर और उसके साथियों ने उस पर से इन भाषाओं का जुआ उतार फेंका उसके बाद ही अंगरेज़ी भाषा ऐसी फली फूली कि आज संसार की भाषाओं में उसका नाम सबसे आगे लिया जाता है. अब अगर अंगरेज़ी

तीन

भाषा के सब चालू शब्दों को निकाल कर उनकी जगह लातीनी और यूनानी के शब्द भर दिये जाय और उनके रूप भी लातीनी और यूनानी के व्याकरण के अनुसार बनाए जाय तो अंगरेजी भाषा का क्या हाल होगा यह हम सहज ही में समझ सकते हैं. सरकार की ओर से निकले हिन्दी अनुवाद की भाषा कुछ ऐसी ही हो गई है. 'मिलावट' की जगह 'अपमिश्रण', 'गोद लेना' की जगह 'दत्तकग्रहण', 'कम करना' की जगह 'अल्पीकरण', 'दिवाला' (Insolvency) की जगह 'शोधाक्षमता', 'इकहरे बदलते वोट' (Single transferable vote) की जगह 'एकल संक्रमणीय मत', 'परची' (Ballot) की जगह 'शक्ताका', 'बुढ़ापा पेनशन' (Old age pension) की जगह 'वार्धक्य निवृत्ति वेतन', 'साख' (Credit) की जगह 'आकलन', 'बेवसीयती' (Intestacy) की जगह 'इच्छापत्रहीनत्व', 'वधार लेना' की जगह 'वृद्धारग्रहण', 'किया माना गया' की जगह 'कर्तुर्मभिप्रेत', 'जुआ' की जगह 'द्युत', 'तखमीन' (Estimate) की जगह 'प्राक्कलन', 'इस काम से' की जगह 'एतद्द्वारा', 'मिली जुली कलचर' (Composite culture) की जगह 'सामाजिक (?) संस्कृति', इसी तरह के सैकड़ों नहीं हजारों शब्द इस अनुवाद में भरे पड़े हैं.

इससे हिन्दी की हमें कोई भलाई होती दिखाई नहीं देती. इस तरह की भाषा भारत की मिली जुली कलचर को तो किसी भी तरह जाहिर नहीं करती. वह न कहीं बोली जाती है और न देश के किसी भाग की भाषा है. उसे समझने में तो क्या पढ़ने में भी कष्ट होता है. फिर उसमें हिन्दी हिन्दुस्तानी की रवानी और उसके मुहावरे आ ही कैसे सकते हैं.

अंगरेजी मूल को ही देखिये कि उसे शुरू से आखिर तक पढ़ जाइये और शायद एक बार भी आपको किसी शब्द के माने समझने के लिये कोश का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और इस अनुवाद को देखिये कि बिना अंगरेजी मूल को देखे और पग पग पर उसकी शब्दावली का सहारा लिये इसका समझना लगभग असम्भव है.

जनता की जरूरत और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तानी कलचर सोसाइटी ने यह मुनासिब समझा कि हमारे

विधान का एक ऐसा अनुवाद तैयार किया जाय जिसकी भाषा बही हो जो विधान की दफा 343 और 351 में बताई गई है, जिसमें अंगरेजी मूल का अर्थ व्यों का त्यों आ जाय और जिसे देश की जनता पढ़ सके और समझ सके.

हमारे अनुवाद करने वालों ने भाषा की सरलता और मुहाबिरे का तो ध्यान रखा ही है उनकी यह भी कोशिश रही है कि अंगरेजी मूल का हर शब्द और हर वाक्य जिन मानों में आया है ठीक वही माने अनुवाद में भी आ जाय. इसके लिये यह जरूरी नहीं कि एक अंगरेजी शब्द के लिये हर जगह एक ही हिन्दी का शब्द रखा जाय. शब्दों के ठीक ठीक माने प्रसंग से ही जाने जाते हैं. अंगरेजी मूल में कई जगह एक एक शब्द कई कई अर्थों में आया है. हिन्दी में उसका एक ही शब्द से अर्थ करने में अर्थ का अनर्थ हो सकता था. इसलिये अनुवाद करने वालों ने कहीं कहीं एक अंगरेजी शब्द के लिये, जहां जैसा जंचा, एक से अधिक हिन्दी शब्द रखे हैं, जैसे—'public service' में पबलिक का अर्थ 'सरकारी' है तो 'public welfare' में पबलिक का अर्थ 'जनता की', 'civil court' में 'civil' का अर्थ 'दीवानी' है तो 'civil service' में 'civil' का अर्थ 'नागरी' है, 'adopt' का अर्थ कहीं 'गोद लेना' है तो कहीं 'अपनाना', 'constitution' का अर्थ कहीं 'विधान' है तो कहीं 'बनाबट'. फिर भी अनुवादकों ने यह कोशिश की है कि जहां तक हो सके एक अंगरेजी शब्द के लिये एक ही हिन्दी शब्द आवे.

इंडिया का अनुवाद 'भारत' और 'हिन्द' दोनों किया गया है. इस विधान के आरंभ होने से पहले वाले 'इंडिया' को अनुवादकों ने 'हिन्द' कहा है, और जहां कहीं इंडिया का मतलब उस पूरे देश से है जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल थे वहां भी इंडिया का अर्थ 'हिन्द' किया गया है. और सब जगह 'भारत' अर्थ किया गया है.

गवर्नर शब्द का अर्थ 'रियासतपति' किया गया है, पर विधान के आरंभ होने से पहले के सूबों के गवर्नरों को गवर्नर ही कहा गया है.

विधान के भाग पाँच और भाग छै की बहुत सी दफाएँ मिलती जुलती हैं। अनुवाद में इन दोनों भागों की जवाबी दफाओं का जहां तक ठीक समझा गया एक सा अनुवाद किया गया, पर भाग छै की कुछ दफाओं के अनुवाद की वाक्य रचना में कहीं कहीं अन्तर भी है क्योंकि गुरु के फार्म छप जाने के बाद अनुवादकों को वाद की वाक्य रचना ज्यादा अच्छी मालूम हुई। इससे मतलब में ज़रा भी फ़रक नहीं पड़ा है। इसी तरह की एक दो मिसालें और भी हैं।

जहां तक हो सका अनुवाद करने वालों ने उन शब्दों से काम लिया है जो उत्तर भारत में आम तौर पर बोले और समझे जाते हैं। दूसरी प्रांतीय भाशाओं के भी चालू शब्द जहां तहां लिये गए हैं। यूनानी, अंगरेज़ी, फ़्रांसीसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ़ारसी, अरबी जैसी भाशाओं के जो शब्द हिन्दी में चल पड़े हैं और देश के कोने कोने में समझे जाते हैं, उनसे भी इस अनुवाद में काम लिया गया है।

आज अंगरेज़ी भाशा संसार की सब भाशाओं से आगे है, उसका मूल कारन यही है कि अंगरेज़ी लेखक संसार की लगभग सभी भाशाओं से शब्द लेकर अपने शब्द भंडार को बढ़ाने में कभी नहीं हिचके। अंगरेज़ी भाशा का मूल आधार पुरानी जर्मैनिक भाशा का एक अंग पुरानी सेक्सन भाशा है, पर आजकल की अंगरेज़ी के तीन चौथाई से भी अधिक शब्द दूसरी भाशाओं से लिये हुए हैं, जिनमें अरबी, तुर्की, चीनी, जापानी, हिन्दुस्तानी और अफ्रीकी भाशाएँ भी शामिल हैं। अंगरेज़ी में हिन्दुस्तानी से लिये शब्दों की गिनती अब हज़ारों में होती है और इन शब्दों को सिर्फ़ आम बोल चाल की भाशा में ही नहीं क़ानूनी भाशा तक में जगह मिल गई है। इन शब्दों को अंगरेज़ी ने अपने अन्दर पूरी तरह पचा लिया है। हिन्दी में भी यह पाचन शक्ति हमेशा से थी और है। आज हमें इस पाचन शक्ति को क़ायम रखना और बढ़ाना है। पड़ोसी प्रान्तों की भाशाओं से तो बहुत कुछ हिन्दी ने लिया ही है इसे दक्खिन की भाशाओं से भी अभी बहुत कुछ लेना है। और जैसे जैसे नए भारत का संसार के दूसरे देशों से मेल जोल

बढ़ता जायगा वैसे वैसे चीनी, जापानी, बर्मी, श्यामी, हिन्दीचीनी, इन्डोनेशी आदि भाशाओं के शब्द भंडार भी हिन्दी के लिये खुल जायंगे और हिन्दी के लेखकों को जहां तक भी हो सके उनसे लाभ उठाने की कोशिश करनी होगी. हिन्दी का जो विशाल भवन तैयार हो रहा है उसके दरवाजे हमें बन्द नहीं खोल कर रखने होंगे जिससे उसमें हमेशा ताज़ा हवा आती रहे.

शब्दों के चुनने में अनुवाद करने वालों ने एक और सिद्धान्त का भी ध्यान रखा है. एक ही माने रखने वाले अलग अलग मूल के दो शब्द कभी कभी अलग अलग मानों में इस्तेमाल होने लगते हैं. इससे भाशा की शक्ति बढ़ती है. हिन्दी में भी एक ही अर्थ रखने वाले अलग अलग मूल के अनेक शब्द हैं. उन्हें विशेष मानों में लगाना अब हमारा काम है. अनुवाद करने वालों ने इस तरह के कुछ शब्दों को अलग अलग मानी में बरता है, जैसे :— Rule—नियम; Regulation—क्रायदा; Article—दफ़ा; Clause—धारा; Minister—बख़ीर; Secretary—मंत्री; Road—सड़क; Way—मार्ग.

हिन्दी का धातु भंडार अथाह है. पर शब्द भंडार अभी इतना बड़ा नहीं है कि आजकल के सब बिचारों और पदार्थों के लिये काफी हो. इसलिये नए शब्द बनाना भी जरूरी हो जाता है. इसके लिये संस्कृत, अरबी, लातीनी, यूनानी जैसी प्राचीन भाशाओं से तत्सम शब्द ले लेना या उनके व्याकरण की मदद से बना लेना सहज है पर यह वही मार्ग है जिसे हम 'कन्ने काटना' (escapism) कहते हैं. किसी भी जीती जागती भाशा के लिये यह विनाश का मार्ग है. जहां जरूरत हो वहां हम संस्कृत से और दूसरी भाशाओं से भी शब्द ले सकते हैं पर जो शब्द हम बनाएँ वह हमारे मुहाबिरे और हमारे व्याकरण के अनुकूल होने चाहियें. अनुवाद करने वालों ने इसी सिद्धान्त पर कुछ नए शब्द बनाए हैं, जैसे :—Adjustment—बैठबिठाव; Successor—पदगाही; International—अन्तर-क्रौमी; Corporation—एकतनी; Entry—अन्तरी; Contingency—जोगाजोग; Import—आयासी; Export—निकासी; Appointment—नियोजन.

कुछ पुरानी ध्वनियां जैसे व्य, खु, ष ब्रजभाषा आदि में और खड़ी बोली में कम से अनुस्वार, नकार और 'श', 'स' या 'ख' की ध्वनियों में बदल गई हैं और बदलती जा रही हैं। जब हिन्दी की खड़ी बोली में संस्कृत तत्सम शब्दों की बाढ़ आई तभी से यह ध्वनियां संस्कृत तत्सम शब्दों के रास्ते हिन्दी में फिर रख दी गईं, पर अब भी हम इनको आम बोल चाल में नहीं बोलते। 'कञ्चन' को 'कंचन', 'कारखु' को 'कारन', रोष को 'रोश', 'विष' को 'बिस' और 'वर्षा' को 'बरखा' कहते ही हैं। इसीलिये अनुवादकों ने इन ध्वनियों को नहीं रखा। उन्होंने इनका चालू रूप अपनाया है। इससे शब्दों के बोलने में मदद मिलती है और लिखावट भी काफी सरल हो जाती है।

हमारी पहल बात कुछ लम्बी हो गई पर यह सब इसलिये लिखा गया है कि भाषा के संबंध में तरह तरह के विचार लोगों में फैल रहे हैं। हिन्दी एक भाषा है और उन सबकी है जो उसे बोलते हैं। इस भाषा को ऐसा रूप नहीं देना चाहिये कि फिर वह इने गिने आदमियों की ही चीज रह जाय। यह भाषा सैकड़ों बरस से भारत के बड़े भाग की भाषा रही है और अब यह सारे देश की अन्तर-रियासती भाषा है या होने जा रही है। विधान की दफा 351 में इस भाषा के सम्बन्ध में हमें वह बीज नज़र आते हैं जिनको अगर सचाई से और ठीक ठीक पानी मिलता रहा तो भारत की सूबाई और फिरकावारी गुटबन्दी मिट कर भारत के लोग सच्चे मानों में एक 'नेशन' का रूप ले सकेंगे। बोली जिस तरह आदमी आदमी को पास लाती है उसी तरह आदमी आदमी को दूर भी कर सकती है। जाने अनजाने मुहत्तों से जगह जगह यह रीत चली आई है कि हुकूमत और पंडित लोग कुछ और बोली बोलते हैं और जनता कुछ और। इस तरह बोली के दो रूप हो जाते हैं। हुकूमत और पंडित तो जनता की बोली समझते हैं पर जनता उनकी बहुत कम बात समझ पाती हैं। हो सकता है यह ढंग उस समय काम देता हो जब देशों की बागडोर राजाओं और रईसों के हाथ में हुआ करती थी और विद्या पर पंडितों का इजारा था। अब

जब कि हुकूमत की बागडोर कानूनी रूप से जनता के हाथ में मान ली गई है तब सरकार और जनता की दो अलग अलग बोलियों का होना बेजा और बड़ी खतरनाक बात है। जनता की बोली में ही हमारा अधिक से अधिक काम होना चाहिये। जनता का दिया विधान भी जनता की बोली में ही होना चाहिये। सरकार का सारा काम भी जहां तक हो सके उसी बोली में किया जाना चाहिये। विधान की दफा 351 इसी सचार्ड को ध्यान में रख कर बनाई गई है।

अगर हिन्दी को सचमुच केवल दफ्तरी भाषा से बढ़ते बढ़ते कौमी और अन्तरकौमी भाषा बनना है और फलना फूलना है और संसार की बड़ी बड़ी भाषाओं में अपना स्थान लेना है तो इसको खुली हवा में पनपना होगा, दूसरी देशी और विदेशी भाषाओं के साथ अपना मेलजोल बढ़ाना होगा और बिना हिचक नये शब्द, नए वाक्य और नए मुहाविरे अपने ढंग पर ढाल कर अपने अन्दर समाने होंगे। यही इसकी तरक्की का रास्ता है, यही कल्याण का मार्ग।

हम मानते हैं कि हमारे इस अनुवाद में भी सुधार की गुंजाइश है। भाषा के संबंध में विधान सभा ने विधान के अन्दर जो कुछ तय किया है उसके अनुसार हिन्दी को अभी बढ़ाना और रूप लेना है। उसके दरवाजे अभी पूरी तरह खुले रखे गए हैं। अभी उसकी न कोई शैली आखिरी शैली है और न कोई शब्दावली आखिरी शब्दावली है। आगे के लिये यही एक उम्मीद का रास्ता है। इसीलिये हम विधान के इस अनुवाद को सरकार और जनता के सामने रख रहे हैं ताकि इसे पढ़कर देश के बहुत से लोग अपने विधान को समझ सकें और हमारे अनुवाद करनेवालों की यह छोटी सी कोशिश हिन्दी को कानूनी और कौमी रूप देने और बढ़ाने में सरकार और जनता दोनों को थोड़ी बहुत मदद दे सके।

40-A, हनुमान रोड,
नई दिल्ली.
15 अगस्त, 1950.

सुंदरलाल
मंत्री हिन्दुस्तानी क़रार सोसाइटी

पढ़ने वालों से

सफ़ा 34, दफ़ा 78 में “बड़े वज़ीर” की जगह “प्रधान वज़ीर” पढ़िये. सफ़ा 52, दफ़ा 112 (3) (सी) में “बट्टे खाते का खर्च” की जगह “करज़ा चुकाई कोश खर्च” पढ़िये. सक्त भर देखभाल के बाद भी अगर कहीं छापे आदि की भूलें रह गई हों तो सुधार लेने की कृपा करें.

भारत का विधान

व्योरा

सरलेख

सफा

1

भाग एक

यूनियन और उसका भूभाग

दफा

- | | | | |
|---|---|-----|-----|
| 1 | यूनियन का नाम और भूभाग | ... | 2 |
| 2 | नई रियासतों को दाखिल करना या क़ायम करना | ... | 2 |
| 3 | नई रियासतों का बनाना और मौजूदा रियासतों के छेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलना | ... | 2—3 |
| 4 | दफा 2 और 3 के अधीन बने क़ानूनों में पहली और चौथी पट्टी के सुधार के लिए और पूरक, प्रसंगी और परिनामो मामलों के लिये बंधान | ... | 3 |

भाग दो

नागरता

- | | | | |
|----|---|-----|-----|
| 5 | विधान के आरम्भ होने पर नागरता | ... | 4 |
| 6 | कुछ ऐसे लोगों के नागरता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत में आ बसे हैं | ... | 4—5 |
| 7 | पाकिस्तान में जा बसने वाले कुछ लोगों के नागरता के अधिकार | ... | 5 |
| 8 | भारत के बाहर बसने वाले हिन्दी निकास के कुछ लोगों के नागरता के अधिकार | ... | 5 |
| 9 | अपनी धरती से किसी विदेशी राज की नागरता हासिल करने वाले लोगों का नागर न होना | ... | 6 |
| 10 | नागरता के अधिकारों का जारी रहना | ... | 6 |

दफ़ा	सफ़ा
11 राजपंचायत का क़ानून बना कर नागरता के अधिकार की क़ायदाबन्दी करना ...	6

भाग तीन

मूल अधिकार

आम

12 परिभाषा ...	7
13 मूल अधिकारों से मेल न खाने वाले या उनको कम करने वाले क़ानून ...	7

बराबरी का अधिकार

14 क़ानून के सामने बराबरी ...	7—8
15 धर्म, नसल, जात, ज़िन्स या जन्मस्थान की बिना पर भेद भाव की मनाही ...	8
16 सरकारी कामगारी के मामलों में बराबरी के मौक़े ...	8—9
17 अछूतपन का अन्त ...	9
18 ख़िताबों का अन्त ...	9

आज़ादी का अधिकार

19 बोलने वगैरा की आज़ादी के बारे में कुछ अधिकारों की रक्षा ...	9—11
20 जुमों का दोषी ठहराए जाने के बारे में रक्षा ...	11
21 जान और निजी स्वतंत्रता की रक्षा ...	11
22 कुछ सूत्रों में गिरफ़्तारी और नज़रबन्दी से रक्षा ...	11—13

शोशन के ख़िलाफ़ अधिकार

23 इन्सानों के ब्यापार और ज़बरी मज़दूरी की मनाही ...	13
24 फ़ैक्टरियों वगैरा में बच्चों को काम पर लगाने की मनाही ...	13

धार्मिक आज़ादी का अधिकार

25 अन्तरात्मा को आज़ादी और किसी धर्म को मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी ...	14
26 धार्मिक मामलों का प्रबन्ध करने की आज़ादी ...	14

दफ़ा	सफ़ा
27 किसी विशेष धर्म को बढ़ाने के लिये टैक्स देने के बारे में आज्ञादी ...	15
28 कुछ तालीमी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा-बन्धों में हाज़िरी के बारे में आज्ञादी ...	15
<i>कलचरी और तालीमी अधिकार</i>	
29 कमीयतों के हितों की रक्षा ...	15
30 कमीयतों को तालीमी संस्थाएँ क़ायम करने और उनके प्रबन्ध करने का अधिकार ...	15—16
<i>जायदाद का अधिकार</i>	
31 जायदाद का जबरन हासिल करना ...	16—17
<i>विधानी उपायों का अधिकार</i>	
32 इस भाग में दिये अधिकारों पर अमल कराने के लिये उपाय ...	17—18
33 इस भाग में दिये अधिकारों के फ़ौजों के लिये छागू हाने पर उनमें अदल बदल करने की राजपंचायत की शक्ति ...	18
34 जब किसी छेत्र में फ़ौजी क़ानून छागू हो तो इस भाग में दिये अधिकारों पर रुकावट ...	18
35 इस भाग के बन्धानों को अमल में लाने के लिये क़ानून बनाना ...	18—19

भाग चार

राज की नीति के निर्देशक सिद्धान्त

36 परिभाषा ...	20
37 इस भाग में आए सिद्धान्तों को छागू करना ...	20
38 लोगों की खुशहाली बढ़ाने के लिये राज का एक समाजी व्यवस्था को पक्का करना ...	20
39 नीति के कुछ सिद्धान्त जिन पर राज चलेंगा ...	20—21
40 गाँव-पंचायतों का संगठन ...	21
41 काम, तालीम और कुछ सूतों में सरकारी मदद पाने का अधिकार ...	21

दफा	सफा
42 काम- की हालतों में न्याय और इनसानियत का और जापा मदद का प्रबन्ध ...	21
43 कामगारों के लिये पेट भर मजदूरी वगैरा ...	21
44 नागरों के लिये एक सी दोबानी पद्धत ...	21
45 बच्चों के लिये मुफ्त और ज़बरी तालिम का प्रबन्ध ...	21
46 पट्टी-दर्ज जातियों, पट्टी-दर्ज कबीलों और दूसरी निबल टुकड़ियों के तालीमी और आर्थिक हितों को बढ़ाना ...	21
47 तनपालन-तल और जीवनस्तर को ऊँचा करना और जन-तन्दुरुस्ती को सुधारना राज का फ़रज़ ...	22
48 खेती बाड़ी और पशु-पालन का संगठन ...	22
49 क़ौमी महत्व की यादगारों और जगहों और चोज़ों की रक्षा ...	22
50 काजकारी से न्यायकारी का अलग करना ...	22
51 अन्तर-क़ौमी शान्ति और सुरक्षा को बढ़ाना ...	22

भाग पाँच

यूनियन

खंड एक—काजकारी

राजपति और उप-राजपति

52 भारत का राजपति ...	23
53 यूनियन की काजकारी शक्ति ...	23
54 राजपति का चुनाव ...	23
55 राजपति के चुनाव का ढंग ...	23—24
56 राजपति की पद-भियाब ...	24—25
57 फिर चुनाव के लिये पात्रता ...	25
58 राजपति चुने जाने के लिये षोगताएँ ...	25
59 राजपति के पद की शर्तें ...	25—26
60 राजपति का हलफ़ उठाना या बचन भरना ...	26
61 राजपति पर दोष लगाने का दस्तूर ...	26—27

दृष्टा	सफा
62 राजपति के पद की सूची को भरने के लिए चुनाव का समय और औसरी सूची भरने के लिये चुने आदमी की पद-मियाद ...	27
63 भारत का उप-राजपति ...	27
64 उप-राजपति पदनाते रियासत सदन का मसनदी होगा...	27
65 राजपति की ना-मौजूदगी में या उसके पद की औसरी सूचियों के समय उप-राजपति का राजपति की जगह काम करना या उसके पद के काम निभारना ...	28
66 उप-राजपति का चुनाव ...	28—29
67 उप-राजपति की पद-मियाद ...	29
68 उप-राजपति के पद की सूची को भरने के लिये चुनाव का समय और औसरी सूची भरने के लिये चुने आदमी की पद-मियाद ...	29—30
69 उप-राजपति का हलफ उठाना या वचन भरना ...	30
70 दूसरे जोगाजोगों में राजपति के कामों को निभारना ...	30
71 राजपति या उप-राजपति के चुनाव के बारे में या उससे संबंध रखने वाले मामले ...	30
72 कुछ सूतों में माफ़ी वगैरा देने और सज़ाओं के हुकुम को रोके रखने या कम करने या बदलने की राजपति की शक्ति ..	31
73 यूनिशन की काजकारी शक्ति का फैलाव ...	31—32

वज़ीर मंडल

74 राजपति को सहायता और सलाह देने के लिये वज़ीर मंडल ...	32
75 वज़ीरों के बारे में दूसरे बन्धान ...	32—33

भारत का सरमुखतार

76 भारत का सरमुखतार ...	33
-------------------------	----

सरकारी काम का संचालन

77 भारत सरकार के काम का संचालन ...	33—34
------------------------------------	-------

दृष्टा	संका
78 राजपति को सूचना देने बगैरा के बारे में प्रधान वज्जीर के फ़रज़	34

खंड दो—राजपंचायत

आम

79 राजपंचायत की बनावट	34
80 रियासत सदन की रचना	34—35
81 लोकसदन की रचना	35—36
82 भाग (सी) की रियासतों के और रियासतों को छोड़कर दूसरे भूभागों के प्रतिनिधान के बारे में खास बन्धान	36
83 राजपंचायत के सदनों की मुद्दत	36
84 राजपंचायत की मेम्बरी के लिये जोगता	37
85 राजपंचायत के इजलास, उसे बरखास्त करना और भंग करना	37
86 राजपति को सदनों में सर-बचन देने और संदेसे भेजने का अधिकार	37
87 हर इजलास के आरंभ में राजपति का खास सर-बचन	38
88 सदनों के बारे में वज्जीरों और सरमुखतार के अधिकार	38

राजपंचायत के अफ़सर

89 रियासत सदन का मसनदी और उप-मसनदी	38
90 उप-मसनदी का पद सूना होना, उसका इस्तीफ़ा देना और पद से हटाया जाना	38—39
91 उप-मसनदी को या किसी दूसरे आदमी को मसनदी के पद के फ़रज़ पूरे करने या मसनदी की जगह काम करने की शक्ति	39
92 मसनदी या उप-मसनदी उस समय सदारत नहीं करेगा जब कि उसको पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार किया जा रहा हो	39—40
93 लोक सदन का समामुख और उप-समामुख	40
94 समामुख और उप-समामुख का पद सूना होना, उनका इस्तीफ़ा देना और पद से हटाया जाना	40

दफ़ा	सफ़ा
95 उप-सभामुख या किसी दूसरे आदमी को सभामुख के पद के फ़रज़ पूरा करने या सभामुख की जगह काम करने की शक्ति ...	40—41
96 सभामुख या उप-सभामुख सदारत नहीं करेगा जब कि उसको पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार किया जा रहा हो ...	41
97 मसनदी और उप-मसनदी और सभामुख और उप-सभामुख की तनखाहें और भत्ते ...	41
98 राजपंचायत की मंत्रायत ...	41—42

काम का संचालन

99 मेम्बरों का हलफ़ उठाना या वचन भरना ...	42
100 सदनों में वोट लेना, सूनियाँ होने पर भी सदनों को काम करने की शक्ति, और कोरम ...	42—43

मेम्बरों की अजोगताएं

101 सीटों का सूना होना ...	43—44
102 मेम्बरों के लिये अजोगताएं ...	44
103 मेम्बरों की अजोगताओं के बारे में सवालों पर फ़ैसला ...	44
104 दफ़ा 99 के अधीन हलफ़ उठाने या वचन भरने से पहले या जोग न होने या अजोग ठहराए जाने पर बैठने और वोट देने पर दंड ...	45

राजपंचायत और उसके मेम्बरों की शक्तियाँ, उनके

निजनियम और उनकी बरीयतें

105 राजपंचायत के सदनों की और उनके मेम्बरों और कमेटियों की शक्तियाँ, निजनियम वगैरा ...	45—46
106 मेम्बरों की तनखाहें और भत्ते ...	46

कानूनकारी दस्तूर

107 बिल रखने और पास करने के बारे में बन्धान ...	46
108 कुछ सूतों में दोनों सदनों की मिजीजुली बैठक ...	46—48
109 नक़दी बिलों के बारे में खास दस्तूर ...	48—49

दफ़ा		सफ़ा
110	“नक्रदी बिल” की परिभाषा	49—50
111	बिलों पर मंजूरी	50—51

माली मामलों में दस्तूर

112	सालाना माली व्योरा	51—52
113	तख्मीनों के बारे में राजपंचायत का दस्तूर	53
114	मद्-बटबारा बिल	53—54
115	पूरक, सहायक या अधिक देनगियां	54
116	हिसाब पर वोट, साख की वोट और अलग देनगियां	55
117	माली बिलों के बारे में खास बन्धान	56

आम दस्तूर

118	दस्तूर के नियम	56—57
119	माली काम के सम्बन्ध में राजपंचायत के दस्तूर की क़ानून से क़ायदाबन्दी	57
120	राजपंचायत में काम में आने वाली भाषा	57—58
121	राजपंचायत में बहस पर रुकावट	58
122	राजपंचायत की कारवाई के बारे में अदालतें पूछताछ नहीं करेंगी	58

खंड तीन—राजपति की क़ानूनकारी शक्तियां

123	राजपंचायत की छुट्टी के दिनों में राजपति को राजहुकुम जारी करने की शक्ति	58—59
-----	--	-------

खंड चार—यूनियन की म्यायकारी

124	आला अदालत का क़ायम होना और उसकी बनावट	59—60
125	जजों की तनखाहें वगैरा	61
126	कारकर सरजज का नियोजन	61
127	ज़रूरती जजों का नियोजन	61—62
128	आला अदालत की बैठकों में सेवामुक्त जजों का आना	62
129	आला अदालत एक नज़ीरी अदालत होगी	62
130	आला अदालत के बैठने की जगह	62
131	आला अदालत को पहली सुनवाई का अधिकार	63

दफ़ा	सफ़ा
132 कुछ सूत्रों में आला अदालत को हाईकोर्टों की अपीलें सुनने की अपीली अमलदारी ...	63—64
133 दीवानी मामलों के बारे में हाईकोर्टों की अपीलें सुनने की आला अदालत की अपीली अमलदारी ...	64—65
134 फ़ौजदारी मामलों के बारे में आला अदालत की अपीली अमलदारी ...	65—66
135 मौजूदा क़ानून के अधीन संघ अदालत की अमलदारी और शक्तियों से आला अदालत का काम ले सकना ...	66
136 आला अदालत का अपील की खास इजाज़त देना ...	66
137 आला अदालत की फ़ैसलों या हुकुमों पर नज़रसानी ...	66
138 आला अदालत की अमलदारी को बढ़ाना ...	66—67
139 आला अदालत को कुछ परवाने जारी करने की शक्तियाँ सौंपना ...	67
140 आला अदालत की सहायक शक्तियाँ ...	67
141 आला अदालत जो क़ानून ठहरा दे उस से सब अदालतें बंधी होंगी ...	67
142 आला अदालत को डिगिरियों और हुकुमों पर अमल, और खोज बग़ैरा के बारे में हुकुम ...	67—68
143 राजपति को आला अदालत से राय लेने की शक्ति ...	68
144 दीवानी और न्यायकारी अधिकारियों का आला- अदालत की मदद के लिये काम करना ...	68
145 अदालत के नियम बग़ैरा ...	68—70
146 आला अदालत के अफ़सर और नौकर और खर्च ...	70—71
147 अर्थ ...	71

खंड पांच—भारत का दाब अफ़सर और सर पड़तालिया

148 भारत का दाब अफ़सर और सर पड़तालिया ...	71—72
149 दाब अफ़सर और सर पड़तालिया के फ़रज और शक्तियाँ...	73
150 दाब अफ़सर और सर पड़तालिया को हिसाब किताब के सम्बन्ध में निर्देश देने की शक्ति ...	73

दफ़ा		सफ़ा
151	पञ्चाल की रिपोर्टें	73

भाग छै

पहली पट्टी के भाग (ए) की रियासतें

खंड एक—ग्राम

152	परिभाषा	74
-----	---------	----

खंड दो—काजकारी

रियासतपति

153	रियासतों के रियासतपति	74
154	रियासत की काजकारी शक्ति	74
155	रियासतपति का नियोजन	74
156	रियासतपति की पद-मियाद	74—75
157	रियासतपति नियोजे जाने के लिये जोगनाएं	75
158	रियासतपति के पद की शर्तें	75
159	रियासतपति का हल्फ़ उठाना या वचन भरना	75—76
160	कुछ जोगाजोगों में रियासतपति के काम निभारना	76
161	रियासतपति को कुछ सूरतों में माफ़ी वगैरा देने और सज़ा के हुकुमों को रोके रखने, बाकी हुकुम रद्द कर देने या सज़ा का रूप बदल देने की शक्ति	76
162	रियासत की काजकारी शक्ति का फैलाव	76

वज़ीर मंडल

163	रियासतपति को सहायता और सलाह देने के लिये वज़ीर मंडल	77
164	वज़ीरों के बारे में दूसरे बन्धान	77—78

रियासत का सर वकील

165	रियासत का सर वकील	78
-----	-------------------	----

सरकारी काम का संचालन

166	किसी रियासत की सरकार के काम का संचालन	78—79
167	रियासतपति को सूचना देने वगैरा के बारे में बड़े वज़ीर के फ़रज़	79

दफा	सफा
खंड तीन—रियासत की क़ानून सभा	
आम	
168 रियासतों की क़ानून सभाओं को बनावट	79
169 रियासतों में खास सदनों का अन्त करना या बनाना ...	79—80
170 आम सदनों की रचना ...	80
171 खास सदनों की रचना	81—82
172 रियासत की क़ानून सभाओं की सुदत	82—83
173 रियासत की क़ानून सभा की मेम्बरी के लिये जोगता ..	83
174 रियासत की क़ानून सभा के इजलास, उनका बरखास्त करना और भंग करना ...	83
175 रियासतपति को सदन या सदनों में सर-बचन देने या संदेसे भेजने का अधिकार ...	83—84
176 हर इजलास के आरम्भ में रियासतपति का खास सर-बचन	84
177 सदनों के बारे में वज़ीरों और सर वकील के अधिकार	84
रियासत की क़ानून सभा के अफ़सर	
178 आम सदन का सभामुख और उप-सभामुख	84
179 सभामुख और उप-सभामुख का पद सूना होना, उनका इस्तीफ़ा देना और पद से हटाया जाना ...	85
180 उप-सभामुख को या किसी दूसरे आदमी को सभामुख के पद के फ़रज़ पूरा करने या सभामुख की जगह काम करने की शक्ति ...	85
181 जब उसको पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार किया जा रहा हो तब सभामुख या उप-सभामुख सदारत नहीं करेगा ...	85—86
182 खास सदन का मसनदी और उप-मसनदी ...	86
183 मसनदी और उप-मसनदी का पद सूना होना, उनका इस्तीफ़ा देना और पद से हटाया जाना ...	86—87
184 उप-मसनदी या किसी दूसरे आदमी को मसनदी के पद के फ़रज़ पूरा करने या मसनदी की जगह काम करने की शक्ति ...	87

दफा		सफा
185	जब उसको उसके पद से हटाने के लिए किसी ठहराव पर विचार किया जा रहा हो तो मसनदी या उप-मसनदी सदारत नहीं करेगा	87
186	मसनदी और उप-मसनदी और सभामुख और उप-सभामुख की तनखाहें और भत्ते	87—88
187	रियासत की क़ानून सभा की मंत्रायत	88

काम का संचालन

188	मेम्बरों का हलफ उठाना या वचन भरना	88
189	सदनों में वोट लेना, सीटें सूनी होने पर भी सदनों को काम करने की शक्ति और कोरम	88—89

मेम्बरों की अजोगताएं

190	सीटों का सूना होना	89—90
191	मेम्बरी के लिये अजोगताएं	90—91
192	मेम्बरों की अजोगताओं के बारे में सवालों का फ़ैसला	91
193	दफा 188 के अधीन हलफ उठाने या वचन भरने से पहले या जोग न होने या अजोग ठहराए जाने पर सदन में बैठने और वोट देने पर दंड	91—92

रियासत की क़ानून सभाओं और उनके मेम्बरों की शक्तियां,

निजनियम और बरीयतें

194	क़ानून सभाओं के सदनों, उनके मेम्बरों और उनकी कमे-टियों की शक्तियां, निजनियम बगैरा	92
195	मेम्बरों की तनखाहें और भत्ते	93

क़ानूनकारी दस्तूर

196	बिल रखने और पास करने के बारे में बन्धान	93
197	नक़दी बिलों को छोड़ कर दूसरे बिलों के सम्बन्ध में खास सदन की शक्तियों पर रुकावट	93—94
198	नक़दी बिलों के बारे में खास दस्तूर	94—95
199	“नक़दी बिलों” की परिभाषा	95—97
200	बिलों पर मंजूरी	97

दफ़ा		सफ़ा
201	विचार के लिये रखे हुए बिल	97—98
	माली मामलों में दस्तूर	
202	सालाना माली ब्योरा	98—99
203	तख्मीनों के बारे में क़ानून सभा का दस्तूर	99
204	मद्-बटवारा बिल	99—100
205	पूरक, सहायक या अधिक देनगियां	100—101
206	हिसाब पर वोट, साख की वोट और अलग देनगियां	101—102
207	माली बिलों के बारे में खास बन्धान	102—103
	आम दस्तूर	
208	दस्तूर के नियम	103
209	माली काम के सम्बन्ध में रियासत की क़ानून सभा के दस्तूर की क़ानून से क़ायदाबन्दी	103—104
210	क़ानून सभा में काम में आने वाली भाशा	104
211	क़ानून सभा में बहस पर रुकावट	104
212	क़ानून सभा की कारवाइयों के बारे में अदालतें पूछताह नहीं करेंगी	104
	खंड चार—रियासतपति की क़ानूनकारी शक्ति	
213	क़ानून सभा की छुट्टी के दिनों में रियासतपति को राज-हुकुम जारी करने की शक्ति	105—106
	खंड पांच—रियासतों की हाईकोर्टें	
214	रियासतों के लिये हाईकोर्टें	106—107
215	हाईकोर्टें नज़ीरी अदालतें होंगी	107
216	हाईकोर्टों की बनावट	107
217	हाईकोर्ट के हर जज का नियोजन और उसके पद की शतें	107—108
218	आला अदालत से सम्बन्ध रखने वाले कुछ बन्धानों का हाईकोर्टों पर लागू होना	108
219	हाईकोर्टों के जजों का हलफ़ उठाना या वचन भरना	108—109
220	जजों को अदालतों में या किसी अधिकारी के सामने वक़ालत करने की मनाही	109

दफा	सफा
221 जजों की तनखाहें बगैरा	109
222 किसी जज का एक हाईकोर्ट से दूसरी में तबादला	109
223 कारकर सरजज का नियोजन	109
224 हाईकोर्टों की बैठकों में सेवामुक्त जजों का आना	110
225 मौजूदा हाईकोर्टों की अमलदारी	110—111
226 कुछ परवाने जारी करने की हाईकोर्टों की शक्ति	111
227 हाईकोर्ट को सब अदालतों पर निगरानी रखने की शक्ति	111—112
228 कुछ मुकदमों का हाईकोर्ट में तबादला	112
229 हाईकोर्टों के अफसर, नौकर और खर्च	112—113
230 हाईकोर्टों की अमलदारी को बढ़ाना या कम करना	113
231 किसी रियासत की किसी ऐसी हाईकोर्ट की अमलदारी के सम्बन्ध में रियासतों की कानून सभाओं की कानून बनाने की शक्तियों पर रुकावटें जिस हाईकोर्ट की अमलदारी उस रियासत के बाहर भी हो	113—114
232 अर्थ	114—115
खंड छै—मातहत अदालतें	
233 जिला जजों का नियोजन	115
234 न्यायी नौकरी में जिला जजों को छोड़ कर और लोगों की भरती	115
235 मातहत अदालतों पर दबान	115
236 अर्थ	115—116
237 इस खंड के बन्धानों का मजिस्ट्रेटों की किसी खास जमात या जमातों पर लागू होना	116

भाग सात

पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतें

238 पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों पर भाग छै के बन्धानों का लागू होना	117—119
---	---------

भाग आठ

पहली पट्टी के भाग (सी) की रियासतें

239 पहली पट्टी के भाग (सी) की रियासतों का शासन	120
--	-----

दफ़ा	सफ़ा
240	मुकामी क़ानून सभाओं या सलाहकार मंडल या वज़ीर मंडल का बनाना या जारी रखना ... 120—121
241	पहली पट्टी के भाग (सी) की रियासतों के लिये हार्डिकोट ... 121
242	कुर्ग ... 121—122

भाग नौ

पहली पट्टी के भाग (डी) के भूभाग और वह दूसरे
भूभाग जो उस पट्टी में दर्ज नहीं हैं

243	पहली पट्टी के भाग (डो) में दर्ज भूभागों का और उन दूसरे भूभागों का शासन जो उस पट्टी में दर्ज नहीं हैं ... 123
-----	---

भाग दस

पट्टी-दर्ज छेत्र और क़बायली छेत्र

244	पट्टी-दर्ज छेत्रों और क़बायली छेत्रों का शासन ... 124
-----	---

भाग ग्यारह

यूनियन और रियासतों के बीच सम्बन्ध

खंड एक—क़ानूनकारी सम्बन्ध

क़ानूनकारी शक्तियों का बटवारा

245	राजपंचायत के बनाए और रियासतों की क़ानून सभाओं के बनाए क़ानूनों का फैलाव ... 125
246	राजपंचायत के बनाए और रियासतों की क़ानून सभाओं के बनाए क़ानूनों का विषय ... 125—126
247	कुछ अधिक अदालतों को क़ायम करने के लिये बन्धान करने की राजपंचायत की शक्ति ... 126
248	क़ानून बनाने की बची शक्तियाँ ... 126
249	क़ौमी हित के लिये रियासत तालिका के किसी मामले के बारे में राजपंचायत को क़ानून बनाने की शक्ति ... 126—127
250	अज्ञानकी का कोई ऐलान अमल में होने की सूत्र में रियासत तालिका के किसी भी मामले के बारे में राज- पंचायत को क़ानून बनाने की शक्ति ... 127

दफ़ा	सफ़ा
251 दफ़ा 249 और 250 के अधीन राजपंचायत के बनाए क़ानूनों का रियासतों की क़ानून सभाओं के बनाए क़ानून के साथ अनमेल	... 127—128
252 राजपंचायत को दो या अधिक रियासतों के लिये उनकी अनुमति से क़ानून बनाने की शक्ति और किसी दूसरी रियासत का ऐसे क़ानूनों को अपनाना	... 128
253 अन्तर-क्रौमी समझौतों पर अमल कराने के लिये क़ानून बनाना	... 128
254 राजपंचायत के बनाए क़ानूनों और रियासतों की क़ानून सभाओं के बनाए क़ानूनों में अनमेल	... 129
255 सिफ़ारिशों के और पहले से मंज़ूरियां लेने के दरकार होने को सिर्फ़ दस्तूरी मामला समझा जायगा	... 129—130

खंड दो

शासनी संबंध

आम

256 रियासतों की और यूनिन की ज़िम्मेदारी	... 130
257 कुछ सूरतों में यूनिन का रियासतों पर दबान	... 130—131
258 कुछ सूरतों में रियासतों को शक्तियां वगैरा देने की यूनिन को शक्ति	... 131—132
259 पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों में इथियार बन्द फ़ौजें	... 132
260 भारत के बाहर भूभागों के संबंध में यूनिन को अमलदारी	... 132
261 सरकारी काम, लेखे और अदालती कारवाइयां	... 132—133

पानी के संबंध में झगड़े

262 अन्तर-रियासती नदियों या उनकी घाटियों के पानी के सम्बन्ध में झगड़ों का अदालती फ़ैसला	... 133
---	---------

रियासतों के बीच तालमेल

263 अन्तर-रियासती मंडल के बारे में बन्धान	... 133
---	---------

दफ़ा

सफ़ा

भाग बारह

माल, जायदाद, ठेके और नालिशें

खंड एक—माल

आम

- 264 अर्थ ... 134
- 265 क़ानून के अधिकार सिवा टैक्स नहीं लगाए जायेंगे ... 134
- 266 भारत के और रियासतों के मूठकोश और सरकारी
हि़साब ... 134—135
- 267 जोगाजोग कोश ... 135
यूनियन और रियासतों के बीच मालगुज़ारी का बटवारा
- 268 वह महसूल जिन्हें यूनियन लगाए पर जिन्हें रियासतें
जमा करें और खर्च की मदों में डाले ... 135—136
- 269 वह टैक्स जो यूनियन लगाए और जमा करे पर जो
रियासतों के नाम कर दिये जायें ... 136—137
- 270 वह टैक्स जो यूनियन लगाए और जमा करे और जो
यूनियन और रियासतों के बीच बाँटे जायें ... 137—138
- 271 कुछ महसूलों और टैक्सों पर यूनियन के मतलबों के लिये
अधिक-टैक्स ... 138
- 272 वह टैक्स जो यूनियन लगाती है और जमा करती है और
जो यूनियन और रियासतों के बीच बाँटे जा सकते हैं ... 138
- 273 पटसन और पटसन से बनी चोज़ों पर निकासी-महसूल के
बदलें में देनगियाँ ... 138
- 274 जिन टैक्सों में रियासतों का हित हो उन पर असर डालने
वाले बिलों पर राजपति की पहले से सिफ़ारिश दरकार ... 139
- 275 यूनियन की तरफ़ से कुछ रियासतों को देनगियाँ ... 139—140
- 276 पेशों, ब्योपारों, रोज़गारों और कामगारियों पर टैक्स ... 140—141
- 277 बचावे ... 141—142
- 278 कुछ माली मामलों के सम्बन्ध में पहली पट्टी के भाग
(बी) की रियासतों से समझौता ... 142

दफ़ा	सफ़ा
279 "असल बसूली" का हिसाब लगाना, वगैरा	... 143
280 माल कमीशन	... 143—144
281 माल कमीशन की सिफ़ारिशें	... 144

फुटकर माली बन्धान

282 खर्चा जो यूनियन या कोई रियासत अपना मालगुज़ारी में से कर सकती है	... 144
283 मूठकोश, जोगाजोग कोश और सरकारी हिसाबों में जमा हुई रक़मों की रखवाली वगैरा	... 144—145
284 सायलों की जमा की हुई रक़मों और उन दूसरी रक़मों की रखवाली जो सरकारी नौकरों और अदालतों को मिलें	... 145
285 यूनियन की जायदाद का रियासती टैक्सों से बरी होना	... 146
286 माल की बिकरी या खरीद पर टैक्स लगाने के सम्बंध में रुकावटें	... 146—147
287 बिजली के टैक्सों से बरी होना	... 147—148
288 कुछ सूरतों में पानी या बिजली के बारे में रियासतों के टैक्सों से बरी होना	... 148
289 रियासत की जायदाद और आमदनी का यूनियन के टैक्सों से बरी होना	... 148—149
290 कुछ खर्चों और पेनशनों के बारे में बैठ-बिठाव	... 149—150
291 शासकों की निजी थैलियों की रक़में	... 150

खंड दो—उधार लेना

292 भारत सरकार का उधार लेना	... 150—151
293 रियासतों का उधार लेना	... 151

खंड तीन—जायदाद, ठेके, अधिकार, देनदारियां,

ज़िम्मेदारियां और नालिशें

294 कुछ सूरतों में जायदाद, लेनदारियों, अधिकारों, देनदारियों और ज़िम्मेदारियों का बिरसा	... 151—152
--	-------------

दफ़ा	सफ़ा
295 दूसरी सूरतों में जायदाद, लेनदारियों, अधिकारों, देन- दारियों और ज़िम्मेदारियों का विरसा	... 152—153
296 सरकारी ज़ब्त, या हक़ खतम हो जाने, या वारिस न रहने के कारन मिलने वाली जायदाद	... 153—154
297 भूमागी जल में जो क्रीमती चीज़ें हों वह यूनिन को हासिल होंगी	... 154
298 जायदाद हासिल करने की शक्ति	... 154
299 ठेके	... 154—155
300 नाखिशें और कारवाइयां	... 155

भाग तेरह

भारत के भूभाग के अन्दर ब्योपार, तिजारत

और अन्तर-ब्योहार

301 ब्योपार, तिजारत और अन्तर-ब्योहार की आज्ञादी	... 156
302 ब्योपार, तिजारत और अन्तर-ब्योहार पर रुकावटें लगाने की राजपंचायत की शक्ति	... 156
303 ब्योपार और तिजारत के बारे में यूनिन और रियासतों की क़ानूनकारी शक्तियों पर रुकावटें	... 156
304 रियासतों के बीच ब्योपार, तिजारत और अन्तर-ब्योहार पर रुकावटें	... 156—157
305 दफ़ा 301 और 303 का मौजूदा क़ानूनों पर असर	... 157
306 पहली पट्टी के भाग (बी) की कुछ रियासतों को ब्योपार और तिजारत पर रुकावटें लगाने की शक्ति	... 157
307 दफ़ा 301 से 304 तक के मतलबों पर अमल कराने के लिये अधिकारी का नियोजन	... 158

भाग चौदह

यूनिन और रियासतों के अधीन नौकरियां

खंड एक—नौकरियां

308 अर्थ	... 159
----------	---------

दफ़ा	सफ़ा
309 यूनियन की या किसी रियासत की नौकरी करने वाले लोगों की भरती और नौकरी की शर्तें	... 159
310 यूनियन की या किसी रियासत की नौकरी करने वाले आदमियों की पद-मियाद	... 159—160
311 यूनियन या किसी रियासत के अधीन नागरी हैसियत से नौकरी करने वालों का बरखास्त किया जाना, हटाया जाना या रुतबा घटाया जाना	... 160—161
312 कुल-भारत नौकरियां	... 161—162
313 बिचवत्ती बन्धान	... 162
314 कुछ नौकरियों के मौजूदा अफ़सरों की रक्षा के लिये बन्धान	... 162

खंड दो —सरकारी नौकरी कमीशन

315 यूनियन के लिये और रियासतों के लिये सरकारी नौकरी कमीशन	... 162—163
316 मेम्बरों का नियोजन और पद-मियाद	... 163—164
317 किसी सरकारी नौकरी कमीशन के मेम्बर का हटाया जाना और मुअत्तल किया जाना	... 164—165
318 कमीशन के मेम्बरों और अमले की नौकरी की शर्तों के बारे में क्रायदाबन्दी करने की शक्ति	... 165
319 कमीशन के मेम्बरों को मेम्बर न रहने के बाद पदों पर रहने के बारे में मनाही	... 166
320 सरकारी नौकरी कमीशनों के काम	... 166—169
321 सरकारी नौकरी कमीशनों के कामों को बढ़ाने की शक्ति	... 169
322 सरकारी नौकरी कमीशनों के खर्च	... 169
323 सरकारी नौकरी कमीशनों की रिपोर्टें	... 169—170

भाग पंद्रह

चुनाव

324 चुनावों की निगरानी, निर्देशन और दबान एक चुनाव कमीशन के हाथ में रहेगा	... 171—172
---	-------------

दफ़ा	सफ़ा
325 धर्म, नसल, जाल या जिनस की बिना पर कोई आदमी किसी खास चुनाव चिट्ठे में शामिल होने का अपात्र न होगा और न शामिल किये जाने का दावा करेगा ...	172
326 लोक सदन के लिये और रियासतों के आम सदनों के लिये चुनाव बालिग वोट के आधार पर होंगे ...	172—173
327 कानून सभाओं के चुनावों के बारे में राजपंचायत को बन्धान करने की शक्ति ...	173
328 किसी रियासत की कानून सभा की उस कानून सभा के चुनावों के बारे में बन्धान करने की शक्ति ...	173
329 चुनाव के मामलों में अदालतों के दखल देने पर रोक ...	173—174

भाग सोलह

कुछ जमातों से संबंध रखने वाले खास बन्धान

330 लोक सदन में पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज कबीलों के लिये सीटें अलग रखना ...	175
331 लोक सदन में ऐंग्लो इन्डियन समाज का प्रतिनिधान ...	175
332 रियासतों के आम सदनों में पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज कबीलों के लिये सीटों का अलग रखा जाना ...	175—176
333 रियासतों के आम सदनों में ऐंग्लो इन्डियन समाज का प्रतिनिधान ...	176
334 सीटों का अलग रखा जाना और खास प्रतिनिधान दस साल बाद बन्द ...	176—177
335 नौकरियों और जगहों के लिये पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज कबीलों के दावे ...	177
336 कुछ नौकरियों में ऐंग्लो इन्डियन समाज के लिये खास बन्धान ...	177—178
337 ऐंग्लो इन्डियन समाज के फ़ायदे के लिये तालीमी देन-गियों के बारे में खास बन्धान ...	178
338 पट्टी-दर्ज जातों, पट्टी-दर्ज कबीलों वगैरा के लिये खास अफ़सर ...	178—179

वक्रा	सक्रा
339 पट्टो-दर्ज छेत्रों के शासन और पट्टी-दर्ज कबीलों को भलाई पर यूनिशन का दबान	... 179
340 पिछड़ी हुई जमातों की हालत की जाँच करने के लिये कमीशन का नियोजन	... 179—180
341 पट्टो-दर्ज जातें 180
342 पट्टी-दर्ज कबीले	... 180—181

भाग सतरह

दफ़्तरी भाषा

खंड एक—यूनिशन की भाषा

343 यूनिशन की दफ़्तरी भाषा	... 182
344 दफ़्तरी भाषा पर कमीशन और राजपंचायत की कमेटी	... 183—184

खंड दो

इलाक़ा भाषाएं

345 किसी रियासत की दफ़्तरी भाषा या भाषाएं	... 184
346 एक रियासत और दूसरी रियासत के बीच या किसी रियासत और यूनिशन के बीच आपसी व्योहार की दफ़्तरी भाषा	... 184—185
347 किसी रियासत की आबादी की किसी टुकड़ी में बोली जाने वाली भाषा के बारे में खास बन्धान	... 185

खंड तीन—आला अदालत, हाईकोर्टों वगैरा की भाषा

348 आला अदालत में और हाईकोर्टों में और एक्टों, जिलों वगैरा के लिये काम में जाने वाली भाषा	... 185—186
349 भाषा के संबंध में कुछ क़ानूनों के बनाए जाने के लिये खास इस्तुर	... 186

खंड चार—खास निर्देश

350 तकलीफ़ों के दूर कराने के लिये अरज़ी पत्रों में काम जाने वाली भाषा 187
351 हिन्दी भाषा के विकास के लिये निर्देश 187

दफ़ा

सफ़ा

भाग अठारह

अचानकी बन्धान

- 352 अचानकी का ऐलान ... 188—189
- 353 अचानकी के ऐलान का असर ... 189
- 354 जब अचानकी का कोई ऐलान अमल में हो तब माल-
गुज़ारी के बटवारे के संबन्ध के बन्धानों का छागू होना 189
- 355 रियासतों की बाहरी हमले और भीतरी गड़बड़ी से रक्षा
करना यूनिन का फ़रज़ ... 189—190
- 356 रियासतों में विधानी मशीन के फ़ेल हो जाने की सूत
में बंधान ... 190—192
- 357 दफ़ा 356 के अधीन जारी हुए ऐलान के अधीन क़ानून-
कारी शक्तियों से काम लेना 192—193
- 358 अचानकी के दौरान में दफ़ा 19 के बंधानों का
मुअत्तल रहना 193
- 359 अचानकियों के दौरान में भाग तीन में दिये अधिकारों
पर अमल का मुअत्तल रहना ... 193—194
- 360 माली अचानकी के बारे में बंधान 194—195

भाग उन्नीस

फ़ुटकर

- 361 राजपति और रियासतपतियों और राजप्रमुखों की रक्षा ... 196—197
- 362 देसी रियासतों के शासकों के अधिकार और
निषेधनियम 197
- 363 कुछ सन्धिनामों, समझौतों बग़ैरा से पैदा होने वाले
झगड़ों में अदालतों के दखल देने पर रोक 197—198
- 364 बड़े बन्दरगाहों और हवाई अड्डों के लिये ख़ास
बंधान 198—199
- 365 यूनिन के दिये निर्देशों पर न चल सकने या उन पर
अमल न कर सकने का असर ... 199
- 366 परिभाषाएँ ... 199—203

दफ़ा		सफ़ा
367	अर्थ	204

भाग बीस

विधान में सुधार

368	विधान में सुधार के लिये दस्तूर	205
-----	--------------------------------	-----

भाग इक्कीस

आरज़ी और बिचवक्ती बन्धान

369	रियासत तालिका के कुछ मामलों के बारे में राजपंचायत को क़ानून बनाने की आरज़ी शक्ति, मानो वह मामले संग-चारी तालिका में हों	206
370	जम्मू और काश्मीर रियासत के संबंध में आरज़ी बन्धान	207—208
371	पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों के बारे में आरज़ी बन्धान	208
372	मौजूदा क़ानूनों का अमल जारी रहना और उनका अनुकूलन	208—210
373	कुछ सूतों में उन लोगों के बारे में जो रोकथामी नजर-बन्दी में हैं हुक़म देने की राजपति को शक्ति	210
374	संघ अदालत के जजों के बारे में और संघ अदालत में या कौंसिल समेत सम्राट के सामने चालू कारवाइयों के बारे में बन्धान	210—211
375	इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए अदालतों, अधिकारियों और अफ़सरों का काम करते रहना	212
376	हाईकोर्ट के जजों के बारे में बन्धान	212
377	भारत के दाब अफ़सर और सर पड़तालिया के बारे में बन्धान	212—213
378	सरकारी नौकरी कमीशनों के बारे में बन्धान	213
379	कामचलाल राजपंचायत के और उसके समामुख और उप-समामुख के बारे में बन्धान	213—215
380	राजपति के बारे में बन्धान	215
381	राजपति का वज़ीर मंडल	215—216

- 382 पहली पट्टी के भाग (ए) की रियासतों के लिये काम
चलाऊ क़ानून सभाओं के बारे में बन्धान ... 216—217
- 383 सूबों के गवरनरों के बारे में बन्धान ... 217
- 384 रियासतपतियों के वज़ीर मंडल ... 217
- 385 पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों में काम चलाऊ
क़ानून सभाओं के बारे में बन्धान ... 217
- 386 पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों के लिये
वज़ीरमंडल ... 217—218
- 387 कुछ चुनावों के मतलबों के लिये आबादी तय करने के
बारे में खास बन्धान ... 218
- 388 काम चलाऊ राजपंचायत में और रियासतों की काम
चलाऊ क़ानून सभाओं में औसरी सूनियों को भरने के
बारे में बन्धान ... 218—220
- 389 डोमिनियन क़ानून सभा में और सूबों और देसी रियासतों
की क़ानून सभाओं में पेश बिलों के बारे में बन्धान 220
- 390 विधान के आरंभ और 31 मार्च सन् 1950 के बीच
जो रक़में मिलें या जुटाई जायं या जो खर्च किया जाय ... 220—221
- 391 कुछ जोगाजोगों में राजपति को पहली और चौथी पट्टियों
में सुधार करने की शक्ति ... 221
- 392 कठिनाइयों को दूर करने की राजपति की शक्ति ... 221

भाग बाईस

छोटा सरनामा, आरंभ, और रद्द

- 393 छोटा सरनामा ... 222
- 394 आरम्भ ... 222
- 395 रद्द ... 222

पट्टियां

पहली पट्टी—भारत की रियासतें और उसके भूभाग 223—225

दूसरी पट्टी—

भाग (ए)—राजपति के और पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज

रियासतों के रियासतपतियों के बारे में बन्धान 226

- भाग (बी)—यूनियन के और पहली पट्टी के भाग (ए)
और भाग (बी) की रियासतों के बज़ीरों के
बारे में बन्धान 227
- भाग (सी)—लोकसदन के सभामुख और उप-सभामुख,
रियासत सदन के मसनदी और उप-मसनदी,
पहली पट्टी के भाग (ए) की हर रियासत के
आम सदन के सभामुख और उप-सभामुख,
और ऐसी हर रियासत के खास सदन के मसनदी
और उप-मसनदी के बारे में बन्धान ... 227—228
- भाग (डी)—आला अदालत के जजों के बारे में और पहली
पट्टी के भाग (ए) की रियासतों की हाईकोर्टों
के जजों के बारे में बन्धान ... 228—231
- भाग (ई)—भारत के दाब अफसर और सर पड़तालिया के
बारे में बन्धान 231
- तीसरी पट्टी—हलफ या वचन के रूप 232—234
- चौथी पट्टी—रियासत सदन की सीटों का बटवारा 235—236
- पांचवी पट्टी—पट्टी-दर्ज छेत्रों और पट्टी-दर्ज कबीलों के शासन
और दबान के बारे में बन्धान
- भाग (ए)—आम 237
- भाग (बी)—पट्टी-दर्ज छेत्रों और पट्टी-दर्ज कबीलों का
शासन और दबान ... 237—239
- भाग (सी)—पट्टी-दर्ज छेत्र ... 239—240
- भाग (डी)—इस पट्टी में सुधार 240
- छठी पट्टी—आसाम के क्वाइली छेत्रों के शासन के बारे में बन्धान.... 241—259
- सातवीं पट्टी—
- तालिका एक—यूनियन तालिका ... 260—268
- तालिका दो—रियासत तालिका ... 268—273
- तालिका तीन—संगचारी तालिका 273—276
- आठवीं पट्टी—माझाएं ... 277

भारत का विधान

भारत का विधान

सरलेख

हम भारत के लोग गम्भीरता के साथ निश्चय
करके कि भारत को खुद-मालिक लोकशाही जनराज
बनाया जाय, और उसके सब नागरों के साथ :

इनसाफ़ हो, समाजी, धन-दौलती, और राजकाजी;

सबको

आज़ादी हो, विचारों की, उन्हें जाहिर करने की,
विश्वास, धर्म और पूजा बंदगी की;

सबको

बराबरी का दर्जा और बराबरी के मौक़े मिलें; और

सबमें

भाईचारा बढ़े, जिससे हर आदमी का मान और
क़ौम की एकता बनी रहे;

अपनी विधान सभा में, नवम्बर उन्नीस सौ
उनचास के इस छब्बीसवें दिन, आज की इस कारवाई
से, इस विधान को अपनाते हैं, क़ानून बनाते
हैं, और खुद अपने को देते हैं.

भाग एक

यूनियन और उसका भूभाग

यूनियन का नाम
और भूभाग

- 1—(1) इंडिया यानी भारत रियासतों का एक यूनियन होगा.
(2) रियासतें और उनके भूभाग वह रियासतें और उनके भूभाग होंगे जो पहली पट्टी के भाग (ए), (बी) और (सी) में दर्ज हैं.
(3) भारत के भूभाग में—
(ए) रियासतों के भूभाग,
(बी) वह भूभाग जो पहली पट्टी के भाग (डी) में दर्ज हैं, और
(सी) दूसरे ऐसे भूभाग जिन्हें हासिल कर लिया जाय, शामिल होंगे.

नई रियासतों को
दाखिल करना या
क्रायम करना

- 2—राजपंचायत, कानून बनाकर, जिन बन्धनों और शर्तों पर ठीक समझे, नई रियासतों को यूनियन में दाखिल कर सकती है या नई रियासतें क्रायम कर सकती है.

नई रियासतों का
बनाना और मौजूदा
रियासतों के क्षेत्रों,
सीमाओं या नामों
को बदलना

- 3—राजपंचायत कानून बनाकर—

- (ए) किसी रियासत का कोई भूभाग उससे अलग करके, या दो या दो से अधिक रियासतों को या उनके भागों को मिलाकर, या किसी भूभाग को किसी रियासत के किसी भाग से मिलाकर, एक नई रियासत बना सकती है;
(बी) किसी रियासत का क्षेत्र बढ़ा सकती है;
(सी) किसी रियासत का क्षेत्र घटा सकती है;
(डी) किसी रियासत की सीमाएँ बदल सकती है;
(ई) किसी रियासत का नाम बदल सकती है :

शर्तें कि इस मतलब के लिये कोई बिल राजपंचायत के किसी सदन में नहीं रखा जायगा जब तक कि राजपति उसकी सिफारिश न करे और जब तक कि, जहां उस बिल में आए हुए सुझाव से पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत या रियासतों की सीमाओं पर या नाम या नामों पर असर पड़ता है

वहां, राजपति ने उस बिल को रखने के सुझाव और बिल के बन्धानों दोनों के बारे में उस रियासत की या, जैसी सूरत हो, उनमें से हर रियासत की कानून सभा का मत मालूम न कर लिया हो।

4—(1) हर ऐसे कानून में जिसकी चरचा दफा (2) या दफा (3) में की गई है पहली पट्टी और चौथी पट्टी में सुधार करने के लिये ऐसे बंधान रहेंगे जो उस कानून के बंधानों पर अमल कराने के लिये जरूरी हों, और उसमें ऐसे पूरक, प्रसंगी या परिनामी बंधान भी रह सकेंगे जिन्हें राजपंचायत जरूरी समझे (राजपंचायत के या उस रियासत या उन रियासतों की कानून सभा या कानून सभाओं के प्रतिनिधान संबंधी बन्धानों समेत जिस रियासत या रियासतों पर उस कानून का असर पड़ता हो)।

दफा 2 और 3 के अधीन बने कानूनों में पहली और चौथी पट्टी के सुधार के लिये और पूरक, प्रसंगी और परिनामी मामलों के लिये बंधान

(2) ऊपर कहे किसी कानून को दफा 368 के मतलबों के लिये इस विधान का सुधार नहीं समझा जायगा।

भाग दो

नागरता

विधान के आरम्भ होने पर नागरता

5—इस विधान के आरंभ होने पर हर वह आदमी जिसका भारत के भूभाग में निवास है और—

(ए) जो भारत के भूभाग में पैदा हुआ था; या

(बी) जिसके माँ बाप में से कोई भारत के भूभाग में पैदा हुआ था, या

(सी) जो विधान के आरम्भ से ठीक पहले कम से कम पांच बरस तक आम तौर पर भारत के भूभाग में रहता रहा है,

भारत का नागर होगा.

कुछ ऐसे लोगों के नागरता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत में आ बसे हैं

6—दफा 5 में किसी बात के रहते भी, हर वह आदमी, जो उस भूभाग से जो इस समय पाकिस्तान में शामिल है भारत के भूभाग में आ बसा है, इस विधान के आरंभ होने पर भारत का नागर समझा जायगा, अगर—

(ए) वह या उसके माँ बाप में से या उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई उस हिन्द में पैदा हुआ था, जिसकी परिभाषा हिन्द सरकार एक्ट, 1935, में (जैसा वह एक्ट शुरू में बना था) की गई है; और

(बी) (एक) उस सूरत में जब कि वह आदमी जुलाई 1948 के उन्नीसवें दिन से पहले इस तरह आ बसा है, अपने आ बसने की तारीख से वह आम तौर पर भारत के भूभाग में रहता रहा है, या

(दो) उस सूरत में जब कि वह आदमी जुलाई 1948 के उन्नीसवें दिन या उसके बाद इस तरह आ बसा है, उसने, इस विधान के आरंभ होने से पहले, उस रूप में और उस ढंग से जो हिन्द डोमिनियन की सरकार ने तय कर दिया हो, एक अरबी हिन्द का नागर होने के

लिये उस अफसर को दी हो, जिसे हिन्द डोमिनियन की सरकार ने इस काम के लिये नियोजा हो, और उस अफसर ने उसे हिन्द का नागर रजिस्टर कर लिया हो :

शर्ते कि किसी आदमी की इस तरह रजिस्टरी नहीं की जायगी जब तक कि वह अपनी अरजी की तारीख से ठीक पहले कम से कम छै महीने तक भारत के भूभाग में न रह चुका हो.

7—दफा 5 और 6 मे किसी बात के रहते भी, कोई आदमी जो मार्च 1947 के पहले दिन के बाद भारत के भूभाग से उस भूभाग में जा बसा है जो इस समय पाकिस्तान में शामिल है, भारत का नागर नहीं समझा जायगा :

शर्ते कि इस दफा की कोई बात उस आदमी पर लागू नहीं होगी, जो उस भूभाग में जो इस समय पाकिस्तान में शामिल है इस तरह जा बसने के बाद, एक ऐसे परमिट के अधीन भारत के भूभाग में लौट आया है, जो फिर बसने या पक्की बापसी के लिये किसी कानून के अधिकार से या उसके अधीन जारी किया गया हो, और दफा 6 की धारा (बी) के मतलबों के लिये यह समझा जायगा कि हर ऐसा आदमी जुलाई 1948 के उन्नीसवें दिन के बाद भारत के भूभाग में आ बसा है.

पाकिस्तान में जा बसने वाले कुछ छोगों के नागरता के अधिकार

8—दफा 5 में किसी बात के रहते भी, हर वह आदमी जो खुद या जिसके मां बाप में से या दादा दादी या नाना नानी में से कोई उस हिन्द में पैदा हुआ था, जिसकी परिभाषा हिन्द सरकार एक्ट, 1935, में (जैसा वह एक्ट शुरू में बना था) की गई है, और जो, आमतौर पर, इस तरह बताए हिन्द के बाहर किसी देश में रहता हो, भारत का नागर समझा जायगा अगर उसने, इस विधान के आरंभ से पहले या उसके बाद में एक अरजी उस रूप में और उस ढंग से जो हिन्द डोमिनियन की सरकार ने या भारत सरकार ने इस मतलब के लिये तय कर दिया हो, जिस देश में वह उस समय रह रहा हो, वहाँ पर भारत के राजदूती या बनिजदूती प्रतिनिधि को, भारत का नागर बनने के लिये दी हो, और उस राजदूती या बनिजदूती प्रतिनिधि ने उसे भारत का नागर रजिस्टर कर लिया हो.

भारत के बाहर बसने वाले हिन्दी विकास के कुछ छोगों के नागरता के अधिकार

अपनी मरजी से किसी विदेशी राज की नागरता हासिल करने वाले लोगों का नागर न होना

9—दफ्ता 5 की रू से कोई आदमी भारत का नागर नहीं होगा, न दफ्ता 6 या दफ्ता 8 की रू से भारत का नागर समझा जायगा, अगर उसने अपने मरजी से किसी विदेशी राज की नागरता हासिल कर ली है.

नागरता के अधिकारों का जारी रहना

10—हर वह आदमी, जो इस भाग में ऊपर-लिखे बंधानों में से किसी के अधीन भारत का नागर है या समझा जाता है, भारत का नागर बना रहेगा, पर यह बात ऐसे हर कानून के बंधानों का ध्यान रखते हुए होगी जो राजपंचायत बनाए.

राजपंचायत का कानून बनाकर नागरता के अधिकार की क्रायदा-बन्दी करना

11—इस भाग में ऊपर-लिखे बंधानों की कोई बात राजपंचायत की इस शक्ति को कम नहीं करेगी कि वह नागरता हासिल करने, नागरता खतम होने और नागरता संबंधी दूसरे सब मामलों के बारे में कोई भी बंधान करे.



भाग तीन

मूल अधिकार

आम

12—जब तक प्रसंग से कुछ और दरकार न हो, इस भाग में “राज” शब्द के अन्दर, भारत की सरकार और भारत की राज-पंचायत, हर रियासत की सरकार और वहाँ की कानून सभा, और भारत के भूभाग के अन्दर या भारत सरकार के दबान में सब मुकामी या दूसरे अधिकारी, शामिल हैं।

13—(1) इस विधान के आरम्भ से ठीक पहले जितने कानून भारत के भूभाग में अमल में थे वह सब जहाँ तक इस भाग के बंधानों से बेमेल हैं उस बेमेल होने की हद तक रद्द हो जायेंगे।

मूल अधिकारों से मेल न खाने वाले या उनको कम करने वाले कानून

(2) राज कोई ऐसा कानून नहीं बनायगा जिससे लोगों के वह अधिकार छिन जायं या उनमें कमी आ जाय जो इस भाग में दिये गए हैं, और जो भी कानून इस धारा के खिलाफ बनेगा वह, उस खिलाफ होने की हद तक रद्द होगा।

(3) इस दफा में जब तक प्रसंग से कुछ और दरकार न हो,—

(ए) “कानून” शब्द के अन्दर वह सब राज हुकुम, हुकुम, छुट कानून, नियम, क्रायदे, नोटिस, रीत या रिवाज शामिल हैं जो भारत के भूभाग में कानून का असर रखते हैं।

(बी) “अमल में कानून” के अन्दर वह कानून शामिल हैं, जो इस विधान के आरम्भ से पहले भारत के भूभाग के अन्दर किसी कानून सभा या किसी दूसरे हकदार अधिकारी ने पास किये हों या बनाए हों, और जो इससे पहले रद्द न कर दिये गए हों, भले ही ऐसा कोई कानून या उसका कोई भाग उस समय बिलकुल या किन्हीं खास क्षेत्रों में अमल में न हो।

बराबरी का अधिकार

14—राज, भारत के भूभाग के अन्दर किसी आदमी को, कानून कानून के सामने

बराबरी

के सामने बराबरी, या कानूनों के जरिये बराबर की रक्षा, देने से इनकार नहीं करेगा.

धर्म, नसल, जात,
जिन्स या जन्म-
स्थान की बिना
पर भेदभाव की
मनाही

15—(1) राज केवल धर्म, नसल, जात, जिन्स, जन्म-स्थान या इनमें से किसी की बिना पर किसी नागर से भेद भाव नहीं करेगा.

(2) कोई नागर केवल धर्म, नसल, जात, जिन्स, जन्म-स्थान या इन में से किसी की बिना पर नीचे लिखी बातों के बारे में किसी तरह की असक्त, देनदारी, रुकावट या शर्त के अधीन न होगा :—

(प) दुकानों, आम जलपान घरों, होटलों और आम मनोरंजन की जगहों में जासकना; या

(बी) ऐसे कुओं, तलाबों, नहानघाटों, सड़कों और आम लोगों के आने जाने की जगहों का इस्तेमाल करना जिनका कुल या कुछ खर्च राज के रूप से चलता हो या जो आम जनता के इस्तेमाल से लिये दे दी गई हों.

(3) इस दफा की कोई बात राज को औरतों और बच्चों के लिये कोई खास बंधान करने से नहीं रोकेगी.

सरकारी कामगारी
के मामलों में
बराबरी के मौके

16—(1) राज के अधीन कामगारी से या किसी पद पर नियोजन से संबंध रखनेवाले मामलों में सब नागरों को बराबर के मौके मिलेंगे.

(2) कोई नागर केवल धर्म, नसल, जात, जिन्स, वंश, जन्मस्थान, रिहाइश या इनमें से किसी की बिना पर राज के अधीन किसी कामगारी या पद के लिये अपात्र नहीं होगा न उससे भेदभाव किया जायगा.

(3) इस दफा की कोई बात राजपंचायत को कोई ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकेगी जिससे पहली पट्टी में दर्ज किसी रियासत के अधीन, या उस रियासत के भूभाग के अन्दर किसी मुकामी या दूसरे अधिकारी के अधीन, किसी क्रिम या क्रिमों की कामगारी के, या किसी पद पर नियोजन के, संबंध में, काम मिलने या नियोजन होने से पहले, उस रियासत के अन्दर रिहाइश की कोई शर्त हो.

(4) इस दफा की कोई बात राज को नागरों की किसी ऐसी पिछड़ी हुई जमात के लिये नियोजनों या जगहों को अलग रखने का कोई बन्धान करने से नहीं रोकेगी जिसके, राज की राय में, राज के अधीन नौकरियों में काफ़ी प्रतिनिधि नहीं हैं.

(5) इस दफा की किसी बात का किसी ऐसे क़ानून के अमल पर कोई असर नहीं होगा जो यह बन्धान करता है कि किसी धार्मिक या फिरक़ेवाराना संस्था के मामलों से संबंध रखने वाले किसी पद पर जो आदमी हों या उस संस्था की प्रबंध कमेटी का जो मेम्बर हो वह एक विशेष धर्म का माननेवाला या विशेष फिरक़े का ही हो.

17—“अछूतपन” का अन्त किया जाता है, और किसी रूप में भी अछूतपन बरतने की मनाही की जाती है. अछूतपन की बिना पर किसी को ज़बरदस्ती किसी असकत के अधीन रखना जुर्म होगा जिसकी सज़ा क़ानून के अनुसार दी जा सकेगी.

अछूतपन का अन्त

18—(1) फ़ौजी या तालीमी संस्थाओं संबंधी उपाधियों को छोड़कर राज कोई खिताब नहीं देगा.

खिताबों का अन्त

(2) भारत का कोई नागर किसी विदेशी राज से कोई खिताब स्वीकार नहीं करेगा.

(3) कोई आदमी जो भारत का नागर नहीं है, जब तक वह राज के अधीन किसी लाभ या भरोसे के पद पर है, राजपति की अनुमति बिना, किसी विदेशी राज से कोई खिताब स्वीकार नहीं करेगा.

(4) कोई आदमी जो राज के अधीन किसी लाभ या भरोसे के पद पर है, राजपति की अनुमति बिना किसी विदेशी राज से या उसके अधीन कोई भेंट, वेतन, या किसी तरह का पद स्वीकार नहीं करेगा.

आज़ादी का अधिकार

19—(1) सब नागरों को नीचे लिखे अधिकार होंगे :

- (ए) बोलने और विचार ज़ाहिर करने की आज़ादी का;
- (बी) शांति से और बिना हथियार इकट्ठे होने का;
- (सी) सभाएँ या यूनियन बनाने का;
- (डी) भारत के सारे भूभाग में आज़ादी से आने जाने का;
- (ई) भारत के भूभाग के किसी हिस्से में बसने और बस जाने का;

बोलने वगैरा की आज़ादी के बारे में कुछ अधिकारों की रक्षा

(एफ) जायदाद हासिल करने, रखने और दे देने का; और
(जी) कोई पेशा अपनाने, या कोई धंधा, ब्योपार या
कारबार करने का.

(2) धारा (1) की उप-धारा (ए) की किसी बात का किसी मौजूदा क़ानून के अमल पर वहाँ तक कोई असर नहीं होगा जहाँ तक कि उस क़ानून का संबंध अपमान-लेख, अपमान-वचन, मान-हानि, अदालत की तौहीन या ऐसे किसी मामले से है जो भलमंसी या सदाचार के खिलाफ़ है या जो राज की सुरक्षा की जड़ खोखली करता है, या जिसका झुकाव राज को उलट देने की तरफ़ है, और न उस उप-धारा की किसी बात से राज को कोई ऐसा क़ानून बनाने से रोका जा सकेगा जिसका संबंध इन में से किसी से हो.

(3) उस धारा की उप-धारा (बी) की किसी बात का किसी मौजूदा क़ानून के अमल पर वहाँ तक कोई असर नहीं होगा जहाँ तक वह क़ानून जन-व्यवस्था के हितों में उस अधिकार से काम लेने पर उचित रुकावटें लगाता है जो उस उप-धारा में दिया गया है, और न उस उप-धारा की किसी बात से राज को कोई ऐसा क़ानून बनाने से रोका जा सकेगा.

(4) उस धारा की उप-धारा (सी) की किसी बात का किसी मौजूदा क़ानून के अमल पर वहाँ तक कोई असर नहीं होगा जहाँ तक वह क़ानून जन-व्यवस्था या सदाचार के हितों में उस अधिकार से काम लेने पर उचित रुकावटें लगाता है जो उस उप-धारा में दिया गया है, और न उस उप-धारा की किसी बात से राज को कोई ऐसा क़ानून बनाने से रोका जा सकेगा.

(5) उस धारा की उप-धारा (डी), (ई), और (एफ़) की किसी बात का किसी मौजूदा क़ानून के अमल पर वहाँ तक कोई असर नहीं होगा जहाँ तक वह क़ानून आम जनता के हितों में या किसी पक्षी-दर्ज क़बीले के हितों को रक्षा के लिये उन अधिकारों में से किसी से भी काम लेने पर उचित रुकावटें लगाता है जो उन उप-धाराओं में दिये गए हैं, और न उन उप-धाराओं की किसी बात से राज को कोई ऐसा क़ानून बनाने से रोका जा सकेगा.

(6) उस धारा की उप-धारा (जी) की किसी बात का

किसी मौजूदा क़ानून के अमल पर वहाँ तक कोई असर नहीं होगा जहाँ तक वह क़ानून आम जनता के हितों में उस अधिकार से काम लेने पर उचित रुकावटें लगाता है जो उस उप-धारा में दिया गया है, और न उस उप-धारा की किसी बात से राज को कोई ऐसा क़ानून बनाने से रोका जा सकेगा; और, विशेष कर, उस उप-धारा की किसी बात का किसी मौजूदा क़ानून के अमल पर वहाँ तक कोई असर नहीं होगा जहाँ तक वह क़ानून ऐसी पेशे-संबंधी या तकनीकी जोग-ताएँ तय करता है या किसी अधिकारी को उनके तय करने की शक्ति देता है जो किसी पेशे को अपनाने या कोई धन्धा, व्यापार या कारबार करने के लिये ज़रूरी हों, और न उस उप-धारा की किसी बात से राज को कोई ऐसा क़ानून बनाने से रोका जा सकेगा।

20—(1) कोई आदमी किसी जुर्म का दोशी नहीं ठहराया जायगा, जब तक कि वह किसी ऐसे क़ानून को न तोड़े जो जुर्म बताए जाने वाले काम के करने के समय अमल में था, और न उसे उससे अधिक दंड दिया जा सकेगा जो उस जुर्म के करने के समय अमल में रहने वाले क़ानून के अधीन दिया जा सकता था।

जुर्मों का दोशी ठहराए जाने के बारे में रक्षा

(2) किसी आदमी पर एक ही जुर्म के लिये एक बार से अधिक न मुक़दमा चलाया जायगा न एक बार से अधिक सज़ा दी जायगी।

(3) किसी आदमी को, जिस पर कोई जुर्म लगाया गया हो, अपने खिलाफ़ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जायगा।

21—न किसी आदमी को जान ली जायगी और न किसी की निजी स्वतंत्रता छीनी जायगी सिवाय जब कि क़ानून के क़ायम किये हुए दस्तूर के अनुसार ऐसा किया जाय।

जान और निजी स्वतंत्रता की रक्षा

22—(1) किसी ऐसे आदमी को जो गिरफ्तार किया जाय, जितनी जल्दी हो सके, उसकी गिरफ्तारी की बिना बताए बौर, न हिरासत में रखा जायगा और न अपनी पसंद के वकील से सलाह करने और अपनी सफ़ाई दिलाने के उसके अधिकार से इनकार किया जायगा।

कुछ सूतों में गिरफ्तारी और नज़रबन्दी से रक्षा

(2) हर आदमी को जिसे गिरफ्तार किया जाय और हिरासत में रखा जाय, उसकी गिरफ्तारी से चौबीस घंटे के अन्दर अन्दर पास से पास वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायगा।

इस चौबीस घंटे में गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट की अदालत तक सफ़र के लिये जो समय जरूरी होगा वह नहीं गिना जायगा, और मजिस्ट्रेट के हुकुम के बिना किसी ऐसे आदमी को इस अरसे के बाद हिरासत में नहीं रखा जायगा.

(3) धारा (1) और (2) की कोई बात नीचे लिखे आदमियों पर लागू नहीं होगी :

(ए) किसी ऐसे आदमी पर जो उस समय शत्रु और विदेशी हो; या

(बी) किसी ऐसे आदमी पर जो रोकथामी नज़रबन्दी के लिये बन्धान करने वाले किसी क़ानून के अधीन गिरफ्तार या नज़रबन्द हो.

(4) रोकथामी नज़रबन्दी का बन्धान करने वाला कोई क़ानून किसी आदमी के तीन महीने से अधिक अरसे के लिये नज़रबन्द रखने का किसी को अधिकार नहीं देगा, जब तक कि—

(ए) एक सलाहकार बोर्ड ने, जिसमें ऐसे आदमी हों जो किसी हाईकोर्ट के जज हैं या रह चुके हैं या नियोजे जाने के योग्य हैं, तीन महीने के इस अरसे के बीत जाने से पहले, यह रिपोर्ट न दे दी हो कि उस बोर्ड की राय में ऐसी नज़रबन्दी के लिये काफ़ी कारन है :

शर्तेंकि इस उप-धारा की कोई बात धारा (7) की उप-धारा (बी) के अधीन राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में जो अधिक से अधिक अरस बताया गया हो उससे अधिक किसी आदमी को नज़रबन्द रखने का किसी को अधिकार नहीं देगी; या

(बी) उस आदमी को धारा (7) की उप-धारा (ए) और (बी) के अधीन राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून के बन्धानों के अनुसार नज़रबन्द न किया गया हो.

(5) जब किसी आदमी को रोकथामी नज़रबन्दी का बन्धान करने वाले किसी क़ानून के अधीन दिये हुए किसी हुकुम की तामील में नज़रबन्द किया जाय तो हुकुम देने वाला अधिकारी, जितनी जल्दी भी हो सकेगा, उस आदमी को

सूचना देगा कि वह हुकुम किन बिनाओं पर दिया गया है, और उसको उस हुकुम के खिलाफ अरजी पत्र देने का जल्दी से जल्दी मौका देगा।

(6) धारा (5) की किसी बात से यह दरकार नहीं होगा कि उस धारा में जिस हुकुम की चरचा की गई है उसे देनेवाला अधिकारी ऐसी बातों को प्रगट करे जिनको प्रगट करना वह जन-हित के खिलाफ समझता है।

(7) राजपंचायत कानून बनाकर तय कर सकती है कि—

(ए) किन हालतों में, और किस तरह की या किस किस तरह की सूरतों में किसी आदमी को धारा (4) की उप-धारा (ए) के बन्धानों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय लिये बिना, रोकथामी नज़रबन्दी का बन्धान करनेवाले किसी कानून के अधीन, किसी आदमी को तीन महीने से अधिक अरसे के लिये नज़रबन्द रखा जा सकता है;

(बी) रोकथामी नज़रबन्दी का बन्धान करनेवाले किसी कानून के अधीन, किस तरह की या किस किस तरह की सूरतों में, किसी आदमी को अधिक से अधिक कितने अरसे के लिये नज़रबन्द रखा जा सकता है; और

(सी) धारा (4) की उप-धारा (ए) के अधीन पूछताछ करने में सलाहकार बोर्ड को किस दस्तूर पर चलना होगा।

शोशन के खिलाफ अधिकार

23—(1) इनसानों के व्यापार, और बेगार, और जबरी मजदूरी के इसी तरह के दूसरे रूपों, की मनाही की जाती है, और इस बन्धान को किसी तरह भी तोड़ना जुर्म होगा जिसकी सज़ा कानून के अनुसार दी जा सकेगी।

इनसानों के व्यापार और जबरी मजदूरी की मनाही।

(2) इस दफ़ा की कोई बात राज को सरकारी कामों के लिये जबरी सेवा लागू करने से नहीं रोकेगी और ऐसी सेवा लागू करने में केवल धर्म, नसल, जात या जमात या इनमें से किसी की बिना पर राज कोई भेदभाव नहीं करेगा।

24—चौदह बरस से कम उमर के किसी बालक को किसी फ़ैक्टरी या खदान में काम पर नहीं लगाया जायगा और न किसी और जोखम के काम पर लगाया जायगा।

फ़ैक्टरियों वगैरा में बच्चों को काम पर लगाने की मनाही

धार्मिक आज़ादी का अधिकार

अन्तरात्मा की आज़ादी और किसी धर्म को मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी

25—(1) जन-व्यवस्था, सदाचार, और तनदुरुस्ती का ध्यान रखते हुए, और इस भाग के दूसरे बन्धानों का ध्यान रखते हुए, सब लोग अन्तरात्मा की अज़ादी के, और अज़ादी के साथ अपने धर्म को मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने के अधिकार के, बराबर के हक़दार हैं।

(2) इस दफ़ा की किसी बात का किसी ऐसे मौजूदा क़ानून के अमल पर असर न होगा, न वह राज को कोई ऐसा क़ानून बनाने से रोकेगी, जो—

(ए) किन्हीं धार्मिक, माली, राजकाजी या दूसरे ऐसे दुनियावी कामों की क़ायदाबन्दी करता है या उन पर रुकावट लगाता है जिनका संबंध किसी धर्म पर अमल करने से है;

(बी) समाज की भलाई और समाज सुधार का, या हिन्दुओं की ऐसी धार्मिक संस्थाओं को जो जनता के लिये हों हिन्दुओं की सब जमातों और सब टुकड़ियों के लिये खोलने का, बन्धान करता है।

समझाव (1)—किरपान रखना और लेकर चलना सिख धर्म को मानने में शामिल समझा जायगा।

समझाव (2)—धारा (2) की उप-धारा (बी) में हिन्दुओं की चरचा में सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वालों की चरचा शामिल समझी जायगी, और हिन्दू धार्मिक संस्थाओं की चरचा को भी इसी तरह समझा जायगा।

धार्मिक मामलों का प्रबन्ध करने की आज़ादी

26—जन-व्यवस्था, सदाचार और तनदुरुस्ती का ध्यान रखते हुए, हर धार्मिक फ़िरक़े या उसकी हर टुकड़ी को अधिकार होगा कि—

(ए) धर्म और ख़ैरात के मतलबों के लिये संस्थाएं क़ायम करे और चलाए;

(बी) धर्म के मामलों में अपने कामों का आप प्रबन्ध करे;

(सी) चल और अचल जायदाद की मालिक हो और इस तरह की जायदाद हासिल करे; और

(डी) क़ानून के अनुसार इस तरह की जायदाद का प्रबन्ध करे।

27—किसी आदमी को कोई ऐसे टैक्स देने के लिये मजबूर नहीं किया जायगा जिसकी वसूली की बाबत यह तय है कि वह किसी विशेष धर्म या धार्मिक फ़िरके को बढ़ाने या बनाए रखने के खर्च की मद में डाली जाय।

किसी विशेष धर्म को बढ़ाने के लिये टैक्स देने के बारे में आज्ञादी

28—(1) किसी ऐसी तालीमी संस्था में जिसका कुल खर्च राज के रुपए से चलता हो किसी धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जायगा।

कुछ तालीमी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा बंदगी में हाज़िरी के बारे में आज्ञादी

(2) धारा (1) की कोई बात किसी ऐसी तालीमी संस्था पर लागू न होगी जिसका प्रबन्ध राज करता है पर जो किसी ऐसे देन या ट्रस्ट के अधीन क़ायम की गई हो, जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना दरकार हो।

(3) किसी भी आदमी के लिये जो किसी ऐसी तालीमी संस्था में जाता हो जो राज की तरफ से मानी हुई है या जिसे राज के रुपए से सहायता मिलती है यह दरकार नहीं होगा कि वह किसी ऐसी धार्मिक शिक्षा में भाग ले जो उस संस्था में दी जाती हो, या किसी ऐसी धार्मिक पूजा बंदगी में हाज़िर हो जो उस संस्था में या उससे संबंध रखने वाली किसी जगह पर की जाती हो, जब तक कि उस आदमी ने या अगर वह नावालिग है तो उसके संरक्षक ने इसके लिये अपनी अनुमति न दे दी हो।

कलचरी और तालीमी अधिकार

29—(1) भारत के भूभाग में या उसके किसी भाग में बसने वाले नागरों की किसी ऐसी टुकड़ी को जिसकी अपनी अलग भाशा, लिखावट या कलचर है, उन्हें बनाए रखने का अधिकार होगा।

कमीयनों के हितों की रक्षा

(2) राज से चलाई जाने वाली या राज के रुपए से सहायता पाने वाली किसी तालीमी संस्था में किसी भी नागर को केवल धर्म, नसल, जात, भाशा या इनमें से किसी की बिना पर दाखिल करने से इनकार नहीं किया जायगा।

30—(1) सब कमीयतों को, चाहे वह धर्म के आधार पर हों चाहे भाशा के, अपनी पसन्द की तालीमी संस्थाएँ क़ायम करने और उनका प्रबन्ध करने का अधिकार होगा।

कमीयतों को तालीमी संस्थाएँ क़ायम करने और उनके प्रबन्ध करने का अधिकार

(2) तालीमी संस्थाओं के लिये सहायता मंजूर करने में राज

किसी तालीमी संस्था से इस बिना पर भेदभाव नहीं बरतेगा कि वह संस्था किसी कमीयत के प्रबन्ध में है, चाहे वह कमीयत धर्म के आधार पर हो और चाहे भाषा के।

जायदाद का अधिकार

जायदाद का जबरन
हासिल करना

31—(1) किसी आदमी को उसकी जायदाद से बेदखल नहीं किया जायगा जबतक कानून इसका अधिकार न दे,

(2) किसी जायदाद पर चाहे वह चल हो या अचल, और चाहे वह किसी तिजारती या उद्योगी कारबार में किसी तरह के हित के रूप में हो, या किसी ऐसी कम्पनी में किसी तरह के हित के रूप में हो जो किसी तिजारती या उद्योगी कारबार की मालिक है, किसी ऐसे कानून के अधीन जो इस तरह की जायदाद पर सरकारी कामों के लिये कब्जा करने या उसे हासिल करने का अधिकार देता है, तब तक कब्जा नहीं किया जायगा, न उसे हासिल किया जायगा जब तक कि उस कानून में जायदाद पर इस तरह कब्जा करने या उसे हासिल करने की नुकसान-भरपाई देने का बन्धान न हो, और या तो इस नुकसान-भरपाई की रकम तय कर दी गई हो या वह सिद्धान्त और वह ढंग बता दिये गए हों जिनसे नुकसान - भरपाई की रकम तय की जानी है और दी जानी है।

(3) धारा (2) में किसी रियासत की कानूनसभा के बनाए जिस कानून की चरचा की गई है उसका तब तक कोई असर नहीं होगा जब तक कि उसे राजपति के विचार के लिये अलग रखे जाने के बाद राजपति की मंजूरी न मिल गई हो।

(4) अगर कोई बिल इस विधान के आरम्भ होने पर किसी रियासत की कानून सभा में पेश था और वह उस कानून सभा में पास हो गया हो और उसके बाद राजपति के विचार के लिये अलग रखा गया हो और राजपति ने उस पर अपनी मंजूरी दे दी हो तो इस विधान में किसी बात के रहते भी, इस तरह मंजूर हुए कानून पर किसी अदालत में इस बिना पर कोई सवाल नहीं उठाया जायगा कि वह धारा (2) के बन्धानों के खिलाफ पड़ता है।

(5) धारा (2) की किसी बात का—

(ए) धारा (8) के बन्धान जिस क़ानून पर लागू होते हैं उसको

छोड़कर किसी मौजूदा क़ानून के बन्धानों पर, या—

(बी) किसी ऐसे क़ानून के बन्धानों पर, जो राज आगे चलकर—

(1) कोई टैक्स या दंड लगाने के मतलब के लिये बनाए,
या

(2) जन-तन्दुरुस्ती को बढ़ाने या जान या माल को खतरे
से बचाने के लिये बनाए, या

(3) किसी ऐसी जायदाद के बारे में जिसे क़ानून ने
घरछुट जायदाद ठहरा दिया हो, हिन्द डोमिनियन
की सरकार या भारत सरकार और किसी दूसरे देश
की सरकार के बीच किसी समझौते की तामील में
या किसी दूसरी तरह बनाए,

असर नहीं होगा.

(6) राज का कोई क़ानून जो इस विधान के आरंभ होने से
पहले, अठारह महीने के अन्दर अन्दर बनाया गया हो, विधान के
आरंभ होने के बाद तीन महीने के अन्दर राजपति के सामने उसकी सनद
के लिये रखा जा सकता है; और इस पर अगर राजपति आमनोटिस
निकालकर सनद कर दे तो उस क़ानून पर किसी अदालत में
इस बिना पर कोई सवाल नहीं उठाया जायगा कि वह इस दफ़ा की धारा
(2) के बन्धानों के खिलाफ़ पड़ता है या कि वह हिन्द सरकार एक्ट,
1935, दफ़ा 299 को उपदफ़ा (2) के बन्धानों के खिलाफ़ है.

विधानी उपायों का अधिकार

32—(1) इस भाग में दिये अधिकारों पर अमल कराने के
लिये आला अदालत में मुनासिब कारबाइयों से क्ररियाद करने के
अधिकार की गारंटो की जाती है.

इस भाग में
दिये अधिकारों पर
अमल कराने के
लिये उपाय

(2) इस भाग में दिये अधिकारों में से किसी पर अमल
कराने के लिये आला अदालत को शक्ति होगी कि ऐसे आदेश या हुकुम
या परवाने, जिनमें परवाना तनतलबी, परवाना हुकुम, परवाना मनाही,
परवाना अधिकार-बताई और परवाना मिसल-मंगाई जैसे परवाने
शामिल हैं, जो भी मुनासिब हो, जारी करे.

(3) धारा (1) और (2) से आला अदालत को जो शक्तियाँ दी गई हैं उन्हें कम किये बिना, राजपंचायत कानून बनाकर किसी दूसरी अदालत को उसकी अमलदारी की मुकामी सीमाओं के अन्दर उन सब शक्तियों या उनमें से किसी शक्ति से काम लेने का अधिकार दे सकती है, जिनसे आला अदालत धारा (2) के अधीन काम ले सकती है।

(4) इस दफा से गारंटी किया हुआ अधिकार मुअत्तल नहीं किया जायगा सिवाय इसके कि इस विधान में किसी दूसरी तरह का बन्धान कर दिया गया हो।

इस भाग में दिये अधिकारों के फौजों के किये लागू होने पर उनमें बदल बदल करने की राजपंचायत की शक्ति

33—राजपंचायत कानून बनाकर यह तय कर सकती है कि इस भाग में दिये अधिकारों में से किसी को, हथियारबन्द फौजों या उन फौजों के लोगों के लिये जिनपर जन-व्यवस्था बनाए रखने का भार है लागू होने पर, कहां तक कम किया जा सकता है या रह किया जा सकता है, जिससे इस बात का पक्का भरोसा हो जाए कि फौजों अपने फरजों का उचित पालन कर सकें और उनमें क्रायदादारी बनी रहे।

जब किसी छेत्र में फौजी कानून लागू हो तो इस भाग में दिये अधिकारों पर रुकावट

34—इस भाग में ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत कानून बनाकर किसी आदमी को जो यूनिन की या किसी रियासत की नौकरी में है या किसी दूसरे आदमी को किसी ऐसे काम के बारे में बरीयत दे सकती है जो उसने भारत के भूभाग में किसी ऐसे छेत्र के अन्दर जहाँ फौजी कानून लागू था व्यवस्था बनाए रखने या फिर से व्यवस्था क्रायम करने के सम्बन्ध में किया हो, या उस छेत्र में फौजी कानून के अधीन अगर कोई सज्जा का हुकुम दिया गया हो, या सज्जा दी गई हो, या ज़बती का हुकुम दिया गया हो, या और कोई काम किया गया हो तो उसे सरदुरुस्त ठहरा सकती है।

इस भाग के बन्धानों को अमल में लाने के लिये कानून बनाना

35—इस विधान में किसी बात के रहते भी—

(ए) राजपंचायत को यह शक्ति होगी, और किसी रियासत की कानूनसभा को नहीं होगी, कि—

(एक) जिन मामलों के लिये दफा 16 की धारा (3), दफा 32 की धारा (3), और दफा 33 और 34 के

अधीन राजपंचायत कानून बना सकती है, उनमें से किसी के लिये; और

(दो) इस भाग में जिन कामों को जुर्म ठहराया गया है उनकी सजा तय करने के लिये;

कानून बनाए,

और राजपंचायत इस विधान के आरंभ होने के बाद जितनी जल्दी हो सके उन कामों के लिये जिनकी उपधारा (दो) में चरचा की गई है, सजा तय करने के लिये कानून बनाएगी.

(बी) धारा (ए) की उपधारा (एक) में जिन मामलों की चरचा की गई है उनमें से किसी के बारे में, या उस धारा की उपधारा (दो) में जिस किसी काम की चरचा की गई है उसके लिये सजा का बन्धान करने वाला, कोई कानून जो भारत के भूभाग में इस विधान के आरम्भ होने से ठीक पहले लागू था, अपनी शर्तों के अधीन और उन अनुकूलनों या अदल बदल के अधीन जो दफा 372 के अधीन उस कानून में किये जायँ, तब तक लागू रहेगा जब तक कि राजपंचायत उसे बदल न दे, या रह न कर दे, या उसमें सुधार न कर दे.

समझाव :—इस दफा में “लागू कानून” शब्दों के वही मानी हैं जो दफा 372 में हैं.

भाग चार

राज की नीति के निर्देशक सिद्धान्त

परिभाषा

36—अगर प्रसंग से कुछ और दरकार न हो तो इस भाग में “राज” के वही मानी हैं जो भाग तीन में.

इस भाग में आए सिद्धान्तों को लागू करना

37—इस भाग में आए बन्धानों पर किसी अदालत के जरिये अमल नहीं कराया जा सकेगा, पर फिर भी इनमें बताए सिद्धान्त देश की हुकूमत की नींव हैं और कानून बनाने में इन सिद्धान्तों को लागू करना राज का फरज होगा.

लोगों की खुशहाली बढ़ाने के लिये राज का एक समाजी व्यवस्था को पक्का करना

38—राज की कोशिश होगी कि जितने भी असरदार ढंग से हो सके एक ऐसी समाजी व्यवस्था को पक्का करके और उसकी रक्षा करके, जिसमें समाजी, आर्थिक और राजकाजी इन्साफ क़ौमी जीवन की सब संस्थाओं में समाया हुआ हो, लोगों की खुशहाली को बढ़ाए.

नीति के कुछ सिद्धान्त जिनपर राज चलेगा

39—राज खास कर अपनी नीति को ऐसे चलायगा कि :—

(ए) सब नागरों को, नर और नारी को एक बराबर, रोज़ी के काफ़ी साधन मिलने का अधिकार हो;

(बी) समाज के माही साधनों की मिलकियत और उनपर दबान इस तरह बँटे हों कि जिससे सबका बहुत से बहुत भला हो ;

(सी) अर्थ-व्यवस्था के चलने का यह नतीजा न हो कि धन और पैदावार के साधन इस तरह कील दिये जाएँ जिससे आम लोग घाटे में रहें;

(डी) नर और नारी दोनों को बराबर काम के लिये बराबर का वेतन मिले;

(ई) नर नारी कामगारों की तन्दुरुस्ती और शक्ति और बालकों की क़च्ची उमर का बुरा उपयोग न हो, और आर्थिक जरूरतों से मजबूर होकर नागरों को ऐसे रोज़गारों में न जाना पड़े जो उनकी उमर या शक्ति के अनुकूल न हों;

(एफ) शोशन से और नैतिक आचरणगी और बेचरबारीगी से बच्चों और नौजवानों को बचाया जाय.

40—राज गांव-पंचायतों का संगठन करने के लिये क्रम उठायागा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार देगा जो उन्हें स्वराज की इकाइयों के रूप में काम करने के जोग बनाने के लिये जरूरी हों.

गांव पंचायतों का संगठन

41—राज, अपनी आर्थिक सकत और बिकास की सीमाओं के अन्दर रहते हुए, सबको काम पाने, तालीम पाने, और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, अंगभंग हो जाने, और दूसरी अनकरी जरूरतों में सरकारी मदद पाने का अधिकार दिलाने का असरदार प्रबन्ध करेगा.

काम, तालीम और कुछ सूरतों में सरकारी मदद पाने का अधिकार

42—राज काम की हालतों में न्याय और इनसानियत का और औरतों को जापा-मदद दिलाने का प्रबन्ध करेगा.

काम की हालतों में न्याय और इनसानियत का और जापामदद का प्रबन्ध कामगारों के लिये पेटभर मजदूरी वगैरा

43—राज उचित क्रानून बनाकर या आर्थिक संगठन करके या और जिस तरह हो जतन करेगा कि खेतिहरों, मिल-मजदूरों और दूसरे सब कामगारों को काम और पेटभर मजदूरी मिले, और वह ऐसी हालतों में काम करें जिनसे यह भरोसा हो जाय कि उनके रहन सहन का ढंग भले लोगों का सा है, और वे फुरसत के समय से, और समाजी और कलचरी अबसरों से पूरा लाभ उठा सकें, और खास कर राज देहातों में घरेलू उद्योगों को निजी या सहकारी आधार पर बढ़ाने का जतन करेगा.

44—राज इस बात का जतन करेगा कि भारत के सारे भूभाग में नागरों के लिये एक सी दीवानी पद्धत हो.

नागरों के लिये एकसी दीवानी पद्धत

45—राज इस विधान के आरम्भ होने से दस बरस के अरसे के अन्दर सब बच्चों को उनके चौदह बरस की उमर पूरी करने तक मुफ्त और जबरती तालीम देने का जतन करेगा.

बच्चों के लिये मुफ्त और जबरती तालीम का प्रबन्ध

46—राज जनता की निबल दुकड़ियों के, और खास कर पट्टी-दर्ज जातियों और पट्टी दर्ज कबीलों के तालीमी और आर्थिक हितों को खास सावधानी से बढ़ायेगा और समाजी अन्याय और सब तरह के शोशन से उनकी रक्षा करेगा.

पट्टी-दर्ज जातियों, पट्टी-दर्ज कबीलों और दूसरी निबल दुकड़ियों के तालीमी और आर्थिक हितों की रक्षा

तनपालन तल और
जीवन-स्तर को ऊँचा
करना और जन-
तन्दुरुस्ती को सुधा-
रना राज का फ़रज़

47—राज अपने लोगों की ख़ुराक में तनपालन-तल और उनके जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना और जन-तन्दुरुस्ती का सुधारना अपने सबसे पहले फ़रज़ों में से मानेगा, और खास कर नशीले पानों और तन्दुरुस्ती बिगाड़नेवाली जड़ी-बूटियों की, सिवाय दवा के मतलबों के लिये, खपत बन्द कराने का जतन करेगा.

खेतीबाड़ी और पशु-
पालन का संगठन

48—राज खेतीबाड़ी और पशुपालन का नई और साइंसी रीतियों के अनुसार संगठन करने का जतन करेगा, और खास कर गायों और बछड़ों और दूसरे दुधारी और भारवाही ढोरों की नसलों को बनाए रखने और सुधारने के लिये और उनके बध को रोकने के लिये क़दम उठायागा.

क्रौमी महत्व की
यादगारों और
जगहों और चीज़ों
की रक्षा

49—राज के लिये लाजमी होगा कि हर ऐसी यादगार या जगह या चीज़ को, जो कला या इतिहास की निगाह से दिलचस्प हो, और जिसे राजपंचायत ने क़ानून बनाकर क्रौमी महत्व का ठहरा दिया हो, लूट खसोट, रूप बिगाड़, बरबादी, हटाए जाने, दे डाले जाने या देश से बाहर भेजे जाने से, जैसी सूरत हो, बचावे.

काजकारी से न्याय-
कारी का अलग
करना

50—राज अपनी सरकारी नौकरियों में न्यायकारी को काजकारी से अलग करने के लिये क़दम उठायागा.

अन्तर-क्रौमी शान्ति
और सुरक्षा को
बढ़ाना

51—राज,

(ए) अन्तर-क्रौमी शान्ति और सुरक्षा को बढ़ाने का;

(बी) क्रौमों के बीच न्यायी और सम्मानी रिश्तों को बनाए रखने का;

(सी) संगठित क्रौमों के एक दूसरे से बरताव में अन्तर-क्रौमी क़ानून और सन्धि-बन्धनों के लिये आदर बढ़ाने का;
और

(डी) अन्तर-क्रौमी झगड़ों को पंचकैसले से निपटाने के लिये बढ़ावा देने का,
जतन करेगा.

भाग पाँच

यूनियन

खंड एक—काजकारी

राजपति और उपराजपति

52—भारत का एक राजपति होगा.

भारत का राजपति

53—(1) यूनियन की काजकारी शक्ति राजपति को हासिल होगी और वह उससे खुद या अपने अधीन अफसरों के जरिये इस विधान के अनुसार काम लेगा.

यूनियन की काजकारी शक्ति

(2) उपर बताए बन्धान की आमियत में कमी किये बिना यूनियन की बच्चाव फौजों की आला कमान राजपति को हासिल होगी और उस कमान से काम लेने की क्रायदाबन्दी कानून से की जायगी.

(3) इस दफ्ता की किसी बात से—

(ए) जो काम किसी मौजूदा कानून ने किसी रियासत को सरकार या दूसरे अधिकारी को सौंपे हैं वह काम राजपति को तबदीले नहीं समझे जायंगे; या

(बी) राजपति को छोड़ दूसरे अधिकारियों को कानून बनाकर काम सौंपने से राजपंचायत को नहीं रोका जायगा.

54—राजपति को एक चुनाव मंडल के मेम्बर चुनेंगे जिसमें—

राजपति का चुनाव

(ए) राजपंचायत के दोनों सदनों के चुने हुए मेम्बर; और

(बी) रियासतों के आम सदनों के चुने हुए मेम्बर,

होंगे.

55—(1) जहाँ तक बन पड़ेगा राजपति के चुनाव में अलग अलग रियासतों के प्रतिनिधान के पैमाने में एकरूपता होगी.

राजपति के चुनाव का ढंग

(2) रियासतों के बीच आपस में ऐसी एकरूपता लाने के लिये, और कुल रियासतों और यूनियन के बीच बराबरी रखने के लिये, राजपंचायत का और हर रियासत के आमसदन का हर चुनाव हुआ मेम्बर चुनाव में जितने वोट देने का हकदार होगा उनकी तादाद नीचे लिखे ढंग से तय की जायगी :—

(ए) किसी रियासत के आमसदन के हर चुने हुए मेम्बर

के इतने वोट होंगे जितने कि एक हजार के गुने उस

भागफल में हों जो रियासत की आबादी को आम-सदन के चुने हुए मेम्बरों की कुल गिनती से भाग देने से आए.

(बी) ऊपर बताए एक हजार के गुनों को लेने के बाद अगर बाक़ी पांच सौ से कम न हो तो हर उस मेम्बर का जिसकी चरचा उपधारा (ए) में की गई है, एक वोट और बढ़ जायगा.

(सी) राजपंचायत के दोनों सदनों के हर चुने हुए मेम्बर के वोटों की गिनती वही होगी जो 'उपधारा (ए) और (बी) के अधीन रियासतों के आम सदनों के मेम्बरों को दिए हुए वोटों की कुल गिनती को राजपंचायत के दोनों सदनों के चुने हुए मेम्बरों की कुल गिनती से भाग देने से आए, जिसमें आधे से अधिक टुक को एक गिना जायगा और बाकी टुकों को नहीं गिना जायगा.

(3) राजपति का चुनाव निसबती प्रतिनिधान के ढंग के अनुसार इकट्ठे बदलते वोट से होगा और ऐसे चुनाव में वोट बन्द परचियों से लिये जायंगे.

समझाव :—इस दफ़ा में "आबादी" शब्द के मानी वह आबादी है जो उस पिछले आखिरी गिनावे में मालूम की गई है जिसके संगत आंकड़े निकल चुके हैं.

राजपति की पद-
मियाद

56—(1) राजपति अपना पद संभालने की तारीख से पांच बरस की मियाद तक पद पर रहेगा :

शर्तें कि—

(ए) राजपति उप-राजपति के नाम अपनी दसखती लिखत भेज कर अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकता है.

(बी) विधान तोड़ने पर राजपति उस ढंग से दोष लगाकर पद से हटाया जा सकता है जिसका बंधान दफ़ा 61 में किया गया है .

(सी) राजपति अपनी मियाद पूरी हो जाने पर भी अपने पदगाही के पद संभालने तक पद पर रहेगा.

(2) धारा (1) की शर्त की धारा (ए) के अधीन उप-राजपति के नाम इस्तीफे की सूचना उप-राजपति तुरन्त लोकसदन के सभामुख को देगा।

57—कोई आदमी जो राजपति के पद पर है या रह चुका है फिर चुनाव के इस विधान के दूसरे बंधानों का ध्यान रखते हुए उस पद के लिये लिए पात्रता फिर चुने जाने का पात्र होगा।

58—(1) कोई आदमी राजपति चुने जाने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह— राजपति चुने जाने के लिए योग्यताएँ

(ए) भारत का नागर न हो,

(बी) अपनी उमर का पैंतीसवाँ बरस पूरा न कर चुका हो, और

(सी) लोकसदन का मेम्बर चुने जाने की योग्यता न रखता हो।

(2) कोई आदमी जो भारत सरकार के या किसी रियासत की सरकार के अधीन या इन सरकारों में से किसी के दबान में किसी मुकामी या दूसरे अधिकारी के अधीन किसी लाभ के पद पर है, राजपति चुने जाने का पात्र नहीं होगा।

समझाव :—इस दफ्ता के मतलबों के लिये कोई आदमी केवल इसी कारन किसी लाभ के पद पर नहीं समझा जायगा कि वह यूनियन का राजपति या उप-राजपति या किसी रियासत का रियासत-पति या राजप्रमुख या उप-राजप्रमुख है या यूनियन का या किसी रियासत का बच्चीर है।

59—(1) राजपति न तो राजपंचायत के किसी सदन का मेम्बर होगा और न किसी रियासत की कानूनसभा का मेम्बर होगा, और अगर राजपंचायत के किसी सदन का या किसी रियासत की कानून सभा के किसी सदन का कोई मेम्बर राजपति चुना जाय तो यह समझा जायगा कि उसने उस सदन की अपनी जगह उस तारीख से सूनी कर दी है जिस दिन उसने राजपति का पद संभाला। राजपति के पद की शर्तें

(2) राजपति किसी दूसरे लाभ के पद पर नहीं रहेगा।

(8) राजपति को अपने सरकारी मकानों को बिना किराया दिये इस्तेमाल करने का अधिकार होगा, और वह उस बेतन, भत्तों

और निजनियमों को पाने का हक्कदार होगा जो राजपंचायत कानून बनाकर तय करे, और जब तक इसके लिये इस तरह प्रबन्ध न हो तब तक वह उस वेतन, भत्तों और निजनियमों को पाने का हक्कदार होगा जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं.

(4) राजपति का वेतन और भत्ते उसकी पद-मियाद के दौरान में घटाए नहीं जायेंगे.

राजपति का हलफ
उठाना या वचन
भरना

60—हर राजपति और हर आदमी जो राजपति की जगह काम करेगा या उसके काम निभारेगा, अपना पद संभालने से पहले, भारत के सरजज या उसके मौजूद न होने पर आला अदालत के उस बड़े से बड़े जज के सामने जो मिल सके, नीचे दिये रूप में हलफ उठायगा या वचन भरेगा और उस पर दसखत करेगा, यानी यह कि—

“मैं.....(नाम)..... ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं भारत गम्भीरता से वचन भरता हूँ

के राजपति के पद पर रह कर वफादारी से काम करूंगा (या भारत के राजपति के काम वफादारी से निभाऊंगा) और अपनी पूरी जोगता से विधान और कानून को बनाए रखूंगा, उनकी रक्षा और उनका बचाव करूंगा, और मैं भारत के लोगों की सेवा और उनकी भलाई में तन मन से लगा रहूंगा.”

राजपति पर दोष-
लगाने का दस्तूर

61—(1) जब किसी राजपति पर विधान तोड़ने का दोष लगाना हो तो राजपंचायत का कोई एक सदन दोष-लेखा पेश करेगा.

(2) ऐसा कोई दोष-लेखा पेश नहीं किया जायगा जब तक कि—

(ए) दोष-लेखा पेश करने का सुझाव एक ऐसे ठहराव में न रखा गया हो जिसे पेश करने के इरादे का लिखा नोटिस उस सदन के मेम्बरों की कुल गिनती के कम से कम एक चौथाई के दसखत से कम से कम चौदह दिन पहले न दिया जा चुका हो, और उसके बाद वह ठहराव पेश न किया गया हो; और

(बी) उस सदन के कुल मेम्बरों की कम से कम दो तिहाई बक़ीयत ने वह ठहराव पास न किया हो.

(3) जब राजपंचायत का कोई सदन इस तरह दोश-लेखा पेश कर दे तो दूसरा सदन उस दोश-लेखे की जांच करेगा या जांच करायगा, और इस तरह की जांच में आने और अपना प्रतिनिधि भेजने का राजपति को अधिकार होगा.

(4) अगर जांच का नतीजा यह हो कि जिस सदन ने दोश-लेखे की जांच की थी या कराई थी उसके कुल मेम्बरों की कम से कम दो तिहाई बढीयत यह ठहराव पास कर दे कि जो दोश-लेखा राजपति के खिलाफ पेश किया गया था वह ठीक साबित हो गया है, तो उस ठहराव का यह असर होगा कि ठहराव के इस तरह पास होने की तारीख से राजपति अपने पद से हट जायगा.

62—(1) राजपति की पद-मियाद पूरी हो जाने से पैदा हुई सूनी को भरने के लिये चुनाव मियाद पूरी होने से पहले ही पूरा कर लिया जायगा.

(2) राजपति की मौत हो जाने, उसके इस्तीफा देने या हटाए जाने या किसी दूसरे कारन से उसका पद सूना हो जाने पर उस सूनी को भरने के लिये चुनाव सूनी होने की तारीख के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा और हर सूरत में उस तारीख से छै महीने के अन्दर किया जायगा, और सूनी को भरने के लिये जो आदमी चुना जाय वह, दफा 56 के बन्धानों का ध्यान रखते हुए, अपने पद संभालने की तारीख से लेकर पांच बरस की पूरी मियाद तक पद पर रहने का हकदार होगा.

63—भारत का एक उप-राजपति होगा.

64—उप-राजपति पदनाते रियासत सदन का मसनदी होगा और दूसरे किसी लाभ के पद पर नहीं रहेगा :

शर्तें कि जब जितने अरसे तक उप-राजपति राजपति की जगह काम करेगा या दफा 65 के अधीन राजपति के काम निभारेगा तब उस अरसे तक वह रियासत-सदन के मसनदी के पद के फरज अदा नहीं करेगा, और दफा 97 के अधीन रियासत सदन के मसनदी को मिलने वाली किसी तनखा या भत्ते का हकदार न होगा.

राजपति के पद की सूनी को भरने के लिये चुनाव का समय और औसरी सूनी भरने के लिये चुने आदमी की पद मियाद

भारत का उप-राज-पति

उप-राजपति पदनाते रियासत सदन का मसनदी होगा

राजपति की नामौजूदगीमें या उसके पद की मौसरी सूनिषों के समय उप-राजपति का राजपतिकी जगह काम करना या उसके पद के काम निभारना

65—(1) राजपति की मौत हो जाने, उसके इस्तीफा देने या हटाए जाने या किसी दूसरे कारन से उसका पद सूना होने की सूरत में उप-राजपति उस तारीख तक राजपति की जगह काम करेगा जब तक कि उस सूनी को भरने के लिये इस खंड के बन्धानों के अनुसार चुना हुआ नया राजपति अपना पद न संभाल ले.

(2) नामौजूदगी, बीमारी या दूसरे किसी कारन से जब राजपति अपने काम निभारने के अजोग हो तब उप-राजपति उसके काम उस तारीख तक निभारेगा जिस तारीख को राजपति फिर से अपने फरज संभाल ले.

(3) उप-राजपति को उस अरसे में और उसके बारे में जब वह इस तरह राजपति की जगह काम कर रहा हो या उसके कामों को निभार रहा हो, राजपति की सब शक्तियां और बरीयतें होंगी, और वह उस वेतन, भत्तों और निजनियमों को पाने का हकदार होगा जो राजपंचायत कानून बनाकर तय कर दे, और जब तक इसके लिये इस तरह बन्धान नहीं किया जाता तब तक वह उस वेतन, भत्तों और निजनियमों का हकदार होगा जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं.

उप-राजपति का चुनाव

66—(1) उप-राजपति राजपंचायत के दोनों सदनों के मेम्बरों की मिलीजुली मिलनी में निसबती प्रतिनिधान के ढंग के अनुसार इकहरे बदलते वोट से चुना जायगा और ऐसे चुनाव में वोट बन्द परचियों से लिये जायंगे.

(2) उप-राजपति राजपंचायत के किसी सदन या किसी रियासत की कानूनसभा के किसी सदन का मेम्बर नहीं होगा, और अगर राजपंचायत के किसी सदन या किसी रियासत की कानूनसभा के किसी सदन का कोई मेम्बर-उप-राजपति चुना जाय तो यह समझा जायगा कि उसने उस सदन की अपनी जगह उस तारीख को सूनी कर दी जिस तारीख को उसने उप-राजपति का पद संभाला.

(3) कोई आदमी उप-राजपति चुने जाने का पात्र न होगा जब तक कि वह—

(१) भारत का नागर न हो ;

(बी) अपनी उमर का पैंतीसवां बरस पूरा न कर चुका हो; और
(सी) रियासत सदन का मेम्बर चुने जाने की जोगता न रखता हो.

(4) कोई आदमी जो भारत सरकार के या किसी रियासत की सरकार के अधीन या उन सरकारों में से किसी के दवान में किसी मुकामी या दूसरे अधिकारी के अधीन किसी लाभ के पद पर है, उप-राजपति चुना जाने का पात्र न होगा.

समझाव:—इस दफा के मतलबों के लिये कोई आदमी केवल इसी लिये किसी लाभ के पद पर नहीं समझा जायगा कि वह यूनियन का राजपति या उप-राजपति है या किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख या उप-राजप्रमुख है या यूनियन या किसी रियासत का बजौर है.

67—उप-राजपति अपने पद संभालने की तारीख से पांच बरस की मियाद तक पद पर रहेगा:

उप-राजपति की पद-मियाद

शर्तें कि—

(ए) उप-राजपति राजपति के नाम अपनी दसखर्ची लिखत भेज कर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है ;

(बी) उप-राजपति रियासत सदन के ऐसे ठहराव से अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे रियासतसदन के उस समय के सब मेम्बरों की बड़ीयत ने पास किया हो और जिसे लोकसभा ने मान लिया हो; पर इस धारा के मतलब के लिये कोई ठहराव पेश न किया जायगा जबतक कि उस ठहराव को पेश करने के इरादे का कम से कम चौदह दिन का नोटिस न दे दिया गया हो;

(सी) उप-राजपति अपनी मियाद पूरी हो जाने पर भी अपने पदगाही के पद संभालने तक पद पर बना रहेगा.

68—(1) उप-राजपति की पद-मियाद के पूरा हो जाने से पैदा हुई सूनी को भरने के लिये चुनाव मियाद पूरी होने से पहले ही पूरा कर लिया जायगा.

उप-राजपति के पद की सूनी को भरने के लिये चुनाव का समय और औसरी सूनी भरने के लिये चुने

(2) उप-राजपति की मौत हो जाने, उसके इस्तीफा देने या हटाए जाने, या किसी दूसरे कारन से उसका पद सूना हो जाने पर उस

आदमी की पद-
मियाद

सूनी को भरने के लिये चुनाव, सूनी होने के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा, किया जायगा, और सूनी को भरने के लिये जो आदमी चुना जाय वह दफा 67 के बन्धानों का ध्यान रखते हुए अपना पद संभालने की तारीख से लेकर पाँच बरस की पूरी मियाद तक पद पर रहने का हकदार होगा।

उप-राजपति का
हलफ उठाना या
वचन भरना

69—हर उप-राजपति अपना पद संभालने से पहले राजपति के सामने या किसी आदमी के सामने जिसे राजपति इस काम के लिए नियोजित नीचे लिखे रूप में हलफ उठायगा या वचन भरेगा, यानी कि—

“मैं.....(नाम)..... ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के गम्भीरता से वचन भरता हूँ

उस विधान का जो कानून से क़ायम हुआ है सच्चाई से बफ़ादार और भक्त रहूँगा और जो फ़रज़ मैं अब संभालने वाला हूँ उसे बफ़ादारी के साथ निभाऊँगा।”

दूसरे जोगाजोगों में
राजपति के कार्यों
को निभारना

70—किसी ऐसे जोगाजोग में जिसका इस खंड में बन्धान नहीं किया गया है, राजपति के काम निभारने के लिये राजपंचायत जैसा उचित समझे बन्धान कर सकती है।

राजपति या उप-
राजपति के चुनाव
के बारे में या
उससे सम्बन्ध रखने
वाले मामले

71—(1) राजपति या उप-राजपति के चुनाव से पैदा होने वाले या उसके बारे में सब संदेहों और झगड़ों की पूछताछ और उनका फैसला आला अदालत करेगी, और उसका फैसला आखिरी होगा।

(2) अगर किसी आदमी का राजपति या उप-राजपति चुना जाना आला अदालत रद्द ऐलान कर दे, तो राजपति के या उप-राजपति के, जैसी सूरत हो, अपने पद की शक्तियों से काम लेने और अपने फ़रज़ पूरा करने के दौरान में बसने, आला अदालत के फैसले की तारीख पर या उससे पहले, जो काम किये हों वह उस ऐलान के कारन ना-सरदुरुस्त नहीं माने जायेंगे।

(3) इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए राजपति या उप-राजपति के चुनाव के संबंध में या उसकी बाबत किसी मामले की क़ायदाबन्दी राजपंचायत कानून बनाकर कर सकती है।

72—(1) किसी आदमी को जिसे किसी जुर्म का दोशी ठहराया गया हो माफ़ कर देने, उसकी सज़ा मुलतवी कर देने, उसे मुहलत देने या बाकी सज़ा माफ़ कर देने या उसकी सज़ा के हुकुम को रोक देने, सज़ा के बाकी हुकुम को रद्द कर देने, या सज़ा का रूप बदल देने की शक्ति राजपति को उन सब सूरतों में होगी—

कुछ सूरतों में माफ़ी वगैरा देने और सज़ाओं के हुकुम को रोक रखने या कम करने या बदलने की राजपति की शक्ति

(ए) जिनमें किसी फ़ौजी अदालत ने सज़ा दी हो या सज़ा का हुकुम दिया हो ;

(बी) जिनमें सज़ा या सज़ा का हुकुम किसी ऐसे क़ानून के अधीन जुर्म के लिये दिया गया हो जिस क़ानून का संबंध किसी ऐसे मामले से है जिस तक यूनियन की काजकारी शक्ति का फैलाव है ;

(सी) जिनमें हुकुम मौत की सज़ा का हुकुम है.

(2) धारा (1) की उपधारा (ए) की किसी बात का उस शक्ति पर कोई असर नहीं होगा जो यूनियन की हथियारबन्द फ़ौजों के किसी अफसर को किसी फ़ौजी अदालत के दिये हुए सज़ा के हुकुम को रोक देने, कम कर देने या बदल देने के लिये क़ानून से दी गई हो.

(3) धारा (1) की उपधारा (सी) की किसी बात का उस शक्ति पर कोई असर नहीं होगा जिससे उस समय लागू किसी क़ानून के अधीन किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख मौत की सज़ा को रोक देने, माफ़ कर देने या दूसरी सज़ा में बदल देने के लिये काम ले सकता हो.

73—(1) इस विधान के बंधानों के अधीन रहते हुए यूनियन की काजकारी शक्ति का फैलाव—

यूनियन की काजकारी शक्ति का फैलाव

(ए) उन मामलों तक होगा जिनके बारे में राजपंचायत को क़ानून बनाने की शक्ति है ; और

(बी) ऐसे अधिकारों, सत्ता और अमलदारी से काम लेने तक होगा जिनसे किसी खंघिनामे या राजीनामे की रू से भारत सरकार काम ले सकती है :

शर्तें कि उपधारा (ए) में जिस काजकारी शक्ति की चरबा की गई है उसका फैलाव पहली पट्टी के

भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत में ऐसे मामलों तक न होगा जिनके बारे में रियासत की कानूनसभा को भी कानून बनाने की शक्ति है, सिवाय जब कि इस विधान में या राजपंचायत के बनाए किसी कानून में इसका साफ तौर पर बन्धान कर दिया गया हो.

(2) जबतक राजपंचायत कुछ और बन्धान न करे, तबतक इस दफा में किसी बात के रहते भी, कोई रियासत और किसी रियासत का कोई अफसर या अधिकारी उन मामलों में जिनके बारे में राजपंचायत को उस रियासत के लिये कानून बनाने की शक्ति है, ऐसी काजकारी शक्ति से काम ले सकता है या ऐसे काम कर सकता है जिससे कि वह रियासत या उसके अफसर या अधिकारी इस विधान के आरंभ से ठीक पहले काम ले सकते थे या काम कर सकते थे.

वज़ीर मंडल

राजपति को सहायता और सलाह देने के लिये वज़ीर मंडल 74—(1) राजपति को उसके काम पूरा करने में सहायता और सलाह देने के लिये एक वज़ीर मंडल होगा जिसका सरमुख प्रधान वज़ीर होगा.

(2) किसी अदालत में इस बात की पूछताछ नहीं की जा सकेगी कि वज़ीरों ने राजपति को कोई सलाह दी या नहीं और अगर दी तो क्या दी.

वज़ीरों के बारे में दूसरे बन्धान 75—(1) प्रधान वज़ीर का नियोजन राजपति करेगा, और दूसरे वज़ीरों का नियोजन राजपति प्रधान वज़ीर की सलाह से करेगा.

(2) वज़ीर अपने पद पर राजपति के इच्छाकाल तक रहेंगे.

(3) वज़ीरमंडल के वज़ीर सबके सब मिलकर लोकसदन को जिम्मेदार होंगे.

(4) किसी वज़ीर के अपना पद संभालने से पहले राजपति उससे तीसरी पदवी में इस मतलब के लिये दिये हुए रूपों के अनुसार पद और राजदारी के हलक ठोकायगा.

(5) कोई वज़ीर जो लगातार छै महीने के किसी अरसे

तक राजपंचायत के किसी सदन का मेम्बर न रहे, उस अरसे के बीच जाने पर बज्जीर न रहेगा.

(6) वज्जीरों की तनखाहें और भत्ते वह होंगे जो समय समय पर राजपंचायत कानून बनाकर तय करे और जबतक राज पंचायत इस तरह तय न करे तबतक वह होंगे जो दूसरी पट्टी में दर्ज

भारत का सरमुखतार

76—(1) राजपति किसी ऐसे आदमी को भारत का सरमुखतार नियोजेगा जो आला अदालत के जज नियोजे जाने की जोगता रखता हो. भारत का सरमुख-
तार

(2) सरमुखतार का फरज होगा कि वह भारत सरकार को ऐसे कानूनी मामलों पर सलाह दे और ऐसे कानूनी ढंग के दूसरे फरज पूरा करे जो राजपति उसे समय समय पर भेजे या सौंपे, और उन कामों को निभारे जो इस विधान से या उस समय लागू किसी दूसरे कानून से या इनके अधीन उसे दिये गए हों.

(3) अपने फरजों को पूरा करने में सरमुखतार को भारत के भूभाग की सब अदालतों में सुनवाई का अधिकार होगा.

(4) सरमुखतार राजपति के इच्छाकाल तक अपने पद पर रहेगा और उसको वह मेहनताना मिलेगा जो राजपति तय करे.

सरकारी काम का संचालन

77—(1) भारत सरकार का सारा काजकारी काम राजपति के नाम से किया हुआ कहा जायगा. भारत सरकार के
काम का संचालन

(2) राजपति के नाम से दिये हुए हुकुमों और उसके नाम से किये हुए दूसरे पट्टों का सहीकरन उस ढंग से किया जायगा जो राजपति के बनाए नियमों में बताया जाय, और इस तरह सही किये हुए किसी ऐसे हुकुम या पट्टे की सरदुरुस्ती पर इस बिना पर कोई खवाल नहीं उठाया जायगा कि वह हुकुम राजपति ने नहीं दिया या वह पट्टा राजपति ने नहीं किया.

(3) राजपति भारत सरकार के काम को अधिक आसानी से चलाने के लिये और उस काम को बज्जिरों में बांटने के लिये नियम बनायगा. ^{प्रधान}

राजपति को सूचना देने वगैरा के बारे में बड़े बज्जिर के फ़रज़

78—बड़े बज्जिर का फ़रज़ होगा कि—

(ए) यूनियन के मामलों के शासन सम्बन्धी बज्जिर मंडल के सारे फ़ैसले और क़ानून बनाने के सब सुझाव राजपति को पहुँचावे;

(बी) यूनियन के मामलों के शासन सम्बन्धी और क़ानून बनाने के सुझाव सम्बन्धी जो बातें राजपति पूछे उसको बताए; और

(सी) राजपति के चाहने पर किसी ऐसे मामले को, जिस पर किसी एक बज्जिर ने फ़ैसला कर दिया है पर बज्जिर मंडल ने विचार नहीं किया है, बज्जिरमंडल के सामने विचार के लिये रखे.

खंड दो—राजपंचायत

आम

राजपंचायत की बनावट

79—यूनियन की एक राजपंचायत होगी जिसमें राजपति और दो सदन होंगे, जो अलग अलग रियासत सदन और लोक सदन कहलायेंगे.

रियासत सदन की रचना

80—(1) रियासत सदन में—

(ए) बारह मेम्बर ऐसे होंगे जिनको धारा (3) के बन्धानों के अनुसार राजपति नामज़द करेगा; और

(बी) रियासतों के प्रतिनिधि होंगे जो दो सौ अड़तीस से अधिक नहीं होंगे.

(2) रियासत सदन में रियासतों के प्रतिनिधियों से भरी जाने वाली सीटों का बंटवारा उन बंधानों के अनुसार किया जायगा जो इस काम के लिये चौथी पट्टी में दिये हैं.

(3) धारा (1) की उपधारा (ए) के अधीन राजपति जिन मेम्बरों को नामज़द करेगा वे ऐसे आदमी होंगे जिन्हें इस तरह के मामलों के बारे में जैसे नीचे दिये गए हैं खास जानकारी या अमली तज़रबा हो, यानी :—

अदब-साहित्य, साइन्स, कला और समाजसेवा.

(4) रियासत सदन में पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज हर रियासत के प्रतिनिधियों को उस रियासत के आम सदन के चुने हुए मेम्बर निम्नबतों प्रतिनिधान के ढंग पर इकहरे बदलते वोट से चुनेंगे.

(5) रियासत सदन में पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज रियासतों के प्रतिनिधि उक्त ढंग से चुने जायेंगे जो राजपंचायत कानून बनाकर बतावे.

81—(1), (ए) धारा (2) के और दफा 82 और दफा 331 के लोकसदन की रचना
बन्धानों के अधीन रहते हुए, लोकसदन के मेम्बर पांच सौ से अधिक नहीं होंगे और उन्हें रियासतों के वोटर सीधे चुनेंगे.

(बी) उपधारा (ए) के मतलब के लिये एक रियासत में कई, या कई रियासतों का एक, या एक रियासत का एक, इस तरह रियासतों के भूभागी चुनाव-हलके बनाए जायेंगे, और ऐसे हर चुनाव-हलके को मिलने वाले मेम्बरों की तादाद इस तरह तय की जायगी जिसे कि यह पक्का हो जाय कि आबादी के हर सात लाख पचास हजार आदमियों पीछे एक से कम मेम्बर नहीं होगा, और हर पांच लाख पीछे एक से अधिक मेम्बर नहीं होगा.

(सी) हर भूभागी चुनाव-हलके को जो मेम्बर दिये जायेंगे उनकी गिनती, और उस हलके की आबादी की वह गिनती जो उस पिछले आखरी गिनावे में मालूम की जा चुकी है, जिसके संगत आंकड़े निकल चुके हैं, इन दोनों में जहां तक हो सकेगा भारत के सारे भूभाग में एक ही अनुपात होगा.

(2) लोक सदन में उन भूभागों का प्रतिनिधान, जो भारत के भूभाग में शामिल हैं लेकिन किसी रियासत में शामिल नहीं हैं, वह होगा जो राजपंचायत कानून बनाकर तय कर दे.

(3) हर गिनावे के पूरा हो जाने पर, लोकसदन में अलग अलग भूभागी चुनाव-हलकों के प्रतिनिधान में वह अधिकारी उस ढंग से और उस तारीख से लागू होने के लिये घटत बढ़त करेगा जैसे राजपंचायत कानून बनाकर तय करदे:

शर्तें कि इस तरह की घटत बढ़त का लोकसदन के प्रतिनिधान पर तबतक कोई असर नहीं पड़ेगा जबतक कि उस समय का सदन भंग न हो जाय.

भाग (सी) की रियासतों के और रियासतों को छोड़कर दूसरे भूभागों के प्रतिनिधान के बारे में खास बन्धान

82—दफ़ा 81 की धारा (1) में किसी बात के रहते भी, राज पंचायत कानून बनाकर, लोकसदन में, पहली पट्टी के भाग (डी) में दर्ज किसी रियासत के, या किसी ऐसे भूभागों के जो भारत के भूभाग में शामिल हैं पर किसी रियासत में शामिल नहीं हैं, उस धारा में जो बन्धान किया गया है उसको छोड़कर किसी दूसरे आधार पर या किसी दूसरे ढंग से प्रतिनिधान का बन्धान कर सकती है.

राज पंचायत के सदनों की मुद्दत

83—(1) रियासत सदन को भंग न किया जा सकेगा, पर हर दूसरे बरस के बीत जाने पर जितनी जल्दी हो सकेगा सदन के मेम्बरों में से करीब से करीब एक तिहाई, उन बन्धानों के अनुसार जो राजपंचायत कानून के जरिये इस काम के लिये बनादे, अलग हो जाया करेंगे.

(2) लोकसदन अगर पहले ही भंग न कर दिया गया हो तो जो तारीख उसकी पहली मिलनी के लिये तय की गई थी उससे पांच बरस तक चलेगा, और अधिक नहीं, और इस पांच बरस के अरसे के बीत जाने से ही लोकसदन भंग माना जायगा:

शर्तें कि किसी ऐसे समय में जब कोई अधिवेशन का ऐलान अमल में हो, राजपंचायत कानून बनाकर इस अरसे को एक और अरसे के लिये बढ़ा सकती है जो एक बार में एक बरस से अधिक न होगा, और जो किसी भी सूरत में ऐलान का अमल खतम होने के बाद छै महीने के अरसे से अधिक न चलेगा.

84—कोई आदमी राजपंचायत में कोई सीट भरने के लिये चुने जाने के जोग नहीं होगा जब तक कि वह —

राजपंचायत की
मेम्बरी के लिये
जोगता

(ए) भारत का नागर न हो;

(बी) रियासत सदन की सीट के लिये कम से कम तीस बरस की और लोकसदन की सीट के लिये कम से कम पच्चीस बरस की उमर का न हो; और

(सी) ऐसी और जोगताएँ न रखता हो जो इस काम के लिये राजपंचायत के बनाए हुए किसी कानून में या उसके अधीन बताई जायं.

85—(1) राज पंचायत के सदनों को हर बरस में कम से कम दो बार मिलने के लिये बुलाया जायगा और एक इजलास में उनकी आखरी बैठक और अगले इजलास में पहली बैठक की जो तारीख ठहराई गई हो उनके बीच छै महीने नहीं बीतने पायंगे.

राजपंचायत के
इजलास, उसे बर-
खास्त करना और
भंग करना

(2) धारा (1) के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपति समय समय पर—

(ए) राजपंचायत के सदनों को या किसी एक सदन को मिलने के लिये जिस समय और जिस जगह ठीक समझे बुला सकता है;

(बी) सदनों को बरखास्त कर सकता है;

(सी) लोकसदन को भंग कर सकता है.

86—(1) राजपति राजपंचायत के किसी भी सदन में या दोनों सदनों की मिलीजुली बैठक में सर-बचन दे सकता है और इस मतलब के लिये मेम्बरों की हाजरी तलब कर सकता है.

राजपति को सदनों
में सर-बचन देने
और संदेसे भेजने
का अधिकार

(2) राजपति राजपंचायत के किसी भी सदन को किसी ऐसे बिल के बारे में जो उस समय राजपंचायत के सामने हो या किसी और मतलब के लिये संदेसे भेज सकता है, और जिस सदन को इस तरह का कोई संदेसा भेजा जाय वह जितनी जल्दी सुभीते के साथ कर सकेगा उस मामले पर सोच विचार करेगा जिस पर सोच विचार करने को उस संदेसे में कहा गया हो.

हर इजलास के आरंभ में राष्ट्रपति का खास सर-बचन

87—(1) हर इजलास के आरंभ में राजपति राजपंचायत के दोनों सदनों को इकट्ठा करके सर-बचन देगा और राजपंचायत को उसके बुलाए जाने के कारन बतायगा।

(2) हर सदन के दस्तूर की क्रायदाबन्दी करने वाले नियमों में इस बात का बन्धान किया जायगा कि इस तरह के सर-बचन में जिन मामलों की चरचा की गई हो उनपर बहस करने के लिये समय रखा जाय और यह बहस सदन के और कामों से पहले हो।

सदनों के बारे में वज़ीरों और सर मुख्तार के अधि-कार

88—हर वज़ीर को और भारत के सरमुख्तार को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में या सदनों की किसी भी मिलीजुली बैठक में और राजपंचायत की किसी भी ऐसी कमेटी में, जिसके मेम्बरों में उसका नाम हो, बोले और दूसरी तरह कारबाई में हिस्सा ले, मगर वोट देने का हकदार वह इस दफा की रू से नहीं होगा।

राजपंचायत के अफ़सर

रियासतसदन का मसनदी और उप-मसनदी

89—(1) भारत का उप-राजपति पद-नाते रियासत सदन का मसनदी होगा।

(2) रियासत सदन जितनी जल्दी हो सकेगा, सदन के किसी मेम्बर को उसका उप-मसनदी चुन लेगा और जब जब उप-मसनदी का पद सूना होगा, सदन किसी दूसरे मेम्बर को अपना उप-मसनदी चुन लेगा।

उप-मसनदी का पद सूना होना, उसका इस्तीफ़ा देना और पद से हटाया जाना

90. कोई मेम्बर जो रियासत सदन के उप-मसनदी के पद पर हो—

(ए) अगर सदन का मेम्बर न रहे तो अपना पद सूना कर देगा;

(बी) किसी समय भी मसनदी के नाम अपनी दसखती लिखत भेजकर अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकता है; और

(सी) सदन के एक ऐसे ठहराव से अपने पद से हटाया

जा सकता है जिसे सदन के उस समय के कुल मेम्बरों की बड़ीयत ने पास किया हो:

शर्तें कि धारा (बी) के मतलब के लिये कोई ठहराव पेश नहीं किया जायगा जब तक कि उस ठहराव को पेश करने के इरादे का कम से कम चौदह दिन का नोटिस न दिया गया हो.

91—(1) जब कभी मसनदी का पद सूना हो, या उस अरसे में जब उप-राजपति राजपति की जगह काम कर रहा हो या उसके काम निभार रहा हो, मसनदी के पद के फ़रज़ उप-मसनदी पूरे करेगा, या अगर उप-मसनदी का पद भी सूना हो तो रियासत सदन का वह मेम्बर करेगा जिसको राजपति इस मतलब के लिये नियोजे.

उप-मसनदी को या किसी दूसरे आदमी को मसनदी के पद के फ़रज़ पूरे करने या मसनदी की जगह काम करने की शक्ति

(2) रियासत सदन की किसी बैठक में मसनदी के मौजूद न रहने पर उप-मसनदी, या अगर वह भी मौजूद नहीं है तो कोई ऐसा आदमी, जिसे सदन के दस्तूर के नियम तय करें, या अगर ऐसा कोई आदमी मौजूद नहीं है तो कोई ऐसा दूसरा आदमी जिसे सदन तय करे, मसनदी की जगह काम करेगा.

92—(1) रियासत सदन की किसी बैठक में जब कि उप-राजपति को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो मसनदी, या जब उप-मसनदी को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो उप-मसनदी, मौजूद होने पर भी सदारत नहीं करेगा, और दफ़ा 91 की धारा (2) के बंधान इस तरह की हर बैठक के बारे में उसी तरह लागू होंगे जिस तरह किसी उस बैठक के बारे में लागू होते जिसमें, मसनदी या उप-मसनदी, जैसी सूरत हो, मौजूद न होता.

मसनदी या उप-मसनदी उस समय सदारत नहीं करेगा जबकि उसको पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार किया जा रहा हो

(2) जब रियासत सदन में उप-राजपति को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो मसनदी को सदन में बोलने और दूसरी तरह कारबाई में भाग लेने का अधिकार होगा, पर दफ़ा 100 में किसी बात के रहते भी उस ठहराव

पर या ऐसी कारबाइयों के दौरान में किसी और मामले पर वह वोट देने का बिलकुल हक्कदार नहीं होगा।

लोकसदन का
सभामुख और उप-
सभामुख

93—लोक सदन जितनी जल्दी हो सकेगा सदन के दो मेम्बरों को अलग अलग सदनका सभामुख और उप-सभामुख चुनेगा और जब जब सभामुख या उप-सभामुख का पद सूना होगा, सदन किसी और मेम्बर को सभामुख या उप-सभामुख, जैसी सूरात हो, चुन लेगा।

सभामुख और उप-
सभामुख का पद
सूना होना, उनका
इस्तीफा देना और
पद से हटाया
जाना

94—कोई मेम्बर जो लोक सदन के सभामुख या उप-सभामुख के पद पर है—

(ए) अगर लोक सदन का मेम्बर न रहे तो अपना पद सूना कर देगा;

(बी) अगर वह मेम्बर सभामुख है तो उप-सभामुख के नाम और अगर वह मेम्बर उप-सभामुख है तो सभामुख के नाम किसी समय भी अपनी दसखती लिखत भेजकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है; और

(सी) लोक सदन के एक ऐसे ठहराव से अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे सदन के उस समय के कुल मेम्बरों की बड़ीयत पास कर दे:

शर्तें कि धारा (सी) के मतलब के लिये कोई ठहराव पेश नहीं किया जायगा जबतक कि उस ठहराव को पेश करने के इरादे का कम से कम चौदह दिन का नोटिस न दिया जा चुका हो:

और शर्तें कि जब कभी लोक सदन को भंग किया जाय तो, सदन के भंग होने के बाद अगले लोक सदन की पहली मिलनी के ठीक पहले तक सभामुख अपना पद सूना नहीं करेगा।

उप-सभामुख या
किसी दूसरे आदमी
को सभामुख के
पद के फ़रज़ पूरा
करने या सभामुख
को जगह काम
करने की शक्ति

95—(1) जब कभी सभामुख का पद सूना होगा, उसके पद के फ़रज़ उप-सभामुख पूरे करेगा, या अगर उप-सभामुख का पद भी सूना हो तो लोकसदन का कोई ऐसा मेम्बर करेगा जिसका राजपति इस मतलब के लिये नियोजन कर दे।

(2) लोकसदन की किसी बैठक में सभामुख के मौजूद न रहने पर उप-सभामुख या अगर वह भी मौजूद नहीं है तो कोई ऐसा आदमी जिसे सदन के दस्तूर के नियम तय करें, या अगर ऐसा

कोई आदमी भी मौजूद नहीं है, तो कोई और ऐसा आदमी जिसे सदन तय करे, सभामुख की जगह काम करेगा.

96—(1) लोक सदन की किसी बैठक में जब कि सभामुख को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो सभामुख या जब कि उप-सभामुख को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो उप-सभामुख, मौजूद होने पर भी, सदारत नहीं करेगा, और दफा 95 की धारा (2) के बन्धान हर ऐसी बैठक के बारे में उसी तरह लागू होंगे जिस तरह किसी ऐसी बैठक के बारे में लागू होते जिसमें सभामुख या उप-सभामुख, जैसी सूरत हो, मौजूद न होता.

सभामुख या उप-सभामुख सदारत नहीं करेगा जब कि उसको पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार किया जा रहा हो

(2) लोक सदन में सभामुख को उसके पद से हटाने के लिये जब किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो सभामुख को उस सदन में बोलने और दूसरी तरह कारवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, और दफा 100 में किसी बात के रहते भी वह पहली बार तो उस ठहराव पर या उस कारवाई के दौरान में किसी भी दूसरे मामले पर वोट देने का हक़शार होगा पर बराबर के बोट आने की हालत में नहीं होगा.

97—रियासत सदन के मसनदी और उप-मसनदी को और लोक सदन के सभामुख और उप-सभामुख को वह तनखाहें और भत्ते मिलेंगे जो राजपंचायत क्रानून बनाकर अलग अलग तय कर दे और जब तक इसके लिये इस तरह का कोई बन्धान नहीं होता तब तक उनको वह तनखाहें और भत्ते मिलेंगे जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं.

मसनदी और उप-मसनदी और सभामुख और उप-सभामुख को तनखाहें और भत्ते

98—(1) राजपंचायत के हर सदन का अलग अलग मंत्रायती अमला होगा:

राजपंचायत की मंत्रायत

शर्तें कि इस धारा की किसी बात से यह मतलब नहीं लिया जायगा कि वह राजपंचायत के दोनों सदनों के लिये शामिलती जगहें बनाए जाने को रोकती है.

(2) राजपंचायत क्रानून बनाकर अपने किसी सदन के मंत्रायती अमले में नियोजे जाने के लिये लोगों की भरती और उनकी नौकरी की शर्तों की क़ायदाबन्दी कर सकती है.

(3) जब तक धारा (2) के अधीन राजपंचायत कोई बन्धान नहीं करती तब तक राजपति लोकसदन के सभामुख से या रियासत सदन के मसनदी से, जैसी सूरत हो, सलाह करने के बाद लोकसदन के या रियासत सदन के मंत्रायती अमले में नियोजे जाने वाले लोगों की भरती और उनकी नौकरी की शर्तों की क्रायदाबन्दी करनेवाले नियम बना सकता है, और जो नियम इस तरह बनाए जायेंगे उनका असर उस धारा के अधीन बने हुए कानून के बन्धानों के अधीन होगा.

काम का संचालन

मेम्बरों का हलफ
ठठाना या वचन
भरना

99. राजपंचायत के हर सदन का हर मेम्बर अपनी सीट लेने से पहले राजपति के सामने या इस काम के लिये राजपति के नियोजे हुए किसी आदमी के सामने, उस रूप के अनुसार हलफ उठायगा या वचन भरेगा और उस पर दसखत करेगा जो रूप इस मतलब के लिये तीसरी पट्टी में दिया हुआ है.

सदनों में वोट
लेना, सुनिया होने
पर भी सदनों को
काम करने की
शक्ति, और कोरम

100—(1) सिवाय जबकि इस विधान में कुछ और बन्धान किया गया हो, किसी भी सदन को किसी बैठक में या दोनों सदनों की मिली जुली बैठक में सब सवाल, सभामुख को या उस आदमी को जो मसनदी या सभामुख की जगह काम कर रहा हो छोड़कर, उस समय मौजूद और वोट देने वाले सब मेम्बरों के वोटों की बढ़ीयत से तय किये जायेंगे.

मसनदी या सभामुख या वह आदमी जो उनकी जगह काम कर रहा हो पहले तो वोट नहीं देगा, मगर बराबर वोट आने की सूरत में उसको जिताऊ वोट देने का अधिकार होगा और वह उससे काम लेगा.

(2) राजपंचायत के हर सदन को शक्ति होगी कि उस सदन के मेम्बरों की कुछ सीटें सूनी होने पर भी काम करे, और राजपंचायत की हर कारवाई सरदुरुस्त होगी, भले ही बाद में यह पता चले कि कोई ऐसा आदमी सदन में बैठा, उसने वोट दिया या और किसी तरह कारवाई में भाग लिया जो ऐसा करने का हकदार नहीं था.

(3) जब तक राजपंचायत क़ानून बनाकर कोई दूसरा बन्धान नहीं करती तब तक राजपंचायत के हरसदन की मिलनी के लिये कोरम उस सदन के कुल मेम्बरों की गिनती का एक दसवाँ होगा.

(4) अगर किसी सदन की किसी मिलनी के दौरान में किसी समय कोरम न रहे तो मसनदी का या सभामुख का या उस आदमी का जो उनकी जगह काम कर रहा हो, फ़रज़ होगा कि या तो सदन को मुलतवी कर दे या उस मिलनी को कोरम पूरा हो जाने तक के लिये रोक दे.

मेम्बरों की अजोगताएं

101—(1) कोई आदमी राजपंचायत के दोनों सदनों का मेम्बर नहीं होगा, और राजपंचायत क़ानून बनाकर इस बात का बन्धान करेगी कि अगर कोई आदमी दोनों सदनों का मेम्बर चुना जाय तो वह दोनों में से किसी एक सदन में अपनी सीट सूनी कर दे.

सीटों का सुना होना

(2) कोई आदमी राजपंचायत और पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की क़ानून सभा, दोनों का मेम्बर नहीं होगा, और अगर कोई आदमी राजपंचायत और ऐसी किसी रियासत की क़ानूनसभा, दोनों का मेम्बर चुना जाय, तो उस अरसे के पूरा होने पर जो राजपति के बनाए नियमों में दिया हो, राजपंचायत में उस आदमी की सीट सूनी हो जायगी, जब तक कि उसने इससे पहले ही रियासत की क़ानून सभा में अपनी सीट से इस्तीफ़ा न दे दिया हो.

(3) अगर राजपंचायत के किसी सदन का कोई मेम्बर—

(ए) दफ़ा 102 की धारा (1) में बताई किसी अजोगता के अधीन हो जाए; या

(बी) मसनदी या सभामुख के नाम, जैसी सूरत हो, अपनी दसखती लिखत भेजकर अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे दे, तो इस पर उसकी सीट सूनी हो जायगी.

(4) अगर राजपंचायत के किसी सदन का कोई मेम्बर साठ दिन के अरसे तक सदन की इजाज़त बिना सदन की सब मिलनियों में नामौजूद रहे तो सदन उसकी सीट को सूनी ठहरा सकता है.

शर्त्तें कि साठ दिन के इस अरसे के गिनने में वह अरसा नहीं गिना जायगा जब कि सदन बरखास्त रहा हो या लगातार चार दिन से अधिक के लिये मुलतबी कर दिया गया हो.

मेम्बरी के लिये
अजोगताएँ

102—(1) वह आदमी राजपंचायत के किसी सदन का मेम्बर चुने जाने या मेम्बर होने के अजोग होगा—

(प) जो भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत की सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर हो, सिवाय किसी ऐसे पद के जिसे राजपंचायत ने कानून बनाकर यह ठहरा दिया हो कि उस पद पर रहने से कोई आदमी अजोग नहीं समझा जायगा;

(बी) जिसका दिमाग ठीक नहीं है और जिसे किसी अधिकाारी अदालत ने ना-ठीक दिमाग का ठहरा दिया है;

(सी) जो ऐसा दिवालिया है जिसे अभी तक बरी नहीं किया गया है;

(डी) जो भारत का नागर नहीं है, या जो अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज का नागर बन गया है, या जो किसी विदेशी राज की भक्ति या उससे लगाव मान चुका है;

(ई) जो राजपंचायत के बनाए किसी कानून से या उसके अधीन इसके लिये अजोग ठहराया गया है.

(2) इस दफा के मतलबों के लिये कोई आदमी भारत सरकार या किसी रियासत की सरकार के अधीन केवल इसी कारन किसी लाभ के पद पर नहीं समझा जायगा कि वह यूनियन का या उस रियासत का बज्जीर है.

मेम्बरों की अजोग-
ताओं के बारे में
सवालों पर फ़ैसला

103—(1) अगर कोई ऐसा सवाल उठे कि राजपंचायत के किसी सदन का कोई मेम्बर दफा 102 की धारा (1) में बताई किसी अजोगता के अन्दर आ गया है या नहीं तो इस सवाल को राजपति के फ़ैसले के लिये भेजा जायगा और उसका फ़ैसला आखरी होगा.

(2) ऐसे किसी सवाल पर कोई फ़ैसला देने से पहले, राजपति चुनाव कमीशन की राय लेगा और उस राय के अनुसार काम करेगा.

104—अगर कोई आदमी दफा 99 की जरूरतों को पूरा करने से पहले, या जब वह यह जानता हो कि वह राजपंचायत के किसी सदन की मेम्बरी के जोग नहीं है, या उसे उसके अजोग ठहराया गया है, या राजपंचायत के बनाए किसी कानून के बन्धानों से उसको मेम्बर की तरह बैठने या वोट देने की मनाही की गई है, राजपंचायत के उस सदन में मेम्बर की तरह बैठेगा या वोट देगा तो जितने दिन वह इस तरह बैठेगा या वोट देगा, उस पर हर दिन के लिये पाँच सौ रुपये दंड लगाया जा सकेगा जो उससे यूनियन के क्ररजे के रूप में वसूल किया जायगा.

दफा 99 के अधीन हलफ उठाने या वचन भरने से पहले या जोग न होने या अजोग ठहराए जाने पर बंधने और वोट देने पर दंड

राजपंचायत और उसके मेम्बरों की शक्तियाँ, उनके निज- नियम और उनकी बरीयतें

105—(1) इस विधान के बन्धानों और राजपंचायत के दस्तूर की क़ायदाबन्दी करने वाले नियमों और क़ायमी हुकुमों के अधीन रहते हुए, राजपंचायत में बोलने की आज़ादी होगी.

राजपंचायत के सदनों की और उनके मेम्बरों और कमेटियों की शक्तियाँ, निज-नियम वगैरा

(2) राजपंचायत के किसी मेम्बर ने जो कुछ राजपंचायत में या उसकी किसी कमेटी में कहा हो या जिस तरह वोट दिया हो उसके बारे में उस मेम्बर के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई कारवाई नहीं की जा सकेगी, और राजपंचायत के किसी सदन की तरफ से या उसके हुकुम से जो कोई रिपोर्ट कागज़, वोट या कारवाई निकाली जाय उसके बारे में किसी आदमी के खिलाफ इस तरह की कोई कारवाई नहीं की जा सकेगी.

(3) और बातों में राजपंचायत के हर सदन की और हर सदन के मेम्बरों और कमेटियों की शक्तियाँ, निजनियम और बरीयतें यह होंगी, जो राजपंचायत समय समय पर कानून बनाकर तय करदे, और जब तक इस तरह न तय करदी जाएं तब तक वह होंगी जो इस विधान के आरम्भ के समय यूनाइटेड किंगडम (इंगलिस्तान) की पार्लिमेंट के हाउस आफ कामन्स को और उसके मेम्बरों और कमेटियों को हासिल हों.

(4) धारा (1), (2) और (3) के बन्धान जिस तरह राजपंचायत के मेम्बरों के सम्बन्ध में लागू होते हैं वही तरह उन

लोगों के सम्बन्ध में लागू होंगे जिनको इस विधान की रू से राज-पंचायत के किसी सदन में या उसकी किसी कमिटी में बोलने का या किसी और तरह कारवाई में भाग लेने का अधिकार है.

मेम्बरों की तनखाहें और भत्ते

106—राजपंचायत के हर सदन के मेम्बर वह तनखाहें और भत्ते पाने के हक्कदार होंगे जो राजपंचायत समय समय पर कानून बनाकर तय करे, और जब तक इस बारे में इस तरह का बन्धान न किया जाय तब तक उनको उसी दर से और उन्हीं शर्तों पर भत्ते मिलेंगे जिनपर इस विधान के आरम्भ से ठीक पहले हिन्दू डोमिनियन की विधान सभा के मेम्बरों को मिलते थे.

कानूनकारी दस्तूर

बिल रखने और पास करने के बारे में बन्धान

107—(1) नक़दी बिलों और दूसरे माली बिलों के बारे में दफ़ा 109 और दफ़ा 117 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, किसी भी बिल की पहल राजपंचायत के किसी भी सदन में की जा सकती है.

(2) दफ़ा 108 और 109 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, कोई बिल राजपंचायत के सदनों से पास हुआ उस समय तक नहीं समझा जायगा जब तक कि दोनों सदनों ने, या तो बिना सुधार या केवल ऐसे सुधारों के साथ जिन्हें दोनों सदनों ने मान लिया हो, उस बिल को मान न लिया हो.

(3) कोई बिल जो राजपंचायत के सामने पेश है सदनों के बरखास्त हो जाने के कारन गिर नहीं जायगा.

(4) कोई बिल जो रियासत सदन के सामने पेश है और जिसे लोकसदन ने पास नहीं किया है लोकसदन के भंग होने पर गिर नहीं जायगा.

(5) अगर कोई बिल लोकसदन में पेश है या लोकसदन से पास होकर रियासत सदन में पेश है, तो वह दफ़ा 108 के बन्धानों का ध्यान रखते हुए लोकसदन के भंग होने पर गिर

कुछ शर्तों में दोनों सदनों की मंजी ज़रूरी बैठक.

108—(1) अगर किसी बिल के एक सदन से पास होकर दूसरे सदन को भेज दिये जाने के बाद—

(ए) दूसरे सदन ने बिल को नामंजूर कर दिया है; या

- (बी) बिल में जो सुधार करने हों, उनके बारे में सदनों की राय आखीर में मिली न हो; या
(सी) दूसरे सदन में बिल के आने की तारीख से छै महीने से अधिक बीत गए हों और उस सदन ने उसे तब तक पास न किया हो,

तो राजपति, जबतक कि वह बिल लोकसदन के भंग होने के कारन गिर न गया हो, अगर सदनों की बैठकें हो रही हों तो संदेश भेज कर या अगर उनकी बैठकें नहीं हो रही हैं तो आम नोटिस निकाल कर दोनों सदनों को इत्तला दे सकता है कि वह उस बिल पर सोच विचार करने और वोट देने के लिये सदनों की एक मिली जुली बैठक बुलाने का इरादा रखता है.

शर्तें कि इस धारा की कोई बात किसी नकदी बिल पर नहीं लागेगी.

(2) धारा (1) में जिस छै महीने के अरसे की चरचा की गई है उसका हिसाब लगाने में वह समय नहीं गिना जायगा जब उस धारा की उप-धारा (सी) में जिस सदन की चरचा की गई है वह बरखास्त रहा हो या लगातार चार दिन से अधिक के लिये मुत्ततवी कर दिया गया हो.

(3) जब राजपति ने धारा (1) के अधीन दोनों सदनों की मिली जुली बैठक बुलाने के इरादे का नोटिस दे दिया हो, तो कोई सदन बिल पर आगे कारवाई नहीं करेगा, पर राजपति नोटिस की तारीख के बाद किसी समय भी, जो मतलब नोटिस में बताया गया है उसके लिये सदनों की मिली जुली बैठक बुला सकता है, और अगर वह ऐसा करे तो जिस तरह वह बताए उस तरह सदनों की बैठक होगी.

(4) अगर दोनों सदनों की मिली जुली बैठक में ऐसे सुधारों के साथ (अगर कोई ऐसे सुधार हैं तो) जिन्हें मिली जुली बैठक ने मान लिया है, वह बिल दोनों सदनों के मौजूद और वोट देने वाले कुल मेम्बरों की बड़ीयत से पास हो जाय, तो इस विधान के मतलबों के लिये वह समझा जायगा कि बिल को दोनों सदनों ने पास कर दिया है.

शर्तें कि मिली जुली बैठक में—

(ए) अगर वह बिल एक सदन से पास हो कर दूसरे सदन में सुधारों के साथ पास नहीं होता और जिस सदन में बिल की पहल की गई थी उसको लौटा दिया जाता है तो उस बिल में सिवाय ऐसे सुधारों के (अगर कोई ऐसे सुधार हों तो) जो बिल के पास होने में देर हो जाने के कारन जरूरी हो गए हों, कोई और सुधार नहीं रखा जायगा.

(बी) अगर बिल इस तरह पास करके लौटा दिया गया है तो बिल में केवल ऊपर बताए सुधार और ऐसे दूसरे सुधार ही रखे जा सकेंगे जो उन मामलों से संगत हों जिनके बारे में सदनों की एक राय नहीं है;

और सदारत करने वाले आदमी का यह फैसला कि इस धारा के अधीन कौन से सुधार लिये जा सकते हैं, आखरी होगा.

(5) इस दफा के अधीन मिली जुली बैठक हो सकती है, और उसमें बिल पास किया जा सकता है, भले ही राजपति के सदनों की बैठक बुलाने के इरादे का नोटिस दिये जाने के बाद लोक सदन भंग कर दिया गया हो.

नक़दी बिलों के बारे में खास दस्तुर 109—(1) कोई नक़दी बिल पहले रियासत सदन में नहीं रखा जायगा.

(2) नक़दी बिल लोक सदन से पास होकर रियासत सदन को उसकी सिफ़ारिशों के लिये भेजा जायगा और रियासत सदन बिल के आने की तारीख़ से चौदह दिन के अरसे के अन्दर अन्दर अपनी सिफ़ारिशों के साथ बिल लोक सदन को लौटा देगा, इस पर लोक सदन चाहे तो रियासत सदन की सारी सिफ़ारिशें या कोई सी सिफ़ारिश मान ले या न माने.

(3) अगर लोक सदन रियासत सदन की सिफ़ारिशों में से किसी को मान लेता है तो यह समझा जायगा कि नक़दी बिल

को, उन सुधारों के साथ जिनकी रियासत सदन ने सिफारिश की है और जिन्हें लोकसदन ने मान लिया है, दोनों सदनों ने पास कर दिया है.

(4) अगर लोक सदन रियासत सदन की सिफारिशों में से किसी को भी नहीं मानता तो यह समझा जायगा कि नक़दी बिल को, बिना उन सुधारों में से किसी के जिनकी सिफारिश रियासत सदन ने की है, उसी रूप में जिसमें लोक सदन ने उसे पास किया था, दोनों सदनों ने पास कर दिया है.

(5) अगर कोई नक़दी बिल लोक सदन से पास होकर सिफारिशों के लिये रियासत सदन को भेजा गया हो और ऊपर कहे चौदह दिन के अरसे के अन्दर लोक सदन को न लौटाया गया हो, तो यह समझा जायगा कि इस अरसे के बीत जाने पर उस बिल को, उसी रूप में जिसमें लोकसदन ने उसे पास किया था, दोनों सदनों ने पास कर दिया है.

110—(1) इस खंड के मतलबों के लिये वह बिल 'नक़दी बिल' "नक़दी बिल" की समझा जायगा जिसमें केवल वही बन्धान हों जिनका नीचे लिखे परिभाषा सब मामलों से या इनमें से किसी मामले से सम्बन्ध है, यानी—

(ए) किसी टैक्स का लगाना, अन्त करना, उसमें कूट देना, उसे बदलना या उसकी क़ायदाबन्दी करना;

(बी) रुपया उधार लेने की क़ायदाबन्दी करना, या भारत सरकार का कोई गारन्टी देना, या किसी ऐसी माली ज़िम्मेदारियों के बारे में, जो भारत सरकार ने ले रखी हों या जिन्हें वह लेने वाली हो, क़ानून में कोई सुधार करना;

(सी) भारत के मूठकोश या जोगाजोग कोश की रखबाली, ऐसे किसी कोश में रुपया जमा करना, या उसमें से रुपया निकालना;

(डी) भारत के मूठकोश में से रुपय को खर्च की मदों में डालना;

(ई) किसी खर्च को भारत के मूठकोश में से किये जाने

बाला खर्च ठहराना, या इस तरह के किसी खर्च की रकम को बढ़ाना;

(एफ) भारत के मूठकोश के हिसाब में, या भारत के सरकारी हिसाब में रुपया वसूल करना या ऐसे रुपए की रखवाली करना या उसका निकास करना, या यूनियन या किसी रियासत के हिसाब किताब को पढ़तालना; या

(जी) (ए) से (एफ) तक की उपधाराओं में दर्ज मामलों में से किसी के साथ प्रसंग से आया हुआ कोई और मामला.

(2) किसी बिल को केवल इसी कारन नक्रदी बिल नहीं समझा जायगा कि वह जुरमाने करने, या रुपए पैसे का कोई दूसरा दंड देने, या लाइसेंसों के लिये या जो कोई सेवाएँ की गई हों उनके लिये फीस मांगने या फीस देने, का बन्धान करता है, या इस कारन कि वह मुकामी मतलबों के लिये किसी मुकामी अधिकारी या संस्था के कोई टैक्स लगाने, अन्त करने, उसमें छूट देने, उसको बदलने या उसकी क्रायदाबन्दी करने का बन्धान करता है.

(3) अगर ऐसा कोई सवाल उठे कि कोई बिल नक्रदी बिल है या नहीं, तो इस पर लोकसदन के सभामुख का फैसला आखरी होगा.

(4) जब कोई नक्रदी बिल दफा 109 के अधीन रियासत सदन को भेजा जाय और जब कोई नक्रदी बिल दफा 111 के अधीन मंजूरी के लिये राजपति के सामने रखा जाय, तो हर ऐसे बिल पर लोक सदन के सभामुख की दखलती सनद होगी कि वह बिल नक्रदी बिल है.

बिलों पर मंजूरी

111—जब कोई बिल राजपंचायत के सदनों से पास हो जाय तो उसे राजपति के सामने रखा जायगा, और राजपति ऐलान करेगा कि वह उस बिल पर मंजूरी देता है या उससे अपनी मंजूरी रोक लेता है:

शर्तें कि किसी बिल के राजपति के सामने मंजूरी के लिये रखे जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके राजपति उस बिल को, अगर वह नक़दी बिल नहीं है, तो एक ऐसे संदेसे के साथ सदनों को लौटा सकता है जिसमें यह प्रार्थना की गई हो कि वह बिल पर या उसके किन्हीं बताए हुए बन्धानों पर फिर से सोच विचार करें और खास कर इस बात को सोचें कि अगर राजपति ने अपने संदेसे में किन्हीं सुधारों की सिफ़ारिश की है तो ऐसे किन्हीं सुधारों को ले लेना चाहिये या नहीं, और जब कोई बिल इस तरह वापिस किया जायगा तो उस संदेसे के अनुसार दोनों सदन बिल पर फिर से सोच विचार करेंगे, और अगर दोनों सदन बिल को फिर बिना सुधार या सुधारों के साथ पास कर देते हैं, और वह मंजूरी के लिये राजपति के सामने रखा जाता है, तो राजपति उससे अपनी मंजूरी नहीं रोकेगा।

माली मामलों में दस्तूर

112—(1) राजपति हर माली साल के बारे में राजपंचायत के दोनों सदनों के सामने उस साल के लिये भारत सरकार की आमदनी और खर्च के तख़्मीने का एक ब्योरा रखवाएगा जिसकी चरचा इस भाग में “सालाना माली ब्योरा” कह कर की गई है।

(2) सालाना माली ब्योरे के अन्दर खर्च के जो तख़्मीने रहेंगे उनमें यह रक़में अलग अलग दिखाई जाएंगी—

(ए) वह रक़में जो उस खर्च के लिये दरकार होंगी जिसे इस विधान में भारत के मूठकोश के खाते में पड़ने वाला खर्च बताया गया है; और

(बी) वह रक़में जो उन दूसरे खर्चों के लिये दरकार होंगी जिनके बारे में यह सुझाव है कि वह भारत के मूठकोश में से किये जाएँ,

और उसमें सालगुजारी खाते खर्च और दूसरे खर्चों में फ़रक़ किया जायगा।

(3) नीचे लिखे खर्च वह खर्च होंगे जो भारत के मूठकोश के खाते में पड़ेंगे—

(ए) राजपति का वेतन और भत्ते और उसके पद

सम्बन्धी दूसरे खर्च;

(बी) रियासत सदन के मसनदी और उप-मसनदी और लोकसदन के सभामुख और उप-सभामुख की तनखाहें और भत्ते;

(सी) करजा खर्च जिसके लिये भारत सरकार देनदार है, जिसमें सूद-ब्याज, बट्टे खाते का खर्च और भुगतान खर्च, और उधार लेने, करजा जारी रखने और करजा चुकाने के सम्बन्ध में दूसरे खर्च शामिल होंगे;

(डी) (एक) वह तनखाहें, भत्ते और पेनशनें जो आला अदालत के जजों को या उनके बारे में दी जानी हों;

(दो) वह पेनशनें जो संघ अदालत के जजों को या उनके बारे में दी जानी हों ;

(तीन) वह पेनशनें जो किसी ऐसी हाईकोर्ट के जजों को या उनके बारे में दी जानी हों जिसकी अमलदारी किसी ऐसे क्षेत्र में है जो भारत के भू-भाग में शामिल है या जिसकी अमलदारी इस विधान के आरंभ से पहले किसी समय भी किसी ऐसे क्षेत्र में थी जो पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज किसी रियासत के जबाबी सूबे में शामिल था.

(ई) भारत के दाब अफसर और सर पड़तालिया को या उसके बारे में दी जाने वाली तनखाह, भत्ते और पेनशन;

(एफ) वह रकमों को किसी अदालत या पंचायती अदालत के किसी फैसले, डिगरी या पंच फैसले को चुकाने के लिये दरकार हों;

(जी) कोई दूसरा खर्च जिसे यह विधान या राजपंचायत कानून बनाकर ऐसा खर्च ठहरा दे.

113—(1) उतने तखमीने जितनों का सम्बन्ध भारत के मूठकोश के खाते में पड़नेवाले खर्च से है राजपंचायत के सामने वोट के लिये नहीं रखे जायँगे, पर इस धारा की किसी बात का बह मतलब नहीं लिया जाएगा कि बह राजपंचायत के किसी सदन में उन तखमीनों में से किसी पर बहस होने को रोकती है.

तखमीनों के बारे में राजपंचायत का दस्तूर

(2) उतने तखमीने जितनों का सम्बन्ध दूसरे खर्च से है देनगी की मांगों के रूप में लोक सदन के सामने रखे जायँगे, और लोक सदन को यह शक्ति होगी कि बह किसी मांग को मंजूर कर ले या मंजूर करने से इनकार कर दे, या किसी मांग को उस मांग की दर्ज रकम में कुछ कमी करके मंजूर कर ले.

(3) राजपति की सिफारिश के बिना किसी देनगी की मांग नहीं की जायगी.

114—(1) दफा 113 के अधीन लोक सदन के देनगियां पास कर देने के बाद जितनी जरूरी हो सकेगा, एक बिल रखा जाएगा जिस में भारत के मूठकोश में से नीचे लिखे खर्चों के लिये दरकार रुपयों को खर्च के मदों में डालने का बन्धान किया जाएगा—

मद्-बटवारा बिल

(ए) जो देनगियां लोकसदन ने इस तरह पास कर दी हों; और

(बी) भारत के मूठकोश के खाते में पड़नेवाले खर्च, पर जो किसी सूरत में भी राजपंचायत के सामने पहले से रखे हुए व्योरे में दिखाई रकम से अधिक न होंगे.

(2) ऐसे किसी बिल में राजपंचायत के किसी सदन में सुधार का कोई सुझाव नहीं रखा जाएगा जिससे इस तरह पास की हुई किसी देनगी की रकम घटाई बढ़ाई जा सके या उसके देन स्थान को बदल दिया जाए, या भारत के मूठकोश के खाते में पड़ने वाले किसी खर्च की रकम बदल दी जाए, और सशरत करने वाले आदमी का यह फ़ैसला कि इस धारा के अधीन कोई सुधार लिया जा सकता है या नहीं आख़री होगा.

(3) दफा 115 और 116 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, भारत के मूठकोश में से कोई रुपया नहीं निकाला जाएगा सिवाय जब कि इस दफा के बन्धानों के अनुसार क़ानून पास कर के उसके जरिये बनी हुई खर्चों की मदों के अधीन ऐसा किया जाए.

पूरक, सहायक या
अधिक देनगियां

115 —(1), (ए) अगर दफा 114 के बन्धानों के अनुसार बने किसी क़ानून से किसी खास सेवा पर चालू माली साल के लिये खर्च किये जाने को अधिकारी हुई रक़म उस बरस के मतलबों के लिये नाक़फी पाई जाय, या जब किसी चालू माली साल में किसी ऐसी नई सेवा के पूरक या सहायक खर्च की ज़रूरत पैदा हो गई हो जिसका विचार उस साल के सालाना माली ब्योरे में नहीं किया गया था, या

(बी) अगर किसी माली साल की बाबत किसी सेवा के लिये मंज़ूर रक़म से अधिक कोई रुपया उस सेवा पर उस साल खर्च हो गया है,

तो राजपति राजपंचायत के दोनों सदनों के सामने उस खर्च के तख़मीने की रक़म को दिखाने वाला दूसरा ब्योरा रखवाएगा या लोकसदन के सामने ऐसे अधिक खर्च की मांगें पेश कराएगा, जैसी सूरत हो.

(2) ऐसे किसी ब्योरे और खर्च या मांग के सम्बन्ध में, और ऐसी मांग के बारे में उस देनगी या खर्च को पूरा करने के लिये भारत के मूठकोश में से रुपए को खर्चों की मदों में डालने का अधिकार देने के लिये बनाए जानेवाले किसी क़ानून के सम्बन्ध में, दफा 112, 113 और 114 के बन्धानों का बड़ी असर होगा जो उनका सालाना माली ब्योरे और उसमें बताए खर्च या किसी देनगी की मांग, और उस खर्च या देनगी को पूरा करने के लिये भारत के मूठकोश में से रुपए को खर्चों की मदों में डालने का अधिकार देने के लिये बनाए जाने वाले किसी क़ानून के सम्बन्ध में होता है.

116—(1) इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, लोकसदन को यह शक्ति होगी कि—

हिसाब पर वोट,
साख की वोट और
अलग देनगियाँ

(प) किसी देनगी पर वोट लेने के लिये दफ्ता 113 में जो दस्तूर बताया गया है उसके पूरा होने से पहले, और उस खर्च के बारे में दफ्ता 114 के बन्धानों के अनुसार कानून पास होने से पहले, किसी माली साल के किसी भाग के लिये खर्च के तखमीने की बाबत पहले से कोई देनगी मंजूर कर दे ;

(बी) भारत के साधनों पर किसी अचानक मांग को पूरा करने के लिये, उस सूरत में जब कि उस सेवा के फैलाव या अनिश्चित रूप के कारन वह मांग उन तफसीलों के साथ बयान नहीं की जा सकती जो आम तौर पर सालाना माली व्योरे में दी जाती हैं, देनगी मंजूर कर दे ;

(सी) कोई ऐसी अलग देनगी जो किसी माली साल की किसी चालू सेवा का कोई भाग नहीं है, मंजूर कर दे ;

और राजपंचायत को शक्ति होगी कि कानून बनाकर, वह देनगियाँ जिन मतलबों के लिये मंजूर की गई हैं उनके लिये भारत के मूठकोश में से रुपए निकालने का अधिकार दे दे.

(2) धारा (1) के अधीन कोई देनगी मंजूर करने के सम्बन्ध में, और उस धारा के अधीन बनाए जाने वाले किसी कानून के सम्बन्ध में, दफ्ता 113 और 114 के बन्धानों का वैसा ही असर होगा जैसा कि सालाना माली व्योरे में बताए किसी खर्च के बारे में कोई देनगी मंजूर करने के सम्बन्ध में, और ऐसे खर्च को पूरा करने के लिये भारत के मूठकोश में से रुपए को खर्च की मदों में खालने का अधिकार देने के लिये बनाए जाने वाले कानून के सम्बन्ध में, होता है.

माली बिलों के बारे में खास बन्धान

117—(1) दफा 110 की धारा (1) की (ए) से (एक) तक की उप-धाराओं में जो मामले दर्ज हैं उनमें से किसी के लिये बन्धान करने वाला कोई बिल या सुधार नहीं रखा जा सकेगा, न पेश किया जा सकेगा, जब तक कि राजपति उसकी सिफारिश न करे, और इस तरह का बन्धान करनेवाला कोई बिल पहले रियासत सदन में नहीं रखा जायगा:

शर्तें कि किसी ऐसे सुधार को पेश करने के लिये जो किसी टैक्स को कम करने या उसका अंत करने का बन्धान करता हो, इस धारा के अधीन कोई सिफारिश दरकार न होगी.

(2) कोई बिल या सुधार केवल इसी कारन उपर बताए किसी मामले के लिये, बन्धान करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माने करने या रुपए पैसे का कोई दूसरा दंड देने या लाइसेंसों के लिये या जो कोई सेवाएँ की गई हों उनके लिये फीस मांगने या फीस देने का बन्धान करता है, या इस कारन कि वह मुक्तामी मतलबों के लिये किसी मुक्तामी अधिकारी या संस्था के कोई टैक्स लगाने, अन्त करने, उसमें छूट देने, उसको बदलने या उसकी क्रायदाबन्दी करने का बन्धान करता है.

(3) अगर किसी बिल के कानून बन जाने और उस पर अमल होने से भारत के मूठकोश में से खर्च करना पड़े, तो उस बिल को राजपंचायत का कोई सदन पास नहीं करेगा जबतक कि राजपति ने उस बिल पर सोच विचार करने की उस सदन से सिफारिश न की हो.

आम दस्तूर

दस्तूर के नियम

118—(1) इस विधान की शर्तों के अधीन रहते हुए राजपंचायत का हर सदन अपने दस्तूर और काम के संचालन की क्रायदाबन्दी करने के लिये नियम बना सकता है.

(2) जबतक धारा (1) के अधीन नियम नहीं बनते तब तक दस्तूर के जो नियम और जो क्रायमी हुकुम इस विधान के जारी होने से ठीक पहले हिन्दू डोमिनियन की कानून सभा के बारे में लागू थे वही राजपंचायत के सम्बन्ध में भी लागू होंगे, पर रियासत

सदन का मसनदी या लोकसदन का सभामुख, जैसी सूरत हो, उनमें अदल बदल और अनुकूलन कर सकता है.

(3) राजपति, रियासत सदन के मसनदी और लोक सदन के सभामुख से सलाह करके, दोनों सदनों की मिली जुली बैठकों के बारे में और उनके बीच आवा जाई के बारे में दस्तूर के नियम बना सकता है.

(4) दोनों सदनों की मिली जुली बैठक में लोक सदन का सभामुख या जब वह मौजूद न हो तो कोई ऐसा आदमी जिसे धारा (3) के अधीन बने दस्तूर के नियम तय करें बैठक का सदन होगा.

119—माली काम को समय के अन्दर पूरा करने के मतलब के लिये, राजपंचायत, कानून बना कर, किसी माली मामले के सम्बन्ध में या भारत के मूठकोश में से रुपए को खर्च की मर्दों में डालने वाले किसी बिल के सम्बन्ध में, राजपंचायत के हर सदन के दस्तूर की और काम के संचालन की क्रायदाबन्दी कर सकती है, और अगर इस तरह बने किसी कानून का कोई बन्धान दफा 118 की धारा (1) के अधीन राजपंचायत के किसी सदन के बनाए किसी नियम से या किसी ऐसे नियम या क्रायमी हुकुम से जो उस दफा की धारा (2) के अधीन राजपंचायत के सम्बन्ध में असर रखता हो मेल नहीं खाता, तो उस मेल न खाने की हद तक वह बन्धान ही चलेगा.

माली काम के सम्बन्ध में राजपंचायत के दस्तूर की कानून से क्रायदाबन्दी

120—(1) भाग सत्रह में किसी बात के रहते भी, पर दफा 348 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपंचायत का काम हिन्दी में या अंगरेजी में किया जायगा:

राजपंचायतमें काम आनेवाली भाशा

शर्तें कि रियासत सदन का मसनदी या लोकसदन का सभामुख या उनकी जगह काम करने वाला कोई आदमी, जैसी सूरत हो, किसी ऐसे मेम्बर को जो हिन्दी में या अंगरेजी में अपने आपको पूरी तरह अदा न कर सकता हो, सदन में अपनी मातृ भाशा में बोलने की इजाजत दे सकता है.

(2) जब तक राजपंचायत कानून बनाकर कुछ और बन्धान न करे, तब तक इस दफा का, इस बिधान के आरम्भ से

पन्द्रह बरस का अरसा बीत जाने के बाद, वही असर होगा मानो “या अंगरेजी में” ये शब्द इस दफा में से निकाल दिये गए हों।

राजपंचायत में
बहस पर रुकावट

121—आला अदालत के या किसी हाईकोर्ट के किसी जज ने अपने फरज निभारने में जो कुछ किया हो उसके बारे में राजपंचायत में कोई बहस नहीं की जायगी, सिवाय उस समय जब कि राजपति को इस तरह की एक निवेदनी देने के लिये सुझाव पेश हो जिसमें, जैसा कि आगे चल कर बन्धान किया गया है, उस जज को हटाने के लिये प्रार्थना की गई हो।

राजपंचायत की
कारवाई के बारे में
अदालतें पूछन-छ
नहीं करेंगी

122—(1) राजपंचायत की किसी कारवाई की सरदुरुस्ती के बारे में इस बिना पर कोई सवाल नहीं उठाया जायगा कि उसमें दस्तूर की कोई बेक़ायदगी बताई गई है।

(2) राजपंचायत का कोई अफसर या मेम्बर, जिसको इस विधान से या इसके अधीन, राजपंचायत के दस्तूर की या काम के संचालन की क़ायदाबन्दी करने के लिये, या राजपंचायत में व्यवस्था बनाए रखने के लिये, शक्तियाँ हासिल हैं, उन शक्तियों से काम लेने के बारे में किसी अदालत की अमलदारी के अधीन न होगा।

खंड तीन—राजपति की क़ानूनकारी शक्तियाँ

राजपंचायत की छुट्टी
के दिनों में राजपति
को राजहुकुम जारी
करने की शक्ति

123—(1) अगर किसी समय, सिवाय जब कि राजपंचायत के दोनों सदनों का इजलास हो रहा हो, राजपति को यह भरोसा हो जाय कि सूरतें ऐसी हैं जिनमें उसे तुरन्त कारवाई करने की ज़रूरत है तो राजपति ऐसे राजहुकुम जारी कर सकता है जो उन सूरतों में उसे ज़रूरी मालूम हों।

(2) इस दफा के अधीन जो राजहुकुम जारी किया जायगा उसका वही बल और असर होगा जो राजपंचायत के किसी ऐक्ट का, पर हर ऐसे राजहुकुम को—

(ए) राजपंचायत के दोनों सदनों के सामने रखा जायगा, और राजपंचायत के फिर मिलने से छै हफ़्ते बीत जाने पर या अगर इस अरसे के बीच चुकने से पहले ही दोनों सदनों ने उस राजहुकुम को नापसन्द करने के ठहराव पास कर दिये हैं तो

इनमें से दूसरे ठहराव के पास होने पर, वह राज-
हुकुम आगे अमल में नहीं रहेगा; और

(बी) राजपति कभी भी वापस ले सकता है.

समझाव—जब राजपंचायत के सदनों को फिर से मिलने के लिये
अलग अलग तारीखों पर बुलाया गया हो, तो इस धारा के मतलबों
के लिये छै हफ्ते का अरसा उन तारीखों में से पिछली तारीख से
गिना जायगा.

(3) अगर और जहाँ तक, इस दफ्ता के अधीन कोई राज-
हुकुम कोई ऐसा बन्धान करता है जिसे राजपंचायत को इस बिधान
के अधीन कानून का रूप देने का अधिकार नहीं है, वहाँ तक वह
राजहुकुम रद्द होगा.

खंड चार—यूनियन की न्यायकारी

124—(1) भारत की एक आला अदालत होगी जिसमें भारत
का सरजज होगा और, जब तक राजपंचायत कानून बनाकर कोई
अधिक गिनती न तय करे तब तक सात से अधिक दूसरे जज
नहीं होंगे.

आला अदालत का
कायम होना और
उसकी बनावट

(2) आला अदालत के हर जज का नियोजन राजपति,
आला अदालत के और रियासतों की हाईकोर्टों के उन जजों से
सलाह करके, जिन्हें राजपति इस मतलब के लिये जरूरी समझे, एक
हुकुमनामे से करेगा जिस पर उसके दसखत होंगे और मुहर
होगी, और वह जज पैंसठ बरस की उमर पूरी करने तक अपने
पद पर रहेगा:

शर्तें कि सरजज को छोड़कर और किसी जज का नियोजन करने
में भारत के सरजज की सलाह हमेशा ली जायगी:

और शर्तें कि—

(ए) कोई जज राजपति के नाम अपनी दसखती लिखत
भेजकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है ;

(बी) धारा (4) में बताए ढंग से किसी भी जज को उसके
पद से हटाया जा सकता है.

(3) कोई आदमी आला अदालत का जज नियोजे जाने

के जोग नहीं होगा जब तक वह भारत का नागर न हो, और

(ए) कम से कम पांच बरस तक किसी हाईकोर्ट का या लगातार दो या अधिक हाईकोर्टों का जज न रह चुका हो ; या

(बी) कम से कम दस बरस तक किसी हाईकोर्ट में या लगातार दो या अधिक हाईकोर्टों में वकील न रह चुका हो.

(सी) राजपति की राय में नामी कानून शास्त्री न हो.

समझाव (1)—इस धारा में “हाईकोर्ट” का अर्थ है वह हाईकोर्ट जिसकी अमलदारी भारत के भूभाग के किसी भाग में है या इस विधान के आरम्भ से पहले किसी समय थी.

समझाव (2)—इस धारा के मतलब के लिये उस अरसे को गिनने में जिसमें कोई आदमी वकील रहा है वह अरसा भी शामिल कर लिया जायगा जब वकील बनने के बाद उसने किसी ऐसे जजी के पद पर काम किया हो जो जिला जज के पद से नीचा न हो.

(4) आला अदालत का कोई जज अपने पद से हटाया नहीं जायगा, सिवाय जब कि राजपंचायत के हर सदन ने एक ही इजलास में किसी जज के इस बिना पर हटाए जाने के लिये एक निवेदनी राजपति के सामने रखी हो, कि उस जज का बद्ब्योहार या उसकी नाक्राबलियत साबित हो चुकी है, और उस निवेदनी का सदन के कुल मेम्बरों की बड़ीयत ने और सदन में उस समय मौजूद और वोट देने वाले मेम्बरों में से कम से कम दो तिहाई की बड़ीयत ने समर्थन किया हो, और इसके बाद राजपति एक हुकुम जारी करके उस जज को हटाए.

(5) धारा (4) के अधीन निवेदनी रखे जाने के लिये और किसी जज के बद्ब्योहार या नाक्राबलियत की जांच और सबूत के लिये जो दस्तूर होगा उसकी क्रायदाबन्दी राजपंचायत कानून बना कर कर सकती है.

(6) हर वह आदमी जो आला अदालत का जज नियोजा जाय अपना पद संभालने से पहले राजपति के सामने या किसी

दूसरे आदमी के सामने, जिसे राजपति ने इस काम के लिये नियोजित हो, उस रूप में हलफ उठायगा या वचन भरेगा जो इस मतलब के लिये तीसरी पट्टी में दिया गया है और उस पर दसखत करेगा।

(7) कोई आदमी जो आला अदालत के जज के पद पर रह चुका है, भारत के भूभाग के अन्दर किसी अदालत में या किसी अधिकारी के सामने वकालत नहीं करेगा, न काम करेगा।

125—(1) आला अदालत के जजों को वह तनखाहें दी जायंगी जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं।

जजों को तनखाहें
बगैरा

(2) हर जज वह निजनियम और भत्ते पाने का हकदार होगा और छुट्टी और पेनशन के बारे में उसके वह अधिकार होंगे जो समय समय पर राजपंचायत के बनाए कानून में या उसके अधीन तय कर दिये जायँ, और जब तक इस तरह तय नहीं किये जाते तब तक उसको वह निजनियम, भत्ते और अधिकार मिलेंगे जो दूसरी पट्टी में बताए गए हैं:

शर्तें कि किसी जज के नियोजन के बाद उसके निजनियमों या भत्तों में या छुट्टी या पेनशन के बारे में उसके अधिकारों में कोई ऐसी अदल बदल नहीं की जायगी जिससे वह घाटे में रहे।

126—जब भारत के सरजज का पद सूना हो या जब नामौजूदगी या किसी और कारन से सरजज अपने पद के फरज पूरे न कर सके तो उसके पद के फरज उस अदालत के दूसरे जजों में से कोई एक ऐसा जज पूरा करेगा जिसका राजपति इस मतलब के लिये नियोजन करे।

कारकर सर जज
का नियोजन

127—(1) अगर किसी समय आला अदालत के इजलास करने या जारी रखने के लिये अदालत के जजों का कोरम पूरा न हो, तो भारत का सरजज, पहले से राजपति की अनुमति लेकर, किसी हाईकोर्ट के किसी ऐसे जज से, जो क्रायदे से आला अदालत के जज नियोजे जाने के जोग हो, और जिसे भारत का सरजज उस पद पर नामजद कर सके, उस हाईकोर्ट के सरजज से सलाह कर के, जितने जरूरी के लिये जरूरी हो, आला अदालत की बैठकों

जरूरती जजों का
नियोजन

में जरूरती जज की हैसियत से आने के लिये लिख कर प्रार्थना कर सकता है.

(2) जिस जज को इस तरह नामजद किया गया हो उसका यह फरज होगा कि वह, अपने पद के और फरजों को पूरा करने से पहले, जिस समय और जितने अरसे के लिये उसकी हाजरी दरकार हो, आला अदालत की बैठकों में आए, और जब तक वह इस तरह आता रहेगा उसको आला अदालत के जज की पूरी अमलदारी, शक्तियाँ और निजनियम मिलेंगे और वह जज के फरज निभारेगा.

आला अदालत की बैठकों में सेवामुक्त जजों का आना

128—इस खंड में किसी बात के रहते भी, भारत का सरजज किसी समय भी, राजपति की पहले से अनुमति लेकर, किसी ऐसे आदमी से जो कभी आला अदालत के या संघ अदालत के जज के पद पर रह चुका है, प्रार्थना कर सकता है कि वह आला अदालत के जज की हैसियत से बैठे और काम करे, और हर वह आदमी जिससे इस तरह की प्रार्थना की गई हो, जब तक वह इस तरह बैठेगा और काम करेगा उन भत्तों का हकदार होगा जो राजपति हुकुम देकर तय कर दे और उसे आला अदालत के जज की सारी अमलदारी, शक्तियाँ और निजनियम मिलेंगे, मगर वह किसी और तरह उस अदालत का जज नहीं समझा जायगा:

शर्तें कि इस दफा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि किसी ऐसे आदमी को जिसकी चरचा ऊपर की गई है आला अदालत का जज बन कर बैठना और काम करना होगा जब तक कि वह ऐसा करने को राजी न हो जाय.

आला अदालत एक नज्जीरी अदालत होगी

129—आला अदालत एक नज्जीरी अदालत होगी और उसे अपनी तौहीन के लिये सजा देने की शक्ति समेत नज्जीरी अदालत की सब शक्तियाँ होंगी.

आला अदालत के बैठने की जगह

130—आला अदालत देहली में या किसी और ऐसी जगह या जगहों में बैठेगी जो भारत का सरजज, राजपति की रजामन्दी से, समय समय पर तय करे.

131—इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, नीचे लिखे मामलों में पहली सुनवाई का अधिकार आला अदालत को होगा और किसी दूसरी अदालत को नहीं होगा—

आला अदालत को पहली सुनवाई का अधिकार

(ए) भारत सरकार और एक या अधिक रियासतों के बीच कोई झगड़ा; या

(बी) कोई ऐसा झगड़ा जिसमें भारत सरकार और एक या अधिक रियासतें एक तरफ हों और एक या अधिक रियासतें दूसरी तरफ हों; या

(सी) दो या अधिक रियासतों के बीच कोई झगड़ा.

यह अधिकार उस सूरत में और उस हद तक ही होगा जिस हद तक उस झगड़े में कोई ऐसा (कानूनी या वाक्याती) सबाल उठता हो जिस पर किसी कानूनी अधिकार का होना या उसका फैलाव निर्भर हो:

शर्तें कि सुनवाई का यह अधिकार उस झगड़े में नहीं होगा—

(एक) जिसमें एक फ़रीक़ पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज कोई रियासत है, अगर वह झगड़ा किसी ऐसे संधिनामे, समझौते, मुआहिदे, इक्रारनामे, सनद या ऐसे ही किसी और पट्टे की किसी शर्त से उठा है जो इस विधान के आरंभ से पहले किया गया था या लिखा गया था और जो विधान के आरंभ के बाद अमल में रहा है या रखा गया है;

(दो) जिसमें एक फ़रीक़ कोई रियासत है, अगर वह झगड़ा किसी ऐसे संधिनामे, समझौते, मुआहिदे, इक्रारनामे, सनद या ऐसे ही किसी और पट्टे की किसी शर्त से उठा है जिसमें यह बन्धान कर दिया गया है कि इस अमलदारी का फैलाव उस तरह के झगड़े तक नहीं होगा.

132—(1) अगर भारत के भूभाग में कोई हाईकोर्ट यह सनद दे दे कि उसकी किसी दीवानी, फौजदारी या दूसरी कारवाई में इस विधान के अर्थ करने के बारे में कानून का कोई ठोस सबाल उठता है तो उस कारवाई में उस हाईकोर्ट के किसी फ़ैसले, डिगरी या आख़री हुक़ूम की अपील आला अदालत में की जा सकेगी.

कुछ सूरतों में आला अदालत को हाईकोर्टों की अपीलें सुनने की अपीली अमलदारी

(2) जहाँ हाईकोर्ट ने उस तरह की सनद देने से इनकार कर दिया हो, वहाँ अगर आला अदालत को भरोसा हो जाए कि उस मुकदमे में विधान के अर्थ करने के बारे में कानून का कोई ठोस सवाल उठता है तो आला अदालत इस तरह के फैसले, डिगरी या आखरी हुकुम की अपील करने के लिये खास इजाजत दे सकती है।

(3) जहाँ इस तरह की सनद दे दी गई हो, या इस तरह इजाजत दे दी गई हो, वहाँ उस मुकदमे का कोई फरीक इस बिना पर कि किसी ऐसे सवाल का फैसला जिसकी चरचा ऊपर की गई है गलत दिया गया है, और आला अदालत की इजाजत से किसी दूसरी बिना पर भी, अपील कर सकता है।

समाप्ति—इस दफा के मतलबों के लिये “आखरी हुकुम” शब्दों में वह हुकुम शामिल है जो किसी ऐसे उठावे का फैसला करता हो जिसका फैसला अगर अपील करने वाले के हक में हो जाए तो वह मुकदमे को निबटाने के लिये काफी हो।

दीवानी मामलों के बारे में हाईकोर्टों की अपीलें सुनने की आला अदालत की अपीली अमल-दारी

133—(1) भारत के भूभाग में हर हाईकोर्ट की किसी दीवानी कारवाई के अन्दर किसी फैसले, डिगरी या आखरी हुकुम की अपील आला अदालत में की जा सकेगी, अगर हाईकोर्ट यह सनद दे दे कि—

(ए) सबसे पहली अदालत में जिस चीज पर झगड़ा था और जिस पर अपील के समय तक झगड़ा चल रहा है, उसकी रकम या मालियत बीस हजार रुपए से कम नहीं थी और न है, या उस रकम से कम नहीं है जो राजपंचायत कानून बनाकर इस काम के लिये तय करदे ; या

(बी) उस फैसले, डिगरी या आखरी हुकुम में सीधे या ना सीधे उतनी ही रकम या मालियत की आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई दावा या सवाल आ जाता है या

(सी) मुकदमा आला अदालत में अपील के कालिबल है;

और अगर उपधारा (सी) में जिस मुकदमे की चरचा की गई है उसको छोड़कर किसी और मुकदमे में, उस फ़ैसले, डिगरी या आखरी हुकुम में जिसकी अपील की गई है, ठीक निचली अदालत के फ़ैसले को ही पक्का किया गया हो, तो हाईकोर्ट यह भी सनद दे कि अपील में क़ानून का कोई ठोस सवाल आ जाता है.

(2) दफ़ा 132 में किसी बात के रहते भी, कोई फ़रीक़ जो धारा (1) के अधीन आला अदालत में अपील करे वह इस तरह के अपील की एक बिना यह भी रख सकता है कि मुकदमे में, इस विधान के अर्थ करने के सम्बन्ध में, क़ानून के किसी ठोस सवाल का फ़ैसला ग़लत दिया गया है.

(3) इस दफ़ा में किसी बात के रहते भी, किसी हाईकोर्ट के किसी एक जज के किसी फ़ैसले, डिगरी या आखरी हुकुम के खिलाफ़ आला अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकेगी, जबतक कि राजपंचायत क़ानून बना कर कोई और बन्धान न कर दे.

134—(1) आला अदालत को भारत के भूभाग में किसी हाईकोर्ट की किसी फ़ौजदारी कारवाई में किसी फ़ैसले, आखरी हुकुम या सज़ा के हुकुम की अपील सुनने का अधिकार होगा अगर हाईकोर्ट ने—

फ़ौजदारी मामलों के बारे में आला अदालत की अपीली अमलदारी

(ए) अपील में किसी मुलज़िम की बेगुनाही के हुकुम को उलट दिया हो, और उसको मौत की सज़ा दे दी हो ; या

(बी) कोई मुकदमा अपने अधिकार के मातहत किसी अदालत से हटाकर जाँच के लिये अपने पास मंगवा लिया हो, और उसमें मुलज़िम को दोषी ठहराया हो और मौत की सज़ा दी हो; या

(सी) यह सनद दी हो कि मुकदमा आला अदालत में अपील के क़ाबिल है:

शर्तें कि उपधारा (सी) के अधीन अपील उन बन्धानों के अधीन रहते हुए ही की जा सकेगी जो दफ़ा 145 की धारा (1) के अधीन

इस बारे में बनाए जायें और उन शर्तों के अधीन होंगे जो हाईकोर्ट क्रायम कर दे या चाहे.

(2) राजपंचायत, कानून बना कर, उन शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए जो उस कानून में बताई गई हों, आला अदालत को भारत के भूभाग में किसी हाईकोर्ट की किसी फौजदारी कारवाई में किसी फ़ैसले, आखरी हुकुम या सज़ा के हुकुम की अपील लेने और सुनने की और अधिक शक्तियाँ दे सकती है.

मौजूदा कानून के अधीन संघ अदालत की अमलदारी और शक्तियों से आला अदालत का काम ले सकना

135—जब तक राज पंचायत कानून बना कर कुछ और बन्धान न कर दे, तब तक आला अदालत की अमलदारी और शक्तियाँ किसी ऐसे मामले के बारे में भी होंगी जिस पर दफा 133 या दफा 134 के बन्धान लागू नहीं होते, अगर उस मामले के सम्बन्ध में उस अमलदारी और उन शक्तियों से किसी मौजूदा कानून के अधीन इस विधान के आरंभ से ठीक पहले संघ अदालत काम ले सकती थी.

आला अदालत का अपील की खास इजाज़त देना

136—(1) इस खंड में किसी बात के रहते भी, आला अदालत, अपनी समझ से, किसी मुकदमे या मामले में, भारत के भूभाग के अन्दर की किसी अदालत या पंचायती अदालत के किसी फ़ैसले, डिगरी, निबटारे, सज़ा के हुकुम या दूसरे हुकुम की अपील करने की खास इजाज़त दे सकती है.

(2) धारा (1) की कोई बात किसी ऐसे फ़ैसले, निबटारे, सज़ा के हुकुम या दूसरे हुकुम पर लागू नहीं होगी जो किसी ऐसी अदालत या पंचअदालत ने दिया हो जो अदालत या पंच अदालत हथियार बन्द फौजों से सम्बन्ध रखनेवाले किसी कानून से या उसके अधीन बनाई गई हो.

आला अदालत के फ़ैसलों या हुकुमों पर नज़रसानी

137—राजपंचायत के बनाए किसी कानून के बन्धानों का या दफा 145 के अधीन बने किन्हीं नियमों का ध्यान रखते हुए, आला अदालत को हर फ़ैसले पर जो उसने सुनाया हो या हर हुकुम पर जो उसने दिया हो नज़रसानी करने की शक्ति होगी.

आला अदालत को अमलदारी को बढ़ाना

138—(1) आला अदालत को, यूनियन तालिका में दर्ज किसी भी मामले के बारे में, वह अमलदारी और शक्तियाँ भी होंगी जो राजपंचायत कानून बना कर उसे सौंपे.

(2) आला अदालत को किसी भी मामले के बारे में वह अमलदारी और शक्तियां भी होंगी जो भारत सरकार और किसी रियासत की सरकार आपस में खास समझौता करके उसे सौंप दें, अगर राजपंचायत कानून बना कर इस बात का बन्धान कर दे कि आला अदालत उस अमलदारी और उन शक्तियों से काम ले सकती है.

139—राजपंचायत, कानून बनाकर, दफा 32 की धारा (2) में बताए मतलबों को छोड़ कर किसी और मतलब के लिये, निर्देश, हुकुम, या परवाने जारी करने की शक्ति आला अदालत को सौंप सकती है; इन परवानों में परवाना तन-तलबी, परवाना हुकुम, परवाना मनाही, परवाना अधिकार-बताई और परवाना मिसल-मंगाई जैसे या इनमें से कोई परवाने भी हो सकते हैं.

140—राजपंचायत, कानून बना कर, आला अदालत को ऐसी पूरक शक्तियां सौंपने का बन्धान कर सकती है जो इस विधान के किसी बन्धान से बेमेल न हों और जिनको राजपंचायत इस मतलब के लिये जरूरी या चहीती समझे कि आला अदालत उस अमलदारी से अधिक असरदार ढंग से काम ले सके जो इस विधान में या इसके अधीन उस अदालत को दी गई हैं.

141—आला अदालत जो कानून ठहरा देगी उससे भारत के भूभाग के अन्दर की सब अदालतें बंधी होंगी.

142—(1) अपनी अमलदारी से काम लेने में आला अदालत कोई ऐसी डिगरी जारी कर सकती है या कोई ऐसा हुकुम दे सकती है जो किसी ऐसे मुकद्दमे या मामले में, जो उसके सामने पेश हो, पूरा इन्साफ करने के लिये जरूरी हो, और उस डिगरी या उस हुकुम पर भारत के सारे भूभाग में उस ढंग से अमल कराया जा सकेगा जो राजपंचायत के बनाए किसी कानून में या उसके अधीन बताया गया हो, और जबतक इस काम के लिये इस तरह बन्धान न किया जाय तब तक उस ढंग से अमल कराया जायगा जो राजपति हुकुम देकर बताए.

आला अदालत को कुछ परवाने जारी करने की शक्तियां सौंपना

आला अदालत की सहायक शक्तियां

आला अदालत जो कानून ठहरा दे उससे सब अदालत बंधी होंगी

आला अदालत की डिगरियों और हुकुमों पर अमल, और खोज वगैरा के बारे में हुकुम

(2) राज पंचायत के बनाए किसी ऐसे क़ानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए जो इस काम के लिये बना हो, आला अदालत को भारत के सारे भूभाग में पूरी और हर तरह की शक्ति होगी कि वह किसी आदमी को हाज़िर कराने, किन्हीं कारज़ पत्रों को खोज निकलवाने या पेश कराने, या खुद अपनी किसी तौहीन की जाँच कराने या उसकी सज़ा दिलाने के लिये कोई हुकूम जारी करे।

राजपति को आला
अदालत से राय
लेने की शक्ति

143—(1) अगर किसी समय राजपति को मालूम हो कि कोई ऐसा क़ानूनी या वाक्याती सवाल उठा है या उठ सकता है जो इस तरह का और इतने लोक महत्व का है कि उस पर आला अदालत की राय लेना समयोचित होगा, तो वह उस सवाल को सोच विचार के लिये आला अदालत के पास भेज सकता है, और आला अदालत, ऐसी सुनवाई के बाद जो वह ठीक समझे, उस सवाल पर अपनी राय की रिपोर्ट राजपति को भेज सकती है।

(2) दफ़ा 131 की शर्त की धारा (1) में किसी बात के रहते भी, राजपति, उस धारा में जिस तरह के फ़गड़े का जिक्र आया है, उसे राय के लिये आला अदालत के पास भेज सकता है, और आला अदालत, ऐसी सुनवाई के बाद जिसे वह ठीक समझे, उस फ़गड़े पर अपनी राय की रिपोर्ट राजपति को देगी।

दीवानी और न्याय-
कारी अधिकारियों
का आला अदालत
की मदद के लिये
काम करना

144—भारत के भूभाग के सब दीवानी और न्यायकारी अधि-
कारी आला अदालत की मदद के लिये काम करेंगे।

अदालत के नियम
बग़ैर

145—(1) किसी भी ऐसे क़ानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए जो राजपंचायत बनाए, आला अदालत, समय समय पर, राजपति की रज़ामन्दी से, अपने काम और इस्तूर की अम क़ायदाबन्दी के लिये, नियम बना सकती है, जिनमें नीचे लिखे नियम भी हो सकते हैं—

(ए) उस अदालत के सामने बकालत करने वाले लोगों के बारे में नियम ;

(बी) अपीलें सुनने के दस्तूर के और अपीलों से सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे मामलों के बारे में नियम, जिनमें यह भी आजायगा कि कितने समय के अन्दर अदालत में अपीलें दाखिल हो जानी चाहियें;

(सी) भाग (तीन) के जरिये दिये हुए अधिकारों में से किसी पर अमल कराने के लिये उस अदालत में कारवाई के नियम ;

(डी) दफा 134 की धारा (1) की उपधारा (सी) के अधीन अपीलें लेने के बारे में नियम ;

(ई) उन शर्तों के बारे में नियम जिनके अधीन उस अदालत के सुनाए हुए किसी फैसले या उसके किसी हुकुम पर नज़रसानी की जा सके, और इस तरह की नज़रसानी के लिये दस्तूर संबंधी नियम जिनमें यह भी आजायगा कि कितने समय के अंदर इस तरह की नज़रसानी के लिये अदालत में दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं ;

(एफ) उस अदालत के अन्दर किसी कारवाई के खर्चों और उस कारवाई के प्रसंगी खर्चों के बारे में, और उस अदालत की कारवाई के सम्बन्ध में ली जाने वाली फीसों के बारे में नियम ;

(जी) जमानत की मंजूरी के बारे में नियम ;

(एच) कारवाई रोक दिये जाने के बारे में नियम ;

(आइ) किसी ऐसी अपील को फटपट निबटा देने के लिये बन्धान करनेवाले नियम जो अपील अदालत की निगाह में लचर हो या तंग करने के लिये या देर लगाने के लिये की गई हो ;

(जे) दफा 317 की धारा (1) में जिस पूछताछ की चरचा की गई है उसके दस्तूर के नियम.

(2) धारा (3) के बन्धानों के अधीन रहते हुए, जो नियम इस दफा के अधीन बनाए जायँ उनमें यह तय किया जा सकता है

कि किसी मतलब के लिये कम से कम कितने जज बैठेंगे, और उनमें इस बात का बन्धान भी किया जा सकता है कि अकेले जजों और डिबिजन अदालतों की क्या क्या शक्तियाँ होंगी.

(3) किसी ऐसे मुकदमे का फैसला करने के लिये जिसमें इस विधान के अर्थ करने के सम्बन्ध में कानून का कोई ठोस सवाल उठता हो, या दफा 143 के अधीन राय लेने के लिये आए हुए किसी मामले को सुनने के लिये, जो जज बैठेंगे उनकी गिनती कम से कम पाँच होगी:

शर्तें कि जहाँ दफा 132 को छोड़कर इस खंड के किसी और बन्धान के अधीन अपील सुननेवाली किसी अदालत में पाँच से कम जज हैं, और अपील सुनने के दौरान में अदालत को भरोसा हो जाय कि अपील में, इस विधान के अर्थ करने के सम्बन्ध में, कानून का कोई ठोस सवाल उठता है, जिसका तय करना अपील के फैसले के लिये जरूरी है, तो वह अदालत ऐसे सवाल को राय के लिये किसी ऐसी अदालत के पास भेज देगी जो इस धारा के अनुसार ऐसे किसी मुकदमे का फैसला करने के लिये, जिसमें इस तरह का सवाल आता है, बनाई गई हो, और उस अदालत की राय आने पर उस राय के मुताबिक उस अपील का फैसला कर देगी.

(4) आला अदालत सिवाय खुले इजलास के अपना कोई फैसला नहीं देगी, और दफा 143 के अधीन कोई रिपोर्ट नहीं करेगी जब तक कि वह रिपोर्ट ऐसी राय के मुताबिक न हो जो खुले इजलास में दी गई है.

(5) आला अदालत कोई फैसला और ऐसी कोई राय नहीं देगी जबतक कि मुकदमे की सुनवाई के समय मौजूद जजों की बड़ीयत उससे सहमत न हो, पर इस धारा की किसी बात से यह न समझा जायगा कि वह किसी जज को जो सहमत नहीं है अपना अनमिल फैसला या अनमिल राय देने से रोकती है.

आला अदालत के
अफसर और नौकर
और खच

146--(1) आला अदालत के अफसरों और नौकरों का नियोजन भारत का सरजज या अदालत का वह दूसरा जज या अफसर करेगा जिसे सरजज निर्देश कर है:

शर्तें कि राजपति नियम बना कर यह दरकार कर सकता है कि, उन सूरतों में जो उस नियम में बताई गई हों, किसी ऐसे आदमी को, जो पहले से आला अदालत से लगा हुआ नहीं है, उस अदालत से संबंध रखने वाले किसी पद पर यूनिनियन सरकारी नौकरी कमीशन से सलाह लिये बिना नहीं नियोजा जायगा।

(2) राजपंचायत के बनाए किसी कानून के बंधनों के अधीन रहते हुए, आला अदालत के अफसरों और नौकरों की नौकरी की शर्तें वह होंगी जो उन नियमों में बताई गई हों जिन्हें भारत के सर जज ने, या अदालत के किसी ऐसे दूसरे जज या अफसर ने बनाया हो जिसे भारत के सर जज ने इस मतलब के लिये नियम बनाने का अधिकार दिया है :

शर्तें कि इस धारा के अधीन बने नियमों के लिये, जहाँ तक उनका संबंध तनखाहों, भत्तों, छुट्टी या पेनशनों से है, राजपति की रजामन्दी दरकार होगी।

(3) आला अदालत के शासनी खर्चें, जिनमें अदालत के अफसरों और नौकरों को या उनके बारे में दी जाने वाली सब तनखाहें, भत्ते और पेनशनें शामिल हैं, भारत के मूठकोश के खाते में पड़ेंगे, और वह अदालत जो फीस या दूसरी रकम में लेगी वह उस कोश का भाग होगी।

147—इस खंड में और भाग छे के खंड पांच में, जहाँ इस अर्थ विधान का अर्थ करने के बारे में कानून के किसी ठोस सवाल की चर्चा की गई है, हिन्द सरकार एक्ट 1935 (जिसमें उस एक्ट में सुधार करने वाले या उसके पूरक एक्ट भी शामिल हैं) या उसके अधीन दिये हुए किसी आर्डर-इन-कौन्सिल (कौंसिल में पास हुकुम) या दूसरे हुकुम या हिन्द आजादी एक्ट 1947 या उसके अधीन दिये हुए किसी हुकुम के अर्थ करने के बारे में कानून के किसी ठोस सवाल की चर्चा भी शामिल समझी जायगी।

खंड पाँच—भारत का दाब असफर और सर पड़तालिया

148—(1) भारत का एक दाब अफसर और सर पड़तालिया होगा जिसको राजपति अपने दसखागी और मोहर लगे हुकुमनामे

भारत का दाबअफ-
सर और सर पड़-
तालिया

से नियोजेगा, और वह अपने पद से केवल उसी ढंग से और वन्हीं बिनाओं पर हटाया जा सकेगा जिन पर आला अदालत का कोई जज हटाया जा सकता है.

(2) हर आदमी जो भारत का दाब अफसर और सर पड़तालिया नियोजा जाए, अपना पद संभालने से पहले, राजपति के या किसी ऐसे आदमी के सामने जिसको राजपति इस काम के लिये नियोजे, तीसरी पट्टी में इस मतलब के लिये दर्ज रूप के अनुसार, हलफ उठायगा या वचन भरेगा और उस पर दसखत करेगा.

(3) दाब अफसर और सर पड़तालिया की तनखाह और नौकरी की दूसरी शर्तें वह होंगी जो राजपंचायत कानून बना कर तय करे, और जब तक इस तरह तय न हों तब तक वह होंगी जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं :

शर्तें कि दाबअफसर और सर पड़तालिया की तनखाह में, और छुट्टी या पेनशन के बारे में या सेवामुक्त होने की उमर के बारे में उसके अधिकारों में, उसके नियोजन के बाद, कोई ऐसी अदल बदल नहीं की जायगी जिससे वह घाटे में रहे.

(4) अपने पद से हट जाने के बाद दाब अफसर और सर पड़तालिया भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत की सरकार के अधीन और कोई पद लेने का पात्र न होगा.

(5) इस विधान के बन्धानों के और राजपंचायत के बनाए किसी कानून के अधीन रहते हुए, भारत पड़ताल और हिसाब महकमें में नौकरी करने वाले लोगों की नौकरी की शर्तें और दाब अफसर और सरपड़तालिया की शासनी शक्तियां वह होंगी जो कि, दाब अफसर और सर पड़तालिया से सलाह करने के बाद, राजपति नियम बनाकर तय करदे.

(6) दाब अफसर और सर पड़तालिया के दफ्तर के शासनी खर्च, जिसमें उस दफ्तर में नौकरी करने वाले लोगों को या उनके बारे में दी जाने वाली सब तनखाहें, भत्ते और पेनशनें भी शामिल होंगी, भारत के मूठकोश के खाते में पड़ेगे.

149. दाब अफसर और सर पड़तालिया यूनियन के, और रियासतों के और किसी दूसरे अधिकारी या संस्था के हिसाब किताब संबंधी ऐसे फरजों को पूरा करेगा और ऐसी शक्तियों से काम लेगा जो राजपंचायत के बनाए किसी कानून में या उसके अधीन बताई जायं, और जब तक इस काम के लिये इस तरह बन्धान नहीं किया जाता तब तक वह यूनियन और रियासतों के हिसाब किताब के संबंध में ऐसे फरज पूरा करेगा और उन शक्तियों से काम लेगा जो हिन्द होमिनियन और सूबों के हिसाब किताब के संबंध में अलग अलग इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द के सर पड़तालिया को सौंपी गई थी या जिनसे वह काम ले सकता था.

दाब अफसर और सर पड़तालिया के फरज और शक्तियां

150—यूनियन के और रियासतों के हिसाब किताब उस रूप में रखे जायंगे जो भारत का दाब अफसर और सर पड़तालिया, राजपति की रजामन्दी से, तय कर दे.

दाबअफसर और सरपड़तालिया को हिसाब किताब के संबंध में निर्देश देने की शक्ति पड़ताल की रिपोर्टें

151—(1) यूनियन के हिसाब किताब के संबंध में भारत के दाब अफसर और सर पड़तालिया की रिपोर्टें राजपति को दी जायंगी, और राजपति उन्हें राजपंचायत के हर सदन के सामने रखवायगा.

(2) किसी रियासत के हिसाब किताब के संबंध में भारत के दाब अफसर और सर पड़तालिया की रिपोर्टें उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख को दी जायंगी और रियासतपति या राजप्रमुख उनको उस रियासत की कानून सभा के सामने रखवायगा.



भाग छै

पहली पट्टी के भाग (ए) की रियासतें

खंड एक—आम

परिभाषा

152—इस भाग में, अगर प्रसंग से कुछ और दरकार न हो, “रियासत” शब्द के मानी हैं पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज कोई रियासत.

खंड दो—काजकारी

रियासतपति

रियासतों के
रियासतपति

153—हर रियासत का एक रियासतपति होगा.

रियासत की
काजकारी शक्ति

154—(1) रियासत की काजकारी शक्ति रियासतपति को हासिल होगी और वह उससे खुद या अपने अधीन अफसरों के जरिये इस विधान के अनुसार काम लेगा.

(2) इस दफा की किसी बात से—

(ए) जो काम किसी मौजूदा क़ानून ने किसी दूसरे अधिकारी को सौंपे हैं वह काम रियासतपति को तबदीले नहीं समझे जायंगे; या

(बी) राजपंचायत को या रियासत की क़ानून सभा को इस बात से नहीं रोका जा सकेगा कि वह क़ानून बनाकर कोई काम रियासतपति के अधीन किसी अधिकारी को सौंपे.

रियासतपति का
नियोजन

155—हर रियासत के रियासतपति को राजपति अपने दस-छत्ती और मोहर लगे हुकुमनामे से नियोजेगा.

रियासतपति
पद-भियाइ

156—(1) राजपति के इच्छाकाल तक रियासतपति पद पर रहेगा.

(2) राजपति के नाम अपनी दसखती लिखत भेजकर रियासतपति अपने पद से इस्तीफा दे सकता है.

(3) इस वफा में ऊपर के बन्धानों के अधीन रहते हुए रियासतपति पद संभालने की तारीख से पाँच बरस की मियाद तक पद पर रहेगा:

शर्तें कि रियासतपति अपनी मियाद पूरी हो जाने पर भी अपने पदगाही के पद संभालने तक पद पर रहेगा.

157—कोई आदमी रियासतपति नियोजे जाने का पात्र न होगा जबतक कि वह भारत का नागर न हो और अपनी उमर का पैंतीसवाँ बरस पूरा न कर चुका हो.

रियासतपति नियोजे जाने के लिये योग्यताएं

158—(1) रियासतपति राजपंचायत के किसी सदन का या पहली पट्टी में दर्ज किसी रियासत की कानून सभा के किसी सदन का मेम्बर नहीं होगा, और अगर राजपंचायत के किसी सदन का या किसी ऐसी रियासत की कानून सभा के किसी सदन का कोई मेम्बर रियासतपति नियोजा जाए, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन की अपनी सीट रियासतपति का पद संभालने की तारीख को सूनी कर दी है.

रियासतपति के पद की शर्तें

(2) रियासतपति किसी दूसरे लाभ के पद पर नहीं रहेगा.

(3) रियासतपति बिना किराया दिये अपने सरकारी मकानों के इस्तेमाल करने का हकदार होगा और वह उन वेतनों, भत्तों और निजनियमों का भी हकदार होगा जो राजपंचायत कानून बना कर तय कर दे, और जबतक इस के लिये इस तरह बन्धान न हो तब तक वह उन वेतनों, भत्तों और निजनियमों का हकदार होगा जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं.

(4) रियासतपति के वेतन और भत्ते उसका पद-मियाद के दौरान में घटाए नहीं जायेंगे.

159—हर रियासतपति और रियासतपति के काम निभारने वाला हर आदमी अपना पद संभालने से पहले उस रियासत के संबंध में अमलदारी रखनेवाली हाईकोर्ट के सरजज या उसके मौजूद न होने पर उस अदालत के उस बड़े से बड़े जज के सामने जो मिल

रियासतपति का हलफ उठाना या वचन भरना

सके नीचे दिये रूप में हस्ताक्षर करेगा या बचन भरेगा और उस पर दसखत करेगा, यानी यह कि—

“मैं.....(नाम)..... ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं(रियासत का नाम) के रियासतपति के पद पर रहकर वफादारी से काम करूँगा (या रियासतपति के काम वफादारी से निभाऊँगा) और अपनी पूरी जोगता से विधान और कानून को बनाए रखूँगा, और उनकी रक्षा और उनका बचाव करूँगा, और मैं.....(रियासत का नाम) के लोगों की सेवा और उनकी भलाई में तन मन से लगा रहूँगा.”

कुछ जोगजोगों में
रियासतपति के
काम निभारना

160—किसी ऐसे जोगजोग में जिसका इस खंड में बन्धान नहीं किया गया है, किसी रियासत के रियासतपति के काम निभारने के लिये राजपति जैसा उचित समझे बन्धान कर सकता है.

रियासतपति को
कुछ सूतों में माफ़ी
बगैरा देने और
सजा के हुकुमों को
रोके रखने, बाक़ी
हुकुम रद्द कर देने
या सजा का रूप
बदल देने की शक्ति

161—हर रियासत के रियासतपति को यह शक्ति होगी कि वह किसी ऐसे आदमी को माफ़ कर दे, उसकी सजा मुक्तवी कर दे, उसे मुहलत दे दे, या बाक़ी सजा माफ़ कर दे, या उसकी सजा के हुकुम को रोके रखे या सजा के बाक़ी हुकुम को रद्द कर दे, या सजा का रूप बदल दे, जिसको किसी ऐसे कानून के खिलाफ़ जुर्म का दोशी ठहराया गया है जो किसी ऐसे मामले की बाबत है जिस तक रियासत की काजकारी शक्ति का फैलाव है.

रियासत की काज-
कारी शक्ति का
फैलाव

162—इस विधान के बंधानों के अधीन रहते हुए, हर रियासत की काजकारी शक्ति का फैलाव उन मामलों तक होगा जिनके बारे में उस रियासत की कानून सभा को कानून बनाने की शक्ति है:

शर्तें कि ऐसे किसी मामले में जिसके बारे में किसी रियासत की कानून सभा और राजपंचायत दोनों को कानून बनाने की शक्ति है, रियासत की काजकारी शक्ति उस काजकारी शक्ति के अधीन और उससे हथियाई हुई होगी जो इस विधान से या राजपंचायत के बनाए किसी कानून से खुले तौर पर यूनिन को या उसके अधि-कारियों को सौंपी गई हो.

बज़ीर मंडल

163—(1) जिस हद तक कि इस विधान में या इसके अधीन रियासतपति को अपने काम या अपना कोई काम अपनी समझ से करने को कहा गया है, उसे छोड़ कर बाक़ी सब कामों के करने में रियासतपति को सहायता और सलाह देने के लिये एक बज़ीर मंडल होगा जिसका सरमुख बड़ा बज़ीर होगा .

रियासतपति को सहायता और सलाह देने के लिये बज़ीर मंडल

(2) अगर यह सवाल उठे कि कोई मामला ऐसा मामला है या नहीं जिसके बारे में इस विधान के अनुसार या इसके अधीन रियासतपति को अपनी समझ से काम करना चाहिये तो इस सवाल पर रियासतपति अपनी समझ से जो फैसला दे वह आखिरी होगा, और रियासतपति जो कुछ करे उसकी सरदुरुस्ती पर इस बिना पर कोई सवाल नहीं उठाया जायगा कि उसे अपनी समझ से काम करना चाहिये था या नहीं.

(3) बज़ीरों ने रियासतपति को कोई सलाह दी या नहीं और अगर दी तो क्या दी इस सवाल की पूछताछ किसी अदालत में नहीं की जायगी.

164—(1) बड़े बज़ीर का नियोजन रियासतपति करेगा और दूसरे बज़ीरों का नियोजन रियासतपति बड़े बज़ीर की सलाह से करेगा, और बज़ीर अपने पद पर रियासतपति के इच्छाकाल तक रहेंगे.

बज़ीरों के बारे में दूसरे बन्धान

शर्तें कि बिहार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा की रियासतों में एक एक बज़ीर ऐसा होगा जिसके ज़िम्मे क़बाइली लोगों की भलाई का काम होगा, और इसके साथ साथ जिसके ज़िम्मे पट्टी-दर्ज जातियों और पिछड़ी हुई जमातों की भलाई का काम या कोई दूसरा काम भी हो सकता है.

(2) बज़ीरमंडल के बज़ीर सबके सब मिलकर रियासत के आम सदन को ज़िम्मेदार होंगे.

(3) किसी बज़ीर के अपना पद संभालने से पहले रियासतपति उससे तीसरी पट्टी में इस मतलब के लिये दिये हुए रूपों के अनुसार पद और राजदारी के हलफ़ उठवायगा.

(4) कोई वजीर जो लगातार छै महीने के किसी अरसे तक उस रियासत की कानून सभा का मेम्बर न रहे, उस अरसे के बीत जाने पर, वजीर नहीं रहेगा.

(5) वजीरों की तनखाहें और भत्ते बढ़ होंगे जो उस रियासत की कानून सभा समय समय पर कानून बनाकर तय करे, और जब तक रियासत की कानून सभा इस तरह तय न करे तबतक वह होंगे जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं.

रियासत का सर वकील

रियासत
सरवकील

का 165—(1) हर रियासत का रियासतपति किसी ऐसे आदमी को उस रियासत का सरवकील नियोजेगा जो हाईकोर्ट का जज नियोजे जाने की योगता रखता हो.

(2) सरवकील का फरज होगा कि वह रियासत की सरकार को ऐसे कानूनी मामलों पर सलाह दे और ऐसे कानूनी ढंग के दूसरे फरज पूरा करे जो रियासतपति उसे समय समय पर भेजे या सौंपे, और उन कामों को निभारे, जो इस विधान से या उस समय लागू किसी दूसरे कानून से या इनके अधीन उसे दिये गए हों.

(3) सरवकील रियासतपति के इच्छाकाल तक अपने पद पर रहेगा और उसको वह मेहनताना मिलेगा जो रियासतपति तय करे.

सरकारी काम का संचालन

किसी रियासत की
सरकार के काम
का संचालन

166—(1) हर रियासत की सरकार का सारा काजकारी काम रियासतपति के नाम से किया हुआ कहा जायगा.

(2) रियासतपति के नाम से दिये हुए हुकुमों और उसके नाम से किये हुए दूसरे पट्टों का सहीकरन उस ढंग से किया जायगा जो रियासतपति के बनाए हुए नियमों में बताया जाय और इस तरह सही किये हुए हुकुम या पट्टे की सरदुरुस्ती पर इस बिना पर कोई सबाल नहीं उठाया जाएगा कि वह हुकुम रियासतपति ने नहीं दिया या वह पट्टा रियासतपति ने नहीं किया.

(3) रियासतपति रियासत की सरकार के काम को अधिक सुभीते से चलाने के लिये और उस काम को वजीरों में बाँटने के लिये नियम बनायगा, जहाँतक कि वह काम ऐसा नहीं है जिसके बारे

में इस विधान के अनुसार या इसके अधीन रियासतपति को अपनी सम्मति से काम करना चाहिये.

167—हर रियासत के बड़े वज़ीर का फ़रज़ होगा कि—

(ए) वज़ीरमंडल के सारे फ़ैसले जिनका सम्बन्ध उस रियासत के मामलों के शासन से और क़ानून बनाने के सुझावों से है रियासतपति को पहुँचाए;

(बी) रियासत के मामलों के शासन सम्बन्धी और क़ानून बनाने के सुझावों सम्बन्धी जो बातें रियासतपति पूछे उसको बताए; और

(सी) राजपति के चाहने पर किसी ऐसे मामले को, जिस पर किसी एक वज़ीर ने कुछ फ़ैसला कर लिया है पर वज़ीर मंडल ने विचार नहीं किया है, वज़ीर मंडल के सामने विचार के लिए रखे.

खंड तीन—रियासत की क़ानून सभा :

आम

168—(1) हर रियासत की एक क़ानून सभा होगी जिसमें एक रियासतपति होगा, और जिसमें,

(ए) बिहार, बम्बई, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पच्छिम बंगाल की रियासतों में, दो दो सदन होंगे; और

(बी) दूसरी रियासतों में, एक सदन होगा.

(2) जहाँ रियासत की क़ानून सभा में दो सदन होंगे वहाँ एक 'खाससदन' कहलायगा और दूसरा 'आमसदन', और जहाँ केवल एक ही सदन होगा वहाँ वह 'आमसदन' कहलायगा.

169—(1) दफ़ा 168 में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत क़ानून बनाकर किसी रियासत में जहाँ खास सदन है उसका अन्त करने के लिये या किसी रियासत में जहाँ खास सदन नहीं है उसको बनाने के लिये बन्धान कर सकती है, अगर रियासत का आम सदन अपने कुल मेम्बरों की बड़ीयत से और उस समय मौजूद और वोट देने वाले सदन के कम से कम दो तिहाई मेम्बरों की बड़ीयत से इस बात के लिये एक ठहराव पास कर दे.

रियासतपति को सूचना देने बग़ैरा के बारे में बड़े वज़ीर के फ़रज़

रियासतों की क़ानून सभाओं की बनावट

रियासतों में खास सदनों का अन्त करना या बनाना

(2) धारा (1) में जिस क़ानून की चरचा की गई है उसमें इस विधान में सुधार करने के लिये ऐसे बन्धान रहेंगे जो उस क़ानून के बन्धानों को अमल में लाने के लिये जरूरी हों, और ऐसे पूरक, प्रसंगी और परिणामी बन्धान भी रहेंगे जिन्हें राजपंचायत जरूरी समझे.

(3) उपर बताया कोई क़ानून दफ़ा 368 के मतलबों के लिये इस विधान का सुधार नहीं समझा जायगा.

आम सदन की
रचना

170—(1) दफ़ा 333 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, हर रियासत के आम सदन में वे मेम्बर होंगे जो सीधे चुनाव से चुने गए हों.

(2) किसी भी रियासत के आम सदन में हर भूभागी चुनाव हलक़े का प्रतिनिधान, पिछले आखरी गिनावे के अनुसार जिसके संगत आंकड़े निकल चुके हैं, उस चुनाव हलक़े की आबादी के आधार पर होगा, और आसाम के स्वाधीन ज़िलों और शिलांग की नगरायत और छावनी के चुनाव हलक़े को छोड़कर, आबादी के हर पिछत्तर हजार आदमियों पीछे एक से अधिक मेम्बर नहीं होगा:

शर्तें कि किसी सूरत में भी किसी रियासत के आम सदन के मेम्बरों की कुल गिनती न पांच सौ से अधिक होगी और न साठ से कम.

(3) हर रियासत के हर भूभागी चुनाव हलक़े को जो मेम्बर दिये जायेंगे उनकी गिनती और उस चुनाव हलक़े की आबादी की वह गिनती जो उस पिछले आखरी गिनावे में मालूम की जा चुकी है जिसके संगत आंकड़े निकल चुके हैं, इन दोनों में जहाँ तक हो सकेगा सारी रियासत में एक ही अनुपात होगा.

(4) हर गिनावे के पूरा हो जाने पर, हर रियासत के आम सदन में अलग अलग भूभागी चुनाव हलक़ों के प्रतिनिधान में वह अधिकारी उस ढंग से और उस तारीख से लागू होने के लिये बटत बढ़त करेगा जिसे राजपंचायत क़ानून बनाकर तय कर दे :

शर्तें कि इस तरह बटत बढ़त का आम सदन के प्रतिनिधान पर तब तक कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक कि उस समय का आम सदन भंग न हो जाय.

171—(1) जिस रियासत में खास सदन है, वहाँ उस सदन के खास सदनों की मेम्बरों की कुल गिनती उस रियासत के आम सदन के मेम्बरों की रचना कुल गिनती की एक चौथाई से अधिक नहीं होगी:

शर्तें कि किसी रियासत के खास सदन के कुल मेम्बरों की गिनती किसी भी सूरत में चालीस से कम न होगी.

(2) जब तक राजपंचायत कानून बनाकर कुछ और बन्धान न करे तब तक किसी रियासत के खास सदन की रचना उस तरह होगी जिस तरह धारा (3) में बन्धान किया गया है.

(3) किसी रियासत के खास सदन के मेम्बरों की कुल गिनती में से—

(ए) एक तिहाई के जितने करीब हो सके उतनों का चुनाव वे चुनावतें करेंगी जिनमें उस रियासत के अन्दर की नगरायतों, जिज्ञा बोर्डों और ऐसी दूसरी मुकामी संस्थाओं के मेम्बर होंगे जो राजपंचायत कानून बना कर तय कर दे;

(बी) एक बारहवें के जितने करीब हो सके उतनों का चुनाव वे चुनावतें करेंगी जिनमें उस रियासत में बसनेवाले वे लोग होंगे जो कम से कम तीन बरस पहले से भारत के भूभाग की किसी विद्यापीठ के सनातक रह चुके हैं, या कम से कम तीन बरस से उनमें वे जोगताएँ रही हैं जो राजपंचायत के बनाए किसी कानून में या उसके अधीन ऐसी किसी विद्यापीठ के सनातक की जोगताओं के बराबर ठहरा दी गई हैं;

(सी) एक बारहवें के जितने करीब हो सके उतनों का चुनाव वे चुनावतें करेंगी जिनमें ऐसे आदमी होंगे जो कम से कम तीन बरस तक रियासत के अन्दर ऐसी तालीमी संस्थाओं में पढ़ाते रहे हैं जिनका दर्जा किसी दूसरी स्कूल के दर्जे से कम नहीं है और जिनको राजपंचायत के बनाए किसी कानून में या उसके अधीन तय कर दिया गया है.

(डी) एक तिहाई के जितने करीब हो सके वतनों का चुनाव उस रियासत के आम सदन के मेम्बर उन लोगों में से करेंगे जो उस सदन के मेम्बर नहीं हैं;

(ई) बाक़ी को रियासतपति धारा (5) के बन्धानों के अनुसार नामजद करेगा.

(4) धारा (3) की उप-धारा (ए), (बी) और (सी) के अधीन जो मेम्बर चुने जायेंगे उनको ऐसे भूभागी चुनाव हलकों में से लिया जायगा जो राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन तय कर दिया गया हो, और उन उप-धाराओं के अधीन और उस धारा की उप-धारा (डी) के अधीन जो चुनाव होंगे वह निसबती प्रतिनिधान के ढंग पर इकट्ठे बदलते वोट से किये जायेंगे.

(5) धारा (3) की उप-धारा (ई) के अधीन रियासतपति जिन मेम्बरों को नामजद करेगा वे ऐसे आदमी होंगे जिन्हें इस तरह के मामलों के बारे में जैसे नीचे दिये गए हैं खास जानकारी या अमली तजरबा हो, यानी :—

अदब-साहित्य, साइन्स, कला, सहकारी आन्दोलन और समाज सेवा.

रियासत की क़ानून
समाओं की मुद्दत

172—(1) हर रियासत का हर आम सदन, अगर पहले ही भंग न कर दिया गया हो, तो जो तारीख उसकी पहली मिलनी के लिये तय की गई थी, उससे पांच बरस तक चलेगा और अधिक नहीं, और इस पांच बरस के अरसे के बीत जाने से ही आम सदन भंग माना जाएगा:

शर्तें कि किसी ऐसे समय में जब कोई अवानको का ऐतान अमल में हो, राजपंचायत क़ानून बना कर इस अरसे को एक और अरसे के लिये बढ़ा सकती है जो एक बार में एक बरस से अधिक न होगा, और जो किसी भी सूरत में ऐतान का अमल खतम होने के बाद छै महीने के अरसे से अधिक न चलेगा.

(2) किसी रियासत के खास रुदन को भंग नहीं किया जा सकेगा, पर हर दूसरे बरस के बीत जाने पर जितनी जरूरी

हो सकेगा खास सदन के मेम्बरों में से करीब से करीब एक तिहाई, उन बन्धानों के अनुसार जो राजपंचायत कानून के जरिये इस काम के लिये बना दे, अलग हो जाया करेंगे.

173—कोई आदमी किसी रियासत की कानून सभा में कोई सीट भरने के लिये चुने जाने के जोग नहीं होगा, जब तक कि वह—

रियासत की कानून सभा की मेम्बरी के लिये जोगता

(ए) भारत का नागर न हो;

(बी) आम सदन की सीट के लिये कम से कम पच्चीस बरस की और खास सदन की सीट के लिये कम से कम तीस बरस की उमर का न हो; और

(सी) ऐसी और जोगताएँ न रखता हो जो इस काम के लिये राजपंचायत के बनाए हुए किसी कानून में या उसके अधीन बताई जायं.

174—(1) हर रियासत की कानून सभा के सदन या सदनों को हर बरस में कम से कम दो बार मिलने के लिये बुलाया जायगा और एक इजलास में उनकी आखरी बैठक और अगले इजलास में पहली बैठक को जो तारीख ठहराई गई हो उन के बीच छै महीने नहीं बीतने पाएंगे.

रियासत की कानून सभा के इजलास, उनका बरखास्त करना और भंग करना

(2) धारा (1) के बंधानों के अधीन रहते हुए, रियासत-पति समय समय पर—

(ए) सदन को या दोनों में से किसी एक सदन को मिलने के लिये जिस समय और जिस जगह ठीक समझे बुला सकता है;

(बी) सदन को या सदनों को बरखास्त कर सकता है;

(सी) आम सदन को भंग कर सकता है.

175—(1) रियासतपति आम सदन में, या जहाँ रियासत में खास सदन भी है वहाँ उस रियासत की कानून सभा के किसी भी सदन में, या दोनों सदनों को इकट्ठा करके, सर-बचन दे सकता है, और इस मतलब के लिये मेम्बरों की हाजरी तलब कर सकता है.

रियासतपति को सदन या सदनों में सर-बचन देने या संदेश भेजने का अधिकार

(2) रियासतपति रियासत की कानून सभा के सदन या

सदनों को किसी ऐसे बिल के बारे में जो उस समय कानून सभा के सामने हो, या किसी और मतलब के लिये, संदेसे भेज सकता है, और जिस सदन को इस तरह कोई संदेसा भेजा जाय वह जितनी जल्दी सुभीते के साथ कर सकेगा उस मामले पर सोच विचार करेगा जिस पर सोच विचार करने को उस संदेसे में कहा गया हो।

हर इजलास के आरंभ में रियासत-पति का खास सर-बचन

176—(1) हर इजलास के आरंभ में, रियासतपति आम सदन को, या जहाँ किसी रियासत में खास सदन भी है वहाँ दोनों सदनों को इकट्ठा करके, सर-बचन देगा, और कानून सभा को उसके बुलाए जाने के कारन बताएगा।

(2) सदन के या दोनों सदनों के दस्तूर की क़ायदाबन्दी करने वाले नियमों में इस बात का बन्धान किया जायगा कि इस तरह के सर-बचन में जिन मामलों की चर्चा की गई है उन पर बहस करने के लिये समय रखा जाए, और यह बहस सदन के और कामों से पहले हो।

सदनों के बारे में वज़ीरों और सर-बकील के अधिकार

177—हर वज़ीर को और रियासत के सर बकील को यह अधिकार होगा कि वह रियासत के आम सदन में या जहाँ रियासत में खास सदन भी है वहाँ दोनों सदनों में बोले और दूसरी तरह कारवाई में हिस्सा ले और कानून सभा की किसी भी ऐसी कमेटी में जिस के मेम्बरों में उसका नाम हो बोले और दूसरी तरह कारवाई में हिस्सा ले, मगर वोट देने का हक़दार वह इस दफ़ा की रू से नहीं होगा।

रियासत की कानूनसभा के अफ़सर

आम सदन का सभामुख और उप-सभामुख

178—हर रियासत का आम सदन जितनी जल्दी हो सकेगा उस सदन के दो मेम्बरों को अलग अलग उसका सभामुख और उप-सभामुख चुन लेगा, और जब जब सभामुख या उप-सभामुख का पद सूना होगा आम सदन किसी दूसरे मेम्बर को सभामुख या उप-सभामुख, जैसी सूराह हो, चुन लेगा।

179—कोई मेम्बर जो किसी आम सदन के सभामुख या उप-सभामुख के पद पर हो—

(प) अगर वह आम सदन का मेम्बर न रहे तो अपना पद सूना कर देगा;

(बी) किसी समय भी अगर वह मेम्बर सभामुख है तो उप-सभामुख के नाम और अगर वह मेम्बर उप-सभामुख है तो सभामुख के नाम, अपनी दसखती लिखत भेज कर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है; और

(सी) आम सदन के एक ऐसे ठहराव से अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे आम सदन के उस समय के कुल मेम्बरों की बड़ीयत ने पास किया हो:

शर्तें कि धारा (सी) के मतलब के लिये कोई ठहराव पेश नहीं किया जाएगा जबतक कि उस ठहराव को पेश करने के इरादे का कम से कम चौदह दिन का नोटिस न दिया गया हो :

और शर्तें कि जब कभी आम सदन को भंग किया जाए तो भंग होने के बाद अगले आम सदन की पहली मिलनी के ठीक पहले तक सभामुख अपना पद सूना नहीं करेगा.

180—(1) जब कभी सभामुख का पद सूना होगा, उसके पद के फरज उप-सभामुख पूरे करेगा, या अगर उप-सभामुख का पद भी सूना हो तो आम सदन का कोई ऐसा मेम्बर करेगा जिसका रियासतपति इस मतलब के लिये नियोजन करदे.

(2) आम सदन की किसी बैठक में सभामुख के मौजूद न रहने पर उप-सभामुख, या अगर वह भी मौजूद नहीं है तो कोई ऐसा आदमी जिसे आम सदन के दस्तूर के नियम तय करें, या अगर ऐसा कोई आदमी भी मौजूद नहीं है तो कोई और ऐसा आदमी जिसे आम सदन तय करे, सभामुख की जगह काम करेगा.

181—(1) आमसदन की किसी बैठक में जब कि सभामुख को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो सभामुख, या जब कि उप-सभामुख को उसके पद से हटाने के लिये

सभामुख और उप-सभामुख का पद सूना होना, उनका इस्तीफा देना और पद से हटाया जाना

उप-सभामुख को या किसी दूसरे आदमी को सभामुख के पद के फरज पूरा करने या सभामुख की जगह काम करने की शक्ति

जब उस को पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार किया जा रहा हो

तब सभामुख
या उप-सभामुख
सद्वारत नहीं करेगा

किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो उप-सभामुख, मौजूद होने पर भी, सद्वारत नहीं करेगा, और दफा 180 की धारा (2) के बन्धान हर ऐसी बैठक के बारे में वसी तरह लागू होंगे जिस तरह किसी ऐसी बैठक के बारे में लागू होते, जिसमें सभामुख या उप-सभामुख, जैसी सूरत हो, मौजूद न होता.

(2) आम सदन में सभामुख को उसके पद से हटाने के लिये जब किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो सभामुख को उस सदन में बोलने और दूसरी तरह कारवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, और दफा 189 में किसी बात के रहते भी, केवल पहली बार उस ठहराव पर या ऐसी कारवाई के दौरान में किसी भी दूसरे मामले पर वह वोट देने का हकदार होगा, मगर बराबर के वोट आने की हालत में नहीं होगा.

खास सदन का
मसनदी और उप-
मसनदी

182—हर उस रियासत में जिसमें खास सदन है वह सदन जितनी जल्दी हो सकेगा सदन के दो मेम्बरों को अलग अलग खास सदन का मसनदी और उप-मसनदी चुनेगा, और जब जब मसनदी या उप-मसनदी का पद सूना होगा, सदन किसी दूसरे मेम्बर को मसनदी या उप-मसनदी, जैसी सूरत हो, चुन लेगा.

मसनदी और उप-
मसनदी का पद
सूना होना, उनका
इस्तीफा देना और
पद से हटाया
जाना

183—कोई मेम्बर जो किसी खास सदन के मसनदी या उप-मसनदी के पद पर है—

(ए) अगर वह खास सदन का मेम्बर न रहे तो अपना पद सूना कर देगा;

(बी) किसी समय भी अगर वह मेम्बर मसनदी है तो उप-मसनदी के नाम और अगर वह मेम्बर उप-मसनदी है तो मसनदी के नाम अपनी दसखती लिखत भेजकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है; और

(सी) खास सदन के एक ऐसे ठहराव से अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे खास सदन के उस समय के कुल मेम्बरों की बड़ीयत ने पास किया हो :

शर्तों कि धारा (सी) के मतलब के लिये कोई ठहराव ऐसा नहीं

किया जाएगा जब तक कि उस ठहराव को पेश करने के इरादे का कम से कम चौदह दिन का नोटिस न दिया गया हो।

184—(1) जब कभी मसनदी का पद सूना होगा, उसके पद के फ़रज़ उप-मसनदी पूरे करेगा, या अगर उप-मसनदी का पद भी सूना हो तो ख़ास सदन का कोई ऐसा मेम्बर करेगा जिसका रियासतपति इस मतलब के लिये नियोजन कर दे।

(2) ख़ास सदन की किसी बैठक में मसनदी के मौजूद न रहने पर उप-मसनदी, या अगर वह भी मौजूद नहीं है तो कोई ऐसा आदमी जिसे ख़ास सदन के दफ़्तर के नियम तय करें, या अगर ऐसा कोई आदमी भी मौजूद नहीं है, तो कोई और ऐसा आदमी जिसे ख़ास सदन तय करे, मसनदी की जगह काम करेगा।

185—(1) ख़ास सदन की किसी बैठक में जब कि मसनदी को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो मसनदी, या जबकि उप-मसनदी को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो उप-मसनदी, मौजूद होने पर भी सदारत नहीं करेगा, और दफ़ा 184 की धारा (2) के बन्धान हर ऐसी बैठक के बारे में वसी तरह लागू होंगे जिस तरह किसी ऐसी बैठक के बारे में लागू होते जिसमें मसनदी या उप-मसनदी, जैसी सूरत हो, मौजूद न होता।

(2) ख़ास सदन में मसनदी को उसके पद से हटाने के लिये जब किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो मसनदी को उस सदन में बोलने और दूसरी तरह कारबाई में भाग लेने का अधिकार होगा, और दफ़ा 189 में किसी बात के रहते भी, केवल पहली बार उस ठहराव पर या ऐसी कारबाई के दौरान में किसी भी दूसरे मामले पर वह वोट देने का हक़दार होगा, मगर बराबर के वोट आने की हालत में नहीं होगा।

186—आम सदन के सभामुख और उप-सभामुख को, और ख़ास सदन के मसनदी और उप-मसनदी को, वह तनखाहें और भत्ते मिलेंगे जो उस रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर अलग अलग तय कर दे, और जब तक इसके लिये इस तरह का कोई

उप-मसनदी या किसी दूसरे आदमी को मसनदी के पद के फ़रज़ पूरा करने या मसनदी की जगह काम करने की शक्ति

जब उसको उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार किया जा रहा हो तो मसनदी या उप-मसनदी सदारत नहीं करेगा

मसनदी और उप-मसनदी और सभामुख, और उप-सभामुख की तनखाहें और भत्ते

बन्धान नहीं होता तब तक उनको वह तनखा है और भत्ते मिलेंगे जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं.

रियासत की क़ानून सभा की मंत्रायत

187—(1) रियासत की क़ानून सभा के सदन या हर सदन का अलग अलग मंत्रायती अमला होगा :

शर्तों कि इस धारा की किसी बात से यह मतलब नहीं लिया जायगा कि वह जिस रियासत की क़ानून सभा में खास सदन है, वहाँ उस क़ानून सभा के दोनों सदनों के लिये शामिलती जगहें बनाए जाने को रोकती है.

(2) किसी रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर उस रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों के मंत्रायती अमले में नियोजे जाने के लिये लोगों की भरती और उनकी नौकरी की शर्तों की क़ायदाबन्दी कर सकती है.

(3) जब तक धारा (2) के अधीन रियासत की क़ानून सभा कोई बन्धान नहीं करती तब तक रियासतपति आमसदन के सभामुख से या खास सदन के मसनदी से, जैसी सूरत हो, सलाह करने के बाद आमसदन के या खाससदन के मंत्रायती अमले में नियोजे जाने वाले लोगों की भरती और उनकी नौकरी की शर्तों की क़ायदाबन्दी करने वाले नियम बना सकता है, और जो नियम इस तरह बनाए जायेंगे उनका असर उस धारा के अधीन बने हुए क़ानून के बन्धानों के अधीन होगा.

काम का संचालन

मेम्बरों का हलफ़ उठाना या बचन भरना

188—हर रियासत के आम सदन और खास सदन का हर मेम्बर अपनी सीट लेने से पहले रियासतपति के सामने या इस काम के लिये रियासतपति के नियोजे हुए किसी आदमी के सामने उस रूप के अनुसार हलफ़ उठायगा या बचन भरेगा और उस पर दसख्त करेगा जो रूप इस मतलब के लिये तीसरी पट्टी में दिया हुआ है.

सदनों में बैठ लेना, सीटें सूनी होने पर भी सदनों को काम करने की शक्ति और कोरम

189—(1) सिवाय जब कि इस विधान में कुछ और बन्धान किया गया हो, रियासत की क़ानून सभा के हर सदन की हर बैठक में, सब सवाल, सभामुख को और मसनदी को छोड़ कर, या उस आदमी को छोड़ कर जो सभामुख या मसनदी की जगह काम कर

रहा हो, उस समय मौजूद और वोट देने वाले सब मेम्बरों के वोटों की बढ़ीयत से तय किये जायेंगे.

सभामुख या मसनदी या वह आदमी जो इनकी जगह काम कर रहा हो पहले तो वोट नहीं देगा, पर बराबर वोट आने की सूरत में उसको जितना वोट देने का अधिकार होगा और वह उस अधिकार से काम लेगा.

(2) रियासत की कानून सभा के हर सदन को यह शक्ति होगी कि उस सदन के मेम्बरों की कुछ सीटें सूनी होने पर भी काम करे, और रियासत की कानून सभा की हर कारवाई सरदुरुस्त होगी, भले ही बाद में यह पता चले कि कोई ऐसा आदमी सदन में बैठा, उसने वोट दिया या और किसी तरह कारवाई में भाग लिया जो ऐसा करने का हकदार नहीं था.

(3) जब तक रियासत की कानून सभा कानून बनाकर कोई दूसरा बन्धान नहीं करती तब तक, रियासत की कानून सभा के हर सदन की मिलनी के लिये कोरम दस मेम्बरों का होगा या उस सदन के मेम्बरों की कुल गिनती का एक दसवाँ होगा, जो भी अधिक हो.

(4) अगर किसी रियासत के आम सदन या खास सदन की किसी मिलनी के दौरान में किसी समय कोरम न रहे तो सभामुख का या मसनदी का, या उस आदमी का जो उनमें से किसी की जगह काम कर रहा हो, फ़रज होगा कि वह या तो सदन को मुलतवी कर दे या उस मिलनी को कोरम पूरा हो जाने तक के लिये रोक दे.

मेम्बरों की अजोगताएं

190—(1) कोई आदमी किसी रियासत की कानून सभा के दोनों सदनों का मेम्बर नहीं होगा, और रियासत की कानून सभा कानून बना कर इस बात का बन्धान कर देगी कि अगर कोई आदमी दोनों सदनों का मेम्बर चुन लिया जाय तो वह किसी एक सदन में अपनी सीट सूनी कर दे.

सीटों का सूना होना

(2) कोई आदमी पहली पट्टी में दर्ज दो या अधिक रियासतों की कानून सभा का मेम्बर नहीं होगा, और अगर कोई आदमी ऐसी दो या अधिक रियासतों की कानून सभाओं का मेम्बर चुन लिया जाय तो उस अरसे के पूरा होने पर जो राजपति के बनाए नियमों में दिया गया हो, उन सब रियासतों की कानून सभाओं में उस आदमी की सीटें सूनी हो जाएंगी, जब तक कि इससे पहले ही उसने एक को छोड़ कर बाक़ी सब रियासतों की कानून सभाओं में अपनी सीट से इस्तीफ़ा न दे दिया हो।

(3) अगर रियासत की कानून सभा के किसी सदन का कोई मेम्बर—

(ए) दफ़ा 191 की धारा (1) में बताई किसी अजोगता के अधीन हो जाय; या

(बी) सभामुख या मसनदी के नाम, जैसी सूरत हो, अपनी दसखती लिखत भेजकर अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे दे, तो इस पर उसकी सीट सूनी हो जायगी।

(4) अगर किसी रियासत की कानून सभा के किसी सदन का कोई मेम्बर साठ दिन के अरसे तक, सदन की इजाजत बिना, सदन की सब मिलनियों में नामौजूद रहे तो सदन उसकी सीट को सूनी ठहरा सकता है ;

शर्तें कि साठ दिन के इस अरसे के गिनने में वह अरसा नहीं गिना जायगा जब कि सदन बरखास्त रहा हो या लगातार चार दिन से अधिक के लिये मुलतबी कर दिया गया हो।

मेम्बरी के लिये
अजोगताएँ

191—(1) वह आदमी किसी रियासत के आम सदन का या खास सदन का मेम्बर चुने जाने, और मेम्बर होने, के अजोग होगा—

(ए) जो भारत सरकार के अधीन या पहली पट्टी में दर्ज किसी रियासत की सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर हो, सिवाय किसी ऐसे पद के जिसे रियासत की कानून सभा ने कानून बनाकर यह ठहरा दिया हो कि उस पद पर रहने से कोई आदमी अजोग नहीं होगा ;

(बी) जिसका दिमाग ठीक नहीं है और जिसे किसी अधिकारी अदालत ने ना-ठीक दिमाग का ठहरा दिया है ;

(सी) जो ऐसा दिवालिया है जिसे अभी तक बरी नहीं किया गया है ;

(डी) जो भारत का नागर नहीं है, या जो अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज का नागर बन गया है, या जो किसी विदेशी राज की भक्ति या उससे लगाव मान चुका है ;

(ई) जो राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन इसके लिये अजोग ठहराया गया है.

(2) इस दफ़ा के मतलबों के लिये कोई आदमी भारत सरकार के या पहली पट्टी में दर्ज किसी रियासत की सरकार के अधीन केवल इसी कारन किसी लाभ के पद पर नहीं सम्मत्ता जायगा कि वह यूनियन का या उस रियासत का वज़ीर है.

192—(1) अगर कोई ऐसा सवाल उठे कि किसी रियासत की क़ानून सभा के किसी सदन का कोई मेम्बर दफ़ा 191 की धारा (1) में बताई किसी अजोगता के अन्दर आ गया है या नहीं, तो इस सवाल को रियासतपति के फ़ैसले के लिये भेजा जायगा, और उसका फ़ैसला आख़री होगा.

मेम्बरों की अजोगताओं के बारे में सवालों का फ़ैसला

(2) ऐसे किसी सवाल पर कोई फ़ैसला देने से पहले रियासतपति चुनाव कमीशन से राय लेगा और उस राय के अनुसार काम करेगा.

193— अगर कोई आदमी दफ़ा 188 की ज़रूरतों को पूरा करने से पहले, या जब वह यह जानता हो कि वह किसी रियासत के आम सदन या खास सदन की मेम्बरी के जोग नहीं है या उसे उसके अजोग ठहराया गया है या राजपंचायत या रियासत की क़ानून सभा के बनाए किसी क़ानून के बन्धानों से उसको मेम्बर की तरह बैठने या वोट देने की मनाही की गई है, रियासत के आम सदन या खास सदन में मेम्बर की तरह बैठेगा या वोट देगा तो जितने दिन

दफ़ा 188 के अधीन हलफ़ उठाने या बचन भरने से पहले या जोग न होने या अजोग ठहराए जाने पर सदन में बैठने और वोट देने पर दंड

वह इस तरह बैठेगा या बोट देगा, उस पर हर दिन के लिये पाँच सौ रुपए दंड लगाया जा सकेगा, जो उससे रियासत के करखे के रूप में बसूल किया जायगा।

रियासत की कानून सभाओं और उनके मेम्बरों की शक्तियाँ, निजनिधम और बरीयतें

कानून सभाओं के सदनों, उनके मेम्बरों और उनकी कमे-टियों की शक्तियाँ, निर्बानियम बगैरा

194—(1) इस विधान के बन्धानों, और कानून सभा के दस्तूर की क्रायदाबन्दी करने वाले नियमों और क्रायमी हुकुमों के अधीन रहते हुए, हर रियासत की कानून सभा में बोलने की आजादी होगी।

(2) किसी रियासत की कानून सभा के किसी मेम्बर ने जो कुछ कानून सभा में या उसकी किसी कमेटी में कहा हो या जिस तरह वोट दिया हो उसके बारे में उस मेम्बर के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई कारवाई नहीं की जा सकेगी, और ऐसी कानून सभा के किसी सदन की तरफ से या उसके हुकुम से जो कोई रिपोर्ट, कागज, वोट या कारवाई निकाली जाय, उसके बारे में किसी आदमी के खिलाफ इस तरह की कोई कारवाई नहीं की जा सकेगी।

(3) और बातों में, हर रियासत की कानून सभा के हर सदन की और उस कानून सभा के हर सदन के मेम्बरों और कमेटियों की शक्तियाँ, निजनिधम और बरीयतें वह होंगी जो कानून सभा समय समय पर कानून बनाकर तय कर दे, और जब तक इस तरह तय कर दी जायं तब तक वह होंगी जो इस विधान के आरम्भ के समय यूनाइटेड किंगडम (इंगलिस्तान) की पार्लमेंट के हाउस आफ कामन्स को और उसके मेम्बरों और कमेटियों को हासिल हों।

(4) धारा (1), (2) और (3) के बन्धान जिस तरह किसी रियासत की कानून सभा के मेम्बरों के सम्बन्ध में लागू होते हैं, उसी तरह उन लोगों के सम्बन्ध में लागू होंगे जिनको इस विधान की रू से उस रियासत की कानून सभा के किसी सदन में या उसकी किसी कमेटी में बोलने का या किसी और तरह कारवाई में भाग लेने का अधिकार है।

195—हर रियासत के आम सदन और खास सदन के मेम्बर वह तनखाहें और भत्ते पाने के हकदार होंगे जो उस रियासत की क्रानून सभा समय समय पर क्रानून बनाकर तय करे, और जब तक इस बारे में इस तरह का बन्धान न किया जाय तब तक वह उसी दर से और उन्हीं शर्तों पर तनखाहें और भत्ते पाने के हकदार होंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जबाबी सूबे के आमसदन (लेजिस्लेटिव असेम्बली) के मेम्बरों के लिये लागू थीं.

मेम्बरों की तनखाहें और भत्ते

क्रानूनकारी दस्तूर

196—(1) नक़दी बिलों और दूसरे माली बिलों के बारे में दफ़ा 198 और 207 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, किसी भी बिल की पहल जहां रियासत में खास सदन है वहां रियासत की क्रानून सभा के किसी भी सदन में की जा सकती है.

बिल रखने और पास करने के बारे में बन्धान

(2) दफ़ा 197 और 198 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, कोई बिल जहां रियासत में खास सदन है वहां क्रानून सभा के सदनों में पास हुआ उस समय तक नहीं समझा जायगा जब तक कि दोनों सदनों ने, या तो बिना सुधार या केवल ऐसे सुधारों के साथ जिन्हें दोनों सदनों ने मान लिया हो, उस बिल को मान न लिया हो.

(3) कोई बिल, जो किसी रियासत की क्रानून सभा में पेश है, उसके सदन या सदनों के बरखास्त हो जाने के कारन गिर नहीं जायगा.

(4) कोई बिल जो किसी रियासत के खास सदन में पेश है, और जिसे आम सदन ने पास नहीं किया है, आम सदन के भंग होने पर गिर नहीं जायगा.

(5) अगर कोई बिल रियासत के आम सदन में पेश है या आम सदन से पास होकर खास सदन में पेश है, तो वह उस आम सदन के भंग होने पर गिर जायगा.

197—(1) अगर किसी बिल के, किसी ऐसी रियासत के आम सदन से पास होकर जिसमें खास सदन भी है, खास सदन को भेज दिये जाने के बाद—

नक़दी बिलों को छोड़कर दूसरे बिलों के सम्बन्ध में खास सदन की शक्तियों पर रक़ाबत

(ए) खास सदन ने बिल को नामंजूर कर दिया है; या

(बी) खास सदन के सामने बिल के रखे जाने की तारीख से तीन महीने से अधिक बीत गए हों और उस सदन ने उसे तबतक पास न किया हो; या

(सी) उस सदन ने बिल को ऐसे सुधारों के साथ पास किया हो जिनको आम सदन नहीं मानता,

तो आम सदन, अपने दस्तूर की क्रायशब्दी करने वाले नियमों के अधीन रहते हुए, अगर कोई ऐसे सुधार हों जिन्हें खास सदन ने किया, सुझाया या मान लिया हो तो ऐसे सुधारों के साथ या बिना ऐसे सुधारों के, उस बिल को, वसी या उसके बादवाले किसी इजलास में, फिर पास कर सकता है, और उसके बाद इस तरह पास हुए बिल को खास सदन को भेज सकता है.

(2) अगर आम सदन से दूसरी बार इस तरह पास होकर खास सदन को भेज दिये जाने के बाद किसी बिल को—

(ए) खास सदन ने नामंजूर कर दिया हो; या

(बी) खास सदन के सामने रखे जाने की तारीख से एक महीने से अधिक बीत गया हो, और उस सदन ने पास न किया हो; या

(सी) खास सदन ने ऐसे सुधारों के साथ पास किया हो जिनको आम सदन नहीं मानता,

तो यह समझा जायगा कि उस बिल को, उस रूप में जिस में वह दूसरी बार आम सदन में पास हुआ था, और उन सुधारों के साथ, अगर कोई ऐसे सुधार हों तो, जिन्हें खास सदन ने किया है या सुझाया है और आम सदन ने मान लिया है, रियासत की कानून सभा के सदनों ने पास कर दिया है.

(3) इस दफा की कोई बात किसी नकदी बिल पर लागू नहीं होगी.

नकदी बिलों के बारे में खास दस्तूर जायगा. 198—(1) कोई नकदी बिल पहले खास सदन में नहीं रखा

(2) जहाँ रियासत में खास सदन है वहाँ नक्रदी बिल आम सदन से पास होकर खास सदन को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा जायगा, और खास सदन बिल के आने की तारीख से चौदह दिन के अरसे के अन्दर अन्दर अपनी सिफारिशों के साथ बिल आम सदन को लौटा देगा, इस पर आम सदन चाहे तो खास सदन की सारी सिफारिशें या कोई सी सिफारिश मान ले या न माने.

(3) अगर आम सदन खास सदन की सिफारिशों में से किसी को मान लेता है, तो यह समझा जायगा कि उस नक्रदी बिल को उन सुधारों के साथ जिनकी खास सदन ने सिफारिश की है और जिन्हें आम सदन ने मान लिया है, दोनों सदनों ने पास कर दिया है.

(4) अगर आम सदन खास सदन की सिफारिशों में से किसी को भी नहीं मानता तो यह समझा जायगा कि उस नक्रदी बिल को, बिना उन सुधारों में से किसी के जिनकी सिफारिश खास सदन ने की है उसी रूप में जिसमें उसे आम सदन ने पास किया था, दोनों सदनों ने पास कर दिया है.

(5) अगर कोई नक्रदी बिल आम सदन से पास होकर सिफारिशों के लिये खास सदन को भेजा गया हो और ऊपर कहे चौदह दिन के अरसे के अन्दर आम सदन को न लौटाया गया हो, तो यह समझा जायगा कि इस अरसे के बीत जाने पर उस बिल को उसी रूप में जिसमें आम सदन ने उसे पास किया था दोनों सदनों ने पास कर दिया है.

199—(1) इस खंड के मतलबों के लिये, वह बिल नक्रदी बिल समझा जायगा जिसमें केवल वही बन्धान हों जिनका नीचे लिखे सब मामलों से या उनमें से किसी मामले से सम्बन्ध है, यानी—

“नक्रदी बिलों” की परिभाषा.

(ए) किसी टैक्स का लगाना, अन्त करना, उसमें छूट देना, उसे बदलना या उसकी क्रायदाबन्दी करना ;

(बी) रियासत के रुपया उधार लेने या किसी तरह की गारंटी देने की क्रायदाबन्दी करना या किसी ऐसी माली जिम्मेदारियों के बारे में जो रियासत ने

ले रखी हों या जिन्हें वह लेने वाली हो क़ानून में कोई सुधार करना ;

(सी) रियासत के मूठकोश या जोगाजोग कोश की रखवाली, ऐसे किसी कोश में रुपया जमा करना या उसमें से रुपया निकालना ;

(डी) रियासत के मूठकोश में से रुपए को खर्च की मदों में डालना ;

(ई) किसी खर्च को रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ने वाला खर्च ठहराना, या इस तरह के किसी खर्च की रक़म को बढ़ाना ;

(एफ़) रियासत के मूठकोश के हिसाब में या रियासत के सरकारी हिसाब में रुपया बसूल करना, या ऐसे रुपए की रखवाली करना, या उसका निकास करना ; या

(जी) (ए) से (एफ़) तक की उप-धाराओं में दर्ज मामलों में से किसी के साथ प्रसंग से आया हुआ कोई और मामला.

(2) किसी बिल को केवल इसी कारन नक़दी बिल नहीं समझा जायगा कि वह ज़ुरमाने करने, या रुपए पैसे के दूसरे दंड देने, या लाइसेंसों के लिये या जो कोई सेवाएँ की गई हों उनके लिये फ़ीस माँगने या फ़ीस देने का बन्धान करता है, या इस कारन कि वह मुक़ामी मतलबों के लिये किसी मुक़ामी अधिकारी या संस्था के कोई टैक्स लगाने, अन्त करने, उसमें छूट देने, उसको बदलने, या उसकी क़ायदाबन्दी करने का बन्धान करता है.

(3) अगर किसी ऐसी रियासत में जहाँ खास सदन है किसी ऐसे बिल के बारे में जो रियासत की क़ानून सभा में रखा गया है वह सवाल उठे कि वह बिल नक़दी बिल है या नहीं तो इस पर उस रियासत के आम सदन के सभामुख का फ़ैसला आख़री होगा.

(4) जब कोई नक़दी बिल दफ़ा 198 के अधीन खास

सदन को भेजा जाय और जब कोई नक़दी बिल दफ़ा 200 के अधीन मंजूरी के लिये रियासतपति के सामने रखा जाय, तो हर ऐसे बिल पर आम सदन के सभामुख की दसखती सनद होगी कि वह बिल नक़दी बिल है।

200—जब कोई बिल रियासत के आम सदन से, या उस सूरत में जबकि उस रियासत में खास सदन भी है। रियासत की क्रान्तन सभा के दोनों सदनों से, पास हो जाय तो उसे रियासतपति के सामने रखा जायगा, और रियासतपति ऐलान करेगा कि वह उस बिल पर मंजूरी देता है या उससे अपनी मंजूरी रोक लेता है या उस बिल को राजपति के विचार के लिये रख देता है :

शर्तें कि किसी बिल के रियासतपति के सामने मंजूरी के लिये रखे जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके रियासतपति उस बिल को, अगर वह नक़दी बिल नहीं है तो, एक ऐसे संदेसे के साथ सदन या सदनों को लौटा सकता है जिसमें यह प्रार्थना की गई हो कि वह बिल पर या उसके किन्हीं बताए हुए बन्धानों पर फिर से विचार करें और खास कर इस बात को सोचें कि अगर रियासतपति ने अपने संदेसे में किन्हीं सुधारों की सिफ़ारिश की है तो ऐसे किन्हीं सुधारों को ले लेना चाहिये या नहीं, और जब कोई बिल इस तरह लौटा दिया जायगा तो उस संदेसे के अनुसार वह सदन या दोनों सदन बिल पर फिर से विचार करेंगे, और अगर सदन या दोनों सदन बिल को फिर बिना सुधार या सुधारों के साथ पास कर देते हैं, और वह मंजूरी के लिये रियासतपति के सामने रखा जाता है, तो रियासतपति उससे अपनी मंजूरी नहीं रोकेंगा :

और शर्तें कि रियासतपति हर ऐसे बिल पर, जो उसकी राय में अगर क्रान्तन बन जाय तो हाईकोर्ट की शक्तियों को इस तरह कम कर देगा कि वह जगह जिसको भरने के लिये इस विधान ने हाईकोर्ट को बनाया है ख़तरे में पड़ जायगी, अपनी मंजूरी नहीं देगा, बल्कि उसे राजपति के सोच विचार के लिये रख देगा।

201—जब रियासतपति किसी बिल को राजपति के विचार के लिये रख दे, तो राजपति ऐलान करेगा कि वह उस बिल पर अपनी रखे हुए बिल

मंजूरी देता है या उससे अपनी मंजूरी रोक लेता है :

शर्तें कि, जहाँ बिल नक़दो बिल नहीं है, राजपति रियासतपति को यह निर्देश दे सकता है कि वह उस बिल को एक ऐसे संदेसे के साथ, जो दफ़ा 200 की पहली शर्त में बताया गया है, रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों को, जैसी सूरत हो, लौटा दे, और जब बिल इस तरह लौटा दिया जाय तो सदन या दोनों सदन, ऐसे संदेसे के मिलने की तारीख़ से छै महीने के अरसे के अन्दर अन्दर, बिल पर उस सन्देसे के अनुसार फिर से विचार करेंगे, और अगर उस बिल को, बिना सुधार या सुधारों के साथ, सदन या दोनों सदन फिर पास कर दें तो उसे फिर राजपति के सामने विचार के लिये रखा जायगा.

माली मामलों में दस्तूर

सालाना
ब्यौरा

माली

202—(1) रियासतपति हर माली साल के बारे में रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों के सामने उस साल के लिये रियासत की आमदनी और खर्च के तख़मीने का एक ब्यौरा रखवायगा जिसकी चरचा इस भाग में “सालाना माली ब्यौरा” कह कर की गई है.

(2) सालाना माली ब्यौरे के अन्दर खर्च के जो तख़मीने रहेंगे उनमें यह रक़में अलग अलग दिखाई जायंगी—

(ए) वह रक़में जो उस खर्च के लिये दरकार होंगी जिसे इस विधान में रियासत के मूठकोश के खाते में पड़नेवाला खर्च बताया गया है; और

(बी) वह रक़में जो उन दूसरे खर्चों के लिये दरकार होंगी जिनके बारे में यह सुझाव है कि वह रियासत के मूठकोश में से किये जायं;

और उसमें मालगुज़ारी खाते खर्च और दूसरे खर्चों में फ़रक़ किया जायगा.

(3) नीचे लिखे खर्च वह खर्च होंगे जो हर रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ेंगे—

(ए) रियासतपति के वेतन और भत्ते, और उसके पद सम्बन्धी दूसरे खर्च;

(बी) आम सदन के सभामुख और उप-सभामुख की और, जहाँ रियासत में खास सदन है, वहाँ खास सदन के मसनदी और उप-मसनदी की भी तनखाहें और भत्ते;

(सी) करजा खर्च जिसके लिये रियासत देनदार है, जिसमें सूद-व्याज, करजा चुकाई कोश खर्च, और भुगतान खर्च, और उधार लेने, करजा जारी रखने और करजा भुगतान के सम्बन्ध में दूसरे खर्च शामिल होंगे;

(डी) किसी हाईकोर्ट के जजों की तनखाहों और भत्तों के बारे में खर्च;

(ई) वह रकम में जो किसी अदालत या पंचायती अदालत के किसी फैसले, डिगरी या पंच फैसले को चुकाने के लिये दरकार हों;

(एफ) कोई दूसरा खर्च जिसे यह विधान, या रियासत की कानून सभा कानून बनाकर ऐसा खर्च ठहरा दे.

203—(1) उतने तख्मीने जितनों का सम्बन्ध किसी रियासत के मूठकोश के खाते में पड़नेवाले खर्च से है आम सदन के सामने बोट के लिये नहीं रखे जायंगे, पर इस धारा की किसी बात का यह मतलब नहीं लिया जायगा कि वह कानून सभा में उन तख्मीनों में से किसी पर बहस होने को रोकती है.

तख्मीनों के बारे में कानून सभा का दस्तूर

(2) उतने तख्मीने जितनों का सम्बन्ध दूसरे खर्च से है देनगियों की मांगों के रूप में आम सदन के सामने रखे जायंगे, और आम सदन को यह शक्ति होगी कि वह किसी मांग को मंजूर कर ले या मंजूर करने से इनकार कर दे या किसी मांग को उस मांग में दर्ज रकम में कमी करके मंजूर कर ले.

(3) रियासतपति की सिफारिश के बिना किसी देनगी की मांग नहीं की जायगी.

204—(1) दफा 203 के अधीन आम सदन के देनगियां पास कर देने के बाद जितनी जरूरी हो सकेगा एक बिल रखा जायगा

यह-बटवारा बिल

जिसमें रियासत के मूठकोश में से नीचे लिखे खर्चों के लिये दरकार रुपयों को खर्च की मदों में ढालने का बन्धान किया जायगा—

(ए) जो देनगियां आम सदन ने इस तरह पास कर दी हों ; और

(बी) रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ने वाले खर्च, पर जो किसी सूरत में भी सदन या सदनों के सामने पहले से रखे हुए व्योरे में दिखाई रकम से अधिक न होंगे.

(2) ऐसे किसी बिल में रियासत की कानून सभा के किसी सदन या सदनों में किसी ऐसे सुधार का सुझाव नहीं रखा जायगा जिससे इस तरह पास की हुई किसी देनगी की रकम घटाई बढ़ाई जा सके, या उसके देनस्थान को बदल दिया जाय, या रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ने वाले किसी खर्च की रकम बदल दी जाय, और सदारत करनेवाले आदमी का यह फ़ैसला, कि इस धारा के अधीन कोई सुधार लिया जा सकता है या नहीं आखरी होगा.

(3) दफ़ा 205 और 206 के बन्धानों का ध्यान रखते हुए, रियासत के मूठकोश में से कोई रुपया नहीं निकाला जायगा सिवाय उस मद बटवारे के अधीन जो इस दफ़ा के बन्धानों के अनुसार पास हुए कानून में कर दिया गया हो.

पूरक, सहायक या
अधिक देनगियां

205—(1), (ए) अगर दफ़ा 204 के बन्धानों के अनुसार बने हुए किसी कानून से, किसी खास सेवा पर चालू माली साल में खर्च किये जाने के लिये अधिकारी हुई रकम उस बरस के मतलबों के लिये नाकाफी पाई जाय, या जब किसी चालू माली साल में किसी ऐसी नई सेवा पर पूरक या सहायक खर्च की जरूरत पैदा हो गई हो, जिसका विचार उस साल के सालाना माली व्योरे में नहीं किया गया था, या

(बी) अगर किसी माली साल की बाबत किसी सेवा के लिये मंजूर रकम से अधिक कोई रुपया उस

सेवा पर उस साल खर्च हो गया है,

तो रियासतपति रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों के सामने उस खर्च के तख़मीने की रक़म को दिखानेवाला दूसरा ब्योरा रखवायगा, या रियासत के आम सदन के सामने, जैसी सूरत हो, ऐसे अधिक खर्च की मांग रखवायगा.

(2) ऐसे किसी ब्योरे और खर्च या मांग के सम्बन्ध में, और उस खर्च को पूरा करने के लिये या उस मांग के सम्बन्ध की देनगी को पूरा करने के लिये रियासत के मूठकोश में से रुपये को खर्च की मदों में डालने का अधिकार देने के लिये बनाए जाने वाले किसी क़ानून के सम्बन्ध में, दफ़ा 202, 203, और 204 के बन्धानों का वही असर होगा जो असर उनका सालाना माली ब्योरे और उसमें बताए खर्च या किसी देनगी की मांग और उस खर्च या देनगी को पूरा करने के लिये रियासत के मूठकोश में से रुपये को खर्च की मदों में डालने का अधिकार देने के लिये बनाए जाने वाले क़ानून के सम्बन्ध में होता है.

206—(1) इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, रियासत के आम सदन को यह शक्ति होगी कि—

हिसाब पर बोट, साल की बोट और अलग देनगियाँ

(ए) किसी देनगी पर बोट लेने के लिये दफ़ा 203 में जो दस्तूर बताया गया है उसके पूरा होने से पहले, और उस खर्च के बारे में दफ़ा 204 के बन्धानों के अनुसार क़ानून पास होने से पहले, किसी माली साल के किसी भाग के लिये खर्च के तख़मीने की बाबत पहले से कोई देनगी मंज़ूर कर दे ;

(बी) रियासत के साधनों पर किसी अचानक मांग को पूरा करने के लिये, उस सूरत में जब कि उस सेवा के फैलाव या अनिश्चित रूप के कारन वह मांग उन तक़सीलों के साथ बयान नहीं की जा सकती जो आम तौर पर सालाना माली ब्योरे में दी

जाती हैं, देनगी मंजूर कर दे ;

(बी) कोई ऐसी अलग देनगी, जो किसी माली साल की किसी चालू सेवा का कोई भाग नहीं है, मंजूर कर दे ;

और रियासत की क़ानून सभा को शक्ति होगी कि क़ानून बनाकर वह देनगियां जिन मतलबों के लिये मंजूर की गई हैं उनके लिये रियासत के मूठकोश में से रुपए निकालने का अधिकार दे दे.

(2) धारा (1) के अधीन कोई देनगी मंजूर करने के सम्बन्ध में, और उस धारा के अधीन बनाए जाने वाले किसी क़ानून के सम्बन्ध में, दफ़ा 203 और 204 के बन्धानों का वही असर होगा जो सालाना माली ब्योरे में बताए किसी खर्च के बारे में कोई देनगी मंजूर करने के सम्बन्ध में, और ऐसे खर्च को पूरा करने के लिये रियासत के मूठकोश में से रुपए को खर्च की मदों में ढाँकने का अधिकार देने के लिये बनाए जाने वाले क़ानून के सम्बन्ध में, होता है.

माली बिलों के बारे में खास बन्धान

207—(1) दफ़ा 199 की धारा (1) की (ए) से (एफ़) तक की उप-धाराओं में जो मामले दर्ज हैं उनमें से किसी के लिये बन्धान करने वाला कोई बिल पहले नहीं रखा जा सकेगा, न कोई सुधार पेश किया जा सकेगा, जब तक कि रियासतपति उसकी सिफ़ारिश न करे, और इस तरह का बन्धान करने वाला कोई बिल पहले खास सदन में नहीं रखा जायगा :

शर्तें कि किसी ऐसे सुधार को पेश करने के लिये जो किसी टैक्स को कम करने या उसका अन्त करने का बन्धान करता हो इस धारा के अधीन कोई सिफ़ारिश दरकार न होगी.

(2) कोई बिल या सुधार केवल इसी कारन ऊपर बताए किसी मामले के लिये बन्धान करने वाला नहीं समझा जायगा कि वह ज़ुरमाने करने या रुपए पैसों का कोई दूसरा दंड देने या लाइसेंसों के लिये या जो कोई सेवाएँ की गई हों उनके लिये फ़ीस मांगने या फ़ीस देने का बन्धान करता है, या इस कारन कि वह मुक़ामी मतलबों के लिये किसी मुक़ामी अधिकारी या संस्था के कोई

टैक्स लगाने, अन्त करने, उसमें छूट देने, उसको बदलने, या उसकी क्रायदाबन्दी करने का बन्धान करता है।

(3) अगर किसी बिल के कानून बन जाने और उस पर अमल होने से किसी रियासत के मूठकोश से खर्च करना पड़े तो उस बिल को उस रियासत की कानून सभा का कोई सदन पास नहीं करेगा जब तक कि रियासतपति ने उस बिल पर सोच विचार करने की उस सदन से सिफारिश न की हो।

आम दस्तूर

208—(1) इस विधान के बन्धानों का ध्यान रखते हुए, हर दस्तूर के नियम रियासत की कानून सभा का हर सदन अपने दस्तूर की और काम के संचालन की क्रायदाबन्दी करने के लिये नियम बना सकता है।

(2) जब तक धारा (1) के अधीन नियम नहीं बनते, तब तक दस्तूर के जो नियम और जो क्रायमी हुकुम इस विधान के जारी होने से ठीक पहले जवाबी सूबे की कानून सभा के बारे में अमल में थे वही उस रियासत की कानून सभा के सम्बन्ध में भी लागू होंगे, पर आम सदन का सभामुख या खास सदन का मसनदी, जैसी सूरत हो, उनमें बदल और अनुकूलन कर सकता है।

(3) जिस रियासत में खास सदन है वहाँ रियासतपति, आम सदन के सभामुख और खास सदन के मसनदी से सलाह करके, दोनों सदनों के बीच आवाजाई के बारे में दस्तूर के नियम बना सकता है।

209—माली काम को समय के अन्दर पूरा करने के लिये, किसी रियासत की कानून सभा कानून बनाकर किसी माली मामले के सम्बन्ध में, या रियासत के मूठकोश में से रुपये को खर्च की मदों में डालने वाले किसी बिल के सम्बन्ध में, रियासत की कानून सभा के सदन या सदनों के दस्तूर की, और काम के संचालन की, क्रायदाबन्दी कर सकती है, और अगर इस तरह बने किसी कानून का कोई बन्धान, दफ्ता 208 की धारा (1) के अधीन रियासत की कानून सभा के सदन या दोनों सदनों में से किसी सदन के बनाए हुए किसी नियम से, या किसी ऐसे नियम या क्रायमी हुकुम से

माली काम के सम्बन्ध में रियासत की कानून सभा के दस्तूर की कानून से क्रायदाबन्दी

जो उस दफ्ता की धारा (2) के अधीन रियासत की क़ानून सभा के सम्बन्ध में लागू होता हो, मेल नहीं खाता तो उस मेल न खाने की हद तक वह बन्धान ही चलेगा.

क़ानूनसभा में काम
में आने वाली भाषा

210—(1) भाग सतरह में किसी बात के रहते भी, पर दफ्ता 348 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, हर रियासत की क़ानून सभा में काम उस रियासत की दफ्तरी भाषा या भाषाओं में या हिन्दी में या अंगरेज़ी में किया जायगा :

शर्तें कि आम सदन का सभामुख या खास सदन का मसनद या उनकी जगह काम करने वाला कोई आदमी, जैसी सूरत हो, किसी ऐसे मेम्बर को जो ऊपर कही भाषाओं में से किसी में अपने को पूरी तरह अदा न कर सकता हो, सदन में अपनी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है.

(2) जब तक रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर कुछ और बन्धान न करे तब तक इस दफ्ता का इस विधान के आरंभ से पन्द्रह बरस का अरसा बीत जाने के बाद वही असर होगा मानो “या अंगरेज़ी में” ये शब्द इस दफ्ता में से निकाल दिये गये हों.

क़ानून सभा में
बहस पर रुकावट

211—माला अदालत के या किसी हाईकोर्ट के किसी जज ने अपने फ़रज़ निभारने में जो कुछ किया हो उसके बारे में किसी रियासत की क़ानून सभा में कोई बहस नहीं की जायगी.

क़ानून सभा की
कारवाइयों के बारे
में अक्षत पूछताछ
नहीं करेंगी

212—(1) किसी रियासत की क़ानून सभा की किसी कारवाई की सरदुस्ती के बारे में इस बिना पर कोई सवाल नहीं उठाया जायगा कि उसमें दस्तूर की कोई बेक़ायदगी बताई गई है.

(2) किसी रियासत की क़ानून सभा का कोई अफसर या मेम्बर, जिसको इस विधान में या इसके अधीन क़ानून सभा के दस्तूर की या काम के संचालन की क़ायदाबन्दी करने के लिये या क़ानून सभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिये शक्तियाँ हासिल हैं, उन शक्तियों से काम लेने के बारे में किसी अदालत की अमलदारी के अधीन न होगा.

खंड चार—रियासतपति की कानूनकारी शक्ति

213—(1) अगर किसी समय, सिवाय जबकि किसी रियासत के आम सदन का इजलास हो रहा हो, या जहाँ रियासत में खास सदन भी है वहाँ कानून सभा के दोनों सदनों का इजलास हो रहा हो, रियासतपति को यह भरोसा हो जाय कि उस समय कुछ सूत्रों ऐसी हैं जिनमें उसे तुरंत कारवाई करने की जरूरत है, तो रियासतपति ऐसे राजहुकुम जारी कर सकता है जो उन सूत्रों में उसे जरूरी मालूम हों:

कानून सभा को छुट्टी के दिनों में रियासतपति को राजहुकुम जारी करने की शक्ति

शर्तें कि, रियासतपति, बिना राजपति की हिदायतों के, कोई ऐसा राजहुकुम जारी नहीं करेगा अगर—

(ए) इस विधान के अधीन, उस राजहुकुम के बन्धानों वाले किसी बिल को कानून सभा में रखने के लिये राजपति की पहले से मंजूरी लेना दरकार होता ; या

(बी) वह उन्हीं बन्धानों वाले किसी बिल को राजपति के सोचविचार के लिये रखना जरूरी समझता; या

(सी) उन्हीं बन्धानों वाला रियासत की कानून सभा का कोई एकट इस विधान के अधीन तब तक सर-दुरुस्त न होता जबतक वह राजपति के सोच-विचार के लिये न रखा गया होता और उसे राजपति की मंजूरी न मिल गई होती.

(2) इस दफा के अधीन जो राजहुकुम जारी किया जाय उसका वही बल और असर होगा जो उस रियासत की कानून सभा के किसी ऐसे एकट का होता जिस पर रियासतपति ने मंजूरी दे दी होती ; पर हर ऐसे राजहुकुम को—

(ए) रियासत के आम सदन के सामने या जहाँ रियासत में खास सदन भी है वहाँ दोनों सदनों के सामने रखा जायगा, और कानून सभा के फिर मिलने से छै हफ्ते बीत जाने पर, या अगर इस अरसे के बीत चुकने से पहले ही आम सदन ने उस

राजहुकुम को नापसन्द करने का ठहराव पास कर दिया हो, और जहाँ खास सदन भी है वहाँ खास सदन ने उस ठहराव को मान लिया हो, तो उस ठहराव के पास होने पर, या, जैसी सूरत हो, खास सदन के उस ठहराव को मान लेने पर, वह राजहुकुम आगे अमल में नहीं रहेगा ; और

(बी) रियासतपति कभी भी वापस ले सकता है.

समझाव—जिस रियासत में खास सदन है वहाँ अगर दोनों सदनों को फिर से मिलने के लिये अलग अलग तारीखों पर बुलाया गया हो तो इस धारा के मतलबों के लिये छै हफ्ते का अरसा उन तारीखों में से पिछली तारीख से गिना जायगा.

(3) अगर इस दफा के अधीन कोई राजहुकुम कोई ऐसा बन्धान करता है जिसे अगर रियासतपति से मंजूरी पाए हुए उस रियासत की कानून सभा के किसी एक्ट में कानून का रूप दिया गया होता तो वह बन्धान सरदुरुस्त न होता, तो उस हद तक वह राज-हुकुम रह होगा :

शर्तें कि इस विधान के उन बन्धानों के मतलबों के लिये, जिनका सम्बन्ध किसी रियासत की कानून सभा के ऐसे एक्ट के अन्तर से है जो संगचारी तालिका में गिनाए हुए किसी मामले के बारे में किसी मौजूदा कानून के या राजपंचायत के किसी एक्ट के खिलाफ जाता है, राजपति की हिदायतों पर अमल करते हुए, इस दफा के अधीन, जो राजहुकुम जारी किया जाय, वह उस रियासत की कानून सभा का ऐसा एक्ट समझा जायगा जिसे राजपति के खोच विचार के लिये रखा गया हो और राजपति ने उसपर मंजूरी दे दी हो.

खंड पाँच—रियासतों की हाईकोर्टें

रियासतों के लिये
हाईकोर्टें

214—(1) हर रियासत के लिये एक हाईकोर्ट होगी.

(2) इस विधान के मतलबों के लिये उस हाईकोर्ट को जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले किसी सूबे के संबंध में

अपनी अमलदारी से काम लेती थी जवाबी रियासत के लिये हाईकोर्ट समझा जायगा.

(3) इस खंड के बन्धान हर उस हाईकोर्ट पर लागू होंगे जिसकी चरचा इस दफा में की गई है.

215—हर हाईकोर्ट नज़ीरी अदालत होगी और उसे अपनी हाईकोर्टें नज़ीरो तौहीन के लिये सज़ा देने की शक्ति समेत ऐसी अदालत की सब अदालतें होंगी. शक्तियाँ होंगी.

216—हर हाईकोर्ट में एक सरजज और ऐसे दूसरे जज हाईकोर्टों को होंगे जिन्हें राजपति समय समय पर नियोजना जरूरी समझे : बनावट

शर्तें कि इस तरह नियोजे हुए जज किसी समय भी उस बर्षी से बड़ी गिनती से ज्यादा नहीं होंगे जो राजपति, समय समय पर, उस अदालत के सम्बन्ध में हुकुम देकर तय करदे.

217—(1) हाईकोर्ट के हर जज का नियोजन राजपति, भारत के हाईकोर्ट के हर जज सरजज से, उस रियासत के रियासतपति से, और सरजज को छोड़ का नियोजन और कर किसी और जज के नियोजन में उस हाईकोर्ट के सरजज से, उसके पद की शर्तें सलाह कर के, एक ऐसे हुकुमनामे से करेगा जिस पर राजपति के दसखत होंगे और उसकी मुहर रहेगी, और वह जज साठ बरस की उमर पूरी करने तक अपने पद पर रहेगा:

शर्तें कि—

(ए) कोई जज राजपति के नाम अपनी दसखती लिखत भेज कर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है;

(बी) किसी जज को राजपति उस ठंग पर उसके पद से हटा सकता है जो दफा 124 की धारा (4) में आला अदालत के किसी जज को हटाने के लिये बताया गया है ;

(सी) अगर किसी जज को राजपति आला अदालत का जज नियोज दे या उसकी भारत के भूभाग के अन्दर किसी और हाईकोर्ट को बदली करदे तो उस जज का पहला पद सूना हो जायगा.

(2) कोई आदमी किसी हाईकोर्ट का जज नियोजे जाने

के जोग नहीं होगा जब तक वह भारत का नागर न हो, और—

- (ए) कम से कम दस बरस तक भारत के भूभाग में किसी न्यायी पद पर न रहा हो ; या
- (बी) कम से कम दस बरस तक पहली पट्टी में दर्ज किसी रियासत की हाईकोर्ट में या लगातार दो या अधिक ऐसी हाईकोर्टों में वकील न रह चुका हो.

समभाव—इस धारा के मतलबों के लिये—

- (ए) उस अरसे को गिनने में जिसमें कोई आदमी किसी हाईकोर्ट का वकील रहा है, वह अरसा भी शामिल किया जायगा जब वकील बनने के बाद उसने किसी न्यायी पद पर काम किया हो ;
- (बी) उस अरसे को गनने में जिसमें कोई आदमी भारत के भूभाग में न्यायी पद पर रह चुका है, या किसी हाईकोर्ट का वकील रह चुका है, इस विधान के आरंभ होने से पहले का वह अरसा भी शामिल किया जायगा जिसमें वह आदमी किसी ऐसे क्षेत्र में न्यायी पद पर काम कर चुका है जो 1947 की अगस्त के पन्द्रहवें दिन से पहले उस हिन्द में शामिल था जिसकी परिभाषा हिन्द सरकार एक्ट 1935 में की गई है, या वह ऐसे किसी क्षेत्र में किसी हाईकोर्ट में वकील रह चुका है, जैसी सूरत हो.

आला अदालत से सम्बन्ध रखने वाले कुछ बन्धानों का हाईकोर्टों पर लागू होना

218—दफा 124 की धारा (4) और (5) के बन्धान जिस तरह आला अदालत के सम्बन्ध में लागू होते हैं उसी तरह हर हाईकोर्ट के सम्बन्ध में भी लागू होंगे, और जहाँ उनमें आला अदालत की चरचा की गई है वहाँ उसकी जगह हाईकोर्ट की चरचा समझी जायगी .

हाईकोर्टों के जजों का हलफ उठाना या बचन भरना

219—हर वह आदमी जो किसी रियासत की हाईकोर्ट का जज नियोजा जाय, अपना पद संभालने से पहले, उस रियासत के रियासतपति के सामने या किसी दूसरे आदमी के सामने जिसे रियासतपति ने इस काम के लिये नियोजा हो, उस रूप में हलफ

ठायगा या वचन भरेगा और उस पर दसखत करेगा, जो इस मतलब के लिये तीसरी पट्टी में दिया गया है.

220—कोई आदमी जो इस विधान के आरम्भ होने के बाद किसी हाईकोर्ट के जज के पद पर रह चुका है भारत के भूभाग के अन्दर किसी अदालत में या किसी अधिकारी के सामने वकालत नहीं करेगा, न काम करेगा.

जजों को अदालतों में या किसी अधिकारी के सामने वकालत करने की मनाही

221—(1) हर हाईकोर्ट के जजों को वह तनखाहें दी जायंगी जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं.

जजों की तनखाहें, भौरी

(2) हर जज वह भत्ते पाने का हकदार होगा और छुट्टी और पेनशन के बारे में उसके वह अधिकार होंगे जो समय समय पर राजपंचायत के बनाए कानून में या उसके अधीन तय कर दिये जायं, और जब तक इस तरह तय नहीं किये जाते तब तक उसको वह भत्ते और अधिकार मिलेंगे जो दूसरी पट्टी में बताए गए हैं :

शर्तें कि किसी जज के नियोजन के बाद उसके भत्तों में या छुट्टी या पेनशन के बारे में उसके अधिकारों में कोई ऐसी अदल बदल नहीं की जायगी जिससे वह घाटे में रहे.

222—(1) राजपति भारत के सरजज से सलाह करके भारत के भूभाग के अन्दर किसी जज का एक हाईकोर्ट से किसी दूसरी हाईकोर्ट को तबादला कर सकता है.

किसी जज का एक हाईकोर्ट से दूसरी में तबादला

(2) जब किसी जज का इस तरह तबादला किया जाय तो उस अरसे में जब वह दूसरी अदालत के जज की हैखियत से काम कर रहा हो वह अपनी तनखाह के अलावा वह भरपाई भत्ता पाने का हकदार होगा जो राजपंचायत कानून बनाकर तय करे, और जब तक इस तरह तय न हो तब तक वह भरपाई भत्ता पाने का हकदार होगा जो राजपति हुकुम देकर तय कर दे.

223—जब किसी हाईकोर्ट के सरजज का पद सूना हो, या नामौजूदगी या दूसरे कारन से सरजज अपने पद के फरखों को पूरा न कर सके, तब उस अदालत के दूसरे जजों में से कोई एक, जिसे राजपति इस मतलब के लिये नियोजे, उस पद के फरखों को पूरा करेगा.

कारकर सरजज का नियोजन

L. B. S. National Academy
of Administration, Mussoorie
F. No. 450/450/92
Date 14.1.92

122049

हाईकोर्टों की बैठकों में सेवामुक्त जजों का आना

224—इस खंड में किसी बात के रहते भी, किसी रियासत की हाईकोर्ट का सरजज, किसी समय भी, राजपति की पहले से अनुमति लेकर, किसी ऐसे आदमी से जो कभी उस हाईकोर्ट के या किसी और हाईकोर्ट के जज के पद पर रह चुका है प्रार्थना कर सकता है कि वह उस रियासत की हाईकोर्ट में जज की हैसियत से बैठे और काम करे, और हरवह आदमी जिससे यह प्रार्थना की गई हो, जब तक इस तरह बैठेगा और काम करेगा, उन भत्तों का हकदार होगा जो राजपति हुकुम देकर तय कर दे, और उसे उस हाईकोर्ट के जज की सारी अमलदारी, शक्तियाँ और निजनियम मिलेंगे, मगर वह किसी और तरह उस अदालत का जज नहीं समझा जायगा :

शर्तें कि इस दफा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि किसी ऐसे आदमी को जिसकी चरचा ऊपर की गई है उस हाईकोर्ट के जज की हैसियत से बैठना और काम करना पड़ेगा, जब तक कि वह ऐसा करने के लिये राजी न हो जाय.

मौजूदा हाईकोर्टों की अमलदारी

225—इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, और किसी ऐसे क़ानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए जो किसी मुनासिब क़ानून सभा ने उन शक्तियों की रू से बनाया हो जो इस विधान में उस क़ानून सभा को दी गई हैं, किसी मौजूदा हाईकोर्ट की वही अमलदारी होगी, और उसमें उसी क़ानून पर अमल कराया जायगा, और उस अदालत में न्याय करने के बारे में जजों को अलग अलग वही शक्तियाँ होंगी, जो इस विधान के आरम्भ से ठीक पहले थीं ; इन शक्तियों में अदालत के नियम बनाने की शक्ति और अदालत और उसके जजों की बैठकों के लिये, चाहे वह अकेले बैठें चाहे डिवीजन अदालत के रूप में बैठें, क़ायदाबन्दी करने की शक्ति भी शामिल होगी:

शर्तें कि मालगुजारी सम्बन्धी किसी मामले के बारे में, या मालगुजारी की बसूली में जो कोई काम किया जाय या जिसके करने का हुकुम दिया जाय उससे सम्बन्ध रखने वाले किसी मामले के बारे में, किसी हाईकोर्ट के पहली सुनवाई के अधिकार से काम लेने पर इस विधान के आरम्भ से ठीक पहले अगर कोई उकाबट लगी हुई

भी तो वह रुकावट इसके बाद उस हाईकोर्ट के उस अधिकार से काम लेने पर नहीं रहेगी।

226—(1) दफा 32 में किसी बात के रहते भी, तीसरे भाग में जो अधिकार दिये गए हैं उनमें से किसी पर अमल कराने के लिये या और किसी मतलब के लिये हर हाईकोर्ट को, उन तमाम भूभागों में जिनके सम्बन्ध में उसकी अमलदारी चलती है, उन भूभागों के अन्दर के किसी आदमी या किसी अधिकारी या मुनासिब सूरतों में वहां की किसी सरकार के नाम, निर्देश, हुकुम, या परवाने जारी करने की शक्ति होगी, जिनमें परवाना तनवलवी, परवाना हुकुम, परवाना मनाही, परवाना अधिकार-बताई और परवाना मिसल-मंगाई जैसे या इनमें से कोई परवाने भी हो सकते हैं।

कुछ परवाने जारी करने की हाईकोर्टों की शक्ति

(2) धारा (1) में जो शक्ति हाईकोर्ट को दी गई है, उससे आला अदालत की उस शक्ति में कोई कमी नहीं आयगी जो दफा 32 की धारा (2) में आला अदालत को दी गई है।

227—(1) हर हाईकोर्ट, उन सब भूभागों में जिनके सम्बन्ध में उसकी अमलदारी चलती है, सब अदालतों और पंचायती अदालतों पर निगरानी रखेगी।

हाईकोर्ट को सब अदालतों पर निगरानी रखने की शक्ति

(2) ऊपर के बंधान की आमियत को कम किये बिना, हाईकोर्ट—

(ए) उन अदालतों से व्योरे मांग सकती है;

(बी) उन अदालतों के काम और कारवाइयों की क्वायदाबन्दी करने के लिये आम नियम बना सकती है और जारी कर सकती है और रूप बता सकती है; और

(सी) वह रूप बता सकती है जिनमें ऐसी किसी अदालतों के अफसर अपने यहाँ के खाते, दाखले, और हिसाब किताब रखेंगे,

(3) हाईकोर्ट उन फीसों के भी नकशे तय कर सकती है जो उन अदालतों के शेरिफ, और सब क्लर्कों, और अफसरों को,

और उन अदालतों में बकालत करने वाले मुख्यतारों, वकीलों और प्लीडरों को दी जा सकेंगी :

शर्तें कि धारा (2) या धारा (3) के अधीन जो नियम बनाए जायं, या जो रूप बताए जायं, या नक़्शे तय किये जायं, वह किसी ऐसे क़ानून के बन्धान के ख़िलाफ़ नहीं होंगे जो उस समय अमल में हो, और उन पर पहले से रियासतपति की रज़ामन्दी लेना दरकार होगा.

(4) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह किसी हाईकोर्ट को ऐसी किसी अदालत या पंचअदालत पर निगरानी रखने की शक्तियाँ देती है जो हथियारबन्द क़ौजों से संबंध रखने वाले किसी क़ानूनसे या उसके अधीन बनी हो.

कुछ मुक़दमों का हाईकोर्ट में तथा-
इला

228—अगर हाईकोर्ट को यह भरोसा हो जाय कि, किसी ऐसे मुक़दमे में जो उसकी किसी मातहत अदालत में पेश है, इस विधान के अर्थ करने के बारे में क़ानून का कोई ऐसा ठोस सवाल उठता है जिसका तय करना उस मुक़दमे को निबटाने के लिये ज़रूरी है, तो वह उस मुक़दमे को उस अदालत से उठा लेगी और—

(ए) या तो आप उस मुक़दमे को निबटा देगी, या

(बी) क़ानून के उस सवाल को तय कर देगी, और उस सवाल पर अपने फैसले की नक़ल के साथ मुक़दमा उस अदालत को वापस कर देगी जिससे वह उठाया गया था, और वह अदालत उसके आने पर उस फैसले के अनुसार उस मुक़दमे को निबटाने की कारवाई करेगी.

हाईकोर्टों के अफ़-
सर, नौकर और

229—(1) हाईकोर्ट के अफ़सरों और नौकरों का नियोजन उस अदालत का सरजज करेगा या अदालत का वह दूसरा जज या अफ़सर करेगा जिसे सरजज निर्देश करदे:

शर्तें कि जिस रियासत में उस हाईकोर्ट की खास जगह है उस रियासत का रियासतपति नियम बनाकर यह दरकार कर सकता है कि, उन सूरतों में जो उस नियम में बताई गई हों, किसी ऐसे आदमी को, जो पहले से उस अदालत से लगा हुआ नहीं है, उस अदालत से सम्बन्ध रखने वाले किसी पद पर रियासत सरकारी

नौकरी कमीशन से सलाह किये बिना नहीं नियोजा जायगा.

(2) रियासत की क़ानून सभा के बनाए किसी क़ानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए, हाईकोर्ट के अफ़सरों और नौकरों की नौकरी की शर्तें वह होंगी जो उन नियमों में बताई जायं जिन्हें उस हाईकोर्ट के सरजज ने या उसके किसी ऐसे दूसरे जज या अफ़सर ने बनाया हो जिसे सरजज ने इस मतलब के लिये नियम बनाने का अधिकार दिया है :

शर्तें कि इस धारा के अधीन बने नियमों के लिये जहां तक उनका सम्बन्ध तनखाहों, भत्तों, छुट्टी या पेनशनों से है, उस रियासत के रियासतपति की रज़ामन्दी दरकार होगी जिसमें उस हाईकोर्ट की खास जगह है.

(3) हाईकोर्ट के शासनी खर्च, जिनमें उस अदालत के अफ़सरों और नौकरों को या उनके बारे में दी जाने वाली सब तनखाहें, भत्ते और पेनशनें शामिल हैं, रियासत के मूठकोश के खाते में पढ़ेंगे, और वह अदालत जो फ़ीस या दूसरी रक़में लेगी वे उस कोश का भाग होंगी.

230—राजपंचायत क़ानून बनाकर—

(ए) किसी हाईकोर्ट की अमलदारी को पहली पट्टी में दर्ज किसी ऐसी रियासत तक या किसी ऐसे क्षेत्र तक बढ़ा सकती है, या

(बी) किसी हाईकोर्ट की अमलदारी को पहली पट्टी में दर्ज किसी ऐसी रियासत से या किसी ऐसे क्षेत्र से अलग कर सकती है,

जो वह रियासत नहीं है, या उस रियासत के अन्दर नहीं है, जिसमें उस हाईकोर्ट की खास जगह है.

231—जहाँ किसी हाईकोर्ट की अमलदारी किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में भी चलती है, जो उस रियासत से बाहर है जिसमें उस हाईकोर्ट की खास जगह है, वहाँ इस विधान की किसी बात का यह मतलब नहीं लिया जायगा कि—

(ए) वह उस रियासत की क़ानून सभा को जिसमें उस

हाईकोर्टों की अमल-
दारी को बढ़ाना
या कम करना

किसी रियासत को
किसी ऐसी हाईकोर्ट
की अमलदारी के
सम्बन्ध में रियासतों
की क़ानून सभाओं
की क़ानून बनाने

की शक्तियों पर
रुकावटें जिस
हाईकोर्ट की
अमलदारी उस
रियासत के बाहर
भी हो

हाईकोर्ट की खास जगह है उस अमलदारी को बढ़ाने,
कम करने या खत्म करने की शक्ति देती है;

(बी) वह पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज
किसी ऐसी रियासत की कानून सभा को जिसमें कोई
ऐसा क्षेत्र है, उस अमलदारी को खत्म करने की शक्ति
देती है; या

(सी) वह उस कानून सभा को जिसे ऐसे किसी क्षेत्र के
बारे में उस मतलब के लिये कानून बनाने की शक्ति
है, धारा (बी) के बन्धानों के अधीन रहते हुए, उस
क्षेत्र के सम्बन्ध की उस हाईकोर्ट की अमलदारी के
बारे में ऐसे कानून बनाने से रोकती है, जिन्हें पास
करने का उस कानून सभा को अधिकार होता अगर
उस अदालत की खास जगह उसी क्षेत्र में होती.

अथ

232—जहां किसी हाईकोर्ट की अमलदारी पहली पट्टी में दर्ज
एक से अधिक रियासतों के सम्बन्ध में, या किसी एक रियासत
और एक ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में चलती है जो उस रियासत का
भाग नहीं है, वहां—

(ए) इस खंड में जहां किसी हाईकोर्ट के जजों के
सम्बन्ध में रियासतपति की चरचा की गई है, उससे
मतलब उस रियासत के रियासतपति से लिया जायगा
जिसमें उस हाईकोर्ट की खास जगह है;

(बी) मातहत अदालतों के लिये नियमों, रूपों और नक़शों
पर रियासतपति की रज़ामन्दी की जहां चरचा की
गई है, उससे मतलब उस रियासत के रियासतपति
या राजप्रमुख की रज़ामन्दी से लिया जायगा जिसमें
वह मातहत अदालत है, या अगर वह किसी ऐसे
क्षेत्र में है जो पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी)
में दर्ज किसी रियासत का भाग नहीं है, तो उससे मत-
लब राजपति की रज़ामन्दी से लिया जायगा; और
(सी) रियासत के मूठकोश की जहां जहां चरचा की गई है

उससे मतलब उस रियासत के मूठकोश की चरचा से लिया जायगा जिसमें उस हाईकोर्ट की खास जगह है.

खंड छै—मातहत अदालतें

233—(1) किसी रियासत में जिला जज होने वाले लोगों का नियोजन, उनकी तैनाती और तरक्की उस रियासत का रियासतपति, उस रियासत के संबंध में अमलदारी रखने वाली हाईकोर्ट से सलाह करके करेगा.

जिला जजों का नियोजन

(2) कोई आदमी जो पहले से यूनिन की या रियासत की नौकरी में नहीं है केवल तभी जिला जज नियोजे जाने का पात्र होगा जब वह कम से कम सात बरस तक वकील या सीडर रह चुका है और हाईकोर्ट ने उसके नियोजन की सिफारिश की है.

234—किसी रियासत की न्यायी नौकरी में जिला जजों को छोड़कर दूसरे लोगों का नियोजन उस रियासत का रियासतपति इस काम के लिये अपने बनाए हुए उन नियमों के अनुसार करेगा जो उसने रियासत सरकारी नौकरी कमीशन और उस रियासत के संबंध में अमलदारी रखने वाली हाईकोर्ट से सलाह करके बनाए हों.

न्यायी नौकरी में जिला जजों को छोड़कर और लोगों की सरती

235—जिला अदालतों और उनकी मातहत अदालतों पर दबान हाईकोर्ट को हासिल होगा, जिसमें किसी रियासत की न्यायी नौकरी में काम करने वाले और जिला जज से नीचे पद पर रहने वाले लोगों की तैनाती और तरक्की और उनकी छुट्टी मंजूर करना शामिल होगा, पर इस दफा की किसी बात का यह मतलब नहीं लिया जायगा कि वह किसी ऐसे आदमी का अपील करने का वह अधिकार छीन लेती है जो उसको उसकी नौकरी की शर्तों की क्रायदाबन्दी करनेवाले कानून के अधीन मिला हुआ हो, या यह कि वह हाईकोर्ट को यह अधिकार देती है कि वह उस कानून के अधीन बताई उस आदमी की नौकरी की शर्तों के अनुसार न चलकर उसके साथ किसी दूसरी तरह ब्योहार करे.

मातहत अदालतों पर दबान

236—इस खंड में—

अर्थ

(ए) “जिला जज” शब्दों में नगर दीवानी अदालत का जज, अधिक जिला जज, संगी जिला जज, सहायक

ज़िला जज, खफ़ीफ़ा अदालत का प्रमुख जज, प्रमुख प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, सहायक प्रमुख प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, अधिक सेशन जज और सहायक सेशन जज शामिल होंगे;

(बी) “न्यायी नौकरी” शब्दों के मानी हैं वह नौकरी जिसमें केवल वही लोग होंगे जो ज़िला जज की जगह और ज़िला जज की जगह से नीचे की दूसरी शिवाजी न्यायी जगहों को भरने के लिये हैं.

इस खंड के बन्धानों का मजिस्ट्रेटों की किसी खास जमात या जमातों पर लागू होना

237—रियासतपति आम नोटिस निकाल कर यह निर्देश कर सकता है कि, उस नोटिस में बताए हुए अपवादों और अदल बदल के अधीन रहते हुए, इस खंड के ऊपर लिखे बन्धान और उनके अधीन बने नियम, उस तारीख से जो वह इस काम के लिये तय करे, उस रियासत में मजिस्ट्रेटों की किसी जमात या जमातों पर उसी तरह लागू होंगे जिस तरह वे उस रियासत की न्यायी नौकरी में नियोजित हुए लोगों के संबंध में लागू होते हैं.

भाग सात

पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतें

238—भाग छे के बन्धान पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज रियासतों के संबंध में उसी तरह लागू होंगे जिस तरह वे उस पट्टी के भाग (ए) में दर्ज रियासतों के संबंध में लागू होते हैं, पर नीचे लिखे अदल बदल और छूटों का ध्यान रखते हुए लागू होंगे, यानी :—

पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों पर भाग छे के बन्धानों का लागू होना

(1) भाग छे में जहाँ कहीं “रियासतपति” शब्द आया है उसकी जगह, सिवाय जब वह दफा 232 की धारा (बी) में दूसरी बार आया है, “राजप्रमुख” शब्द रख दिया जायगा.

(2) दफा 152 में “भाग (ए)” इस शब्द और अक्षर की जगह “भाग (बी)” यह शब्द और अक्षर रखे जायंगे.

(3) दफा 155, 156 और 157 छोड़ दिये जायंगे.

(4) दफा 158 में—

(एक) धारा (1) में “नियोजा जाय” शब्दों की जगह “हो जाय” शब्द रख दिये जायंगे;

(दो) धारा (3) की जगह नीचे लिखी धारा रख दी जायगी, यानी :—

“(3) राजप्रमुख, जबतक कि रियासत की सरकार की खास जगह में उसका अपना रहने का मकान न हो, बिना किराया दिये सरकारी मकान को काम में लाने का हकदार होगा और वह उन भत्तों और निजनियमों का भी हकदार होगा जो राजपति आम या खास हुकुम देकर तय करदे.”;

(तीन) धारा (4) में “वेतन और” शब्द छोड़ दिये जायंगे.

(5) दफा 159 में “बड़े से बड़े जज के सामने जो मिल सके” शब्दों के बाद “या ऐसे दूसरे ढंग से जो राजपति इस काम के लिये तय करदे” शब्द जोड़ दिये जायंगे.

(6) दफा 164 में धारा (1) की शर्त की जगह नीचे लिखी शर्त रख दी जायगी, यानी :—

“शर्तें कि मध्यभारत की रियासत में एक वज्जीर ऐसा होगा जिसको क़बीलों की भलाई का काम सौंपा जायगा और जिसको इसके अलावा पट्टी दर्ज जातियों और पिछड़ी जमातों की भलाई का काम या कोई और दूसरा काम भी सौंपा जा सकता है।”

(7) दफ़ा 168 में धारा (1) की जगह नीचे लिखी धारा रखी जायगी, यानी :—

“(1) हर रियासत की एक क़ानून सभा होगी जिसमें राजप्रमुख होगा, और जिस में—

(ए) मैसूर की रियासत में दो सदन होंगे;

(बी) दूसरी रियासतों में एक एक सदन होगा।”

(8) दफ़ा 186 में “जो दूसरी पट्टी में दर्ज है” शब्दों की जगह “जो राजप्रमुख तय कर दे” शब्द रख दिये जायंगे।

(9) दफ़ा 195 में “जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी सूबे के आम सदन (लेजिस्लेटिव असेम्बली) के मेम्बरों के लिये लागू थीं” शब्दों की जगह “जो राजप्रमुख तय कर दे” शब्द रख दिये जायंगे।

(10) दफ़ा 202 की धारा (3) में—

(एक) उप-धारा (ए) की जगह नीचे लिखी उप-धारा रख दी जायगी, यानी :—

“(ए) राजप्रमुख के भत्ते और उसके पद संबंधी दूसरे खर्च जो राजपति आम या खास हुकुम देकर तय करदे;”

(दो) उपधारा (एक) की जगह नीचे लिखी उप धाराएं रखी जायंगी, यानी :—

“(एक) द्रावनकोर-कोचीन रियासत की सूरत में इक्यावन लाख रुपए की वह रक़म, जो इस विधान के आरम्भ होने से पहले द्रावनकोर कोचीन की मिली हुई रियासत बनाने के लिये, द्रावनकोर और कोचीन की देखी रियासतों के शासकों ने जो मुआहिदा किया था उसके अधीन हर साल देव-स्वोम कोश को दी जायगी;

(जी) कोई दूसरा खर्च जिसे यह विधान या रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर ऐसा खर्च ठहरा दे।”

(11) दफा 208 में धारा (2) की जगह नीचे लिखी धारा रख दी जायगी, यानी :—

“(2) जब तक धारा (1) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते तबतक दस्तूर के वह नियम और वह क़ायमी हुकुम जो इस विधान के आरंभ होने से ठीक पहले उस रियासत की क़ानून सभा के बारे में लागू थे, या जहाँ रियासत की क़ानून सभा का कोई सदन नहीं था, वहाँ दस्तूर के वह नियम और वह क़ायमी हुकुम जो इस विधान के आरंभ होने से ठीक पहले उस सूबे के आमसदन (लेजिस्लेटिव एसेम्बली) के बारे में लागू थे जिसे उस रियासत का राजप्रमुख इस काम के लिये तय करदे, उस रियासत की क़ानून सभा के संबंध में ऐसे अदल बदल और अनुकूलन के अधीन जो आम सदन का सभामुख या खास सदन का मसनदी, जैसी सूरत हो, उनमें करदे, असर रखेंगे”

(12) दफा 214 की धारा (2) में “सूबे” शब्द की जगह “देसी रियासत” शब्द रख दिये जायंगे.

(13) दफा 221 की जगह नीचे लिखी दफा रखदी जायगी, यानी :—

“221—(1) हर हाईकोर्ट के जजों को वह तनखाहें दी जायंगी जो राजपति राजप्रमुख से सलाह करके तय कर दे.

जजों की तनखाहें
वगैरा

(2) हर जज उन भत्तों का और छुट्टी और पेनशन के बारे में उन अधिकारों का हक़दार होगा जो समय समय पर राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन तय किये जायं, और जब तक वह इस तरह तय नहीं किये जाते तब तक उन भत्तों और अधिकारों का हक़दार होगा जो राजपति राजप्रमुख से सलाह कर के तय करदे:

शर्तें कि किसी जज के भत्तों में या छुट्टी या पेनशन के बारे में उसके अधिकारों में उसके नियोजन के बाद इस तरह की कोई अदल बदल नहीं की जायगी जिससे वह घाटे में रहे.”

भाग आठ

पहली पट्टी के भाग (सी) की रियासतें

पहली पट्टी के भाग
(सी) की रियासतों
का शासन

239—(1) इस भाग के और बन्धानों के अधीन रहते हुए पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज हर रियासत का शासन राजपति करेगा, और जिस हद तक वह ठीक समझे यह शासन वह एक चीफ कमिश्नर या नायब रियासतपति की मारफत करेगा जिसे वह खुद नियोजेगा या किसी पड़ोसी रियासत की सरकार के मारफत करेगा :

शर्तें कि राजपति किसी पड़ोसी रियासत की सरकार को मारफत उस समय तक यह काम नहीं करेगा जब तक कि—

(ए) उसने उस सरकार से सलाह न कर ली हो; और

(बी) जिस रियासत पर इस तरह शासन करना है वहाँ के लोगों के विचार राजपति ने ऐसे ढंग से मालूम न कर लिये हों जिसे वह सब से अधिक मुनासिब समझे.

(2) इस दफ्ता में किसी रियासत की चरचा में उस रियासत के किसी भाग की चरचा भी शामिल है.

मुकामी क़ानून
सभाओं या सलाह-
कार मंडल या
बज़ीर मंडल का
बनाना या जारी
रखना

240—(1) पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज किसी ऐसी रियासत के लिये जिसका शासन चीफ कमिश्नर या नायब रियासतपति की मारफत होता हो, राजपंचायत क़ानून बना कर—

(ए) एक संस्था, चाहे नामज़द की हुई चाहे चुनी हुई, चाहे कुछ नामज़द की हुई और कुछ चुनी हुई, उस रियासत की क़ानून सभा का काम करने के लिये; या

(बी) सलाहकार मंडल या बज़ीर मंडल,

या दोनों बना सकती है या जारी रख सकती है जिनकी बनावट, शक्तियाँ और काम हर सूरत में वह होंगे जो उस क़ानून में बता दिए गए हों.

(2) धारा (1) में जिस किसी क़ानून की चरचा की गई है उसको दफ्ता 368 के मतलबों के लिये इस विधान का सुधार

नहीं समझा जायगा, भले ही उसमें कोई ऐसा बन्धान हो जो विधान में सुधार करता है या सुधार करने का असर रखता है।

241—(1) राजपंचायत, कानून बनाकर, पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज किसी रियासत के लिये एक हाईकोर्ट बना सकती है, या उस रियासत की किसी अदालत को इस विधान के सब मतलबों या उनमें के किसी मतलब के लिये हाईकोर्ट ठहरा सकती है।

पहली पट्टी के भाग (सी) की रियासतों के लिये हाईकोर्टें

(2) भाग छै के खंड पांच के बन्धान हर उस हाईकोर्ट के संबंध में जिसकी चरचा धारा (1) में की गई है उसी तरह लागू होंगे जिस तरह वह उस हाईकोर्ट के संबंध में लागू होते हैं जिसकी चरचा दफा 214 में की गई है, पर ऐसी अदल बदल और ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए जिनका राजपंचायत कानून बनाकर बन्धान कर दे।

(3) इस विधान के बन्धानों और मुनासिब कानून सभा के किसी ऐसे कानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए जो उन शक्तियों की रू से बनाया गया हो जो इस विधान में या इसके अधीन उस कानून सभा को दी गई हों, जिस किसी हाईकोर्ट की अमलदारी पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज किसी रियासत के या उसमें शामिल किसी क्षेत्र के संबंध में इस विधान के आरंभ से ठीक पहले चलती थी उस हाईकोर्ट की वह अमलदारी उस रियासत या उस क्षेत्र के संबंध में विधान के आरंभ के बाद भी चलती रहेगी।

(4) इस दफा की किसी भी बात से राजपंचायत की वह शक्ति कम नहीं होती जो उसे पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की किसी हाईकोर्ट की अमलदारी को उस पट्टी के भाग (सी) में दर्ज किसी रियासत तक या उस रियासत में शामिल किसी क्षेत्र तक बढ़ा देने की या उससे अलग कर देने की हासिल है।

242—(1) जब तक राजपंचायत कानून बना कर दूसरा बन्धान कुर्ग नहीं करती तब तक कुर्ग के खास सदन की बनावट, उसकी शक्तियाँ और उसके काम वही होंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले थे।

कुर्ग में जो मालगुजारी जमा की जाय उसके बारे में

प्रबन्ध और कुर्ग के सम्बन्ध में खर्च बिना बदले जारी रखे जायेंगे जब तक कि राजपति इस काम के लिये हुक्म देकर कोई दूसरा बन्धान न करदे.

भाग नौ

पहली पट्टी के भाग (डी) के भूभाग और वह दूसरे भूभाग
जो उस पट्टी में दर्ज नहीं हैं

243—(1) पहली पट्टी के भाग (डी) में दर्ज हर भूभाग का शासन और हर ऐसे दूसरे भूभाग का शासन जो भारत के भूभाग में शामिल है पर पहली पट्टी में दर्ज नहीं है, राजपति करेगा, और जिस हद तक वह ठीक समझेगा यह शासन एक चीफ कमिशनर की मारफत या किसी और ऐसे अधिकारी की मारफत करेगा जिसे वह खुद नियोजेगा.

पहली पट्टी के भाग (डी) में दर्ज भूभागों का और उन दूसरे भूभागों का शासन जो उस पट्टी में दर्ज नहीं हैं.

(2) राजपति हर ऐसे भूभाग की शान्ति और वहां अच्छी हुकूमत के लिये क़ायदे बना सकता है, और जो क़ायदा इस तरह बनाया जायगा वह राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून को, या किसी ऐसे मौजूदा क़ानून को जो उस समय उस भूभाग पर लागू हो, रद्द कर सकता है या उसमें सुधार कर सकता है, और जब राजपति किसी ऐसे क़ायदे को जारी कर देगा तो उस क़ायदे का वही बल और असर होगा जो राजपंचायत के किसी ऐसे एक्ट का जो उस भूभाग पर लागू हो.

भाग दस

पट्टीदर्ज क्षेत्र और कबायली क्षेत्र

पट्टी-दर्ज क्षेत्रों
और कबायली
क्षेत्रों का शासन.

244—(1) पांचवीं पट्टी के बन्धान, आसाम की रियासत को छोड़ कर, पहली पट्टी के भाग (ए) और भाग (बी) में दर्ज हर दूसरी रियासत के पट्टी दर्ज क्षेत्रों और पट्टी-दर्ज कबीलों के शासन और उनके दबान के सम्बन्ध में लागू होंगे.

(2) छठी पट्टी के बन्धान आसाम की रियासत के कबायली क्षेत्रों के शासन के सम्बन्ध में लागू होंगे.

भाग ग्यारह

यूनियन और रियासतों के बीच सम्बन्ध

खंड एक—क्रानूनकारी सम्बन्ध

क्रानूनकारी शक्तियों का बटवारा

245—(1) इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राज-पंचायत भारत के सारे भूभाग के लिये या उसके किसी भाग के लिये क्रानून बना सकती है, और हर रियासत की क्रानून सभा उस सारी रियासत या उसके किसी भाग के लिये क्रानून बना सकती है.

राजपंचायत के बनाए और रियासतों की क्रानून सभाओं के बनाए क्रानूनों का पैलाव

(2) राजपंचायत का बनाया हुआ कोई क्रानून इस बिना पर नादुरुस्त नहीं समझा जायगा कि उस पर अमल भूभाग-परे भी होगा.

246—(1) धारा (2) और (3) में किसी बात के रहते भी, अकेले राजपंचायत को ही यह शक्ति है कि वह सातवीं पट्टी की तालिका एक में (जिसकी इस विधान में “यूनियन तालिका” कह कर चरचा की गई है) गिनाए मामलों में से किसी के बारे में क्रानून बनाए.

राजपंचायत के बनाए और रियासतों की क्रानून सभाओं के बनाए क्रानूनों का विषय

(2) धारा (3) में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत को, और धारा (1) के अधीन रहते हुए पहली पट्टी के भाग (ए) और भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की क्रानून सभा को भी यह शक्ति है कि वह सातवीं पट्टी की तीसरी तालिका में (जिसकी इस विधान में “संगचारी तालिका” कह कर चरचा की गई है) गिनाए मामलों में से किसी के बारे में क्रानून बनाए.

(3) धारा (1) और (2) के अधीन रहते हुए, पहली पट्टी के भाग (ए) और भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की क्रानून सभा को ही अकेले यह शक्ति है कि वह उस रियासत के लिये या उसके किसी भाग के लिये सातवीं पट्टी की तालिका दो में (जिसकी इस विधान में “रियासत तालिका” कह कर चरचा की गई है) गिनाए मामलों में से किसी के बारे में क्रानून बनाए.

(4) राजपंचायत को यह शक्ति है कि वह भारत के भूभाग के किसी ऐसे भाग के लिये जो पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में शामिल नहीं है, किसी मामले के बारे में कानून बनाए, भले ही वह मामला ऐसा मामला हो जो रियासत तालिका में गिनाया गया है.

कुछ अधिक अदालतों को क्रायम करने के लिये बन्धान करने की राजपंचायत को शक्ति

247—इस खंड में किसी बात के रहते भी, “यूनियन तालिका” में गिनाए किसी मामले के बारे में किसी मौजूदा कानून पर, या राजपंचायत के बनाए कानूनों पर, अधिक अच्छी तरह अमल कराने के लिये राजपंचायत कानून बनाकर कोई अधिक अदालतें क्रायम करने का बन्धान कर सकती है.

कानून बनाने की बची शक्तियाँ

248—(1) अकेले राजपंचायत को ही यह शक्ति है कि किसी ऐसे मामले के बारे में कोई कानून बनाए जो न संगचारी तालिका में गिनाया गया है न रियासत तालिका में.

(2) इस शक्ति में कोई ऐसा टैक्स लगाने के लिये कानून बनाने की शक्ति भी शामिल होगी जिसकी शरचा उन तालिकाओं में से किसी में नहीं की गई.

क्रौमी हित के लिये रियासत तालिका के किसी मामले के बारे में राजपंचायत को कानून बनाने की शक्ति

249—(1) इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, अगर रियासत सदन ने किसी ऐसे ठहराव से, जिसका उस समय मौजूद और बोट देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई ने समर्थन किया हो, यह ठहरा दिया है कि क्रौमी हित में यह जरूरी है या समयोचित है कि “रियासत तालिका” में गिनाए किसी ऐसे मामले के बारे में जिसकी उस ठहराव में शरचा की गई है राजपंचायत कानून बनाए, तो राजपंचायत के लिये यह कानून-संगत होगा कि जब तक वह ठहराव अमल में रहे राजपंचायत भारत के सारे भूभाग या उसके किसी हिस्से के लिये उस मामले के बारे में कानून बनाए.

(2) धारा (1) के अधीन पास हुआ ठहराव उतने अरसे तक अमल में रहेगा जो एक साल से अधिक न हो और जो ठहराव में बता दिया गया हो:

शर्तें कि अगर, और जितनी बार, किसी ऐसे ठहराव को अमल

में रखने की रज़ामन्दी देने वाला कोई ठहराव धारा (1) में बताए ढंग से पास हो जाय, तो वह पहला ठहराव जिस तारीख़ से इस धारा के अधीन अमल में न रहता उतनी बार उससे एक बरस के और अधिक अरसे तक अमल में रहेगा।

(3) राजपंचायत के बनाए किसी ऐसे क़ानून का, जिसे बनाने का अधिकार राजपंचायत को न होता अगर धारा (1) के अधीन ठहराव पास न हुआ होता, उस ठहराव के अमल में न रहने से छै महीने का अरसा बीत जाने पर, उस अनधिकार की हद् तक, असर न रहेगा, सिवाय उन बातों के बारे में जो इस अरसे के बीत जाने से पहले की जा चुकी हों या करने से छोड़ दी गई हों।

250—(1) इस खंड में किसी बात के रहते भी, जब कभी अचानकी का कोई ऐलान अमल में हो, तो राजपंचायत को शक्ति होगी कि वह रियासत तालिका में गिनाए मामलों में से किसी के बारे में भारत के सारे भूभाग या उसके किसी भाग के लिये क़ानून बनाए।

अचानकी का कोई ऐलान अमल में होने की सूत में रियासत तालिका के किसी भी मामले के बारे में राज-पंचायत को क़ानून बनाने की शक्ति

(2) राजपंचायत के बनाए किसी ऐसे क़ानून का, जिसे बनाने का अधिकार राजपंचायत को न होता अगर अचानकी का ऐलान जारी न हुआ होता, ऐलान के अमल में न रहने के बाद छै महीने का अरसा बीत जाने पर, उस अनधिकार की हद् तक, असर न रहेगा, सिवाय उन बातों के बारे में जो इस अरसे के बीत जाने से पहले की जा चुकी हों या करने से छोड़ दी गई हों।

251—दफ़ा 249 और 250 की कोई बात किसी रियासत की क़ानून सभा की इस शक्ति पर कोई रुकावट नहीं लगा सकेगी कि वह कोई ऐसा क़ानून बनाए जिसे इस विधान के अधीन उसको बनाने की शक्ति है, पर अगर किसी रियासत की क़ानून सभा के बनाए किसी क़ानून का कोई बंधान राजपंचायत के बनाए किसी ऐसे क़ानून के किसी बंधान के खिलाफ़ पड़ता हो, जिसे बनाने की उपर बताई हुई दोनों दफ़ाओं में से किसी के अधीन राजपंचायत को शक्ति है, तो राजपंचायत का बनाया क़ानून ही चलेगा, चाहे वह रियासत की क़ानून सभा के बनाए क़ानून से पहले बना हो और

दफ़ा 249 और 250 के अधीन राजपंचायत के बनाए क़ानूनों का रियासतों की क़ानून सभाओं के बनाए क़ानून के साथ अनमेल

चाहे पीछे, और उस खिलाफ पढ़ने की हद्द तक, पर तभी तक जब तक राजपंचायत के बनाए हुए कानून का असर जारी है, रियासत की कानून सभा का बनाया कानून अमल में नहीं रहेगा।

राजपंचायत को दो या अधिक रियासतों के लिये उनकी अनुमति से कानून बनाने की शक्ति और किसी दूसरी रियासत का ऐसे कानूनों को अपनाना

252—(1) अगर दो या अधिक रियासतों की कानून सभाओं को यह बात चाहनी मालूम हो कि राजपंचायत कानून बनाकर उन रियासतों में किसी ऐसे मामले की क्रायदाबन्दी करदे जिस मामले के बारे में उन रियासतों के लिये कानून बनाने की राजपंचायत को शक्ति नहीं है, सिवाय उस सूरत में जिसका बन्धान दफा 249 और 250 में किया गया है, और इस मतलब के ठहराव उन रियासतों की कानून सभाओं के सब सदनों में पास हो जाते हैं, तो राजपंचायत के लिये यह कानून-संगत होगा कि वह इस तरह उस मामले की क्रायदाबन्दी करने के लिये एक्ट पास कर दे, और कोई एक्ट जो इस तरह पास हो गया हो उन रियासतों में लागू होगा और किसी ऐसी दूसरी रियासत में भी लागू होगा जिस रियासत ने अपनी कानून सभा के सदन में, या जहां दो सदन हैं वहां उस रियासत की कानून सभा के हर सदन में, इस काम के लिये ठहराव पास करके उस एक्ट को बाद में अपना लिया हो।

(2) राजपंचायत के इस तरह पास किये हुए किसी एक्ट में, उसी तरह पास हुए या उसी तरह अपनाए हुए राजपंचायत के ही किसी एक्ट से, सुधार किया जा सकता है या उसे रद्द किया जा सकता है, पर जहां तक किसी ऐसी रियासत का सम्बन्ध है जिसमें वह एक्ट लागू होता है उस रियासत की कानून सभा के किसी एक्ट से न उसमें सुधार किया जा सकेगा न उसे रद्द किया जा सकेगा।

अन्तर क्रौमी सम-
झौतों पर अमल
कराने के लिये
कानून बनाना

253—इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत को शक्ति है कि वह किसी दूसरे देश या देशों के साथ किसी संधिनामे, समझौते या माने हुए रिवाज पर या किसी अन्तर-क्रौमी कानफरेंस, सभा या दूसरी संस्था के किसी फैसले पर अमल कराने के लिये भारत के सारे भूभाग या उसके किसी भाग के लिये कोई कानून बनाए।

254—(1) अगर किसी रियासत की क्रान्तन सभा के बनाए किसी क्रान्तन का कोई बन्धान राजपंचायत के बनाए किसी ऐसे क्रान्तन के किसी बन्धान के खिलाफ पड़ता है जिसे बनाने का राजपंचायत को अधिकार है, या संगचारी तालिका में गिनाए मामलों में से किसी की बावत किसी मौजूदा क्रान्तन के किसी बन्धान के खिलाफ पड़ता है, तो धारा (2) के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपंचायत का बनाया क्रान्तन ही, चाहे वह उस रियासत की क्रान्तन सभा के बनाए क्रान्तन से पहले पास हुआ हो या बाद में, या वह मौजूदा क्रान्तन ही, जैसी सूरत हो, चलेगा, और उस रियासत की क्रान्तन सभा का बनाया क्रान्तन, खिलाफ पड़ने की हद तक, रह होगा।

राजपंचायत के बनाए क्रान्तनों और रियासतों की क्रान्तन सभाओं के बनाए क्रान्तनों में अनमेल

(2) जहां संगचारी तालिका में गिनाए किसी मामले के बारे में पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की क्रान्तन सभा के बनाए किसी क्रान्तन में कोई ऐसा बन्धान है जो पहले से बने हुए राजपंचायत के किसी क्रान्तन के बन्धानों के या उस मामले के बारे में किसी मौजूदा क्रान्तन के बन्धानों के खिलाफ पड़ता है, तो उस रियासत में उस रियासत की क्रान्तन सभा का इस तरह बनाया हुआ क्रान्तन ही चलेगा, अगर उसे राजपति के सोच विचार के लिये रखा गया हो और राजपति ने उस पर अपनी मंजूरी दे दी हो :

शर्तें कि इस धारा की कोई बात राजपंचायत को किसी समय भी, उसी मामले के बारे में कोई क्रान्तन बनाने से नहीं रोकेगी, इसमें कोई ऐसा क्रान्तन भी शामिल होगा जो उस रियासत की क्रान्तन सभा के इस तरह बनाए क्रान्तन में कुछ जोड़े, उसमें सुधार करे, उसका रूप बदल दे या उसे रह कर दे.

255—राजपंचायत का या पहली पट्टी के भाग (ए) और भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की क्रान्तन सभा का कोई एकट, और ऐसे किसी एकट का कोई बन्धान, केवल इसी कारन नादुरुस्त नहीं होगा कि कोई ऐसी सिफारिश या पहले से मंजूरी जो इस विधान के अनुसार दरकार थी उस एकट को नहीं मिली थी, अगर—

सिफारिशों के और पहले से मंजूरीयां लेने के दरकार होने को सिर्फ दस्तूरी मामला सम्भवा जायगा

(ए) जहाँ रियासतपति की सिफारिश दरकार थी, वहाँ

रियासतपति ने या राजपति ने,
 (बी) जहाँ राजप्रमुख की सिफारिश दरकार थी, वहाँ
 राजप्रमुख ने या राजपति ने,
 (सी) जहाँ राजपति की सिफारिश या पहले से मंजूरी
 दरकार थी वहाँ राजपति ने,
 उस ऐक्ट पर अपनी रजामन्दी दे दी हो।

खंड दो

शासनी संबंध

आम

रियासतों की और
 यूनियन की ज़िम्मे-
 दारी

256—हर रियासत की काजकारी शक्ति से इस तरह काम लिया जायगा जिससे राजपंचायत के बनाए हुए क़ानूनों और उस रियासत में लागू मौजूदा क़ानूनों पर अमल होने का भरोसा रहे, और यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में किसी भी रियासत को इस तरह के निर्देश देना शामिल होगा जो भारत सरकार को इस मतलब के लिये ज़रूरी मालूम हों।

कुछ सूत्रों में
 यूनियन का रिया-
 सतों पर दबान

257—(1) हर रियासत की काजकारी शक्ति से इस तरह काम लिया जायगा जिससे यूनियन की काजकारी शक्ति से काम लेने में रुकावट न पड़े, न उसे नुकसान पहुँचे, और यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में किसी रियासत को इस तरह के निर्देश देना भी शामिल होगा जो भारत सरकार को इस मतलब के लिये ज़रूरी मालूम हों।

(2) यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में किसी रियासत को इस तरह के निर्देश देना भी शामिल होगा जो आवा-जार्ई के उन साधनों को बनाने और बनाए रखने के सम्बन्ध में दिये गए हों जिन्हें उस निर्देश में क़ौमी या क़ौजी महत्व का ठहरावा गया हो :

शर्तें कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह राजपंचायत की इस शक्ति पर कि राजपंचायत किन्हीं थल मार्गों या जल मार्गों को क़ौमी थल मार्ग या क़ौमी जल मार्ग ठहरा दे कोई रुकावट लगाती है, या जिन थल मार्गों या जल मार्गों के

सम्बन्ध में ऐसा ठहरा दिया गया है उनके बारे में यूनियन की शक्ति पर कोई रुकावट लगाती है, या यूनियन की इस शक्ति पर कोई रुकावट लगाती है कि यूनियन आवा-जाई के साधनों को समन्दरी, जमीनी और हवाई फौजों की इमारतों के संबंध में अपने कामों का एक भाग समझ कर बनाए और बनाए रखे.

(3) यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में किसी रियासत को ऐसे निर्देश देना भी शामिल होगा कि रियासत के अन्दर रेल मार्गों की रक्षा के लिये क्या क्या तरकीबों की जायं.

(4) जहाँ धारा (2) के अधीन आवा-जाई के किन्हीं साधनों को बनाने या बनाए रखने के संबंध में, या धारा (3) के अधीन किसी रेल मार्ग की रक्षा करने के लिये जो तरकीबों की जानेवाली हैं उनके संबंध में किसी रियासत को दिये हुए किसी निर्देश पर अमल करने में उससे ज्यादा खर्च हो गया हो, जो ऐसा निर्देश न दिये जाने की सूरत में रियासत के अपने मामूली फरज पूरे करने में होता, तो भारत सरकार उस रियासत को वह रकम देगी जिस पर दोनों राजी हो जायं, या अगर राजी न हो सकें तो वह रकम देगी जो भारत के सर जज का नियोजा हुआ कोई पंच रियासत के उस अधिक खर्च के बारे में तय कर दे.

258—(1) इस विधान में किसी बात के रहते भी, राजपति, किसी रियासत की सरकार की राजामन्दी से, उस सरकार को या उसके अफसरों को, कुछ शर्तों के साथ या बिना शर्त, किसी ऐसे मामले के संबंध में काम सौंप सकता है जो मामला यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में शामिल है.

कुछ शर्तों में रियासतों को शक्तियां बगैरा देने की यूनियन को शक्ति

(2) राजपंचायत का बनाया हुआ कोई कानून जो किसी रियासत में लागू होता हो, इस बात के बावजूद कि उसका संबंध किसी ऐसे मामले से है जिसके बारे में उस रियासत की कानून सभा को कानून बनाने की शक्ति नहीं है, उस रियासत को या उसके अफसरों और अधिकारियों को कोई शक्तियां दे सकता है, और उन पर कोई फरज लगा सकता है, या किसी दूसरे को उन्हें शक्तियां देने और उन पर फरज लगाने का अधिकार दे सकता है.

(3) जहां इस दफा की रू से किसी रियासत को या उसके अफसरों या उसके अधिकारियों को कोई शक्तियां दी गई हों और उन पर कोई फरज लगाए गए हों, वहां उन शक्तियों और फरजों से काम लेने के संबंध में रियासत के शासन पर रियासत का जो कुछ अधिक खर्च होगा उसके बारे में भारत सरकार उस रियासत को वह रकम देगी जिस पर दोनों राजी हो जायं या अगर राजी न हो सकें तो वह रकम देगी जो भारत के सरजज का नियोजा हुआ कोई पंच तय कर दे.

पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों में हथियारबन्द फौजों

259—(1) इस विधान में किसी बात के रहते भी, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत में अगर इस विधान के आरंभ से ठीक पहले कोई हथियार बन्द फौजें थीं तो विधान के आरंभ के बाद, जब तक राजपंचायत कानून बनाकर कुछ और बन्धान न करे तब तक, वह रियासत उन फौजों को रख सकेगी, पर उन आम या खास हुकुमों के अधीन जो राजपति समय समय पर इस काम के लिये जारी करे.

(2) धारा (1) में जिन हथियारबन्द फौजों की चरचा की गई है वह सब यूनियन की हथियारबन्द फौजों का भाग होंगी.

भारत के बाहर भूभागों के संबंध में यूनियन की अमलदारी

260—भारत सरकार किसी ऐसे भूभाग की सरकार से सम-झौता करके जो भारत के भूभाग का हिस्सा नहीं है कोई ऐसे काजकारी, कानूनकारी या न्यायकारी काम अपने हाथ में ले सकती है जो उस भूभाग की सरकार को मिले हुए हैं, पर हर ऐसा समझौता उस कानून का ध्यान रखते हुए और उस के अधीन होगा जो विदेशी अमलदारी से काम लेने के संबंध में उस समय अमल में हो.

सरकारी काम, लेखे और अदालती कारवाइयां

261—(1) भारत के सारे भूभाग में यूनियन के और हर रियासत के सरकारी कामों, लेखाओं और अदालती कारवाइयों पर पूरा भरोसा किया जायगा और उनकी पूरी साख होगी.

(2) धारा (1) में जिन कामों, लेखाओं और कारवाइयों की चरचा की गई है, उनको जिस ढंग से और जिन शर्तों के अधीन साबित किया जायगा और उनका असर तय किया जायगा वह ऐसी होंगी जिनका बन्धान राजपंचायत के बनाए कानून में किया गया हो.

(3) भारत के भूभाग के किसी हिस्से में दीवानी अदालतों ने जो आखिरी फैसले सुनाए हों या हुकुम दिये हों उन पर कानून के अनुसार उस भूभाग में कहीं भी अमल कराया जा सकेगा।

पानी के संबंध में झगड़े

262—(1) राजपंचायत कानून बनाकर किसी ऐसे झगड़े या शिकायत के अदालती-फैसले के लिये बन्धान कर सकती है जिसका संबंध किसी अन्तर-रियासती नदी या नदी की घाटी के पानी के इस्तेमाल, बटवारे या दबान से हो।

अन्तर - रियासती नदियों या उनकी घाटियों के पानी के संबंध में झगड़ों का अदालती फैसला

(2) इस विधान में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत कानून बनाकर यह बन्धान कर सकती है कि किसी ऐसे झगड़े या शिकायत के बारे में जिसकी चरचा धारा (1) में की गई है, न आला अदालत की अमलदारी चलेगी न किसी दूसरी अदालत की।

रियासतों के बीच तालमेल

263—अगर किसी समय राजपति को यह मालूम हो कि एक ऐसा मंडल कायम करने से जनता का हित होगा जिसको यह फरज सौंपा जाय कि वह—

अन्तर-रियासती मंडल के बारे में बन्धान

(ए) रियासतों के बीच जो झगड़े खड़े हो गए हों उनकी पूछताछ करे और उन पर सलाह दे;

(बी) उन मामलों की जांच करे और उन पर बहस करे जिनमें कुछ या सब रियासतों का, या यूनियन और एक या अधिक रियासतों का मिला जुला हित हो; या

(सी) ऐसे किसी भी मामले पर सिफारिशें करे, और खास कर उस मामले के बारे में नीति और अमल का अधिक अच्छा तालमेल पैदा करने के लिये सिफारिशें करे,

तो राजपति के लिये यह कानून-संगत होगा कि वह हुकुम देकर एक ऐसा मंडल कायम करदे, और उस मंडल को जिस तरह के कर्तव्य पूरे करने हैं उन्हें और मंडल के संगठन और दस्तूर को तब कर दे।

भाग बारह

माल, जायदाद, ठेके और नालिशें

खंड एक—माल

आम

अर्थ

264—इस भाग में जब तक प्रसंग से कुछ और दरकार न हो—

(ए) “माल कमीशन” के मानी हैं वह माल कमीशन जो दफा 280 के अधीन बनाया गया हो;

(बी) “रियासत” में वह रियासत शामिल नहीं है जो पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज हो;

(सी) पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज रियासतों की चरचा में हर उस भूभाग की चरचा भी शामिल होगी जो पहली पट्टी के भाग (डी) में दर्ज हो, और किसी दूसरे ऐसे भूभाग की चरचा भी शामिल होगी जो भारत के भूभाग में शामिल है पर उस पट्टी में दर्ज नहीं है.

क़ानून के अधिकार सिवा टक्स नहीं लगाए जायेंगे

265—क़ानून के अधिकार बिना न कोई टैक्स लगाया जायगा और न जमा किया जायगा.

भारत के और रियासतों के मूठकोश और सरकारी हिसाब

266—(1) दफा 267 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, और कुछ टैक्सों और महसूलों की असल वसूली के कुल या कुछ भाग को रियासतों के नाम करने के बारे में इस खंड के बन्धानों के अधीन रहते हुए, कुल मालगुजारी जो भारत सरकार को मिले, कुल उधारियां जो भारत सरकार सरकारी ढुंडियां जारी करके ले, उधारियां या राहरीत पेशगियां, और वह सब रकमों जो उस सरकार को उधारियों की अदायगी में मिलें, इन सबका मिलकर एक मूठकोश बनेगा जो “भारत का मूठकोश” कहलायगा, और कुल मालगुजारी जो किसी रियासत की सरकार को मिले, कुल उधारियां जो वह सरकार सरकारी ढुंडियां जारी करके ले, उधारियां या राहरीत पेशगियां, और वह सब रकमों जो उस सरकार को उधारियों की अदायगी में मिलें

इन सबका मिलकर एक मूठकोश बनेगा जो “उस रियासत का मूठ-कोश” कहलायगा।

(2) और सब सरकारी रकमों जो भारत सरकार या किसी रियासत की सरकार को मिलें, या जो उनके नाम से मिलें वह भारत के सरकारी हिसाब में या उस रियासत के सरकारी हिसाब में, जैसी सूरत हो, जमा की जायंगी।

(3) भारत के मूठकोश में से या किसी रियासत के मूठ-कोश में से कोई रकमों खर्च की मदों में नहीं डाली जायंगी सिवाय कानून के अनुसार, और उन मतलबों के लिये, और उस ढंग से जिसका बन्धान इस विधान में किया गया है।

267—(1) राजपंचायत कानून बनाकर पेश-नगदी जैसा एक जोगाजोग कोश कायम कर सकती है जो “भारत का जोगाजोग कोश” कहलायगा, जिसमें समय समय पर वह रकमों जमा की जायंगी जो उस कानून में तय कर दी जायं, और यह कोश राजपति के हाथ में रख दिया जायगा जिससे कि वह तब तक अनसूमे खर्च चलाने के लिये उस कोश में से रुपया पेशगी दे सके जब तक राजपंचायत दफा 115 या 116 के अधीन कानून बनाकर उस खर्च का अधिकार न दे दे।

(2) रियासत की कानून सभा कानून बनाकर पेश-नगदी जैसा एक जोगाजोग कोश कायम कर सकती है जो उस “रियासत का जोगाजोग कोश” कहलायगा, जिसमें समय समय पर वह रकमों जमा की जायंगी जो उस कानून में तय कर दी जायं, और यह कोश उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के हाथ में रख दिया जायगा जिससे कि वह तब तक अनसूमे खर्च चलाने के लिये उस कोश में से रुपया पेशगी दे सके जब तक रियासत की कानून सभा दफा 205 या 206 के अधीन कानून बनाकर उस खर्च का अधिकार न दे दे।

यूनियन और रियासतों के बीच मालगुजारी का बटवारा

268—(1) वह स्टाम्प के महसूल और द्वाइयों और सिंगार के सामान पर वह निकासनी महसूल जो यूनियन तालिका में दिये हुए वह महसूल जिन्हें यूनियन लगाए पर

जिनमें रियासतें हैं भारत सरकार लगायगी, पर—

जमा करें और
खर्चों की मदों में
हालें

(ए) उस सूची में जहां यह महसूल किसी ऐसी रियासत में लगने हैं जो पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज है, उन्हें भारत सरकार जमा करेगी, और

(बी) दूसरी सूची में जिन जिन रियासतों में वह महसूल लगने हैं वह वह रियासतें जमा करेंगी.

(2) किसी माली साल में जो वसूली किसी ऐसे महसूल से हो जो किसी रियासत के अन्दर लगना है, वह भारत के मूठकोश का भाग नहीं होगी, बल्कि उसी रियासत के नाम कर दी जायगी,

वह टैक्स जो
यूनिथन लगाए
और जमा करे पर
जो रियासतों के
नाम कर दिये
जायें

269—(1) नीचे लिखे हुए महसूल और टैक्स भारत सरकार लगायगी और जमा करेगी, पर धारा (2) में बताए ढंग पर उन्हें रियासतों के नाम कर दिया जायगा, यानी:—

(ए) खेतीबाड़ी की जमीन को छोड़कर दूसरी जायदाद की विरासत के बारे में महसूल;

(बी) खेती बाड़ी की जमीन को छोड़कर दूसरी जायदाद के बारे में मिलकियत महसूल;

(सी) रेल मार्ग, समन्दर या हवा से जाने वाले माल या सवारियों पर हदवारी टैक्स;

(डी) रेल मार्ग की सवारियों के किरायों और माल के भाड़े पर टैक्स;

(ई) शेरार बाजारों और पेश बाजारों के सौदों पर स्टाम्प महसूल को छोड़कर दूसरे टैक्स;

(एफ) अखबारों की बिकरी या खरीद पर और उनमें निकलने वाले जाहिरात पर टैक्स.

(2) किसी माली साल में ऐसे किसी महसूल या टैक्स की असल वसूली, सिवाय जहाँ तक कि वह वसूली ऐसी वसूली हो जो पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज रियासतों के हिस्से में वसूल हुई हो, भारत के मूठकोश का भाग नहीं होगी, बल्कि उन रियासतों के नाम कर दी जायगी जिनके अन्दर वह महसूल या टैक्स उस साल

में लगाना हो, और उन रियासतों के बीच बटवारे के उन सिद्धांतों के अनुसार बांटी जायगी जिनको राजपंचायत क्रानून बनाकर रूप दे दे.

270—(1) खेती बाड़ी की आमदनी को छोड़कर दूसरी आमदनी पर टैक्स भारत सरकार लगायगी और वही जमा करेगी, और उन्हें यूनियन और रियासतों के बीच उस ढंग से बांटा जायगा जिसका बन्धान धारा (2) में किया गया है.

वह टैक्स जो न लगाए और जमा करे और जो यूनियन और रियासतों के बीच बांटे जायं

(2) किसी माली साल में ऐसे किसी टैक्स की असल वसूली का वह फ्री सैकड़ा जो बता दिया जाय, सिवाय जिस हद तक कि वह वसूली ऐसी वसूली हो जो पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज रियासतों के हिसाब में वसूल हुई हो, या उन टैक्सों के हिसाब में वसूल हुई हो जो यूनियन वेतनों के बारे में दिये जाने हों, भारत के मूठकोश का भाग नहीं होगा, बल्कि उन रियासतों के नाम कर दिया जायगा जिनके अन्दर उस साल वह टैक्स लगाना है, और उसको उन रियासतों के बीच उस ढंग से और उस समय से बांटा जायगा जो बता दिया जाय.

(3) धारा (2) के मतलबों के लिये हर माली साल में आमदनी पर टैक्सों से जो असल वसूली हो उस में से, उस भाग को छोड़ कर जो यूनियन वेतनों के बारे में दिये जाने वाले टैक्सों की असल वसूली है, बाक़ी का वह फ्री सैकड़ा जो बता दिया जाय, वह वसूली समझा जायगा जो पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज रियासतों के हिसाब में वसूल हुई है.

(4) इस दफ़ा में—

(ए) “आमदनी पर टैक्सों” में एकतनी टैक्स शामिल नहीं है;

(बी) “बता दिया जाय” के मानी हैं—

(एक) जब तक कोई माल कमीशन न बनाया जाय, तबतक जो कुछ राजपति हुकुम देकर बता दे, और

(दो) माल कमीशन बनाए जाने और माल कमीशन की सिफ़ारिशों पर बिचार करने के बाद राजपति अपने हुकुम से जो बता दे;

(सी) “यूनियन वेतनों” में भारत के मूठकोश में से दिये जाने वाले वह सब वेतन और पेनशन शामिल हैं जिनके ऊपर आमदनी टैक्स लिया जा सकता है.

कुछ महसूलों और टैक्सों पर यूनियन के मतलबों के लिये अधिक-टैक्स

271—दफा 269 और 270 में किसी बात के रहते भी, राज-पंचायत किसी समय भी उन दफाओं में जिन महसूलों या टैक्सों की चरचा की गई है उनमें से किसी को यूनियन के मतलबों के लिये अधिक-टैक्स लगाकर बढ़ा सकती है, और ऐसे हर अधिक-टैक्स की कुल वसूली भारत के मूठकोश का भाग होगी.

वह टैक्स जो यूनियन लगाती है और जमा करती है और जो यूनियन और रियासतों के बीच बांटे जा सकते हैं

272—यूनियन तालिका में बताए हुए द्वाइयों और खिगार के सामान पर निकासनी महसूलों को छोड़कर, यूनियन के दूसरे निकासनी महसूल भारत सरकार लगायगी और जमा करेगी, लेकिन अगर राजपंचायत कानून बनाकर बन्धान कर दे तो भारत के मूठकोश में से उन रियासतों को जो उस महसूल को लगाने वाले कानून के फैलाव में आ जाती हैं, उस महसूल की असल वसूली के कुल या कुछ भाग के बराबर रकमों दी जायंगी, और वह रकमों उन रियासतों में बटवारे के उन सिद्धान्तों के अनुसार बांटी जायंगी जिनको उस कानून में रूप दे दिया जाय.

पटसन और पटसन से बनी चीजों पर निकासी-महसूल के बदले में देनगियों

273—(1) आसाम, बिहार, उड़ीसा और पच्छिम बंगाल की रियासतों के नाम, पटसन या पटसन की बनी चीजों पर निकासी-महसूल की हर बरस की असल वसूली का कोई हिस्सा कर देने के बदले में उन रियासतों की मालगुजारी की सहायती देनगियों के रूप में उन्हें वह रकमों हर बरस दी जायंगी जो बता दी जाय, और वह रकमों भारत के मूठकोश के खाते में पड़ेंगी.

(2) जो रकमों इस तरह बता दी जाय वह तब तक भारत के मूठकोश के खाते में पड़ती रहेंगी जब तक पटसन या पटसन की बनी चीजों पर भारत सरकार कोई निकासी महसूल लगाती रहे या जब तक इस विधान के आरंभ होने के बाद इस बरस न बीत जाय, जो भी इनमें से पहले हो.

(3) इस दफा में “बता दी जाय” शब्दों के बड़ी मानी हैं जो दफा 270 में.

274—(1) कोई ऐसा बिल या सुधार, जो कोई ऐसा टैक्स या महसूल लगाता है या उसमें अदल बदल करता है जिसमें रियासतों का हित है, या जो “खेती-बाड़ी की आमदनी” शब्दों के मानी में, जैसी उसको परिभाषा भारत आमदनी टैक्स संबंधी कानूनों के मतलबों के लिये की गई है, अदल बदल करता है, या जिसका असर उन सिद्धान्तों पर पड़ता है जिनके अनुसार इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में से किसी के अधीन रियासतों में रकम बांटी जाती है या बांटी जा सकती है, या जो यूनियन के मतलबों के लिये ऐसा कोई अधिक-टैक्स लगाता है जो इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में बताया गया है, राजपति की सिफारिश के सिवाय राजपंचायत के किसी सदन में न रखा जायगा न पेश किया जायगा।

जिन टैक्सों में रियासतों का हित हो उन पर असर डालने वाले बिलों पर राजपति को पहले से सिफारिश दरकार

(2) इस दफा में “टैक्स या महसूल जिसमें रियासतों का हित है” शब्दों के मानी हैं—

(ए) कोई टैक्स या महसूल जिसकी असल वसूली का कुल या कुछ भाग किसी रियासत के नाम कर दिया गया हो; या

(बी) कोई टैक्स या महसूल जिसकी असल वसूली का हवाला देकर उस समय भारत के मूठकोश में से रकम किसी रियासत को दी जानी हो।

275—(1) हर साल वह रकम जिनका राजपंचायत कानून बनाकर बंधान करे और जो उन रियासतों को उनकी मालगुजारी की सहायती देनगियों के रूप में दी जायगी, जिनके संबंध में राजपंचायत यह तय करे कि उनको मदद की जरूरत है, भारत के मूठकोश के खाते में पड़ेंगी, और अलग अलग रियासतों के लिये अलग अलग रकम तय की जा सकती हैं :

यूनियन की तरफ से कुछ रियासतों को देनगियां

शर्तें कि किसी रियासत को भारत के मूठकोश में से, उस रियासत की सरकारी मालगुजारी की सहायती देनगियों के रूप में, वह पूँजी और वह फिराती रकम दी जायँगी जो इस बात के लिये जरूरी हों कि वह रियासत विकास की उन योजनाओं का खर्च उठा सके जो उस रियासत ने भारत सरकार की रजामन्दी से उस रिया-

सत के पट्टीदर्ज कबीलों की भलाई के कामों को बढ़ाने के लिये या उस रियासत के पट्टीदर्ज छेत्रों के शासन-तल को रियासत के बाक़ी छेत्रों के शासन-तल तक ऊँचा ले जाने के लिये हाथ में ली हों :

और शर्तें कि आसाम को भारत के मूठकोश में से रियासत की मालगुजारी की सहायती देनगियों के रूप में, वह पूँजी की रक़मों और वह फिराती रक़मों दी जायगी जो—

(ए) छटी पट्टी के बीसवें पैरे के साथ दिये हुए नक़शे के भाग (ए) में दर्ज कबाइली छेत्रों के शासन के सम्बन्ध में, इस विधान के आरंभ से ठीक पहले दो साल तक आमदनी से खर्च जितना उथादा रहा हो उसकी औसत के बराबर हों; और

(बी) वह रियासत, भारत सरकार की रज़ामन्दो से, ऊपर कहे छेत्रों के शासन-तल को उस रियासत के बाक़ी छेत्रों के शासन-तल तक ऊँचा उठाने के लिये विकास की जो योजनाएँ हाथ में ले, उनके खर्च के बराबर हों.

(2) जब तक राजपंचायत धारा (1) के अधीन बन्धान नहीं करती तब तक उस धारा के अधीन जो शक्तियाँ राजपंचायत को दी गई हैं उन शक्तियों से राजपति हुकुम जारी करके काम ले सकेगा, और उस धारा के अधीन राजपति जो हुकुम जारी करे उसका असर राजपंचायत के इस तरह बनाए बन्धान के अधीन होगा :

शर्तें कि माल कमीशन के बनाए जाने के बाद उस माल कमीशन की सिफ़ारिशों पर विचार किये बिना राजपति इस धारा के अधीन कोई हुकुम जारी नहीं करेगा.

पेशों, न्योपारों,
रोज़गारों और
कामगारियों पर
टैक्स

276—(1) दफ़ा 248 में किसी बात के रहते भी, किसी रियासत की क़ानून सभा का कोई क़ानून जिसका संबंध उस रियासत के लाभ के लिये या उसको किसी नगरायत, ज़िला बोर्ड, मुक़ामी बोर्ड, या किसी दूसरे मुक़ामी अधिकारी के लाभ के लिये, पेशों, न्योपारों, रोज़गारों या कामगारियों के बारे में लगाए जाने वाले किन्हीं टैक्सों से है, इस बिना पर नादुरुस्त नहीं

होगा कि इसका संबंध आमदनी पर लगने वाले टैक्स से है.

(2) वह कुल रकम जो किसी एक आदमी के बारे में, पेशों, ब्योपारों, रोजगारों और कामगारियों पर टैक्सों के रूप में, उस रियासत को या इसकी किसी एक नगरायत, जिला बोर्ड, मुकामी बोर्ड, या किसी एक दूसरे मुकामी अधिकारी को दी जायगी, दो सौ पचास रुपए सालाना से अधिक न होगी :

शर्तें कि अगर इस विधान के आरंभ से ठीक पहले के माली साल में, किसी रियासत में या ऐसी किसी नगरायत, बोर्ड या अधिकारी संस्था में पेशों, ब्योपारों, रोजगारों या कामगारियों पर कोई ऐसा टैक्स जारी था, जिसकी दर, या जिसकी ज्यादा से ज्यादा दर दो सौ पचास रुपए सालाना से अधिक थी, तो वह टैक्स आगे भी तब तक लगाया जा सकेगा जब तक कि राजपंचायत कानून बना कर इसके खिलाफ बंधान न करदे, और राजपंचायत इस तरह का जो कानून बनाए वह या तो एक आम कानून हो सकता है या किन्हीं खास बताई हुई रियासतों, नगरायतों, बोर्डों या अधिकारियों के सम्बन्ध में हो सकता है.

(3) पेशों, ब्योपारों, रोजगारों और कामगारियों पर टैक्स के बारे में ऊपर बताए हुए कानून बनाने की किसी रियासत की कानून सभा को जो शक्ति है, उसका यह मतलब नहीं लिया जायगा कि वह राजपंचायत की कानून बनाने की उस शक्ति को किसी तरह सिमियाती है जो राजपंचायत को पेशों, ब्योपारों, रोजगारों और कामगारियों से होने वाली या मिलने वाली आमदनी पर टैक्स लगाने के बारे में है.

277—जो कोई टैक्स, महसूल, मुकामी टैक्स, या फीस, इस विधान के आरंभ से ठीक पहले, किसी रियासत की सरकार या कोई नगरायत या कोई दूसरा मुकामी अधिकारी या संस्था उस रियासत, नगरायत, जिले या दूसरे मुकामी क्षेत्र के मतलबों के लिये कानून के अनुसार लगाती थी, वह इस बात के रहते भी कि उन टैक्सों, महसूलों, मुकामी टैक्सों या फीसों का यूनियन ताजिका में जिक्र आया है, आगे भी लगाया जा सकेगा, और उन्हीं मतलबों के

लिये काम में लाया जा सकेगा, जब तक कि राजपंचायत कानून बना कर इसके खिलाफ कोई बन्धान न करे.

कुछ माली मामलों के संबंध में पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों से समझौता.

278—(1) इस विधान में किसी बात के रहते भी, भारत सरकार, धारा (2) के बन्धानों के अधीन रहते हुए, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की सरकार के साथ नीचे लिखी बातों के बारे में समझौता कर सकती है:—

(ए) किसी ऐसे टैक्स या महसूल का लगाना या जमा करना जो भारत सरकार उस रियासत में लगा सकती हो, और उसकी वसूली को इस खंड के बन्धानों के अनुसार न चलते हुए किसी और तरह बांटना;

(बी) भारत सरकार का ऐसी रियासत को उस रियासत की उस मालगुजारी में घाटे के कारन कोई माली मदद मंजूर करना जो मालगुजारी उस रियासत को किसी ऐसे टैक्स या महसूल से मिलती रही हो जिसे इस विधान के अधीन भारत सरकार लगा सकती है, या जो उसे किसी और जरिये से मिलती रही हो;

(सी) किसी ऐसी रकम का जो भारत सरकार दफ्ता 291 की धारा (1) के अधीन दे, वह हिस्सा जो वह रियासत देगी,

और जब इस तरह कोई समझौता हो जाय तो इस खंड के बन्धानों का असर उस रियासत के संबंध में उस समझौते की शर्तों के अधीन होगा.

(2) धारा (1) के अधीन जो समझौता किया जाय वह इस विधान के आरंभ से अधिक से अधिक दस बरस के अरसे तक अमल में रहेगा :

शर्तें कि राजपति विधान के आरंभ से पांच बरस बीत जाने के बाद किसी समय भी ऐसे किसी समझौते को खतम कर सकता है या उसमें बदल बदल कर सकता है, अगर मातृ कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद वह ऐसा करना जरूरी समझे.

279—(1) इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में किसी टैक्स या महसूल के सम्बन्ध में “असल वसूली” के मानी हैं उस टैक्स या महसूल की वसूली में से उसे जमा करने का खर्च निकाल कर जो बचे वह, और उन बंधानों के मतलबों के लिये किसी टैक्स या महसूल की, या किसी टैक्स या महसूल के किसी भाग की असल वसूली जो किसी क्षेत्र से वसूल हो या जो किसी क्षेत्र के हिसाब में वसूल हो, उसका हिसाब भारत का सरपड़तालिया और दाबअफसर लगायगा और उस हिसाब की सनद करेगा और उसकी यह सनद आखिरी होगी।

“असल वसूली” का हिसाब लगाना, वगैरा

(2) ऊपर जो कहा गया है उसके और इस खंड के किसी और साफ साफ बन्धान के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी सूरत में जिसमें किसी महसूल या टैक्स की वसूली रकम इस भाग के अधीन किसी रियासत के नाम की गई है या की जा सकती है, राजपंचायत का बनाया हुआ कोई कानून या राजपति का कोई हुकुम इस बात का बन्धान कर सकता है कि उस वसूली का हिसाब किस ढंग से किया जायगा, और उसकी कोई रकम किस समय से कब और किस ढंग से अदा की जायगी, और एक मासी साल और दूसरे मासी साल में बैठ बिठाव किस तरह होगा, ऐसा कानून या हुकुम किन्हीं और प्रसंगी या सहायक मामलों का भी बन्धान कर सकता है।

280—(1) इस विधान के आरंभ से दो साल के अन्दर माल कमीशन अन्दर, और उसके बाद हर पांचवे साल के बीत जाने पर, या उससे पहले किसी और समय जब राजपति जरूरी समझे, राजपति हुकुम जारी करके एक माल कमीशन बनायगा जिसमें एक मसनदी और चार दूसरे मेम्बर होंगे जिनको राजपति नियोजेगा।

(2) राजपंचायत कानून बनाकर तय कर सकती है कि कमीशन के मेम्बर नियोजे जाने के लिये क्या क्या जोगताएँ दरकार होंगी और मेम्बर किस ढंग पर छांटे जायंगे।

(3) कमीशन का फरज होगा कि वह राजपति से इन बातों के बारे में चिकारिशें करे —

(ए) टैक्सों की जो असल वसूली इस खंड के अधीन

यूनिशन और रियासतों के बीच बांटी जानी है या बांटी जा सकती है उसका बंटबारा और उस वसूली में से रियासतों के अलग अलग हिस्सों का तय किया जाना;

(बी) वह सिद्धान्त जिनके अधीन भारत के मूठकोश में से रियासतों की मालगुजारी की सहायती देनगियां की जायंगी;

(सी) भारत सरकार ने दफा 278 की धारा (1) के अधीन या दफा 306 के अधीन, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की सरकार के साथ जो समझौता किया हो उसकी शर्तों का जारी रखना या बदलना; और

(डी) कोई दूसरा मामला जो राजपति ने माल को पक्का रखने के हित में कमीशन को राय के लिये भेजा हो.

(4) कमीशन अपना दस्तूर तय करेगा, और उसको अपने कामों के करने में वह शक्तियां होंगी जो राजपंचायत उसे कानून बनाकर सौंपे.

माल कमीशन की
सिफारिशें

281— इस विधान के बन्धानों के अधीन माल कमीशन जो भी सिफारिश करेगा उसे राजपति, एक ऐसी बादी के साथ जिसमें यह समझाया गया होगा कि उस सिफारिश पर क्या कारवाई की गई है, राजपंचायत के हर सदन के सामने रखवायगा.

फुटकर माली बन्धान

खर्चा जो यूनिशन या कोई रियासत अपनी मालगुजारी में से कर सकती है

282— यूनिशन या कोई रियासत जनता के किसी मतलब के लिये कोई देनगी कर सकती है, भले ही वह मतलब ऐसा न हो जिसके बारे में राजपंचायत या उस रियासत की कानून सभा, जैसी सूरत हो, कानून बना सकती है.

मूठकोश, जोगा-जोग कोश और सरकारी हिसाबों में जमा हुई रकमों की रखवाली बगैरा

283—(1) भारत के मूठकोश और भारत के जोगाजोग कोश की रखवाली, उन कोशों में रकमों जमा करना, उनमें से रकमों निकालना, उन सरकारी रकमों की रखवाली जो भारत सरकार को मिली हों या जो उसके नाम से की गई हों और जो इन कोशों में जमा न की गई हों उन रकमों का भारत के सरकारी हिसाब में

जमा करना और उस हिसाब में से रकम निकालना, और दूसरे सब मामले जिन का ऊपर कहे मामलों से संबंध हो या जो उनके सहायक हों, इन सबकी क्रायदाबन्दी राजपंचायत कानून बनाकर करेगी, और जब तक इस काम के लिये इस तरह बन्धान न किया जाय तब तक उनकी क्रायदाबन्दी राजपति के बनाए नियमों से होगी।

(2) किसी रियासत के मूठकोश और उसके जोगाजोग कोश की रखवाली, उन कोशों में रकम जमा करना, उनमें से रकम निकालना, उन सरकारी रकमों की रखवाली जो रियासत की सरकार को मिली हों या उसके नाम से ली गई हों और जो इन कोशों में जमा न की गई हों, उन रकमों का रियासत के सरकारी हिसाब में जमा करना और उस हिसाब में से रकम निकालना, और दूसरे सब मामले जिनका ऊपर कहे मामलों से संबंध हो या जो उनके सहायक हों, इन सब की क्रायदाबन्दी रियासत की कानून सभा कानून बना कर करेगी, और जब तक इस काम के लिये इस तरह बन्धान न किया जाय तब तक उनकी क्रायदाबन्दी उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के बनाए नियमों से होगी।

284—वह सब रकमों जो—

(ए) यूनियन के या किसी रियासत के मामलों के संबंध में काम पर लगे हुए किसी अफसर को उसकी उस हैसियत से मिलें या जो उसके पास जमा की जायं, सिवाय उस मालगुजारी या सरकारी रकमों के जो भारत सरकार या उस रियासत की सरकार, जैसी सुरत हो, ले या उसे मिलें, या

सायलों की जमा की हुई रकमों और उन दूसरी रकमों की रखवाली जो सरकारी नौकरों और अदालतों को मिलें

(बी) भारत के भूभाग के अन्दर किसी अदालत को किसी मुकदमें, मामले, हिसाब या किन्हीं आदमियों के नाम से मिलें या जो उसके पास जमा की जायं,

भारत के सरकारी हिसाब में या उस रियासत के सरकारी हिसाब में, जैसी सुरत हो, जमा की जायंगी।

यूनियन की जायदाद का रियासती टैक्सों से बरी होना

285—(1) यूनियन की जायदाद उन सब टैक्सों से बरी होगी जो कोई रियासत या किसी रियासत के अन्दर का कोई अधिकारी लगाए, सिवाय उस हद तक जिस हद तक कि राजपंचायत कानून बनाकर कोई और बंधान कर दे.

(2) जब तक राजपंचायत कानून बनाकर कोई और बंधान न करे, तब तक धारा (1) की कोई बात किसी रियासत के अन्दर के किसी अधिकारी को इस बात से नहीं रोकेगी कि वह यूनियन की किसी जायदाद पर, कोई ऐसा टैक्स लगाए जो इस विधान के आरम्भ से ठीक पहले उस जायदाद पर लग सकता था, या यह माना जाता था कि उस पर वह टैक्स लग सकता है, जब तक कि वह टैक्स उस रियासत में लगता रहे.

माल की बिकरी या खरीद पर टैक्स लगाने के संबंध में रुकावटें

286—(1) किसी रियासत का कोई कानून माल की बिकरी या खरीद पर उस सूरत में कोई टैक्स नहीं लगायगा, न उसके लगाने का किसी को अधिकार देगा जब वह बिकरी या खरीद—

(ए) रियासत के बाहर हो; या

(बी) भारत के भूभाग में बाहर से माल की आयाती या भूभाग से बाहर माल की निकासी के संबंध में हो.

समझाव—उपधारा (ए) के मतलबों के लिये किसी बिकरी या खरीद को उस रियासत में हुआ समझा जायगा जिसमें उस बिकरी या खरीद का सीधा फल यह हो कि वह माल स्वयं के लिये उस रियासत में दे दिया जाय, भले ही माल की बिकरी से संबंध रखने वाले आम कानून के अधीन उस बिकरी या खरीद के कारन उस माल की मिलकियत किसी दूसरी रियासत में चली गई हो.

(2) सिवाय उस हद तक जिस हद तक कि राजपंचायत कानून बनाकर कोई और बन्धान करदे, किसी रियासत का कोई कानून किसी माल की बिकरी या खरीद पर कोई टैक्स नहीं लगायगा न किसी को लगाने का अधिकार देगा जहाँ वह बिकरी या खरीद अन्तर-रियासती ब्योपार या अन्तर-रियासती तिजारत के सम्बन्ध में हुई हो :

शर्तेंकि राजपति हुकुम जारी करके यह निर्देश दे सकता है कि

माल की खरीद या बिकरी पर कोई टैक्स जो इस विधान के आरम्भ से ठीक पहले किसी रियासत की सरकार कानून के अनुसार लगा रही थी मार्च सन् 1951 के इकतीसवें दिन तक लगता रहेगा, भले ही ऐसे टैक्स का लगाना इस धारा के बन्धानों के खिलाफ हो।

(3) किसी रियासत की कानून सभा का बनाया हुआ कोई कानून जो किसी ऐसे माल की बिकरी या खरीद पर कोई टैक्स लगाता है या किसी को लगाने का अधिकार देता है जिस माल को राजपंचायत ने कानून बनाकर समाज के जीवन के लिये जरूरी ठहरा दिया हो, कोई असर नहीं रखेगा जब तक कि उसे राजपति के बिचार के लिये न रखा गया हो और उसको राजपति की मंजूरी न मिल गई हो।

287—सिवाय उस हद तक जिस हद तक कि राजपंचायत कानून बनाकर कोई और बंधान कर दे, किसी रियासत का कोई कानून उस बिजली की (चाहे उसे सरकार पैदा करे या कोई दूसरे आदमी) खपत या बिकरी पर न कोई टैक्स लगायगा न किसी को लगाने का अधिकार देगा, जिसकी—

बिजली के टैक्सों से बरी होना

(ए) भारत सरकार खपत करे या जो भारत सरकार के खपाने के लिये उस सरकार को बेची जाय; या

(बी) किसी रेल मार्ग के बनाने, बनाए रखने या चलाने में भारत सरकार खपत करे, या उस रेल मार्ग को चलाने वाली कोई रेल मार्ग कम्पनी खपत करे, या जो भारत सरकार को या ऐसी किसी रेल मार्ग कम्पनी को किसी रेल मार्ग के बनाने, बनाए रखने या चलाने में खपत के लिये बेची गई हो,

और हर ऐसे कानून में जो बिजली की बिकरी पर कोई टैक्स लगाता हो या लगाने का अधिकार देता हो, इस बात का पक्का प्रबन्ध रहेगा कि भारत सरकार के खपाने के लिये भारत सरकार को जो बिजली बेची जाय, या जो बिजली ऊपर बताई हुई किसी रेल मार्ग कम्पनी को, किसी रेल मार्ग के बनाने, बनाए रखने या चलाने में खपत करने के लिये बेची जाय, उसकी कीमत, काफ़ी बिजली खपत

करने वाले दूसरे गाइकों से जो कीमत ली जाती है, उससे टैक्स की रकम घटा कर ली जायगी।

कुछ सूरतों में पानी या बिजली के बारे में रियासतों के टैक्सों से बरी होना

288—(1) सिवाय उस हद तक जिस हद तक कि राजपति हुकुम दे कर कोई और बन्धान कर दे, किसी रियासत का कोई क़ानून, जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अमल में हो, किसी ऐसे पानी या बिजली के बारे में कोई टैक्स नहीं लगायगा न लगाने का किसी को अधिकार देगा जिसे कोई ऐसी अधिकारी संस्था जमा करे, पैदा करे, खपाए, बांटे या बेचे, जो किसी मौजूदा क़ानून से या राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून से किसी अन्तर-रियासती नदी या नदी-घाटी का बिकास या क़ायदाबन्दी करने के लिये क़ायम की गई हो।

समझाव—इस धारा में “किसी रियासत का कोई क़ानून जो अमल में हो” शब्दों में किसी रियासत का वह क़ानून भी शामिल होगा जो इस विधान के आरंभ होने से पहले पास किया गया हो या बनाया गया हो और जो इससे पहले रह न कर दिया गया हो, भले ही वह कुल क़ानून या उसके कुछ भाग उस समय बिल्कुल ही या कुछ खास क्षेत्रों के अन्दर अमल में न हों।

(2) किसी रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर ऐसा कोई टैक्स जो धारा (1) में बताया गया है लगा सकती है या लगाने का अधिकार दे सकती है, पर ऐसे किसी क़ानून का कोई असर नहीं होगा जब तक कि उसको राजपति के विचार के लिये रखे जाने के बाद राजपति की मंजूरी न मिल गई हो; और अगर कोई ऐसा क़ानून ऐसे टैक्स की दूरों और दूसरी प्रसंगी बातों को, ऐसे नियमों और हुकमों से तब कराने का बन्धान करता है जिन्हें उस क़ानून के अधीन कोई अधिकारी बनाए या दे तो वह क़ानून ऐसे किसी नियम या हुकुम के बनाए जाने या दिये जाने के लिये राजपति की पहले से अनुमति लिये जाने का बन्धान करेगा।

रियासत की जाय-
दाद और आमदनी
का यूनिशन के
टैक्सों से बरी
होना

289—(1) रियासत की जायदाद और आमदनी यूनिशन के टैक्सों से बरी होगी।

(2) धारा (1) की कोई बात यूनिशन को उस हद तक,

अगर कोई ऐसी हद हो तो, किसी टैक्स के लगाने या लगाने का अधिकार देने से नहीं रोकेगी, जिस हद तक, राजपंचायत, किसी तरह के किसी ब्योपार या कारबार की बाबत, जिसे रियासत की सरकार चलाती हो या जो रियासत की सरकार के नाम से चलाया जाता हो, या उससे संबंध रखने वाले किन्हीं कामों की बाबत, या किसी ऐसी जायदाद की बाबत जिसे ऐसे ब्योपार या कारबार के मतलबों के लिये इस्तेमाल किया जाता हो, या जिस पर उन मतलबों के लिये कब्जा किया गया हो, या उसके संबंध में होने वाली या मिलने वाली किसी आमदनी की बाबत, क़ानून बनाकर कोई बन्धान कर दे.

(3) धारा (2) की कोई बात किसी ऐसे ब्योपार या कारबार पर या किसी ऐसी तरह के ब्योपारों या कारबार पर लागू नहीं होगी जिनकी बाबत राजपंचायत क़ानून बनाकर यह ठहरा दे कि वह सरकार के मामूली कामों के साथ कुदरती संबंध रखते हैं.

290—जहाँ इस विधान के बन्धानों के अधीन, किसी अदालत या कमीशन का खर्च, या किसी ऐसे आदमी को या उसके बारे में दी जाने वाली पेनशन, जो इस विधान के आरंभ होने से पहले सम्राट के अधीन हिन्द में नौकरी कर चुका है, या जो विधान के आरंभ होने के बाद यूनियन या किसी रियासत के मामलों के संबंध में नौकरी कर चुका है, भारत के मूठकोश या किसी रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ती हैं, वहाँ—

कुछ खर्चों और पेनशनों के बारे में बैठ-बिठाव

(ए) अगर वह भारत के मूठकोश के खाते में पड़ता है, और वह अदालत या कमीशन, किसी रियासत की अलग ज़रूरतों में से किसी को पूरा करे, या उस आदमी ने बिलकुल या कुछ हद तक किसी रियासत के मामलों के सम्बन्ध में नौकरी की है; या

(बी) अगर वह किसी रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ता है, और वह अदालत या कमीशन यूनियन की या किसी दूसरी रियासत की अलग ज़रूरतों को पूरा करे, या उस आदमी ने बिलकुल या कुछ हद तक

यूनियन या किसी दूसरी रियासत के मामलों के सम्बन्ध में नौकरी की है, तो

उन खर्चों या उस पेनशन का वह हिस्सा जिस पर सब राखी हों या अगर कोई राखी न हो तो जो भारत के सरजज का नियोजन हुआ कोई पंच तय कर दे, उस रियासत के मूठकोश के खाते में डाला जायगा और उस कोश में से दिया जायगा या, जैसी सूरत हो, भारत के मूठकोश के खाते में, या उस दूसरी रियासत के मूठकोश के खाते में, डाला जायगा और उसमें से दिया जायगा।

शासकों की निजी
थलियों की रकमें

291—(1) जहाँ किसी ऐसे मुआहदे या समझौते के अधीन जो इस विधान के आरंभ से पहले किसी देसी रियासत के शासक ने किया हो, टैक्स से बरी किन्हीं रकमों का उस रियासत के शासक को उसकी निजी थैली के रूप में दिया जाना हिन्दू डोमिनियन की सरकार ने गारंटी कर दिया हो या उसका भरोसा दिलाया हो, वहाँ—

(प) वह रकमें भारत के मूठकोश के खाते में पड़ेंगी और उसमें से दी जायंगी; और

(बी) किसी शासक को जो रकमें इस तरह दी जायंगी उन पर कोई आमदनी टैक्स नहीं लिया जायगा।

(2) जहाँ ऊपर कही किसी देसी रियासत के भूभाग पहली पट्टी के भाग (प) और भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत के अन्दर आ जाते हैं, वहाँ धारा (1) के अधीन भारत सरकार जो रकमें देगी उनका वह हिस्सा, अगर कोई हो, और उस अरसे के लिये जो दफ्ता 278 की धारा (1) के अधीन इस बारे में किसी समझौते का ध्यान रखते हुए राजपति हुकुम देकर तय करदे, उस रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ेगा और उसमें से दिया जायगा।

खंड दो—उधार लेना

भारत सरकार का
उधार लेना

292—यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में, भारत के मूठकोश की जमानत पर, उन सीमाओं के अन्दर अगर कोई ऐसी सीमाएं हों तो जो राजपंजायत समय समय पर क़ानून बन्नाकर तय करदे, उधार लेना, और उन्हीं सीमाओं के अन्दर अगर कोई

ऐसी सीमाएं हों तो जो इस तरह तय कर दी गई हों, गारंटिया देना शामिल है।

293—(1) इस दफ्ता के बन्धानों के अधीन रहते हुए, किसी रियासत की काजकारी शक्ति के फैलाव में, भारत के भूभाग के अन्दर, रियासत के मूठकोश की जमानत पर, उन सीमाओं के अन्दर अगर कोई ऐसी सीमाएं हों तो जो उस रियासत की कानून सभा समय समय पर कानून बनाकर तय कर दे, उधार लेना, और उन्हीं सीमाओं के अन्दर अगर कोई ऐसी सीमाएं हों तो जो इस तरह तय कर दी जायं, गारंटियां देना शामिल होगा।

रियासतों का उधार लेना

(2) भारत सरकार, उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो राजपंजायत के बनाए किसी कानून में या उसके अधीन बता दी जायं, किसी रियासत को उधारियां दे सकती है, या किसी रियासत ने जो उधारियां ली हों उनके बारे में, दफ्ता 292 के अधीन तय की हुई सीमाओं के बाहर न जावे हुए, गारंटियां दे सकती है, और जो रकम इस तरह उधारियां देने के लिये दरकार होंगी वह भारत के मूठकोश के खाते में पड़ेंगी।

(3) कोई रियासत भारत सरकार की अनुमति बिना कोई उधारी नहीं ले सकेगी, जब तक किसी ऐसी उधारी का कोई हिस्सा अदा करना बाक़ी है जो भारत सरकार ने या इससे पहले की सरकार ने उस रियासत को दी हो, या जिसके बारे में भारत सरकार ने या इससे पहले की सरकार ने कोई गारंटी दी हो।

(4) धारा (3) के अधीन अनुमति उन शर्तों का ध्यान रखते हुए ही दी जा सकती है, अगर ऐसी कोई शर्तें हों तो, जिन्हें भारत सरकार लगाना ठीक समझे।

खंड तीन—जायदाद, ठेके, अधिकार, देनदारियाँ,

जिम्मेदारियाँ और नालिशें

294—इस विधान के आरंभ होने के समय से—

(ए) सब जायदाद और देनदारियाँ जो विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्दू डोमिनियन की सरकार के मतलबों के लिये सज़ाद को हासिल थीं, और वह सब जाय-

कुछ सूरतों में जायदाद, देनदारियों, अधिकारों, देनदारियों और जिम्मेदारियों का बिरसा

दाद और लेनदारियां जो विधान के आरंभ से ठीक पहले हर गवर्नरी सूबे की सरकार के मतलबों के लिये सम्राट को हासिल थीं, अब अलग अलग यूनियन को और जवाबी रियासत को हासिल होंगी, और

(बी) हिन्द डोमिनियन सरकार के और हर गवर्नरी सूबे की सरकार के सब अधिकार, देनदारियां और ज़िम्मेदारियां, चाहे वह किसी ठेके के कारन पैदा हुई हों या दूसरी तरह पैदा हुई हों, अब अलग अलग भारत सरकार और हर जवाबी रियासत सरकार के अधिकार, देनदारियां और ज़िम्मेदारियां होंगी,

पर उस बैठबिठाव के अधीन रहते हुए जो इस विधान के आरंभ से पहले पाकिस्तान डोमिनियन के, या पच्छिमी बंगाल और पूरबी बंगाल और पच्छिमी पंजाब और पूरबी पंजाब के सूबों के, बनने के कारन किया गया हो या किया जाने जानेवाला हो.

दूसरी सूक्तों में जायदाद, लेनदारियों, अधिकारों, देनदारियों और ज़िम्मेदारियों का विरसा

295—(1) इस विधान के आरंभ होने के समय से—

(ए) वह सब जायदाद और लेनदारियां जो विधान आरंभ होने से ठीक पहले पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की जवाबी देसी रियासत को हासिल थीं अब यूनियन को हासिल होंगी अगर वह मतलब, जिनके लिये वह जायदाद और लेनदारियां विधान के आरंभ से ठीक पहले रखी गई थीं, विधान के आरंभ के बाद यूनियन तालिका में गिनाए मामलों में से किसी के संबंध में यूनियन के मतलब हो जायेंगे, और

(बी) वह सब अधिकार, देनदारियां और ज़िम्मेदारियां, जो पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की जवाबी देसी रियासत की सरकार की थीं, चाहे वह किसी ठेके से पैदा हुई हों चाहे किसी दूसरी तरह पैदा हुई हों, भारत सरकार के अधिकार, देनदारियां और ज़िम्मेदारियां हो जायेंगी, अगर वह मतलब,

जिन मतलबों के लिये विधान आरंभ होने से पहले वह अधिकार हासिल किये गए थे या वह देनदारियाँ या ज़िम्मेदारियाँ ली गई थीं, विधान के आरंभ के बाद, यूनियन तालिका में गिनाए मामलों में से किसी के संबंध में, भारत सरकार के मतलब हो जायेंगे,

पर ऐसे किसी समझौते का ध्यान रखते हुए जो इस काम के लिये भारत सरकार ने उस रियासत की सरकार के साथ किया हो.

(2) ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके अधीन रहते हुए, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज हर रियासत की सरकार, इस विधान के आरंभ होने के समय से, धारा (1) में जिनकी चरचा की गई है उन्हें छोड़कर और सब जायदादों और लेनदारियों और सब अधिकारों, देनदारियों और ज़िम्मेदारियों के संबंध में, चाहे वह किसी ठेके से पैदा हुई हों या दूसरी तरह पैदा हुई हों, अपनी जबाबी देसीरियासत की वारिस होगी.

296—आगे जो कुछ बन्धान किया गया है उसके अधीन रहते हुए, भारत के भूभाग में जो कोई जायदाद, अगर यह विधान अमल में न आया होता तो, सरकारी ज़न्ती, या हक़दार का हक़ खतम हो जाने, या कोई हक़दार मालिक न होने से लावारसी होने के कारन सम्राट को, या जैसी सूरत हो, किसी देसी रियासत के शासक को मिल गई होती, वह जायदाद अगर किसी रियासत में है, तो उस रियासत को हासिल हो जायगी और हर दूसरी सूरत में यूनियन को हासिल हो जायगी :

शर्तें कि जो कोई जायदाद, उस तारीख को जिस दिन वह इस तरह सम्राट को या किसी देसी रियासत के शासक को मिल जाती, भारत सरकार के या किसी रियासत की सरकार के कब्जे बा दवान में थी, वह जायदाद, अगर जिन मतलबों के लिये उस समय उस का इस्तेमाल होता था या जिन मतलबों के लिये उस पर कब्जा था, वह मतलब यूनियन के मतलब थे तो यूनियन को या अगर वह मतलब किसी रियासत के मतलब थे तो उस रियासत को, हासिल हो जायगी.

सरकारी ज़न्ती, या हक़ खतम हो जाने, या वारिस न रहने के कारन मिलने वाली जायदाद

समझाव : इस दफा में "शासक" और "देशी रियासत" शब्दों के वही अर्थ हैं जो दफा 363 में हैं.

भूभागी जल में
जो क्रीमती चीजें
हों वह यूनियन को
हासिल होंगी

297—भारत के भूभागी जल की सीमा के अन्दर समन्दर के नीचे की सारी धरती, खनिज और दूसरी क्रीमती चीजें यूनियन को हासिल होंगी और यूनियन के मतलबों के लिये उसके कब्जे में रहेंगी.

जायदाद हासिल
करने की शक्ति

298—(1) किसी ऐसे कानून का ध्यान रखते हुए जिसे मुनासिब कानून सभा ने बनाया हो, यूनियन की और हर रियासत की काजकारी शक्ति के फैलाव में किसी ऐसी जायदाद की देनगी करना, उसे बेच देना, किसी को दे डालना, या रहन रखना शामिल होगा जिस जायदाद पर यूनियन के या, जैसी सूरत हो, उस रियासत के मतलबों के लिये कब्जा हो, और उस शक्ति के फैलाव में उन अपने अपने मतलबों के लिये जायदाद खरीदना या हासिल करना भी शामिल होगा, और ठेके करना भी शामिल होगा.

(2) यूनियन के या किसी रियासत के मतलबों के लिये जो जायदाद हासिल की जायगी वह सब यूनियन को या उस रियासत को, जैसी सूरत हो, हासिल होगी.

ठेके

299—(1) यूनियन की या किसी रियासत की काजकारी शक्ति से काम लेते हुए जो ठेके किये जायें वह सब राजपति के किये हुए या उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के किये हुए, जैसी सूरत हो, कहे जायेंगे, और उसी शक्ति से काम लेते हुए इस तरह के जो ठेके किये जायें, और जायदाद के बारे में जो भरोसे दिलाए जायें उन सब को राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख की तरफ से वह लोग उस ढंग पर करेंगे या देंगे जिन्हें और जिस ढंग के लिये राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, निर्देश दे या अधिकार दे.

(2) इस विधान के मतलबों के लिये या भारत सरकार से संबंध रखने वाले किसी ऐसे कानून के मतलबों के लिये जो अब तक अमल में हो, राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख किसी ठेके के बारे में जो वह करे या किसी भरोसे के बारे में जो वह

दिलाए, निजी तौर पर देनदार नहीं होगा, और न कोई आदमी जिसने उनमें से किसी की तरफ से ऐसा ठेका किया हो या भरोसा दिलाया हो उसके बारे में निजी तौर पर देनदार होगा।

300—(1) भारत सरकार भारत की यूनियन के नाम से नालिश कर सकती है या उस पर नालिश की जा सकती है, और किसी रियासत की सरकार उस रियासत के नाम से नालिश कर सकती है या उस पर नालिश की जा सकती है, और राजपंचायत के किसी ऐसे एक्ट या उस रियासत की कानून सभा के किसी ऐसे एक्ट के बन्धानों के अधीन रहते हुए जो इस विधान में दी हुई शक्तियों की रू से बनाया गया हो, दोनों अपने अपने मामलों के सम्बन्ध में उन्हीं सूरतों में नालिश कर सकती हैं या उन पर नालिश की जा सकती है, जिन सूरतों में अगर यह विधान न बना होता तो हिन्द डोमीनियन या जवाबी सूबे या जवाबी देसी रियासतें नालिश कर सकती थीं या उन पर नालिशें की जा सकती थीं।

नालिशें और
कारवाइयाँ

(2) अगर विधान के आरंभ होने के समय—

(प) कोई ऐसी कानूनी कारवाइयाँ चल रही हों जिनमें एक फरीक हिन्द डोमीनियन है तो उन कारवाइयों में हिन्द डोमीनियन के नाम की जगह भारत की यूनियन का नाम समझा जायगा; और

(बी) कोई ऐसी कानूनी कारवाइयाँ चल रही हों जिनमें कोई सूबा या कोई देसी रियासत एक फरीक है, तो उन कारवाइयों में उस सूबे के या उस देसी रियासत के नाम की जगह उस सूबे की या उस देसी रियासत की जवाबी रियासत का नाम समझा जायगा।

भाग तेरह

भारत के भूभाग के अन्दर व्योपार,

तिजारत और अन्तर-व्योहार

व्योपार, तिजारत
और अन्तर-व्योहार
की आज्ञादी

301—इस भाग के दूसरे बन्धानों के अधीन रहते हुए, भारत के तमाम भूभाग में व्योपार, तिजारत और अन्तर-व्योहार खुला होगा.

व्योपार, तिजारत
और अन्तर-व्योहार
पर रुकावटें लगाने
की राजपंचायत
की शक्ति

302—राजपंचायत कानून बनाकर एक रियासत और दूसरी रियासत के बीच या भारत के भूभाग के किसी हिस्से के अन्दर व्योपार, तिजारत और अन्तर-व्योहार की आज्ञा दी पर ऐसी रुकावटें लगा सकती है जो जनता के हित में दरकार हों.

व्योपार और तिजारा-
रत के बारे में
यूनियन और रिया-
सतों की कानून-
कारी शक्तियों पर
रुकावटें

303—(1) दफ़ा 302 में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत को या किसी रियासत की कानून सभा को, सातवाँ पट्टी की तालिकाओं में से किसी में व्योपार और तिजारत संबंधी किसी अन्तरी की रू से, कोई ऐसा कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी जो एक रियासत को दूसरी पर कोई तरजीह देता हो, या तरजीह देने का अधिकार देता हो, या एक रियासत और दूसरी रियासत के बीच कोई भेदभाव करता हो या करने का अधिकार देता हो.

(2) धारा (1) की कोई बात राजपंचायत को कोई ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकेंगी जो किसी तरह की तरजीह देता हो या देने का अधिकार देता हो, या कोई भेदभाव करता हो या करने का अधिकार देता हो, अगर ऐसे कानून में यह ऐलान कर दिया गया है कि भारत के भूभाग के किसी हिस्से में माल की कमी से पैदा हुई हालत को संभालने के लिये ऐसा करना जरूरी है.

रियासतों के बीच
व्योपार, तिजारत
और अन्तर-व्योहार
पर रुकावटें

304—दफ़ा 301 या दफ़ा 303 में किसी बात के रहते भी, किसी रियासत की कानून सभा कानून बनाकर—

(ए) दूसरी रियासतों से आप माल पर कोई ऐसा टैक्स लगा सकती है जो उस रियासत में बने या पैदा हुए उसी तरह के माल पर लगता हो, पर इस तरह कि ऐसे आप

माल और इस तरह बने या पैदा हुए माल के बीच कोई भेदभाव न किया जाय; और

(बी) उस रियासत के साथ या उसके अन्दर, ब्योपार, तिजारत या अन्तर-ब्योहार की आजादी पर ऐसी उचित रुकावटें लगा सकती है जो जनता के हित के लिये दरकार हों:

शर्तें कि धारा (बी) के मतलबों के लिये राजपति की पहले से मंजूरी लिये बिना किसी रियासत की कानून सभा में न कोई बिल रखा जायगा न कोई सुधार पेश किया जायगा.

305—दफा 301 और 303 की किसी बात का किसी मौजूदा कानून के बन्धानों पर कोई असर नहीं होगा सिवाय उस हद तक जिस हद तक कि राजपति हुकुम जारी करके कोई दूसरा बन्धान कर दे.

दफा 301 और 303 का मौजूदा कानूनों पर असर

306—इस भाग के ऊपर-लिखे बन्धानों में या इस विधान के किन्हीं दूसरे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज कोई रियासत, जो इस विधान के आरम्भ से पहले दूसरी रियासतों से उस रियासत में आने वाले माल पर या उस रियासत से दूसरी रियासतों में जाने वाले माल पर कोई टैक्स या महसूल लगाती थी, अगर इस काम के लिये भारत सरकार और उस रियासत की सरकार के बीच कोई समझौता हो गया हो तो उस समझौते की शर्तों के अधीन रहते हुए, और उस आरसे के लिये जो उस समझौते में बताया गया हो पर जो इस विधान के आरंभ से लेकर दस साल से अधिक नहीं होगा, उस टैक्स या महसूल को लगाना और जमा करना जारी रख सकती है :

पहली पट्टी के भाग (बी) की कुछ रियासतों को ब्योपार और तिजारत पर रुकावटें लगाने की शक्ति

शर्तें कि राजपति विधान के आरंभ से पांच साल बीत जाने पर किसी समय भी ऐसे किसी समझौते को खतम कर सकता है या उसमें अदल बदल कर सकता है, अगर दफा 280 के अधीन बने माल कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद वह ऐसा करना जरूरी समझे.

दफ्ता 301 से
304 तक के मत-
लबों पर अमल
कराने के लिये
अधिकारी का
नियोजन

307—राजपंचायत कानून बनाकर किसी ऐसे अधिकारी का नियोजन कर सकती है जिसे वह दफ्ता 301, 302, 303 और 304 के मतलबों पर अमल कराने के लिये मुनासिब समझे, और इस तरह नियोजे हुए अधिकारी को वह शक्तियाँ और फरज सौंप सकती है जिन्हें वह जरूरी समझे.

भाग चौदह

यूनियन और रियासतों के अधीन नौकरियाँ

खंड एक—नौकरियाँ

308—अगर प्रसंग से कुछ और दरकार न हो तो इस भाग में “रियासत” शब्द के मानी हैं पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज कोई रियासत.

अथ

309—इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, यूनियन के या किसी रियासत के मामलों से सम्बन्ध रखने वाली सरकारी नौकरियों और जगहों पर जो लोग नियोजे जायेंगे उनकी भरती की और उनकी नौकरी की शर्तों की, मुनासिब कानून सभा के एक्टों से क्रायदाबन्दी की जा सकती है :

यूनियन की या किसी रियासत को नौकरी करने वाले लोगों की भरती और नौकरी की शर्तें

शर्तें कि यूनियन के मामलों से संबंध रखने वाली नौकरियों और जगहों की सूरत में राजपति या कोई ऐसा आदमी जिसे राजपति निर्देश दे, और किसी रियासत के मामलों से संबंध रखने वाली नौकरियों और जगहों के संबंध में उस रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख या कोई ऐसा आदमी जिसे रियासतपति या राजप्रमुख निर्देश दे, तब तक के लिये इस बात का अधिकारी होगा कि वह ऐसी नौकरियों और जगहों पर नियोजे जाने वाले आदमियों की भरती और उनकी नौकरी की शर्तों की क्रायदाबन्दी करने के लिये नियम बनाए, जब तक कि इस काम के लिये इस दफा के अधीन किसी मुनासिब कानून सभा के किसी एक्ट में या उसके अधीन बन्धान नहीं किया जाता, और इस तरह बनाए हुए किन्हीं नियमों का असर ऐसे एक्ट के बन्धानों के अधीन होगा.

310—(1) सिवाय जब कि इस विधान में साफ साफ कुछ और बन्धान किया गया हो, हर वह आदमी, जो यूनियन की किसी बचाव नौकरी में या किसी नागरी नौकरी में नौकर है या किसी कुल-भारत नौकरी में नौकर है या यूनियन के अधीन बचाव संबंधी किसी जगह पर या किसी नागरी जगह पर है, राजपति के इच्छा-काल तक

यूनियन या किसी रियासत की नौकरी करने वाले आदमियों की पद-पियाद

अपने पद पर रहेगा, और हर वह आदमी जो किसी रियासत की किसी नागरी नौकरी में नौकर है या किसी रियासत के अधीन किसी नागरी जगह पर है उस रियासत के रियासतपति के या, जैसी सूरत हो, राजप्रमुख के इच्छा-काल तक अपने पद पर रहेगा।

(2) इस बात के रहते भी कि कोई आदमी जो यूनियन के या किसी रियासत के अधीन किसी नागरी जगह पर है राजपति के या, जैसी सूरत हो, उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के इच्छा-काल तक ही अपने पद पर रह सकता है, अगर किसी ठेके के अधीन कोई आदमी, जो किसी बचाव नौकरी या किसी कुल-भारत नौकरी या यूनियन की या किसी रियासत की किसी नागरी नौकरी में नौकर नहीं है, इस विधान के अधीन किसी ऐसी जगह पर नियोजा जाय, और अगर राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, विशेष जोगताएँ रखने वाले किसी आदमी की सेवाएँ पाने के लिये यह जरूरी समझे, तो उस ठेके में यह बन्धान किया जा सकता है कि अगर उस अरसे के बीतने से पहले जिस पर समझौता था वह जगह तोड़ दी जाय या उस आदमी से, ऐसे कारनों से जिनका संबंध उसके किसी बुरे चलन से नहीं है, वह जगह खाली कराना दरकार हो, तो उसको नुकसान भरपाई दी जायगी।

यूनियन या किसी रियासत के अधीन नागरी हैसियत से नौकरी करने वालों का बरखास्त किया जाना, हटाया जाना या रुतबा घटाया जाना

311—(1) किसी आदमी को जो यूनियन की किसी नागरी नौकरी में या किसी कुल-भारत नौकरी में या किसी रियासत की नागरी नौकरी में नौकर है, या यूनियन के या किसी रियासत के अधीन किसी नागरी जगह पर है, कोई ऐसा अधिकारी जो उसके निबोजने वाले अधिकारी से मातहत दर्जे का है न बरखास्त करेगा और न हटायगा।

(2) ऊपर बताए किसी आदमी को न बरखास्त किया जायगा, न हटाया जायगा और न उसका रुतबा घटाया जायगा, जबतक कि उसके बारे में तजवीज की हुई कारवाई के जिलाफ़ कारन दिखाने का उचित मौक़ा उसे न दिया गया हो :

शर्तें कि यह धारा वहाँ लागू नहीं होगी—

(ए) जहाँ किसी आदमी को किसी ऐसे चलन की बिना पर

जिसके कारन वह किसी फौजदारी जुर्म का दोशी ठहराया जा चुका है, बरखास्त किया गया हो या हटाया गया हो या उसका रुतबा घटाया गया हो;

(बी) जहाँ किसी आदमी को बरखास्त करने, हटाने या उसका रुतबा कम करने की शक्ति रखने वाले किसी अधिकारी को इतमीनान हो जाय कि, किसी ऐसी वजह से जिसे वह अधिकारी लिख रखेगा, उस आदमी को कारन बताने का मौक्का देना समझदारी के खयाल से अमली नहीं है; या

(सी) जहाँ राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख को, जैसी सूरत हो, यह इतमीनान हो जाय कि राज की सुरक्षा के हित में उस आदमी को ऐसा मौक्का देना समयोचित नहीं है.

(3) अगर कोई ऐसा सवाल उठे कि किसी आदमी को धारा (2) के अधीन कारन बताने का मौक्का देना समझदारी के खयाल से अमली है या नहीं, तो ऐसे आदमी को बरखास्त करने या हटाने या उसका रुतबा घटाने की, जैसी सूरत हो, शक्ति रखने वाले अधिकारी का इस बात पर फैसला आखिरी होगा.

312—(1) भाग ग्यारह में किसी बात के रहते भी, अगर रियासत सदन ने, किसी ऐसे ठहराव से जिसका मौजूद और बोट देने वाले मेम्बरों में से कम से कम दो तिहाई ने समर्थन किया हो, यह ऐलान कर दिया हो कि क़ौमी हितमें ऐसा करना जरूरी या समयोचित है तो राजपंचायत क़ानून बनाकर यूनियन और रियासत के लिये एक या एक से अधिक शामिलती कुल-भारत नौकरियां कोलने का बन्धान कर सकती है, और, इस खंड के दूसरे बन्धानों के अधीन रहते हुए, ऐसी किसी नौकरी में नियोजे जाने वाले लोगों की भरती और नौकरी की शर्तों की क़ायदाबन्दी कर सकती है.

कुल भारत
नौकरियां.

(2) इस विधान के आरम्भ होने पर जो नौकरियां हिन्द शासनी नौकरी (इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस) और हिन्द पुलिस नौकरी (इंडियन पुलिस सर्विस) कहलाती थीं वह इस दफ़ा के अधीन राज-

पंचायत की खोली हुई नौकरियां समझी जायंगी।

बिचवकी बन्धान

313—जब तक इस विधान के अधीन इस के लिये कोई दूसरा बन्धान नहीं किया जाता, तब तक वह सब कानून, जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अमल में थे, और जो किसी ऐसी सरकारी नौकरी या किसी जगह के लिये लागू थे जो इस विधान के आरंभ के बाद कुल-भारत नौकरी के रूप में या यूनियन के या किसी रियासत के अधीन नौकरी या जगह के रूप में जारी है, जहां तक इस विधान के बन्धानों से मेल रखते होंगे, अमल में रहेंगे।

कुछ नौकरियों के मौजूदा अफसरों की रक्षा के लिये बन्धान

314—सिवाय जब कि इस विधान में साफ-साफ कुछ और बन्धान किया गया हो, हर वह आदमी, जिसे स्टेट सेक्रेटरी या कौन्सिल समेत स्टेट सेक्रेटरी ने हिन्दू सम्राट की किसी नागरी नौकरी में नियोजन हो और जो इस विधान के आरंभ होने के समय और उसके बाद भारत सरकार के या किसी रियासत की सरकार के अधीन नौकरी करता रहता है, भारत सरकार से और उस रियासत की सरकार से, जिसकी नौकरी वह समय समय पर करता रहता है, मेहनताने, छुट्टी और पेनशन के बारे में नौकरी की वही शर्तें, और क्रायदादारी के मामलों के बारे में वही अधिकार, या उनसे इतने मिलते जुलते अधिकार, जितने बदली हुई हालतें इजाजत दें, पाने का हकदार होगा जिनके पाने का वह इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हकदार था।

खंड दो—सरकारी नौकरी कमीशन

यूनियन के लिये और रियासतों के लिये सरकारी नौकरी कमीशन

315—(1) इस दफा के बन्धानों के अधीन रहते हुए, यूनियन के लिये एक सरकारी नौकरी कमीशन होगा और हर रियासत के लिये एक सरकारी नौकरी कमीशन होगा।

(2) दो या अधिक रियासतें यह समझौता कर सकती हैं कि रियासतों के उस गुट के लिये एक ही सरकारी नौकरी कमीशन होगा, और अगर इस मतलब का कोई ठहराव उन रियासतों में से हर एक की कानून सभा के सदन में था, जहाँ दो सदन हैं वहाँ, हर सदन में पास हो जाता है, तो राजपंचायत कानून बना कर उन रियासतों की जरूरतें पूरी करने के लिये एक मित्र-जुता रियासत

सरकारी नौकरी कमीशन (जिसकी इस खंड में मिला-जुला कमीशन कह कर चर्चा की गई है) नियोजित जाने के लिये बन्धान कर सकती है।

(3) उपर कहे हर कानून में ऐसे प्रसंगी और परिनामी बन्धान रह सकते हैं जो उस कानून के मतलबों पर अमल कराने के लिये जरूरी या चाहनी हों।

(4) यूनियन के सरकारी नौकरी कमीशन से अगर किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख ऐसा करने की प्रार्थना करे तो वह कमीशन, राजपति की रजामन्दी से, उस रियासत की सब या किन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिये राजी हो सकता है।

(5) जब तक प्रसंग से कुछ और दरकार न हो तब तक, इस विधान में यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन की या रियासत सरकारी नौकरी कमीशन की जहाँ जहाँ चर्चा की गई है, वहाँ उस कमीशन से मतलब लिया जायगा जो उस खास मामले के बारे में जिस पर सवाल उठा है यूनियन की या उस रियासत की, जैसी सूरत हो, जरूरतें पूरी करता है।

316—(1) किसी सरकारी नौकरी कमीशन के मसनदी और दूसरे मेम्बरों को, यूनियन कमीशन या किसी मिले-जुले कमीशन की सूरत में, राजपति और, किसी रियासत कमीशन की सूरत में, उस रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख नियोजेगा :

मेम्बरों का नियोजन और पद-मियाद

शर्तें कि हर सरकारी नौकरी कमीशन के आधे के जितने करीब हो सकें उतने मेम्बर ऐसे लोग होंगे जो अपने अपने नियोजन की तारीखों पर भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत की सरकार के अधीन कम से कम दस बरस तक किसी ओहदे पर रह चुके हैं, और इस दस बरस के अरसे को गिनने में इस विधान के आरंभ से पहले का वह अरसा भी शामिल कर लिया जायगा जिसमें वह आदमी हिन्द सम्राट के अधीन या किसी देसी रियासत की सरकार के अधीन किसी ओहदे पर रह चुका है।

(2) सरकारी नौकरी कमीशन का हर मेम्बर अपना पद खंभाकने की तारीख से छै बरस की मियाद तक या, यूनियन

कमीशन की सूरत में, पैंसठ बरस की उमर का होने तक और, किसी रियासत कमीशन की या किसी मिले-जुले कमीशन की सूरत में, साठ बरस की उमर का होने तक, जो भी पहले हो जाय, अपने पद पर रहेगा :

शर्तें कि—

(ग) किसी सरकारी नौकरी कमीशन का कोई मेम्बर, यूनि-यन कमीशन और मिले-जुले कमीशन की सूरत में, राजपति को और, किसी रियासत कमीशन की सूरत में, उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख को, अपनी दसखती लिखत भेज कर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है;

(बी) किसी सरकारी नौकरी कमीशन का कोई मेम्बर दफा 317 की धारा (1) या धारा (3) में बन्धान किये ढंग से अपने पद से हटाया जा सकता है.

(3) कोई आदमी जो किसी सरकारी नौकरी कमीशन के मेम्बर के पद पर है, अपनी पद-मियाद के बीत जाने पर, उस पद पर फिर नियोजे जाने का पात्र न होगा.

किसी सरकारी नौकरी कमीशन के मेम्बर का हटाया जाना और मुअत्तल किया जाना

317—(1) धारा (3) के बन्धानों के अधीन रहते हुए, किसी सरकारी नौकरी कमीशन का मसनवी या कोई दूसरा मेम्बर अपने पद से केवल राजपति के हुकुम से और बद-व्योहार की बिना पर ही हटाया जा सकेगा, और वह तब जब आला अदालत ने, राजपति के उस अदालत की राय मांगने पर, दफा 145 के अधीन इस काम के लिये बताए दस्तूर के अनुसार पूछा-छाह करने के बाद, यह रिपोर्ट दे दी हो कि वह मसनवी या दूसरा मेम्बर, जैसी सूरत हो, ऐसी किसी बिना पर हटाया जाना चाहिये.

(2) यूनिशन कमीशन या किसी मिले-जुले कमीशन की सूरत में राजपति, और किसी रियासत कमीशन की सूरत में रियासतपति या राजप्रमुख, उस कमीशन के मसनवी या ऐसे किसी दूसरे मेम्बर को, जिसके बारे में धारा (1) के अधीन आला अदालत की राय मांगी गई है, उसके पद से तब तक के लिये मुअत्तल कर

सकता है जब तक इस तरह मांगी हुई राय पर आला अदालत की रिपोर्ट मिलने के बाद राजपति हुकुम न दे दे.

(3) धारा (1) में किसी बात के रहते भी, राजपति किसी सरकारी नौकरी कमीशन के मसनदी या दूसरे किसी मेम्बर को उसके पद से हटा सकता है अगर वह मसनदी या दूसरा मेम्बर, जैसी सूरत हो,—

(ए) अदालत से दिवालिया ठहरा दिया जाय; या

(बी) अपनी पद-भियाद के अन्दर अपने पद के फरजों के बाहर कोई और वेतनी काम करने लगे; या

(सी) राजपति की राय में, दिमाग या शरीर की कमजोरी के कारन, अपने पद पर बने रहने के अजोग हो.

(4) अगर किसी सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी या कोई दूसरा मेम्बर भारत सरकार के किये हुए या किसी रियासत की सरकार के किये हुए या उनमें से किसी की तरफ से किये हुए किसी ठेके या समझौते से किसी तरह का संबंध या उसमें अपना कोई हित रखे या रखने लगे, या किसी तरह उसके लाभ में या उससे पैदा होने वाले किसी फायदे या वेतन में हिस्सा लेने लगे, सिवाय जबकि वह किसी एकतनी कम्पनी के मेम्बर की हैसियत से उस कम्पनी के दूसरे मेम्बरों के साथ साथ, ऐसा करे, दो धारा (1) के मतलबों के लिये वह बद्-व्योहारी का अपराधी समझा जायगा.

318—यूनियन कमीशन या किसी मिले-जुले कमीशन की सूरत में राजपति, और किसी रियासत कमीशन की सूरत में उस रियासत का रिवास्तपति या राजप्रमुख, क्रायदे बनाकर—

(ए) कमीशन के मेम्बरों की गिनती और उनकी नौकरी की शर्तें तय कर सकता है; और

(बी) कमीशन के अमले के मेम्बरों की गिनती और उनकी नौकरी की शर्तों के बारे में बन्धान कर सकता है :

शर्तेंकि किसी सरकारी नौकरी कमीशन के किसी मेम्बर के नियोजन के बाद उसकी नौकरी की शर्तों में ऐसी बदल नहीं की जायगी जिससे वह घाटे में रहे.

कमीशन के मेम्बरों और अमले की नौकरी की शर्तों के बारे में क्रायदा-बन्दी करने की शक्ति

कमीशन के मेम्बरों को मेम्बर न रहने के बाद पदों पर रहने के बारे में मनाही

319—अपने पद पर न रहने के बाद—

(ए) यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत की सरकार के अधीन आगे कोई नौकरी करने का पात्र न होगा;

(बी) किसी रियासत सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी, यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी या उसका दूसरा मेम्बर या किसी दूसरे रियासत सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी नियोजे जाने का पात्र होगा, पर भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत सरकार के अधीन किसी दूसरी नौकरी के लिये पात्र न होगा;

(सी) यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन के मसनदी को छोड़कर उसका कोई और मेम्बर यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी या किसी रियासत सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी नियोजे जाने का पात्र होगा, पर भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत की सरकार के अधीन किसी और नौकरी के लिये पात्र न होगा;

(डी) किसी रियासत सरकारी नौकरी कमीशन के मसनदी को छोड़कर उसका कोई और मेम्बर यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी या कोई दूसरा मेम्बर या उसी रियासत सरकारी नौकरी कमीशन या किसी दूसरे रियासत सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी नियोजे जाने का पात्र होगा, पर भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत सरकार के अधीन किसी दूसरी नौकरी के लिये पात्र न होगा.

सरकारी नौकरी कमीशनों के काम

320—(1) यूनियन के और रियासतों के सरकारी नौकरी कमीशनों का यह फरक होगा कि वह यूनियन की नौकरियों और उस रियासत की नौकरियों पर अलग अलग नियोजनों के लिये परीक्षाएं चलाएं

(2) यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन का यह भी फ़रज होगा कि अगर कोई दो या अधिक रियासतें उससे ऐसा करने की प्रार्थना करें तो उन रियासतों को, ऐसी नौकरियों के लिये जिन के लिये खास जोगताएँ रखने वाले उम्मीदवार दरकार हों, मिली जुली भरती की योजनाएं बनाने और चलाने में मदद दे.

(3) यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन से या रियासत सरकारी नौकरी कमीशन से, जैसी सूरत हो, नीचे लिखे मामलों में सलाह लेनी होगी:—

- (ए) वह सब मामले जिन का सम्बन्ध नागरी नौकरियों और नागरी जगहों के लिये भरती करने के तरीकों से है ;
- (बी) वह सिद्धान्त जिन पर चल कर नागरी नौकरियों और जगहों पर नियोजन किये जायंगे, और एक नौकरी से दूसरी नौकरी पर तरक्कियां दी जायंगी और तबादले किये जायंगे, और इस बात पर कि इस तरह के नियोजनों, तरक्कियों या तबादलों के लिये कौन उम्मीदवार ठीक होंगे ;
- (सी) क़ायदादारी के वह सब मामले जिनका असर भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत की सरकार के अधीन नागरी हैसियत में नौकरी करने वाले किसी आदमी पर पड़ता हो, जिसमें ऐसे मामलों से सम्बन्ध रखने वाले आवेदनपत्र या प्रार्थनापत्र भी शामिल होंगे ;
- (डी) किसी ऐसे आदमी का जो भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत की सरकार के अधीन या हिन्द सम्राट के अधीन या किसी देसी रियासत की सरकार के अधीन नागरी हैसियत में नौकरी कर रहा है या कर चुका है, यह दावा, या उसकी तरफ से किया हुआ यह दावा, कि अपना फ़रज पूरा करने के दौरान में जो काम उसने किये या उसके किये माने गए, उनके बारे

में अगर कोई कानूनी कारवाई उसके खिलाफ चलाई गई हो तो उसकी जवाबदेही करने में उसका जो खर्च हुआ हो वह भारत के या उस रियासत के, जैसी सूरत हो, मूठकोश में से दिया जाय;

- (ई) भारत सरकार के या किसी रियासत की सरकार के या हिन्द सम्राट के या किसी देसी रियासत की सरकार के अधीन नागरी हैसियत में नौकरी करते हुए किसी आदमी को अगर कोई आघात पहुँचे हों तो उनके बारे में उसका यह दावा कि उसको उनके लिये पेनशन दी जाय, और इस तरह जो पेनशन दी जाय उसकी रकम के बारे में कोई सवाल,

और सरकारी नौकरी कमीशन का फरज होगा कि जिस किसी मामले पर इस तरह उसकी राय मांगी गई हो और किसी दूसरे ऐसे मामले पर जिस पर राजपति या, जैसी सूरत हो, उस रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख उसकी राय मांगे उस पर सलाह दे:

शर्तें कि कुल-भारत नौकरियों के बारे में और यूनियन के मामलों के संबंध की दूसरी नौकरियों और जगहों के बारे में भी राजपति, और किसी रियासत के मामलों के संबंध की दूसरी नौकरियों और जगहों के बारे में, रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, क्रायदे बना सकता है जिन में वह मामले बता दिये जायं जिन पर या आम तौर पर, या किसी खास तरह की सूरतों में, या किन्हीं खास हालातों में, सरकारी नौकरी कमीशन से सलाह लेना जरूरी नहीं होगा.

(4) धारा (3) की किसी बात से यह दरकार नहीं होगा कि किसी सरकारी नौकरी कमीशन से इस बात के बारे में सलाह ली जाय कि दफ्ता 16 की धारा (4) में जिस बन्धान की चरखा की गई है वह किस ढंग से किया जाय या दफ्ता 335 के बन्धानों पर किस ढंग से अमल कराया जाय.

(5) धारा (3) की शर्त के अधीन राजपति या किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख जो क्रायदे बनाए उन सब

को उनके बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके कम से कम चौदह दिन के लिये राजपंचायत के हर सदन के सामने या उस रियासत की कानून सभा के सदन या हर सदन के सामने, जैसी सूरत हो, रखा जायगा, और उन क़ायदों में ऐसे अदल बदल किये जा सकेंगे, चाहे वह अदल बदल किसी क़ायदे को रद्द करने के रूप में हों या सुधारने के रूप में, जिन्हें राजपंचायत के दोनों सदन या उस रियासत की कानून सभा का सदन या दोनों सदन उस इजलास में कर दें जिसमें कि वह क़ायदे इस तरह रखे गए हों।

321—राजपंचायत का बनाया हुआ कोई एकट या जैभी सूरत हो, किसी रियासत की कानून सभा का बनाया हुआ कोई एकट इस बात का बन्धान कर सकता है कि यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन या उस रियासत का सरकारी नौकरी कमीशन, यूनियन की नौकरियों के बारे में, या उस रियासत की नौकरियों के बारे में, और किसी मुक़ामी अधिकारी की, या कानून से बनी किसी और एक-तन संस्था की, या जनता की किसी संस्था की नौकरियों के बारे में भी, और अधिक काम अपने हाथ में ले।

सरकारी नौकरी
कमीशनों के कामों
को बढ़ाने की शक्ति

322—यूनियन के या किसी रियासत के सरकारी नौकरी कमीशन के खर्च, जिनमें उस कमीशन के मेम्बरों को या उसके अमले के लोगों को या उनके बारे में दी जाने वाली तनखाहें, भत्ते और पेनशनें शामिल होंगी, भारत के या उस रियासत के, जैसी सूरत हो, मूठकोश के खाते में पड़ेंगे।

सरकारी नौकरी
कमीशनों के खर्चे

32 —(1) यूनियन कमीशन का फ़रज़ होगा कि वह हर बरस अपने कामों की राजपति को रिपोर्ट दे, और उस रिपोर्ट के मिलने पर राजपति, उन मामलों के बारे में, अगर कोई ऐसे मामले हों तो, जिनमें कमीशन की सलाह नहीं मानी गई, न मानने के कारणों को समझाने वाले याद-पत्र के साथ, उस रिपोर्ट की एक नक़ल राजपंचायत के हर सदन के सामने रखवायगा।

सरकारी नौकरी
कमीशनों की
रिपोर्टें

(2) रियासत कमीशन का फ़रज़ होगा कि वह हर बरस, अपने कामों की रियासतपति या राजप्रमुख को रिपोर्ट दे, और मिले जुले कमीशन का यह फ़रज़ होगा कि वह हर बरस उन

रियासतों में से हर एक के रियासतपति या राजप्रमुख को, जिनकी जरूरतें वह मिलाजुला कमीशन पूरी करता है, उस रियासत के संबंध में अपने कामों की रिपोर्ट दे, और हर सूरत में रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, उस रिपोर्ट के मिलने पर उन मामलों के बारे में, अगर कोई ऐसे मामले हों तो, जिनमें कमीशन की सलाह नहीं मानी गई, न मानने के कारणों को समझाने वाले याद-पत्र के साथ उस रिपोर्ट की एक नकल उस रियासत की कानून सभा के सामने रखवायगा.

भाग पंद्रह

चुनाव

324—(1) इस विधान के अधीन, राजपंचायत के लिये और हर रियासत की क़ानून सभा के लिये, और राजपति और उप-राजपति के पदों के लिये, जो चुनाव होंगे उन सब के लिये चुनाव-चिट्ठे तैयार कराने की निगरानी, निर्देशन और दबान, और उन सब चुनावों का संचालन, जिसमें उन शंकाओं और झगड़ों का फ़ैसला करने के लिये चुनाव अदालतों का नियोजन भी शामिल होगा जो राजपंचायत और रियासतों की क़ानून सभाओं के चुनावों में या उनके सम्बन्ध में पैदा हों, एक कमीशन के हाथ में रहेगा (जिसकी चरचा इस विधान में चुनाव कमीशन कह कर की गई है).

चुनावों की निगरानी, निर्देशन और दबान एक चुनाव कमीशन के हाथ में रहेगा

(2) चुनाव कमीशन में एक प्रमुख चुनाव कमिशनर और, अगर हों तो, इतने और चुनाव कमिशनर होंगे जितने राजपति समय समय पर तय करे, और प्रमुख चुनाव कमिशनर का और दूसरे चुनाव कमिशनरों का नियोजन, इस काम के लिये बने राजपंचायत के किसी क़ानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपति करेगा.

(3) जब कोई और चुनाव कमिशनर भी इस तरह नियोजा जाय तो प्रमुख चुनाव कमिशनर चुनाव कमीशन के मसनदी का काम करेगा.

(4) लोक सदन के और हर रियासत के आम सदन के हर आम चुनाव से पहले, और खास सदन वाली हर रियासत के खास सदन के पहले आम चुनाव और उसके बाद हर दुबराही चुनाव से पहले, राजपति चुनाव कमीशन से सलाह करके धारा (1) से चुनाव कमीशन को मिले कामों को पूरा करने में चुनाव कमीशन

की मदद करने के लिये ऐसे इलाका कमिश्नर भी नियोजन सकता है जिन्हे वह जरूरी समझे.

(5) राजपंचायत के बनाए किसी कानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए, चुनाव कमिश्नरों और इलाका कमिश्नरों की नौकरी की शर्तें और उनकी पद-मिबाद वह होंगी जो राजपति नियम बना कर तय कर दे :

शर्तें कि जिस ढंग और जिन बिनाओं पर आला अदालत के किसी जज को उसके पद से हटाया जा सकता है उस ढंग और उन बिनाओं के सिवा और किसी ढंग या बिना पर प्रमुख चुनाव कमिश्नर अपने पद से न हटाया जायगा, और प्रमुख चुनाव कमिश्नर के नियोजन के बाद उसकी नौकरी की शर्तों में कोई ऐसी अदल बदल न की जायगी जिससे वह घाटे में रहे :

और शर्तें कि किसी दूसरे चुनाव कमिश्नर या इलाका कमिश्नर को प्रमुख चुनाव कमिश्नर की सिफारिश के बिना पद से न हटाया जायगा.

(6) राजपति या किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख, जब चुनाव कमीशन उससे ऐसी प्रार्थना करे तब, चुनाव कमीशन या किसी इलाका कमिश्नर को वह अमला मिलने का सुभीता कर देगा जो धारा (1) से चुनाव कमीशन को मिले कामों को निभारने के लिये जरूरी हो.

धर्म, नसल, जात या जिनस की बिना पर कोई आदमी किसी खास चुनाव चिट्ठे में शामिल होने का अपात्र न होगा और न शामिल किये जाने का दावा करेगा

325—राजपंचायत के किसी सदन या किसी रियासत की कानून सभा के सदन या सत्रों के चुनाव के लिये हर भूभागी चुनाव हलक़े का एक आम चुनाव चिट्ठा होगा, और केवल धर्म, नसल, जात, जिनस या इनमें से किसी की बिना पर, कोई आदमी न ऐसे किसी चुनाव चिट्ठे में शामिल किये जाने का अपात्र होगा, और न ऐसे किसी चुनाव-हलक़े के लिये किसी खास चुनाव-चिट्ठे में शामिल किये जाने का दावा करेगा.

लोक सदन के लिये और रिया-

326—लोकसदन का और हर रियासत के आम सदन का चुनाव बांतिग बोट के आधार पर होगा; यानी हर आदमी जो

भारत का नागर है और जो उस तारीख पर, जो मुनासिब क़ानून सभा के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन इस काम के लिये तय कर दी जाय, इक्कीस बरस से कम उमर का न हो, और जो इस विधान के अधीन या मुनासिब क़ानून सभा के बनाए किसी क़ानून के अधीन, ना-निवास, दिमाग़ ठीक न होने, जुर्म, घूसखोरी या ग़ैर क़ानूनी आचार की बिना पर अजोग नहीं हो गया है, ऐसे किसी चुनाव के लिये वोटरों में अपना नाम रजिस्टर कराने का हक़दार होगा.

सतों के आम सदनों के लिये चुनाव बालिग़ वोट के आधार पर होंगे

327—इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपंचायत समय समय पर, क़ानून बनाकर, उन सब मामलों के बारे में बंधान कर सकती है जिनका वास्ता या सम्बन्ध राजपंचायत के किसी भी सदन के या किसी रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों के चुनावों से है, जिनमें चुनाव चिट्ठों की तैयारी, चुनाव-हलकों की हदबन्दी और वह दूसरे सब मामले भी शामिल होंगे जो ऐसे सदन या सदनों के, क़ायदे से बनने के लिये ज़रूरी हों.

क़ानून सभाओं के चुनावों के बारे में राजपंचायत को बंधान करने की शक्ति

328—इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, और जहाँ तक कि राजपंचायत ने इस काम के लिये कोई बन्धान न किया हो, किसी रियासत की क़ानून सभा, समय समय पर, क़ानून बना कर, उन सब मामलों के बारे में बन्धान कर सकती है जिनका वास्ता या सम्बन्ध उस रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों के चुनावों से है और जिनमें चुनाव चिट्ठों की तैयारी और वह सब मामले शामिल होंगे जो उस सदन या उन सदनों के, क़ायदे से बनने के लिये ज़रूरी हों.

किसी रियासत की क़ानून सभा की उस क़ानून सभा के चुनावों के बारे में बंधान करने की शक्ति

329—इस विधान में किसी बात के रहते भी—

(ए) दफ़ा 327 या दफ़ा 328 के अधीन बने या बने माने जाने वाले किसी ऐसे क़ानून की सरदुरुस्ती पर किसी अदालत में सबाल नहीं उठाया जायगा जिसका वास्ता चुनाव हलकों की हदबन्दी से या ऐसे चुनाव हलकों को सीटों बांटने से हो.

चुनाव के मामलों में अदालतों के दखल देने पर रोक

(बी) राजपंचायत के किसी सदन के या किसी रियासत की कानून सभा के सदन या सदनों के चुनाव पर सिवाय एक ऐसी चुनाव अरजी के जो उस अधिकारी को, और ऐसे ढंग से, दी गई हो जिसका बन्धान मुनासिब कानून सभा के बनाए किसी कानून में या उसकेअधीन किया गया है, और किसी ढंग से कोई सवाल नहीं उठाया जायगा.

भाग सोलह

कुछ जमातों से संबंध रखने वाले खास बन्धान

330—(1) लोक सदन में—

(ए) पट्टी दर्ज जातों के लिये,

(बी) आसाम के कबाइली छेत्रों के पट्टी-दर्ज कबीलों को छोड़ कर दूसरे पट्टी-दर्ज कबीलों के लिये, और

(सी) आसाम के स्वाधीन जिलों के पट्टी-दर्ज कबीलों के लिये,

सीटें अलग रखी जायंगी.

लोक सदन में पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज कबीलों के लिये सीटें अलग रखना

(2) किसी रियासत की पट्टी-दर्ज जातों या उससे पट्टी-दर्ज कबीलों के लिये धारा (1) के अधीन अलग रखी सीटों की गिनती और लोक सदन में उस रियासत को मिली कुल सीटों की गिनती में जितने करीब से करीब हो सके वही निश्चित होगी जो उस रियासत की उन पट्टी-दर्ज जातों की, या उस रियासत के या उसके किसी भाग के, जैसी सूरत हो, उन पट्टी-दर्ज कबीलों की, जिनके बारे में सीटें इस तरह अलग रखी गई हैं, आबादी और उस रियासत की कुल आबादी में है.

331—दफा 81 में किसी बात के रहते भी, अगर राजपति की यह राय हो कि लोक सदन में ऐंग्लो इंडियन समाज का काफी प्रतिनिधान नहीं है, तो वह उस समाज के अधिक से अधिक दो मेम्बरों को लोक सदन में नामजद कर सकेगा.

लोक सदन में ऐंग्लो इन्डियन समाज का प्रतिनिधान

332—(1) पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज हर रियासत के आम सदन में, आसाम के कबाइली छेत्रों के पट्टी-दर्ज कबीलों को छोड़ कर, सब पट्टी दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज कबीलों के लिये सीटें अलग रखी जायंगी.

रियासतों के आम सदन में पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज कबीलों के लिये सीटों का अलग रखा जाना

(2) आसाम की रियासत के आम सदन में स्वाधीन जिलों के लिये भी सीटें अलग रखी जायंगी.

(3) धारा (1) के अधीन किसी रियासत के आम सदन में पट्टी-दर्ज जातों या पट्टी-दर्ज कबीलों के लिये अलग रखी सीटें

की गिनती और आम सदन की सीटों की कुल गिनती में, जितने क़रीब से क़रीब हो सके, वही निश्चित होगी जो उस रियासत की उन पट्टी-दर्ज जातों की या उस रियासत या उसके किसी भाग के, जैसी सूरत हो, उन पट्टी-दर्ज क़बीलों की, जिनके बारे में सीटें इस तरह अलग रखी गई हैं, आबादी और उस रियासत की कुल आबादी में है।

(4) आसाम की रियासत के आम सदन में किसी स्वाधीन ज़िले के लिये अलग रखी सीटों की गिनती और उस आम सदन में सीटों की कुल गिनती में जो निश्चित होगी वह उससे कम न होगी जो उस ज़िले की आबादी और उस रियासत की कुल आबादी में है।

(5) आसाम के किसी स्वाधीन ज़िले के लिये अलग रखी सीटों के चुनाव हलक़ों में उस ज़िले से बाहर का कोई क्षेत्र शामिल नहीं होगा, सिवाय उस चुनाव हलक़े के जिसमें शिलांग की छावनी और नगरायत शामिल हैं।

(6) कोई आदमी जो आसाम की रियासत के किसी स्वाधीन ज़िले के किसी पट्टी-दर्ज क़बीले का मेम्बर नहीं है उस ज़िले के किसी चुनाव हलक़े से, सिवाय उस चुनाव हलक़े के जिसमें शिलांग की छावनी और नगरायत शामिल हैं, रियासत के आम सदन में चुने जाने का पात्र नहीं होगा।

रियासतों के आम सदन में ऐंग्लो-इण्डियन समाज का प्रतिनिधान

333—दफ़ा 170 में किसी बात के रहते भी, किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख, अगर उसकी यह राय है कि उस रियासत के आम सदन में ऐंग्लो-इण्डियन समाज को प्रतिनिधान की ज़रूरत है और उसमें उसका काफ़ी प्रतिनिधान नहीं है, आम सदन में उस समाज के उतने मेम्बर नामज़द कर सकता है जितने वह मुनासिब समझे।

सीटों का अलग रखा जाना और खास प्रतिनिधान इस साल बाद बन्द

334—इस भाग में ऊपर-लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, इस विधान के वह बन्धान जिनका सम्बन्ध—

(ए) लोक सदन में और रियासतों के आम सदन में पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज क़बीलों के लिये सीटें अलग रखने से है; और

(बी) लोक सदन में और रियासतों के आम सदनों में नाम-जदगी के जरिये ऐंग्लो-इन्डियन समाज के प्रतिनिधान से है,

इस बिधान के आरंभ से दस साल का अरसा बीत जाने पर बेअसर हो जायंगे :

शर्तें कि इस दफा की किसी बात का लोक सदन में या किसी रियासत के आम सदन में किसी प्रतिनिधान पर कोई असर नहीं होगा जब तक कि उस समय का लोक सदन या आम सदन, जैसी सूरत हो, भंग न हो जाय.

335—यूनियन के या किसी रियासत के मामलों के संबंध की नौकरियों या जगहों पर नियोजन करने में, शासन की कुशलता बनाए रखने का खयाल रखते हुए, पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज कबीलों के मेम्बरों के दावों का ध्यान रखना होगा.

नौकरियों और जगहों के लिये पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज कबीलों के दावे

336—(1) इस बिधान के आरम्भ के बाद पहले दो बरस तक यूनियन की रेल मार्ग, विदेसनी महमूल, डाक और तार की नौकरियों की जगहों पर ऐंग्लो इन्डियन समाज के मेम्बरों का नियोजन उसी आधार पर होगा जिस पर अगस्त, 1947 के पंद्रहवें दिन से ठीक पहले होता था.

कुछ नौकरियों में ऐंग्लो इन्डियन समाज के लिये खास बन्धान

हर अगले दो साल के अन्दर जितनी जगहें ऊपर लिखी नौकरियों में उस समाज के मेम्बरों के लिये अलग रखी जायंगी उनकी गिनती, उससे ठीक पहले के दो साल के अन्दर जितनी जगहें इस तरह अलग रखी गई थीं उनसे, दस फी सैकड़ा के जितने करीब से करीब हो सके कम होंगी :

शर्तें कि इस बिधान के आरम्भ से दस बरस खतम हो जाने पर जगहों का इस तरह अलग रखा जाना सब बन्द हो जायगा.

(2) धारा (1) की कोई बात, उस धारा के अधीन जो जगहें ऐंग्लो इन्डियन समाज के लिये अलग रखी गई हैं उनके अलावा था, उनसे ज्यादा, और दूसरी जगहों पर उस समाज के लोगों के नियोजन को नहीं रोकेगी, अगर दूसरे समाजों के लोगों के मुकाबले

में ऐंग्लो इन्डियन समाज के लोग अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर नियोजित जाने के जोग पाए जायं.

ऐंग्लो इन्डियन समाज के फ्रायदे के लिये तालीमी देनगियों के बारे में खास बन्धान

337—इस विधान के आरम्भ के बाद पहले तीन माली सालों में, यूनियन और पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज हर रियासत तालीम के बारे में ऐंग्लो इन्डियन समाज के फ्रायदे के लिये वही देनगियां करेगी, अगर ऐसी कोई देनगियां हों तो, जो मार्च, 1948 के इक्तीसवें दिन खतम होने वाले माली साल में की गई थीं.

हर अगले तीन साल में यह देनगियां उससे ठीक पहले के तीन साल में जो देनगियां की गई थीं उनसे दस फी सैकड़ा कम की जा सकेंगी :

शर्तें कि इस विधान के आरम्भ से दस साल खतम हो जाने पर, ऐंग्लो इन्डियन समाज के लिये खास रियायत होने की हद तक, इस तरह की देनगियां बन्द हो जायंगी :

और शर्तें कि इस दफा के अधीन कोई तालीमी संस्था कोई देनगी पाने की हकदार नहीं होगी जब तक कि उस संस्था के सलाना दाखलों का कम से कम चालीस फी सैकड़ा ऐंग्लो इन्डियन समाज को छोड़ कर दूसरे समाजों के लोगों के लिये खुला न रखा जाय.

पट्टी-दर्ज जातों, पट्टी-दर्ज कबीलों वगैरा के लिये खास अफसर

338—(1) पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज कबीलों के लिये एक खास अफसर होगा जिसको राजपति नियोजेगा.

(2) खास अफसर का फरज होगा कि इस विधान के अधीन पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज कबीलों के लिये जिन बचावनियों का बन्धान किया गया है उनसे सम्बन्ध रखने वाले सब मामलों की जांच करे, और, हर इतने दिनों के बाद जिनका राजपति निर्देश दे, उन बचावनियों के अमल पर राजपति को रिपोर्ट दे, और राजपति ऐसी सब रिपोर्टों को राजपंचायत के हर सदन के सामने रखवायगा.

(3) इस दफा में पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज कबीलों की जहां जहां चरचा की गई है उससे यह मतलब लिया जायगा कि उसमें उन दूसरी पिछड़ी हुई जमातों की चरचा भी शामिल है जिनको, दफा 340 की धारा (1) के अधीन नियोजित हुए किसी

कमीशन की रिपोर्ट मिलने पर, राजपति हुकुम देकर बता दे, और उसमें ऐंग्लो इन्डियन समाज की चरचा भी शामिल समझी जायगी.

339—(1) राजपति किसी समय भी हुकुम दे कर पहली पट्टी के भाग (ए) और भाग (बी) में दर्ज रियासतों के पट्टी-दर्ज क्षेत्रों के शासन पर, और पट्टी-दर्ज कबीलों की भलाई के कामों पर, रिपोर्ट देने के लिये, एक कमीशन का नियोजन कर सकता है, और इस विधान के आरम्भ से दस साल बीत जाने पर उसे ऐसे एक कमीशन का नियोजन करना होगा.

पट्टी-दर्ज क्षेत्रों के शासन और पट्टी-दर्ज कबीलों की भलाई पर यूनिशन का दबान

ऐसे हुकुम में कमीशन की रचना, शक्तियां और दस्तूर सब तय किये जा सकते हैं, और उसमें ऐसे प्रसंगो या सहायक बन्धान भी रह सकते हैं जिन्हें राजपति जरूरी या चाहनी समझे.

(2) यूनिशन की काजकारी शक्ति के फैलाव में ऐसी किसी रियासत को इस तरह की योजनाएं बनाने और उन पर अमल करने के बारे में निर्देश देना भी शामिल होगा, जिन योजनाओं को उस निर्देश में रियासत के पट्टी-दर्ज कबीलों की भलाई के लिये जरूरी बताया गया हो.

340—(1) राजपति हुकुम दे कर एक ऐसे कमीशन का नियोजन कर सकता है जिसमें वह आदमी होंगे जिन्हें राजपति ठीक समझे, और जो भारत के भूभाग में समाजी और तालीमी निगाह से पिछड़ी हुई जमातों की हालत की, और जो कठिनाइयां उन्हें फेलनी पड़ती हैं उनकी, जांच करेगा, और सिफारिशें करेगा कि उन कठिनाइयों को दूर करने और उन लोगों की हालत सुधारने के लिये यूनिशन को या किसी रियासत को क्या क्या कदम उठाने चाहियें, और इस मतलब के लिये यूनिशन को या किसी रियासत को क्या क्या देनगियां किन किन शर्तों पर करनी चाहियें, और जिस हुकुम से इस तरह के कमीशन का नियोजन किया जायगा उसमें कमीशन जिस दस्तूर पर चलेगा वह भी तय कर दिया जायगा.

पिछड़ी हुई जमातों की हालत की जांच करने के लिये कमीशन का नियोजन

(2) जिस कमीशन का इस तरह नियोजन किया जायगा वह जिन जिन मामलों के लिये उससे कहा गया हो उनकी जांच

करेगा और राजपति को एक रिपोर्ट देगा जिसमें वह सब बातें दी होंगी जिनका कमीशन को पता चले और वह सब सिफारिशों की गई होंगी जिन्हें कमीशन ठीक समझे।

(3) जो रिपोर्ट इस तरह राजपति को दी जायगी उसकी एक नकल, एक याद-पत्र के साथ जिसमें यह समझाया गया होगा कि उस रिपोर्ट पर क्या कारवाई की गई है, राजपति राजपंचायत के हर सदन के सामने रखवायगा।

पट्टी-दर्ज जातें

341—(1) राजपति, किसी रियासत के रियासतपति या राज-प्रमुख से सलाह करके, एक आम नोटिस निकाल कर, वह जातें, नसलें या कबीले, या जातों, नसलों या कबीलों के भाग, या उनके अन्दर के गिरोह, तय कर सकता है जो इस विधान के मतलबों के लिये उस रियासत के संबंध में पट्टी-दर्ज जातें समझी जायंगी।

(2) राजपंचायत कानून बनाकर, धारा (1) के अधीन जो नोटिस निकाला गया हो उसमें बताई पट्टी-दर्ज जातों की तालिका में, किसी जात, नसल या कबीले को या किसी जात, नसल या कबीले के किसी भाग को या उनके अन्दर के किसी गिरोह को शामिल कर सकती है या उसमें से निकाल सकती है, पर सिवाय जिस तरह कि यहां कहा गया है ऊपर की धारा के अधीन जो नोटिस निकाला जाय उसमें बाद के किसी नोटिस से कोई अदल बदल नहीं की जायगी।

पट्टी-दर्ज कबीले

342—(1) राजपति, किसी रियासत के रियासतपति या राज-प्रमुख से सलाह करके, एक आम नोटिस निकाल कर, वह कबीले या कबाइली समाज, या उन कबीलों या कबाइली समाजों के भाग, या उनके अन्दर के गिरोह तय कर सकता है जो इस विधान के मतलबों के लिये उस रियासत के संबंध में पट्टी-दर्ज कबीले समझे जायंगे।

(2) राजपंचायत, कानून बनाकर, धारा (1) के अधीन जो नोटिस निकाला गया हो उसमें बताई पट्टी-दर्ज कबीलों की तालिका

में, किसी कबीले या कबायली समाज को या किसी कबीले या कबायली समाज के किसी भाग को या उनके अन्दर के किसी गिरोह को शामिल कर सकती है या उसमें से निकाल सकती है, पर सिवाय जिस तरह कि यहां कहा गया है ऊपर की धारा के अधीन जो नोटिस निकाला जाय उस में बाद के किसी नोटिस से कोई अदल बदल नहीं की जायगी.

भाग सतरह

दफ्तरी भाषा

खंड एक—यूनियन की भाषा

यूनियन की दफ्तरी भाषा 343—(1) यूनियन की दफ्तरी भाषा देव नागरी लिखावट में हिन्दी होगी.

यूनियन के दफ्तरी मतलबों के लिये हिन्दुओं का जो रूप काम में लाया जायगा वह हिन्दुस्तानी हिन्दुओं का अन्तर-क्रौमी रूप होगा.

(2) धारा (1) में किसी बात के रहते भी, इस विधान के आरंभ से पंद्रह बरस के अरसे तक अँगरेजी भाषा यूनियन के उन सब दफ्तरी मतलबों के लिये काम में आती रहेगी जिनके लिये वह विधान के आरंभ से ठीक पहले काम में आती थी :

शर्तेकि राजपति, उस अरसे के दौरान में, हुकुम देकर, अँगरेजी भाषा के साथ साथ हिन्दी भाषा के, और हिन्दुस्तानी हिन्दुओं के अन्तर-क्रौमी रूप के साथ साथ हिन्दुओं के देव नागरी रूप के, यूनियन के दफ्तरी मतलबों में से किसी के लिये काम में लाए जाने का अधिकार दे सकता है.

(3) इस दफ्ता में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत कानून बनाकर पन्द्रह बरस के उस अरसे के बाद—

(ए) अँगरेजी भाषा के, या

(बी) हिन्दुओं के देवनागरी रूप के,

उन मतलबों के लिये जो उस कानून में बताए जायं, काम में लाए जाने का बंधन कर सकती है.

344—(1) राजपति, इस विधान के आरंभ से पांच बरस बीत जाने पर, और उसके बाद विधान के आरंभ से दस बरस बीत जाने पर, हुकुम दे कर, एक कमीशन बनायगा जिसमें एक मसनदी और वह दूसरे मेम्बर होंगे जो आठवीं पट्टी में बताई अलग अलग भाषाओं के प्रतिनिधि हों और जिन्हें राजपति नियोजे, और उस हुकुम में वह दस्तूर तय कर दिया जायगा जिस पर कमीशन चलेगा।

दफ्तरी भाषा पर
कमीशन और
राजपंचायत की
कमेटी

(2) कमीशन का यह फरज होगा कि वह इन बातों के बारे में राजपति से सिफारिशें करे—

(ए) यूनियन के दफ्तरी मतलबों के लिये हिन्दी भाषा का बढ़ता हुआ इस्तेमाल;

(बी) यूनियन के दफ्तरी मतलबों में से सब या किसी के लिये अंगरेजी भाषा के इस्तेमाल पर रुकावटें;

(सी) दफा 348 में बताए मतलबों में से सब या किसी के लिये इस्तेमाल की जाने वाली भाषा;

(डी) यूनियन के किसी एक या अधिक ऐसे मतलबों के लिये जो बता दिये जायं इस्तेमाल किये जाने वाले हिन्दसों का रूप;

(ई) यूनियन की दफ्तरी भाषा, और यूनियन और किसी रियासत के बीच या एक रियासत और दूसरी के बीच आपसी ब्योहार की भाषा, और इन भाषाओं के इस्तेमाल, के संबंध में कोई और मामला जिसे राजपति ने कमीशन के पास राय के लिये भेजा हो।

(3) धारा (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करते समय कमीशन भारत की उद्योगी, कलचरी और साइंसी तरक्की का, और सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में गैर-हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के लोगों के उचित दावों और हितों का, मुनासिब खयाल रखेगा।

(4) तीस मेम्बरों की एक कमेटी बनाई जायगी जिनमें से बीस लोक सदन के मेम्बर होंगे और दस रियासत सदन के, और जिनको, निम्नवती प्रतिनिधान के ढंग के अनुसार इकट्ठे बदलते बोट

के जरिये, लोक सदन के मेम्बर और रियासत सदन के मेम्बर अलग अलग चुनेंगे.

(5) इस कमेटी का फरज होगा कि वह धारा (1) के अधीन बने कमीशन की सिफारिशों को परखे और उन पर अपनी राय की रिपोर्ट राजपति को दे.

(6) दफा 343 में किसी बात के रहते भी, धारा (5) में जिस रिपोर्ट की चरचा की गई है उस पर विचार करने के बाद राजपति उस कुल रिपोर्ट के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश जारी कर सकता है.

खंड दो

इलाका भाशाएँ

किसी रियासत की
दफ्तरी भाशा या
भाशाएँ

345—दफा 346 और 347 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, किसी रियासत की कानून सभा कानून बना कर उस रियासत में काम में आने वाली किसी एक या अधिक भाशाओं को, या हिन्दी को, उस रियासत के सब दफ्तरी मतलबों के लिये या उनमें से किसी के लिये काम में आने वाली भाशा या भाशाओं के तौर पर अपना सकती है:

शर्तें कि जब तक उस रियासत की कानून सभा कानून बना कर दूसरा बन्धान नहीं करती, तब तक उस रियासत के अन्दर उन दफ्तरी मतलबों के लिये, जिनके लिये इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अंगरेजी भाशा काम में आती थी, अंगरेजी भाशा काम में आती रहेगी.

एक रियासत और
दूसरी रियासत के
बीच या किसी
रियासत और यूनि-
यन के बीच आपसी
व्योहार की दफ्तरी
भाशा

346—यूनियन के दफ्तरी मतलबों के लिये इस्तेमाल किये जाने का जिस भाशा को किसी समय अधिकार मिला हुआ हो वही उस समय एक रियासत और दूसरी रियासत के बीच और किसी रियासत और यूनियन के बीच आपसी व्योहार की दफ्तरी भाशा होगी:

शर्तें कि अगर दो या अधिक रियासतें राजी हों कि उन रियासतों के बीच आपसी व्योहार के लिये हिन्दी भाशा दफ्तरी

भाषा होनी चाहिये तो उनके आपसी व्यापार के लिये वह भाषा काम में आ सकती है.

347—इस बात के लिये मांग होने पर, राजपति को अगर यह इतमीनान हो जाय कि किसी रियासत की आबादी का काफी हिस्सा अपने बोलने की किसी भाषा के इस्तेमाल को उस रियासत से मनवाना चाहता है, तो राजपति यह निर्देश दे सकता है कि वह भाषा भी उस सारी रियासत में या उसके किसी भाग में जिस मतलब के लिये राजपति तय कर दे सरकारी तौर पर मान ली जायगी.

किसी रियासत की आबादी की किसी टुकड़ी में बोली जाने वाली भाषा के बारे में खास बन्धान

खंड तीन—आला अदालत, हाईकोर्टों वगैरा की भाषा

348—(1) इस भाग में ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, जब तक राजपंचायत कानून बनाकर कुछ और बन्धान न कर दे तब तक—

आला अदालत में और हाईकोर्टों में और एक्टों, बिलों वगैरा के लिये काम में आने वाली भाषा

(ए) आला अदालत में और हर हाईकोर्ट में सब कार-वाइयां,

(बी) (एक) राजपंचायत के किसी सदन में या किसी रियासत की कानून सभा के सदन या किसी सदन में रखे जाने वाले सब बिलों की और उनपर पेश किये जाने वाले सब सुधारों की प्रमान लिखत,

(दो) राजपंचायत के या किसी रियासत की कानून सभा के पास किये हुए सब एक्टों की और राजपति के या किसी रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के जारी किये हुए सब राजहुकुमों की, प्रमान लिखतें, और

(तीन) उन सब हुकुमों, नियमों, क्रायदों और छुट-कानूनों की प्रमान लिखतें जो इस विधान के अधीन या राजपंचायत के या किसी रियासत की कानून सभा के बनाए किसी कानून के अधीन जारी किये गये हों,

अंगरेजी भाषा में होंगी.

(2) धारा (1) की उप-धारा (ए) में किसी बात के रहते भी, किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख, राजपति की पहले से अनुमति लेकर, हिन्दी भाषा या किसी दूसरी भाषा को जो उस रियासत के किन्हीं दफ्तरी मतलबों के लिये काम में आती हो, उस हाईकोर्ट की कारवाइयों में काम में लाए जाने का अधिकार दे सकता है जिसकी खास जगह उस रियासत में है :

शर्तें कि इस धारा की कोई बात उस हाईकोर्ट के दिये हुए या किये हुए किसी फैसले, डिगरी या हुकुम पर लागू नहीं होगी.

(3) धारा (1) की उपधारा (बी) में किसी बात के रहते भी, जहाँ किसी रियासत की कानूनसभा ने उस रियासत की कानूनसभा में रखे जाने वाले बिलों या पास होने वाले एक्टों में, या उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के जारी किये राजहुकुमों में, या उस उप-धारा के पैरा (3) में जिस किसी हुकुम, नियम, क्रायदे या छुट-कानून की चरचा की गई है उनमें, अँगरेजी भाषा को छोड़ कर किसी दूसरी भाषा का काम में लाया जाना तय कर दिया है, वहाँ उसका अँगरेजी भाषा में अनुवाद, जो उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के अधिकार से उस रियासत के दफ्तरी गजट में निकाला जायगा, इस दफा के अधीन अँगरेजी भाषा में उसकी प्रमान लिखत माना जायगा.

भाषा के संबंध में
कुछ कानूनों के
बनाए जाने के लिये
खास दस्तूर

349—इस विधान के आरंभ से पन्द्रह बरस के अरसे के अन्दर, दफा 348 की धारा (1) में बताए मतलबों में से किसी के लिये काम में आने वाली भाषा का बन्दान करने वाला कोई बिल या सुधार राजपति की पहले से मंजूरी लिये बिना राजपंचायत के किसी सदन में न रखा जायगा, न पेश किया जायगा, और राजपति ऐसे किसी बिल के रखे जाने की या ऐसे किसी सुधार के पेश किये जाने की मंजूरी नहीं देगा सिवाय इसके कि वह दफा 344 की धारा (1) के अधीन बने कमीशन की सिफारिशों पर और उस दफा की धारा (4) के अधीन बनी कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद मंजूरी दे.

खंड चार—खास निर्देश

350—किसी तकलीफ को दूर कराने के लिये, यूनिशन के या किसी रियासत के किसी अफसर या अधिकारी को, यूनिशन में या, जैसी सूरत हो, उस रियासत में काम में आने वाली किसी भी भाशा में, अरज़ी पत्र देने का हर आदमी को हक्क होगा।

तकलीफों के दूर कराने के लिये अरज़ी पत्रों में काम आने वाली भाशा

351—यूनिशन का फ़रज़ होगा कि, हिन्दी भाशा के फैलाव को बढ़ाए, और उसका इस तरह विकास करे कि वह भारत की मिली जुली कलचर के सब अंगों को जाहिर करने का साधन बन सके, और, उसकी आत्मा को छेड़े बिना, जो जो रूप, जो शैली और जो मुहावरे हिन्दुस्तानी में और आठवीं पट्टी में दर्ज भारत की दूसरी भाशाओं में काम में आते हैं उनको उसमें रचा पचा कर, और, जहाँ कहीं जरूरी या चाहनी हो, उसकी शब्दावली के लिये पहले संस्कृत से और फिर दूसरी भाशाओं से शब्द लेकर, उसे मालामाल करे।

हिन्दी भाशा के विकास के लिये निर्देश



भाग अठारह

अचानकी बन्धान

अचानकी
ऐलान का

352—(1) अगर राजपति को इतमीनान हो जाय कि कोई गहरी अचानकी मौजूद है जिससे, चाहे जंग के कारन या बाहरी हमले के कारन या भीतरी गड़बड़ी के कारन भारत की या उसके भूभाग के किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में है, तो वह ऐलान निकाल कर इस बात को जाहिर कर सकता है.

(2) धारा (1) के अधीन जो ऐलान निकाला जाय—

- (ए) उसे बाद के किसी ऐलान से मंसूख किया जा सकता है;
- (बी) उसे राजपंचायत के हर सदन के सामने रखा जायगा;
- (सी) वह दो महीने बीत जाने पर अमल में नहीं रहेगा, जब तक कि उस अरसे के बीत जाने से पहले राजपंचायत के दोनों सदनों ने ठहराव पास करके उस पर रजामन्दी न दे दी हो:

शर्तें कि अगर इस तरह का कोई ऐलान ऐसे समय निकले, जब लोक सदन भंग हो चुका हो, या अगर उप-धारा (बी) में जिस दो महीने के अरसे की चरचा की गई है, उसके अन्दर लोक सदन भंग हो जाय, और रियासत सदन ने ऐलान पर रजामन्दी का ठहराव पास कर दिया हो, पर उस अरसे के बीतने से पहले लोक सदन ने उस ऐलान के बारे में कोई ठहराव पास न किया हो, तो उस तारीख से तीस दिन बीत जाने पर वह ऐलान अमल में नहीं रहेगा, जिस तारीख को लोक सदन के दुबारा बनने के बाद उसकी पहली बैठक हो, जब तक कि उस तीस दिन के अरसे के बीत जाने से पहले ही लोक सदन ने भी उस ऐलान पर रजामन्दी का ठहराव पास न कर दिया हो.

(3) अचानकी का कोई ऐलान, जिसमें यह जाहिर किया गया हो कि जंग या बाहरी हमले या भीतरी गड़बड़ी के कारन भारत की या उसके भूभाग के किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में है,

जंग या उस तरह के किसी हमले या गड़बड़ी के सम्बन्ध शुरू होने से पहले ही निकाला जा सकता है, अगर राजपति को यह इतमीनान हो जाय कि उसका खतरा बिल्कुल सामने है.

353—जब अचानकी का कोई ऐलान अमल में हो तब—

अचानकी के
ऐलान का असर

(ए) इस विधान में किसी बात के रहते भी, यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में किसी रियासत को यह निर्देश देना शामिल होगा कि उस रियासत की काजकारी शक्ति से किस ढंग से काम लिया जाय;

(बी) किसी मामले के बारे में राजपंचायत की कानून बनाने की शक्ति में ऐसे कानूनों के बनाने की शक्ति शामिल होगी जिन से उस मामले के बारे में यूनियन को या यूनियन के अफसरों और अधिकारियों को कोई शक्तियाँ सौंपी जायं और उन पर कोई फरज लगाए जायं या उन्हें शक्तियाँ सौंपने और उन पर फरज लगाने का किसी को अधिकार दिया जाय, भले ही वह मामला ऐसा हो जो यूनियन तालिका में नहीं गिनाया गया है.

354—(1) जिस समय अचानकी का कोई ऐलान अमल में हो उस समय राजपति हुकुम जारी करके यह निर्देश दे सकता है कि दफा 268 से 279 तक की दफाओं के बन्धानों में से सब का या किसी का असर उतने अरसे के लिये जो उस हुकुम में बता दिया गया हो, पर जो किसी सूरत में भी उस माली खाता के खतम होने से आगे नहीं बढ़ेगा जिसमें उस ऐलान पर असर बन्द हो जाय, उन अपवादों या अदल बदल के अधीन होगा जिन्हें राजपति ठीक समझे.

जब अचानकी का कोई ऐलान अमल में हो तब माल-गुजारी के बटवारे के सम्बन्ध के बन्धानों का लागू होना

(2) धारा (1) के अधीन दिया हुआ हर हुकुम दिये जाने के बाद जितनी जरूरी हो सके राजपंचायत के हर सदन के सामने रखा जायगा.

355—यूनियन का फरज होगा कि हर रियासत की बाहरी हमले और भीतरी गड़बड़ी से रक्षा करे, और इस बात को पक्का

रियासतों की बाहरी हमले और भीतरी

गड़बड़ी से रक्षा
करना यूनियन का
फ़रज़

रियासतों में विधानी
मशीन के फ़ौज हो
जाने की सूरत में
बन्धान

करे कि हर रियासत की हुकूमत इस विधान के बन्धानों के अनुसार चलाई जाय.

366—(1) अगर राजपति को किसी रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख से रिपोर्ट मिलने पर, या किसी दूसरी तरह, यह इतमीनान हो जाय कि ऐसी हालत पैदा हो गई है जिसमें इस विधान के बन्धानों के अनुसार उस रियासत की हुकूमत नहीं चलाई जा सकती, तो राजपति ऐलान निकाल कर—

(प) उस रियासत की सरकार के सब या कुछ काम, और उसकी सब या कुछ शक्तियाँ जो रियासतपति या राजप्रमुख को, जैसी सूरत हो, हासिल हैं, या जिनसे वह काम ले सकता है, या जो उस रियासत में, रियासत की क़ानून सभा को छोड़ कर, दूसरी किसी संस्था या अधिकारी को हासिल हैं, या जिनसे वह संस्था या अधिकारी काम ले सकता है, अपने हाथ में ले सकेगा;

(बी) यह जाहिर कर सकता है कि उस रियासत की क़ानून सभा की शक्तियों से राजपंचायत काम ले सकेगी या राजपंचायत के अधिकार के अधीन उन शक्तियों से काम लिया जा सकेगा;

(सी) ऐसे प्रसंगी और परिनामी बन्धान कर सकता है जो उस ऐलान के उद्देशों पर अमल कराने के लिये राजपति को ज़रूरी या चाहनी मालूम हों; इन में ऐसे बन्धान भी शामिल होंगे जो उस रियासत की किसी संस्था या अधिकारी से सम्बन्ध रखने वाले इस विधान के किन्हीं बन्धानों के अमल को पूरे तौर पर या कुछ हद तक मुअत्तल करते हों:

शर्तें कि इस धारा की किसी बात से राजपति को यह अधिकार नहीं होगा कि वह उन शक्तियों में से किसी को अपने हाथ में ले ले जो किसी हाईकोर्ट को हासिल हैं या जिनसे हाईकोर्ट काम ले सकती है, या हाईकोर्टों से सम्बन्ध रखने वाले इस विधान के किसी बन्धान

के अमल को पूरे तौर पर या कुछ हद तक सुअमल कर दे.

(2) हर ऐसा ऐलान बाद के किसी ऐलान से मंसूख किया जा सकता है या बदला जा सकता है.

(3) इस दफा के अधीन हर ऐलान को राजपंचायत के हर सदन के सामने रखा जायगा, और सिवाय उस सूरत में जब कि वह कोई ऐसा ऐलान हो जो किसी पहले ऐलान को मंसूख करता हो, दो महीने बीत जाने पर वह अमल में नहीं रहेगा, जब तक कि उस अरसे के बीत जाने से पहले राजपंचायत के दोनों सदनों ने ठहराव पास करके उस पर रजामन्दी न दे दी हो :

शर्तें कि अगर इस तरह का कोई ऐलान (जो किसी पहले ऐलान को मंसूख करने वाला ऐलान न हो) ऐसे समय निकले जब लोक सदन भंग हो चुका हो, या अगर इस धारा में जिस दो महीने के अरसे की चरचा की गई है, उसके अन्दर लोक सदन भंग हो जाय, और रियासत सदन ने ऐलान पर रजामन्दी का ठहराव पास कर दिया हो, पर उस अरसे के बीतने से पहले लोक सदन ने उस ऐलान के बारे में कोई ठहराव पास न किया हो, तो उस तारीख से तीस दिन बीत जाने पर वह ऐलान अमल में नहीं रहेगा, जिस तारीख को लोक सदन के दुबारा बनने के बाद उसकी पहली बैठक हो, जब तक कि उस तीस दिन के अरसे के बीतने से पहले ही लोक सदन ने भी उस ऐलान पर रजामन्दी का ठहराव पास न कर दिया हो.

(4) जिस ऐलान पर इस तरह रजामन्दी दे दी गई हो, वह, जब तक मंसूख न कर दिया जाय, धारा (3) के अधीन ऐलान पर रजामन्दी देने वाले ठहरावों में से दूसरे ठहराव के पास होने की तारीख से छै महीने का अरसा बीत जाने पर, अमल में नहीं रहेगा :

शर्तें कि अगर और जितनी बार, ऐसे किसी ऐलान के अमल को जारी रखने की रजामन्दी का कोई ठहराव राजपंचायत के दोनों सदनों में पास हो जाय, वो वह ऐलान, जब तक मंसूख न कर दिया जाय, उस तारीख से लेकर जिस से इस धारा के अधीन ठहराव पास न होने की सूरत में वह अमल में न रहता, उतनी ही बार और छै महीने के अरसे तक अमल में रहेगा, पर किसी सूरत में भी

ऐसा कोई ऐलान तीन बरस से ज्यादा अमल में नहीं रहेगा :

और शर्तें कि अगर ऐसे किसी छै महीने के अरसे के अन्दर लोक सदन भंग हो जाय और ऐलान को जारी रखने की रजामन्दी देने वाला ठहराव उस अरसे के अन्दर रियासत सदन में पास हो जाय, पर उस ऐलान के अमल को जारी रखने के बारे में कोई ठहराव उस अरसे के अन्दर लोक सदन में पास न हो, तो लोक सदन के दुबारा बनने के बाद उसकी पहली बैठक की तारीख से तीस दिन बीत जाने पर वह ऐलान अमल में नहीं रहेगा, जब तक कि तीस दिन के उस अरसे के बीतने से पहले ही उस ऐलान के अमल को जारी रखने की रजामन्दी देने वाला ठहराव लोक सदन ने भी पास न कर दिया हो.

दफ़ा 356 के अधीन जारी हुए ऐलान के अधीन क़ानूनकारी शक्तियों से काम लेना

357—(1) जहां दफ़ा 356 की धारा (1) के अधीन जारी होने वाले किसी ऐलान में यह ठहरा दिया गया है कि उस रियासत की क़ानून सभा की शक्तियों से राजपंचायत काम ले सकेगी या राजपंचायत के अधिकार के अधीन उन शक्तियों से काम लिया जा सकेगा वहां—

(ए) राजपंचायत को यह अधिकार होगा कि उस रियासत की क़ानून सभा की क़ानून बनाने की शक्ति राजपति को सौंप दे, और राजपति को यह अधिकार दे दे कि जो शक्ति इस तरह उसे सौंपी गई है उसे वह, उन शर्तों के अधीन जिन्हें राजपति लगाना ठीक समझे, अपनी तरफ़ से किसी ऐसे दूसरे अधिकारी को दे दे जिसे वह इस काम के लिये तय करे;

(बी) राजपंचायत को, या राजपति को, या उस दूसरे अधिकारी को जिसे उप-धारा (ए) के अधीन क़ानून बनाने की इस तरह की शक्ति हासिल हुई है, वह अधिकार होगा कि यूनियन को या उसके अफ़सरों और अधिकारियों को शक्तियां सौंपने और उन पर फ़रज लगाने के लिये, या उनको शक्तियां सौंपने और उन पर फ़रज लगाने का किसी को अधिकार देने के लिये, क़ानून बनाए;

(सी) राजपति को यह अधिकार होगा कि, उन दिनों जब लोक सदन का इजलास न हो रहा हो, रियासत के मूठकोश में से खर्च किये जाने का उस समय तक के लिये अधिकार दे दे जब तक कि राजपंचायत उस खर्च पर अपनी मंजूरी न दे दे.

(2) जिस किसी क़ानून को राजपंचायत या राजपति या कोई दूसरा अधिकारी जिसकी चरचा धारा (1) की उपधारा (ए) में की गई है, रियासत की क़ानून सभा की शक्ति से काम लेते हुए बनाए, और जिसको दफ़ा 356 के अधीन अगर कोई ऐलान जारी न किया गया होता तो राजपंचायत को या राजपति को या ऐसे किसी अधिकारी को बनाने का अधिकार न होता, उसका, अधिकार न होने की हद्द तक, ऐलान के अमल में न रहने के बाद एक बरस का अरसा बीत जाने पर, कोई असर नहीं रहेगा, सिवाय उन बातों के बारे में जो उस अरसे के बीत जाने से पहले ही की जा चुकी हों या करने से छोड़ दी गई हों, जब तक कि वह बंधान जिनका असर इस तरह ख़तम हो जायगा पहले ही मुनासिब क़ानून सभा के एकट के जरिये रद्द न कर दिये गए हों या अदल बदल के साथ या बिना अदल बदल फिर से क़ानून न बना दिये गए हों.

358—उन दिनों जब कि अधानकी का कोई ऐलान अमल में हो, दफ़ा 19 की कोई बात, उस राज की जिसकी परिभाषा भाग तीन में की गई है, इस शक्ति में ठकावट नहीं डालेगी कि वह कोई ऐसा क़ानून बनाए या कोई ऐसा काजकारी काम करे जिसे, अगर भाग तीन के बन्धान न होते, तो उस राज को बनाने या करने का अधिकार होता, लेकिन इस तरह बने किसी क़ानून का, अधिकार न होने की उस हद्द तक, ऐलान का अमल ख़तम होते ही कोई असर नहीं रहेगा, सिवाय उन बातों के बारे में जो उस क़ानून के इस तरह असर न रहने से पहले ही की जा चुकी हों या करने से छोड़ दी गई हों.

अधानकी के दौरान में दफ़ा 19 के बंधानों का मुअत्तल रहना

359—(1) जहां अधानकी का कोई ऐलान अमल में हो, वहां राजपति हुकुम दे कर यह जाहिर कर सकता है कि भाग तीन

अधानकियों के दौरान में भाग तीन

में दिये अधिकारों
पर अमल का
मुअत्तल रहना

में दिये अधिकारों में से उन पर अमल कराने के लिये जो उस हुकुम में बता दिये जायं, किसी अदालत से फरियाद करने का अधिकार उस अरसे तक मुअत्तल रहेगा, और इस तरह बताए अधिकारों पर अमल कराने के लिये किसी अदालत में जो कारवाइयां चल रही होंगी वह सब उस अरसे तक मुअत्तल रहेंगी जिस अरसे तक कि वह ऐलान अमल में रहे, या उस कम अरसे तक जो उस हुकुम में बताया जाय.

(2) ऊपर कहे अनुसार जो हुकुम दिया गया हो उसका फैलाव भारत के सारे भूभाग तक या उस भूभाग के किसी हिस्से तक हो सकता है.

(3) धारा (1) के अधीन दिया हुआ हर हुकुम, दिये जाने के बाद जितनी जरूरी हो सके, राजपंचायत के हर सदन के सामने रखा जायगा.

मालीअचानकी के
बारे में बन्धान

360—(1) अगर राजपति को यह इतमीनान हो जाय कि ऐसी हालत पैदा हो गई है जिससे भारत का या उसके भूभाग के किसी हिस्से का माली टिकाव या उसकी साख खतरे में है, तो वह एक ऐलान निकाल कर इस बात को जाहिर कर सकता है.

(2) दफा 352 की धारा (2) के बन्धान इस धारा के अधीन निकले हुए किसी ऐलान के संबंध में उसी तरह लागू होंगे जिस तरह वह दफा 352 के अधीन जारी हुए अचानकी के किसी ऐलान के संबंध में लागू होते हैं.

(3) उस अरसे के दौरान में जिसमें धारा (1) में बताया कोई ऐलान अमल में हो, यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में किसी रियासत को यह निर्देश देना शामिल होगा कि वह उचित माली ब्योहार के उन असूखों का ध्यान रखे जो उन निर्देशों में बताये गए हों, और ऐसे दूसरे निर्देश देना भी शामिल होगा जिन्हें राजपति इस मतलब के लिये जरूरी और काफ़ी समझे.

(4) इस विधान में किसी बात के रहते भी—

(ए) ऐसे किसी निर्देश में—

(एक) ऐसा बन्धान भी हो सकता है जिससे किसी रियासत

के मामलों के संबंध में नौकरी करनेवाले सब आदमियों या उनकी किसी जमात की तनखाहें और भत्ते घटाना दरकार हो;

(दो) ऐसा बन्धान भी हो सकता है जिससे उन सब नकदी विलों या दूसरे विलों को, जिन पर दफा 207 के बन्धान लागू होते हैं, रियासत की कानून सभा से पास होने के बाद राजपति के विचार के लिये अलग रखा जाना दरकार हो;

(बी) राजपति को यह अधिकार होगा, कि उस अरसे के दौरान में जब इस दफा के अधीन निकला हुआ कोई ऐलान अमल में हो वह यूनियन के मामलों के संबंध में नौकरी करनेवाले सब लोगों की या उनकी किसी जमात की, जिसमें आला अदालत और हाईकोर्टों के जज भी शामिल हो सकते हैं, तनखाहें और भत्ते घटाने के लिये निर्देश जारी करे.

भाग उन्नीस

फुटकर

राजपति और
रियासतपतियों और
राजप्रमुखों की
रक्षा

361—(1) राजपति, या किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख, अपने पद की शक्तियों से काम लेने और उस पद के फरजों को पूरा करने के लिये, या उन शक्तियों से काम लेने और उन फरजों को पूरा करने में जो कोई काम उसने किया हो या उसका किया माना जाता हो उसके लिये, किसी अदालत को जवाबदेह नहीं होगा:

शर्तें कि कोई ऐसी अदालत, पंच अदालत या संस्था, जिसे दफा 61 के अधीन किसी दोशलेखे की जांच के लिये राजपंचायत के किसी सदन ने नियोजा हो या नामजद किया हो, राजपति के चलन की जांच पड़ताल कर सकेगी :

और शर्तें कि इस धारा की किसी बात का यह मतलब नहीं समझा जायगा कि वह भारत सरकार के या किसी रियासत की सरकार के खिलाफ मुनासिब कारवाई करने के किसी आदमी के अधिकार पर रुकावट लगाती है.

(2) राजपति के, या किसी रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के, खिलाफ उसकी पद-मियाद के अन्दर, किसी अदालत में किसी भी तरह की फौजदारी कारवाई न शुरू की जा सकेगी और न जारी रखी जा सकेगी.

(3) राजपति को, या किसी रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख को गिरफ्तार करने या क़ैद करने के लिये कोई हुकुमनामा उसकी पद-मियाद के अन्दर किसी अदालत से जारी नहीं किया जायगा.

(4) राजपति की या किसी रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख की पद-मियाद के अन्दर किसी अदालत में कोई ऐसी दीवानी कारवाई नहीं की जा सकेगी जिसमें राजपति से या उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख से किसी ऐसे काम के बारे में

भरपाई का दावा किया गया हो जो काम राजपति या उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख ने अपना पद संभालने से चाहे पहले या उसके बाद अपनी निजी हैसियत से किया हो, या जो उसका किया माना जाता हो, जब तक कि एक ऐसे लिखे हुए नोटिस को दिये दो महीने न बीत चुके हों जो राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख को, जैसी सूरत हो, दिया गया हो, या उसके दफ्तर में छोड़ दिया गया हो, और जिसमें उस कारवाई की कैफियत, उसके किये जाने का कारन, जो फरीक कारवाई शुरू करने वाला है उसका नाम, व्यौरा और रिहाइश की जगह और जिस भरपाई का वह दावा करता है वह सब बताए गए हों।

362—राजपंचायत की या किसी रियासत की कानून सभा की कानून बनाने की शक्ति से काम लेने में, या यूनियन या किसी रियासत की काजकारी शक्ति से काम लेने में, उस गारंटी या भरोसे का उचित लिहाज रखना होगा जो किसी देसी रियासत के शासक के निजी अधिकारों, निजनियमों और सम्मानों के बारे में किसी ऐसे मुआहदे या समझौते के अधीन दिया गया हो जिसकी चरचा दफा 291 की धारा (1) में की गई है।

देसी रियासतों के शासकों के अधिकार और निजनियम

363—(1) इस विधान में किसी बात के रहते भी, पर दफा 143 के बन्धानों का ध्यान रखते हुए, किसी मगड़े में जो किसी ऐसे सन्धिनामे, समझौते, मुआहदे, इक्करारनामे, सनद या दूसरे इसी तरह के पट्टे के किसी बन्धान से पैदा हुआ हो, जिसे किसी देसी रियासत के शासक ने इस विधान के आरंभ से पहले किया हो या लिखा हो, और जिसमें हिन्द डोमिनियन की सरकार या उसी जगह पर उससे पहले की कोई सरकार एक फरीक रही हो, और जो विधान के आरंभ होने के बाद भी अमल में रहा हो या रखा गया हो, या इसी तरह के किसी संधिनामे, समझौते, मुआहदे, इक्करारनामे, सनद या इसी तरह के दूसरे पट्टे से संबंध रखने वाले इस विधान के बन्धानों में से किसी के अधीन मिलने वाले किसी अधिकार के बारे में या उस बन्धान से पैदा होने वाली किसी देनदारी या जिम्मेदारी के बारे में किसी तरह के मगड़े

कुछ सन्धिनामों, समझौतों वगैरा से पैदा होनेवाले मगड़ों में अदायतों के दखल देने पर रोक

में, न आला अदालत की अमलदारी चलेगी, न किसी दूसरी अदालत की.

(2) इस दफ्ता में—

(ए) “देसी रियासत” के मानी हैं कोई भूभाग जिसे इस विधान के आरम्भ से पहले सम्राट ने या हिन्द डोमिनियन की सरकार ने इस तरह की रियासत मान लिया हो; और

(बी) “शासक” शब्द में वह नरेश, सरदार या दूसरा आदमी शामिल है जिसको विधान के आरम्भ से पहले सम्राट ने या हिन्द डोमिनियन की सरकार ने किसी देशी रियासत का शासक मान लिया हो.

बड़े बन्दरगाहों और
हवाई अड्डों के
लिये खास बंधान

364—(1) इस विधान में किसी बात के रहते भी, राजपति आम नोटिस निकालकर यह निर्देश कर सकता है कि उस तारीख से जो उस नोटिस में बताई गई हो—

(ए) राजपंचायत का या किसी रियासत की कानून सभा का बनाया कोई कानून किसी बड़े बन्दरगाह या हवाई अड्डे पर लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों या अदल बदल के साथ लागू होगा जो उस नोटिस में बता दिये जायं, या

(बी) किसी मौजूदा कानून का किसी बड़े बन्दरगाह या हवाई अड्डे में असर नहीं रहेगा सिवाय उन कामों के बारे में जो उस तारीख से पहले किये जा चुके हों या करने से छोड़ दिये गए हों, या ऐसे बन्दरगाह या हवाई अड्डे पर उस कानून का असर ऐसे अपवादों या अदलबदल के साथ होगा जो उस नोटिस में बता दिये जायं.

(2) इस दफ्ता में—

(ए) “बड़ा बन्दरगाह” के मानी हैं वह बन्दरगाह जो राज-पंचायत के बनाए किसी कानून में या किसी मौजूदा कानून में या ऐसे किसी कानून के अधीन बड़ा

बन्दरगाह ठहरा दिया गया है, और उसमें वह सब क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय उस बन्दरगाह की सीमाओं के अन्दर शामिल हों;

(बी) "हवाई अड्डे" के मानी हैं वह हवाई अड्डा जिसकी परिभाषा हवा मार्गों, हवाई जहाजों और हवाई जहाजरानी से संबंध रखनेवाले कानूनों के मतलबों के लिये की गई है.

365—जहां कोई रियासत ऐसे किसी निर्देशों पर न चल सकी हो या अमल न करा सकी हो जो इस विधान के बन्धानों में से किसी के अधीन यूनियन की काजकारी शक्ति से काम लेते हुए दिये गए हों, तो राजपति के लिये यह क्ररार देना कानून-संगत होगा कि ऐसी हालत पैदा हो गई है जिसमें उस रियासत की हुकूमत इस विधान के बन्धानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती.

यूनियन के दिये निर्देशों पर न चल सकने या उन पर अमल न कर सकने का असर

366—इस विधान में, जब तक कि प्रसंग से कुछ और दरकार न हो, नीचे लिखे शब्दों के वह मानी हैं जो यहां उनमें से हर एक के अलग अलग दिये गए हैं, यानी यह कि—

परिभाषाएं

(1) "खेती बाड़ी की आमदनी" के मानी हैं वह खेती बाड़ी की आमदनी जिसकी परिभाषा भारत आमदनी-टैक्स से संबंध रखनेवाले कानूनों के मतलबों के लिये की गई है;

(2) "ऐंग्लो इन्डियन" के मानी हैं वह आदमी जिसका बाप या जिसके बाप की लाइन में कोई और जनक पुरुष यूरोपियन नसल का है या था, पर जो भारत के भूभाग का निवासी बन गया है, और उस भूभाग के अन्दर ऐसे मां बाप से पैदा हुआ है या पैदा हुआ था जो केवल आरजी मतलबों के लिये यहाँ नहीं रहते थे बल्कि आदतन यहाँ के वासी थे;

(3) "इफ्रा" के मानी हैं इस विधान की कोई इफ्रा;

(4) "उधार लेने" में खालाना क्रिस्तों में अदायगी मंजूर करके रुपया जुटाना शामिल है, और "उधारी" के भी इसी तरह मानी किये जायेंगे;

(5) “धारा” के मानी हैं उस दफा की कोई धारा जिसमें यह शब्द आया हो;

(6) “एकतनी टैक्स” के मानी हैं आमदनी पर कोई टैक्स जहां तक कि वह टैक्स कम्पनियों को भरना है और जो ऐसा टैक्स है जिसमें नीचे लिखी शर्तें पूरी होती हैं :—

(ए) यह कि वह टैक्स खेती बाड़ी की आमदनी के बारे में नहीं लिया जा सकता;

(बी) यह कि उस टैक्स पर लागू होने वाले किसी कानून के जरिये किसी को यह अधिकार न हो कि कम्पनियां जो टैक्स दें उसके बारे में उन लाभ-बटावों में से रुपया काटा जाय जो कम्पनियां लोगों को देती हैं;

(सी) यह कि भारत आमदनी टैक्स के मतलब के लिये इस तरह के लाभ-बटावे पाने वाले लोगों की कुल आमदनी का हिसाब लगाने में, या उस भारत आमदनी टैक्स का हिसाब लगाने में जो इस तरह के लोगों को भरना है या जो उन्हें वापस मिलना है, इस तरह दिये हुए टैक्स को हिसाब में लेने के लिये कोई बन्धान नहीं है;

(7) “जवाबी सूबा”, “जवाबी देसी रियासत”, या “जवाबी रियासत” के मानी हैं, जहां शक हो, वह सूबा, देसी रियासत या रियासत जिसको राजपति उस खास मतलब के लिये जिसका सवाल उठा हो “जवाबी सूबा”, “जवाबी देसी रियासत” या “जवाबी रियासत”, जैसी सूरत हो, तय कर दे;

(8) “कर्ज” में पूँजी की रकमों को सालाना क्रिस्तों में अदा करने की किसी जिम्मेदारी के बारे में हर देनदारी और किसी गारंटी के अधीन हर देनदारी शामिल है, और “कर्जा खर्च” के मानी भी इसी तरह किये जायेंगे ;

(9) “मिलकियत महसूल” के मानी हैं वह महसूल जो उस सब जायदाद की असल क्रीमत पर या असल क्रीमत के हिसाब से आंका जाय जो जायदाद किसी के मरने पर मिलकियत महसूल सम्बन्धी राजपंचायत के बनाए कानूनों या किसी रियासत की कानून

सभा के बनाए कानूनों के बन्धानों के अधीन किसी को मिले या मिली सम्झी जाय; यह असल कीमत उन नियमों के अनुसार तय की जायगी जो ऊपर-लिखे कानूनों में या उनके अधीन बताए गए हों।

(10) “मौजूदा कानून” के मानी हैं कोई कानून, राज-हुकुम, हुकुम, छुट-कानून, नियम या कायदा जो इस विधान के आरंभ से पहले किसी ऐसी कानून सभा, किसी ऐसे अधिकारी या किसी ऐसे आदमी ने पास किया हो या बनाया हो जिसे ऐसा कानून, राज-हुकुम, हुकुम, छुट-कानून, नियम या कायदा बनाने की शक्ति है;

(11) “संघ अदालत” के मानी हैं वह संघ अदालत जो हिन्दू सरकार ऐक्ट 1935 के अधीन बनी थी ;

(12) “माल” में सब सामान, तिजारती माल और चीजें शामिल हैं ;

(13) “गारंटी” में अदायगियां करने की हर वह ज़िम्मेदारी शामिल है जो इस विधान के जारी होने से पहले, किसी कार-बार में, किसी तय की हुई रकम से कम मुनाफ़े होने की सूरत में, अपने ऊपर ली गई हो;

(14) “हाईकोर्ट” के मानी हैं कोई अदालत जो इस विधान के मतलबों के लिये किसी रियासत की हाईकोर्ट सम्झी जाय, और उसमें—

(ए) भारत के भूभाग की हर वह अदालत शामिल होगी जो इस विधान के अधीन हाईकोर्ट बनाई गई हो, या फिर से हाईकोर्ट बनाई गई हो, और

(बी) भारत के भूभाग की हर वह दूसरी अदालत शामिल होगी जिसे राजपंचायत कानून बनाकर इस विधान के मतलबों में से सब या किसी के लिये हाईकोर्ट ठहरा दे.

(15) “देसी रियासत” के मानी हैं कोई भूभाग जिसे हिन्दू डोमिनियन की सरकार ने देसी रियासत माना हो.

(16) “भाग” के मानी हैं इस विधान का कोई भाग.

(17) “पेंशन” के मानी हैं हर तरह की पेंशन, चाहे

वह हिस्सेवारी हो या न हो, जो किसी आदमी को या उसके बारे में दी जानी है, और उसमें सेवा मुक्त लोगों की तनखाह जो किसी आदमी को या उसके बारे में दी जानी है, इनामी रकम जो किसी आदमी को या उसके बारे में दी जानी है, और कोई रकम या रकमों जो प्रोविडेंट फंड की जमा रकमों की वापसी के तौर पर, सूद समेत या बिना सूद या उसमें कुछ और रकम जोड़ कर या न जोड़ कर, किसी आदमी को या उसके बारे में दी जानी हैं, सब शामिल हैं;

(18) “अचानकी का ऐलान” के मानी हैं दफा 352 की धारा (1) के अधीन जारी हुआ कोई ऐलान;

(19) “आम नोटिस” के मानी हैं भारत के गजट में या किसी रियासत के दफ्तरी गजट में, जैसी सूरत हो, निकला नोटिस;

(20) “रेल मार्ग” में—

- (ए) वह ट्राम मार्ग शामिल नहीं है जो कुल किसी नगरायत क्षेत्र में हो, या
- (बी) आवाजाई की कोई और ऐसी लाइन शामिल नहीं है जो कुल किसी एक रियासत में हो और जिसे राजपंचायत ने कानून बनाकर यह ठहरा दिया हो कि वह रेल मार्ग नहीं है;

(21) “राजप्रमुख” के मानी हैं—

- (ए) हैदराबाद रियासत के संबंध में, वह आदमी जिसे उस समय राजपति ने हैदराबाद का निजाम मान लिया हो;
- (बी) जम्मू और काश्मीर रियासत या मैसूर रियासत के संबंध में, वह आदमी जिसे उस समय राजपति ने उस रियासत का महाराजा मान लिया हो; और
- (सी) पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी और रियासत के संबंध में, वह आदमी जिसे उस समय राजपति ने उस रियासत का राजप्रमुख मान लिया हो,

और इसमें उन रियासतों में से किसी के संबंध में वह आदमी भी

शामिल है जिसे उस समय राजपति ने उस रियासत के संबंध में राजप्रमुख की शक्तियों से काम लेने का अधिकारी मान लिया हो;

(22) “शासक” के किसी देसी रियासत के संबंध में मानी हैं वह नरेश, सरदार या दूसरा आदमी जिसने ऐसा कोई मुआहदा या समझौता किया हो जिसकी चरचा दफा 291 की धारा (1) में की गई है और जिसको राजपति ने उस समय उस रियासत का शासक मान लिया हो, और इसमें वह आदमी भी शामिल है जिसको उस समय राजपति ने उस शासक का वरिष्ठ मान लिया हो ;

(23) “पट्टी” के मानी हैं इस विधान के आखार की कोई पट्टी;

(24) “पट्टी-दर्ज जातों” के मानी हैं वे जातें, नसलें या कबीले, या उन जातों, नसलों या कबीलों के भाग, या उनमें के गिरोह, जिनको दफा 341 के अधीन इस विधान के मतलबों के लिये पट्टी-दर्ज जातें समझा गया है;

(25) “पट्टी-दर्ज कबीलों” के मानी हैं वह कबीले या कबायली समाज, या उन कबीलों या कबायली समाजों के भाग, या उनमें के गिरोह, जिनको दफा 342 के अधीन इस विधान के मतलबों के लिये पट्टी-दर्ज कबीले समझा गया है;

(26) “हुन्डियों” में पत्ती पूँजी शामिल है;

(27) “उप-धारा” के मानी हैं उस धारा की कोई उप-धारा जिसमें यह शब्द आया हो;

(28) “टैक्स लगाने” में हर टैक्स या महसूल का लगाना शामिल है, चाहे वह आम हो या मुकामी या खास, और “टैक्स” के भी इसी तरह मानी किये जायंगे;

(29) “आमदनी पर टैक्स” में बढ़ती नफा टैक्स जैसा टैक्स शामिल है;

(30) “उप-राजप्रमुख” के, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत के संबंध में, मानी हैं वह आदमी जिसको उस समय राजपति ने उस रियासत का उप-राजप्रमुख मान लिया हो.

अर्थ

367—(1) जब तक प्रसंग से कुछ और दरकार न हो, तब तक आम धारा एकट (जनरल क्लॉजेज एकट) 1897, ऐसे किन्हीं अनु-कूलनों और अदल बदल का ध्यान रखते हुए जो दफा 372 के अधीन उसमें किये जायं, इस विधान के अर्थ करने में उसी तरह लागू होगा जिस तरह वह हिन्द डोमिनियन की कानून सभा के किसी एकट के अर्थ करने में लागू होता है।

(2) इस विधान में राजपंचायत के एकटों या उसके बनाए हुए कानूनों की, या पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में वर्ज किसी रियासत की कानून सभा के एकटों या उसके बनाए हुए कानूनों की, किसी चरचा का यह मतलब लिया जायगा कि उसमें राजपति के दिये राजहुकुम की, या किसी रियासत-पति या राजप्रमुख के दिये राज हुकुम की, जैसी सूरत हो, चरचा शामिल है।

(3) इस विधान के मतलबों के लिये, “विदेशी राज” के मानी हैं भारत को छोड़ कर कोई और राज :

शर्तें कि, राजपंचायत के बनाए किसी कानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपति हुकुम देकर, उन मतलबों के लिये जो उस हुकुम में बता दिये जायं, किसी राज की बाबत यह ठहरा सकता है कि वह विदेशी राज नहीं है।

भाग बीस

विधान में सुधार

368—इस विधान में किसी सुधार की शुरुआत केवल राज-पंचायत के किसी सदन में इस मतलब के लिये एक बिल रख कर ही की जा सकती है, और जब वह बिल हर सदन में, उस सदन के कुल मेम्बरों की बड़ीयत से, और सदन में उस समय मौजूद और वोट देने वाले मेम्बरों की कम से कम दो तिहाई की बड़ीयत से, पास हो जाय, तो उसे मंजूरी के लिये राजपति के सामने रखा जायगा, और जब बिल पर इस तरह की मंजूरी मिल जाय तब उस बिल की शर्तों के अनुसार विधान में सुधार हो जायगा :

विधान में सुधार
के लिये दस्तूर

शर्तें कि अगर उस सुधार से—

(ए) दफा 54, दफा 55, दफा 73, दफा 162, या
दफा 241 में, या

(बी) भाग पांच के खंड चार, भाग छै के खंड पांच या भाग
ग्यारह के खंड एक में, या

(सी) सातवीं पट्टी की किसी तालिका में, या

(डी) राजपंचायत में रियासतों के प्रतिनिधान में, या

(ई) इस दफा के बन्धानों में,

कोई तबदीली होती हो, तो यह भी दरकार होगा कि, उस सुधार के लिये बंधान करने वाले बिल को मंजूरी के लिये राजपति के सामने रखने से पहले, पहली पट्टी के भाग (ए) और (बी) में दर्ज रियासतों में से कम से कम आधी रियासतों को कानून सभाएँ, उस मतलब के ठहराव पास करके, उस सुधार की तसदीक कर दें.

भाग इक्कीस

आरज़ी और बिचवक्ती बंधान

रियासत तालिका के कुछ मामलों के बारे में राज-पंचायत को क़ानून बनाने की आरज़ी शक्ति, मानो वह मामले संगचारी तालिका में हों

369—इस विधान में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत को, इस विधान के आरंभ से पांच बरस के अरसे तक, नीचे लिखे मामलों के बारे में, उसी तरह क़ानून बनाने की शक्ति होगी मानो वह मामले संगचारी तालिका में गिनाए गए हों, यानी—

(ए) सूती और ऊनी कपड़ों, कच्ची रुई (जिसमें ओटी और अनओटी रुई यानी कपास शामिल हैं), विनौले, कागज (जिसमें न्यूज़ प्रिंट शामिल है), खाने की चीजें (जिसमें खाने के तिलहन और तेल शामिल हैं), ढोरो का चारा (जिसमें खली और दूसरे सार-चारे शामिल हैं), कोयला (जिसमें कोक और कोयले से निकली चीजें शामिल हैं), लोहा, फौलाद, और अबरक का किसी रियासत के अन्दर ब्योपार और तिजारत, और इन चीजों का पैदा करना, मुहय्या करना और बाँटना ;

(बी) धारा (ए) में बताए मामलों में से किसी से सम्बन्ध रखने वाले क़ानूनों के ख़िलाफ़ जुर्म, उन मामलों में से किसी के सम्बन्ध में आला अदालत को छोड़कर सब अदालतों की अमलदारी और शक्तियां, और उन मामलों में से किसी के सम्बन्ध में फीस, जिनमें किसी अदालत में की जाने वाली फीस शामिल नहीं होंगी;

पर राजपंचायत का बनाया हुआ कोई क़ानून, जिसे इस दफ़ा के बन्धानों के न होने पर राजपंचायत बनाने की अधिकारी न होती, उस अधिकार न होने की हद तक, उस अरसे के बीत जाने पर वैधसर हो जायगा, सिवाय उन बातों के बारे में जो उस अरसे के बीत जाने से पहले ही की जा चुकी हों या करने से छोड़ दी गई हों.

370—(1) इस विधान में किसी बात के रहते भी,—

जम्मू और काश्मीर
रियासत के संबंध
में आरज़ी बंधान

(ए) दफ़ा 238 के बन्वान जम्मू और काश्मीर रियासत के संबंध में लागू नहीं होंगे ;

(बी) ऊपर कही रियासत के लिये क़ानून बनाने की राजपंचायत की शक्ति केवल—

(एक) यूनिनयन तालिका और संगचारी तालिका के उन मामलों तक होगी जिनकी बाबत, उस रियासत की सरकार से सलाह करके, राजपति यह ठहरा दे कि यह मामले उन मामलों से मेल रखने वाले मामले हैं जो उस मिलन-पट्टे में दर्ज हैं जिसके अधीन वह रियासत हिन्द डोमिनियन में मिली, और जिन्हें उस मिलन-पट्टे में वह मामले बताया गया है जिनके बारे में डोमिनियन क़ानून सभा उस रियासत के लिये क़ानून बना सकती है; और

(दो) उन तालिकाओं के उन दूसरे मामलों तक होगी जो राजपति, उस रियासत के सरकार की सहमती से, हुकुम जारी करके, बता दे.

समझाव—इस दफ़ा के मतलबों के लिये रियासत की सरकार के मानी हैं वह आदमी जिसको उस समय राजपति ने जम्मू और काश्मीर का महाराजा मान रखा हो और जो उस बज़ीर मंडल की सलाह से काम करता हो जो महाराजा के पांच मार्च सन् 1948 वाले ऐलान के अधीन उस समय पद पर हो.

(सी) दफ़ा (1) के और इस दफ़ा के बन्धान उस रियासत के संबंध में लागू होंगे;

(डी) इस विधान के दूसरे बन्धानों में से वह बन्धान उन अपवादों और अदल बदल के साथ उस रियासत के संबंध में लागू होंगे जो राजपति हुकुम देकर बता दे :

शर्तें कि कोई ऐसा हुकुम जिसका संबंध उस रियासत के उस मिलन-पट्टे में बताए मामलों से है, जिसकी शर्चा उप-धारा (बी) के पैरा (एक) में की गई है, उस रियासत की सरकार से सलाह लिये बिना जारी नहीं किया जायगा :

और शर्तें कि कोई ऐसा हुकुम, जिसका संबंध उन मामलों को

छोड़कर जिनकी चरचा पिछली आखिरी शर्त में की गई है, किन्हीं और मामलों से है, उस रियासत की सहमती के बिना जारी नहीं किया जायगा।

(2) अगर रियासत की सरकार की वह सहमती, जिसकी चरचा धारा (1) की उप-धारा (बी) के पैरा (दो) में या उस धारा की उप-धारा (बी) की दूसरी शर्त में की गई है, उस रियासत का विधान बनाने के मतलब के लिये विधान सभा बुलाए जाने से पहले दे दी जाय, तो वह सहमती उस विधान सभा के सामने ऐसे फैसले के लिये रखी जायगी जो फैसला वह सभा उस पर करे।

(3) इस दफा के उपर-लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, राजपति आम नोटिस निकाल कर यह जाहिर कर सकता है कि यह दफा अमल में नहीं रहेगी, या यह कि वह उस तारीख से केवल उन अपवादों और उन अदल बदल के साथ अमल में रहेगी जो राजपति बता दे:

शर्तें कि राजपति के ऐसा नोटिस निकालने से पहले उस रियासत की उस विधान सभा की सिफारिश जरूरी होगी जिसकी चरचा धारा (2) में की गई है।

पहली पट्टी के भाग
(बी) की रियासतों
के बारे में भारज्जी
बन्धान

371—इस विधान में किसी बात के रहते भी, विधान के आरंभ से दस बरस के अरसे के अन्दर, या इससे अधिक या इससे कम उस अरसे के अन्दर जिसका राजपंचायत किसी रियासत के बारे में कानून बनाकर बन्धान करदे, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज हर रियासत की सरकार राजपति के आम बन्धान में रहेगी और उन खास निर्देशों पर चलेगी, अगर कोई ऐसे निर्देश हों तो, जो राजपति समय समय पर दे :

शर्तें कि राजपति हुकुम देकर निर्देश कर सकता है कि इस धारा के बन्धान उस हुकुम में बताई किसी खास रियासत पर लागू नहीं होंगे।

सौजूदा कानूनों का
अमल जारी रहना
और उनका अनु-
कूलन

372—(1) दफा 395 में जिन कानूनों की चरचा की गई है, इस विधान के जरिये उनके रद्द कर दिये जाने पर भी, पर इस विधान के दूसरे बन्धानों के अधीन रहते हुए, इस विधान के

आरंभ से ठीक पहले भारत के भूभाग में जितने कानून अमल में थे वह सब तब तक उस भूभाग में अमल में रहेंगे जब तक कोई अधिकारी कानून सभा या दूसरा हकदार अधिकारी उन्हें बदल न दे या रह न कर दे या उनमें सुधार न कर दे.

(2) किसी ऐसे कानून के बन्धानों का जो भारत के भूभाग में अमल में हो इस विधान के बन्धानों के साथ मेल बिठाने के लिये, राजपति हुकुम देकर, उस कानून में, चाहे कुछ रह कर के चाहे सुधार करके, ऐसे अनुकूलन और अदल बदल कर सकता है जो जरूरी या समयोचित हों, और यह बन्धान कर सकता है कि उस कानून का असर, उस तारीख से जो उस हुकुम में बताई जाय, उन अनुकूलनों और अदल बदल के अधीन होगा, और ऐसे किसी अनुकूलन या अदल बदल पर किसी अदालत में कोई सवाल नहीं उठाया जायगा.

(3) धारा (2) की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह—

(ए) राजपति को इस विधान के आरंभ होने से दो बरस बीत जाने के बाद किसी कानून में कोई अनुकूलन या अदल बदल करने की शक्ति देती है; या

(बी) किसी अधिकारी कानून सभा या किसी दूसरे हकदार अधिकारी को उस कानून के रह करने या उसमें सुधार करने से रोकती है जिसमें उस धारा के अधीन राजपति ने अनुकूलन या अदल बदल किये हों.

समझाव (1)—इस वक्ता में “अमल में कानून” शब्दों में वह कानून शामिल होगा जिसे इस विधान के आरंभ से पहले भारत के भूभाग के अन्दर किसी कानून सभा या दूसरे हकदार अधिकारी ने पास किया हो या बनाया हो और जो इससे पहले रह न कर दिया गया हो, भले ही वह कानून या उसके कुछ भाग उस समय बिलकुल या किन्हीं खास क्षेत्रों में अमल में न हों.

समझाव (2)—भारत के भूभाग की किसी कानून सभा के या किसी दूसरे हकदार अधिकारी के पास किये हुए या बनाए हुए ऐसे किसी कानून का जिसका इस विधान के आरंभ से ठीक पहले भारत

के भूभाग में असर था और भूभाग-परे भी असर था, उपर कहे किन्हीं अनुकूलनों और बदल बदल के अधीन, वह भूभाग-परे असर जारी रहेगा।

समझाव (3)—इस दफा की किसी बात का यह मतलब नहीं लिया जायगा कि वह किसी ऐसे आरज़ी क़ानून को जो अमल में हो उस तारीख के बाद भी जारी रखती है जो उसके अन्त होने के लिये तय है, या जिस तारीख पर वह क़ानून अन्त हो जाता अगर यह विधान अमल में न आया होता।

समझाव (4)—कोई राजहुकुम जो हिन्द सरकार एक्ट 1935 की दफा 88 के अधीन किसी सूबे के गवर्नर ने जारी किया हो, और जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अमल में हो, अगर पहले ही जवाबी रियासत के रियासतपति ने उसे लौटा न लिया हो, तो विधान आरंभ होने के बाद दफा 382 की धारा (1) के अधीन काम करने वाले उस रियासत के आम सदन की पहली मिलनी से छै हफ्ते बीत जाने पर अमल में नहीं रहेगा, और इस दफा की किसी बात का यह मतलब नहीं लिखा जायगा कि वह ऐसे किसी राजहुकुम को उस अरसे के बाद भी अमल में रखती है।

कुछ एरनों में उन लोगों के बारे में जो रोकथामी नजर-बन्दी में हैं हुकुम देने की राजपति को शक्ति

373—दफा 22 की धारा (7) के अधीन राजपंचायत के कोई बन्धान करने तक, या इस विधान के आरंभ से एक बरस बीत जाने तक, जो भी पहले हो, उस दफा का इस तरह असर होगा मानों उस दफा की धारा (4) और धारा (7) में राजपंचायत की चरचा की जगह राजपति की चरचा की गई है और उन धाराओं में राजपंचायत के बनाए क़ानून की चरचा की जगह राजपति के दिये हुकुम की चरचा की गई है।

संघ अदालत के जजों के बारे में और संघ अदालत में या कौंसिल समेत सम्राट के सामने चालू कारवाइयों के बारे में बन्धान

374—(1) संघ अदालत के वह जज जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अपने पदों पर हों, जब तक कि वह खुद कोई दूसरा फ़ैसला न कर चुके हों, विधान के आरंभ होने पर, आला अदालत के जज हो जायंगे, और उसके बाद वह वही तनखाहें और भत्ते पाने के और छुट्टी और पेनशन के बारे में उन्हीं अधिकारों के हक़दार होंगे जिनका बन्धान दफा 125 में आला अदालत के जजों

के बारे में किया गया है.

(2) इस विधान के आरंभ के समय संघ अदालत में दीवानी या फौजदारी जो नालिशों, अपीलें और कारवाइयाँ, चालू हों वह सब वहाँ से उठ कर आला अदालत में आ जायंगी, और उन्हें सुनने और तय करने की अमलदारी आला अदालत को होगी, और इस विधान के आरंभ से पहले संघ अदालत ने जो फैसले सुना दिये हों या हुकुम दिये हों उनका बल और असर वही होगा मानो वह फैसले या हुकुम आला अदालत ने सुनाए या दिये हों.

(3) इस विधान की किसी बात का यह असर नहीं होगा कि वह कौंसिल समेत सम्राट के उस अमलदारी से काम लेने को ना-सरदुरुस्त ठहरा दे जो कौंसिल समेत सम्राट को भारत के भूभाग के अन्दर की किसी अदालत के किसी फैसले, डिगरी या हुकुम के खिलाफ अपीलें और उनके बारे में प्रार्थनापत्र निपटाने की हसिल है, जहां तक कि कानून उस अमलदारी से काम लेने का अधिकार देता है, और ऐसे किसी अपील या प्रार्थनापत्र पर इस विधान के आरंभ के बाद कौंसिल समेत सम्राट जो कोई हुकुम दे उसका सब मतलबों के लिये वही असर होगा मानो इस विधान से आला अदालत को जो अमलदारी सौंपी गई है उससे काम लेते हुए आला अदालत ने वह हुकुम दिया है या वह डिगरी की है.

(4) इस विधान के आरंभ होने पर और उसके बाद से, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत में प्रीवी कौंसिल की हैसियत से काम करने वाली किसी अधिकारी संस्था की वह अमलदारी नहीं रहेगी जो उसे उस रियासत के अन्दर किसी अदालत के किसी फैसले, डिगरी या हुकुम के खिलाफ अपीलें या उनके बारे में प्रार्थनापत्र लेने और निपटाने की रही हो, और विधान आरंभ होने पर उस अधिकारी संस्था के सामने जो अपीलें और दूसरी कारवाइयाँ चालू होंगी वह सब आला अदालत को तबदील कर दी जायंगी और वही उन्हें निपटायगी.

(5) इस दफा के बंधानों पर अमल कराने के लिये राज-पंचायत कानून बनाकर और भी बंधान कर सकती है.

इस विधान के बंधनों के अधीन रहते हुए अदालतों, अधिकारियों और अफसरों का काम करते रहना

हाईकोर्ट के जजों के बारे में बंधन

375—भारत के सारे भूभाग में, दीवानी, फौजदारी और माली अमलदारी वाली सब अदालतें, और सब न्यायी, काजकारी और वजीरायती अधिकारी और अफसर इस विधान के बंधनों के अधीन रहते हुए अपने अपने काम करते रहेंगे.

376—(1) दफा 217 की धारा (2) में किसी बात के रहते भी, किसी सूबे की हाईकोर्ट के वह जज जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अपने पदों पर हों, जब तक कि वह खुद कोई दूसरा फ़ैसला न कर चुके हों, विधान के आरंभ होने पर, जवाबी रियासत की हाईकोर्ट के जज हो जायंगे, और इसके बाद वह वही तनखाहें और भत्ते पाने के और छुट्टी और पेनशन के बारे में उन्हीं अधिकारों के हकदार होंगे जिनका बंधन उस हाईकोर्ट के जजों के बारे में दफा 221 में किया गया है.

(2) पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की जवाबी देसी रियासत की हाईकोर्ट के जो जज इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अपने पदों पर हों, जब तक कि वह खुद कोई दूसरा फ़ैसला न कर चुके हों, विधान आरंभ होने पर, इस तरह दर्ज रियासत की हाईकोर्ट के जज हो जायंगे, और दफा 217 की धारा (1) और (2) में किसी बात के रहते भी, पर उस दफा की धारा (1) की शर्त के अधीन रहते हुए, वह उस अरसे के बीत जाने तक पद पर रहेंगे जो राजपति हुकुम देकर तय कर दे.

(3) इस दफा में “जज” शब्द में कारकर जज या अधिक जज शामिल नहीं हैं.

भारत के दाब अफसर और सरपड़तालिया के बारे में बंधन

377—हिन्द का वह सरपड़तालिया जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अपने पद पर हो, जबतक कि वह खुद कोई दूसरा फ़ैसला न कर चुका हो, विधान के आरंभ होने पर भारत का दाब अफसर और सरपड़तालिया हो जायगा, और इसके बाद वह वही तनखाहें पाने का और छुट्टी और पेनशन के बारे में उन्ही अधिकारों का हकदार होगा जिनका बन्धान दफा 148 की धारा (3) में भारत के दाब अफसर और सरपड़तालिया के बारे में किया गया है, और वह अपनी उस पद-भियाद के बीत

जाने तक पद पर रहने का हक्कदार होगा, जो पद-मियाद उन बन्धानों के अधीन तय की गई हो जो विधान के आरंभ से ठीक पहले उस पर लागू होते थे।

378—(1) हिन्द डोमिनियन के सरकारी नौकरी कमीशन के वह मेम्बर जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अपने पदों पर हों, जब तक कि वह खुद कोई दूसरा फ़ैसला न कर चुके हों, विधान के आरंभ होने पर यूनियन के सरकारी नौकरी कमीशन के मेम्बर हो जायेंगे, और दफ़ा 316 की धारा (1) और (2) में किसी बात के रहते भी, पर उस दफ़ा की धारा (2) की शर्त के अधीन रहते हुए, अपनी उस पद-मियाद के बीत जाने तक पद पर रहेंगे जो पद-मियाद उन नियमों के अधीन तय की गई हो जो विधान आरंभ होने से ठीक पहले उन मेम्बरों पर लागू होते थे।

सरकारी नौकरी
कमीशन के बारे
में बन्धान

(2) किसी सूबे के सरकारी नौकरी कमीशन के वह मेम्बर या सूबों के किसी गुट की ज़रूरतें पूरी करने वाले सरकारी नौकरी कमीशन के वह मेम्बर जो, इस विधान के आरंभ से ठीक पहले, अपने पदों पर हों, जब तक कि वह खुद कोई दूसरा फ़ैसला न कर चुके हों, विधान के आरंभ होने पर जवाबी रियासत के सरकारी नौकरी कमीशन के मेम्बर या जवाबी रियासतों की ज़रूरतें पूरी करने वाले मिले-जुले रियासत सरकारी नौकरी कमीशन के मेम्बर, जैसी सूरत हो, हो जायेंगे, और दफ़ा 316 की धारा (1) और (2) में किसी बात के रहते भी, पर उस दफ़ा की धारा (2) की शर्त के अधीन रहते हुए, अपनी उस पद-मियाद के बीत जाने तक पद पर रहेंगे जो पद-मियाद उन नियमों के अधीन तय की गई हो जो विधान आरंभ होने से ठीक पहले उन मेम्बरों पर लागू होते थे।

379—(1) जब तक इस विधान के बंधानों के अधीन राज-पंचायत के दोनों सदन क़ायदे से न बन जायें और उन्हें पहले इज-लास के लिये मिलने को न बुलाया जाय, तब तक वह संस्था जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन की विधान सभा की हैसियत से काम कर रही थी कामचलाऊ राजपंचायत हो जायगी, और उन सब शक्तियों से काम लेगी, और उन सब

कामचलाऊ राज-
पंचायत के और
उसके सभामुख और
उप-सभामुख के बारे
में बंधान

फरजों को पूरा करेगी, जो इस विधान के बंधनों से राजपंचायत को सौंपे गए हैं.

समझाव—इस धारा के मतलबों के लिये हिन्द डोमिनियन की विधान सभा में—

(एक) वह मेम्बर जो किसी ऐसी रियासत या दूसरे भूभाग का प्रतिनिधान करने के लिये चुने गए हैं जिसके प्रतिनिधान का बन्धान धारा (2) में किया गया है, और

(दो) वह मेम्बर जो उस सभा में औसरी सूनियां भरने के लिये चुने गए हैं,

शामिल हैं.

(2) राजपति नियम बनाकर—

(ए) धारा (1) के अधीन काम करने वाली कामचलाऊ राजपंचायत में, किसी ऐसी रियासत या दूसरे भूभाग के प्रतिनिधान का, जिसका इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन की विधान सभा में कोई प्रतिनिधि नहीं था,

(बी) उस ढंग का जिस ढंग पर कामचलाऊ राजपंचायत में ऐसी रियासतों या दूसरे भूभागों के प्रतिनिधि चुने जायेंगे, और

(सी) उन जोगताओं का जो ऐसे प्रतिनिधियों में होनी चाहियें, बन्धान कर सकता है.

(3) अगर हिन्द डोमिनियन की विधान सभा का कोई मेम्बर, अक्टूबर सन् 1949 के छठे दिन या उसके बाद इस विधान के आरंभ से पहले किसी समय भी, किसी गवरनरी सूबे की क्रानून सभा के किसी सदन का, या पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की जवाबी देसी रियासत की क्रानून सभा के किसी सदन का, मेम्बर था, या ऐसी किसी रियासत का कोई वजीर था, तो इस विधान के आरंभ होने के बाद से ही विधान सभा में उस मेम्बर की सीट सूनी हो जायगी, जब तक कि इससे पहले ही विधान सभा की उसकी मेम्बरी खतम न हो गई हो, और हर ऐसी

सूनी को औसरी सूनी समझा जायगा.

(4) इस बात के होते भी कि हिन्द डोमिनियन की बिधान सभा में ऐसी कोई सूनी जो धारा (3) में बताई गई है उस धारा के अधीन अभी पैदा नहीं हुई है, उस सूनी को भरने के लिये इस बिधान के आरंभ से पहले ही क़दम उठाए जा सकते हैं, पर ऐसी सूनी को भरने के लिये बिधान के आरंभ से पहले जो आदमी चुना जायगा वह उस सभा में अपनी सीट लेने का तब तक हक़शर नहीं होगा जब तक वह सूनी इस तरह पैदा न हो गई हो.

(5) कोई आदमी जो इस बिधान के आरंभ से ठीक पहले बिधान सभा के सभामुख या उप-सभामुख के पद पर हो, उस समय जब कि बिधान सभा हिन्द सरकार एक्ट 1935 के अधीन डोमिनियन क़ानून सभा की हैसियत से काम कर रही थी, बिधान आरंभ होने पर, धारा (1) के अधीन काम करने वाली कामचलाऊ राजपंचायत का सभामुख या उप-सभामुख, जैसी सूरत हो, हो जायगा.

380—(1) वह आदमी जिसको हिन्द डोमिनियन की बिधान सभा ने इस काम के लिये चुना होगा उस समय तक के लिये भारत का राजपति होगा जब तक कि भाग पांच के खंड एक में दिये बंधानों के अनुसार कोई राजपति न चुना जाय और वह अपना पद न संभाल ले.

राजपति के बारे में
बंधान

(2) हिन्द डोमिनियन की बिधान सभा ने जिस आदमी को इस तरह राजपति चुना हो, उसके मर जाने, इस्तीफ़ा देने या हटाए जाने या किसी दूसरे कारन से उसका पद सूना हो जाने की सूरत में, उस सूनी को वह आदमी भरेगा जिसको दफ़ा 379 के अधीन काम करने वाली कामचलाऊ राजपंचायत इस काम के लिये चुने, और जब तक कोई आदमी इस तरह नहीं चुना जाता तब तक भारत का सर जज राजपति का काम करेगा.

381—वह आदमी जिनको राजपति इस काम के लिये नियोजे, इस बिधान के अधीन राजपति के वज़ीर मंडल के मेम्बर हो जायंगे और जब तक इस तरह के नियोजन नहीं किये जाते तब तक वह

राजपति का वज़ीर
मंडल

सब आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन के वजीरों की हैसियत से अपने पद पर थे, विधान आरंभ होने पर, विधान के अधीन राजपति के वजीर मंडल के मेम्बर हो जायेंगे और अपने पदों पर बने रहेंगे।

पहली पट्टी के भाग (ए) की रियासतों के लिये काम चलाऊ क़ानून सभाओं के बारे में बंधान

382—(1) पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज हर रियासत की क़ानून सभा का सदन या उसके दोनों सदन जब तक इस विधान के बंधानों के अधीन क़ायदे से न बन जायें और उस सदन को या उन सदनों को पहले इजलास के लिये मिलने को न बुलाया जाय, तब तक जबाबी सूबे की क़ानून सभा का वह सदन या उसके वह सदन जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले काम कर रहा था या कर रहे थे, उन शक्तियों से काम लेगा या लेंगे और उन फ़रज़ों को पूरा करेगा या करेंगे जो इस विधान के बंधानों से उस रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों को सौंपे गए हैं।

(2) धारा (1) में किसी बात के रहते भी, जहाँ कहीं इस विधान के आरंभ से पहले किसी सूबे के आम सदन (लेजिस्लेटिव एसेम्बली) के फिर से बनने के लिये आम चुनाव का हुक्म दिया जा चुका है, वहाँ विधान के आरंभ के बाद वह चुनाव इस तरह पूरा किया जा सकता है मानो यह विधान अमल में आया ही न हो, और जो आम सदन इस तरह फिर से बने वह उस धारा के मतलबों के लिये उस सूबे का आम सदन समझा जायगा।

(3) कोई आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले किसी सूबे के आमसदन (लेजिस्लेटिव एसेम्बली) के सभामुख या उप-सभामुख या खास सदन (लेजिस्लेटिव कौंसिल) के सदर या नायब सदर के पद पर हो, इस विधान के आरंभ पर, पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज जबाबी रियासत के आम सदन का सभामुख या उप-सभामुख या खास सदन का मसनवी या उप-मसनवी, जैसी सूरत हो, होगा, जब तक कि वह आम सदन या खास सदन धारा (1) के अधीन काम करे:

शर्तें कि जहाँ इस विधान के आरंभ से पहले किसी सूबे के आम सदन के फिर से बनने के लिये आम चुनाव का हुक्म दे दिया गया

है और इस तरह फिर से बने आम सदन की पहली मिलनी विधान आरंभ होने के बाद होती है तो इस धारा के बंधान लागू नहीं होंगे, और इस तरह फिर से बना आम सदन अपने दो मेम्बरों को अलग अलग सदन का सभामुख और उप-सभामुख चुन लेगा।

383—कोई आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले किसी सूबे के गवर्नर के पद पर हो, विधान आरंभ होने पर पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज जवाबी रियासत का रियासतपति होगा, जब तक कि भाग छै के खंड दो के बंधानों के अनुसार नए रियासतपति का नियोजन न हो जाय और वह अपना पद न संभाल ले।

सूबों के गवर्नरों के बारे में बंधान

384—वह आदमी जिनको किसी रियासत का रियासतपति इस काम के लिये नियोजे इस विधान के अधीन रियासतपति के वज़ीर मंडल के मेम्बर हो जायेंगे और जब तक इस तरह नियोजन नहीं किये जाते तब तक वह सब आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी सूबे के वज़ीरों के पद पर थे, विधान आरंभ होने पर इस विधान के अधीन उस रियासत के रियासतपति के वज़ीर मंडल के मेम्बर हो जायेंगे और अपने पदों पर बने रहेंगे।

रियासतपतियों के वज़ीर मंडल

385—जब तक पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की क़ानून सभा का सदन या दोनों सदन इस विधान के बन्धानों के अधीन क़ायदे से न बन जायें और पहले इजलास के लिये मिलने को न बुलाए जायें, तब तक वह संस्था या अधिकारी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी देसी रियासत की क़ानून सभा की हैसियत से काम कर रही थी या कर रहा था उन शक्तियों से काम लेगी या लेगा और वह फ़रज़ पूरे करेगी या करेगा जो इस तरह दर्ज रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों को इस विधान के बन्धानों से सौंपे गए हैं।

पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों में काम-चलाऊ क़ानून सभाओं के बारे में बन्धान

386—वह आदमी, जिनको पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत का राजप्रमुख इस काम के लिये नियोजे, इस विधान के अधीन उस राजप्रमुख के वज़ीर मंडल के मेम्बर हो जायेंगे, और जब तक इस तरह के नियोजन नहीं किये जाते तब तक वह सब

पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों के लिये वज़ीर मंडल

आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जबाबी देसी रियासत के बज्जियों के पद पर थे, विधान आरंभ होने पर, इस विधान के अधीन, उस राजप्रमुख के बज्जीर मंडल के मेम्बर हो जायेंगे और अपने पदों पर बने रहेंगे.

कुछ चुनावों के मतलबों के लिये आबादी तय करने के बारे में खास बन्धान

387—इस विधान के आरंभ से तीन बरस के अरसे के अन्दर, इस विधान के बंधानों में से किसी के अधीन होने वाले चुनावों के मतलबों के लिये, भारत की या उसके किसी भाग की आबादी, इस विधान में किसी बात के रहते भी, उस ढंग से तय की जा सकती है जिसका राजपति हुकुम दे कर निर्देश करे, और ऐसे हुकुम में अलग अलग रियासतों के लिये और अलग अलग मतलबों के लिये अलग अलग बंधान किये जा सकते हैं.

कामचलाऊ राज-पंचायत में और रियासतों की काम-चलाऊ कानून समारों में औसरी सूनियों को भरने के बारे में बन्धान

388—(1) दफा 379 की धारा (1) के अधीन काम करने वाली कामचलाऊ राजपंचायत के मेम्बरों की सीटों में औसरी सूनियों का भरा जाना, जिनमें उस दफा की धारा (3) और (4) में जिन सूनियों की चरचा की गई है वह शामिल होगी, और उन सूनियों को भरने के संबंध में सब मामलों की क्रायदाबन्दी (जिनमें ऐसी सूनियों को भरने के चुनावों से पैदा होने वाली या उनके संबंध में शंकाओं और म्हागड़ों का फ़ैसला शामिल है)—

(ए) उन नियमों के अनुसार होगी जो राजपति इस काम के लिये बनाए, और

(बी) जब तक इस तरह नियम नहीं बनते तब तक उन नियमों के अनुसार होगी जो, हिन्दू डोमिनियन की विधान सभा में, औसरी सूनियों को भरने और उससे संबंध रखने वाले मामलों के बारे में, इन सूनियों को भरने के समय या इस विधान के आरंभ से ठीक पहले, जैसी सूरत हो, अमल में हों, उन नियमों में ऐसे अपवादों और बदल बदल का ध्यान रखते हुए जो विधान के आरंभ से पहले विधान सभा का सदर और उसके बाद भारत का राजपति उन में कर दे :

शर्तें कि जहाँ ऐसी किसी सीट पर, जिसकी चरचा इस धारा में

की गई है, सूनी होने से ठीक पहले, किसी सूबे का या जैसी सूरत हो पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज किसी रियासत का कोई प्रतिनिधि किसी पट्टी-दर्ज जाति का या मुसलिम समाज का या सिख समाज का हो वहां जब तक विधान सभा का सदर या भारत का राजपति, जैसी सूरत हो, दूसरी तरह का बन्धान करना ज़रूरी या समयोचित न समझे तब तक उस सीट को भरने वाला आदमी वही समाज का होगा :

और शर्त कि पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज किसी रियासत के या किसी सूबे के प्रतिनिधि की सीट की ऐसी किसी सूनी को भरने के लिये जो चुनाव किया जाय उसमें उस सूबे के, या उस जवाबी रियासत के, या उस रियासत के, जैसी सूरत हो, आम सदन का हर मेम्बर भाग लेने और वोट देने का हकदार होगा;

समझाव—इस धारा के मतलबों के लिये—

(ए) उन सब जातों, नसलों या कबीलों को, या उन जातों, नसलों या कबीलों के भागों को, या उनके अन्दर के गिरोहों को, जिनको हिन्दू सरकार (पट्टी दर्ज जातें) हुकुम, 1936, में, किसी सूबे के संबंध में पट्टी-दर्ज जातें बताया गया है, उस सूबे के या उसकी जवाबी रियासत के संबंध में तब तक पट्टी-दर्ज जातें समझा जायगा जब तक कि राजपति ने दफ्ता 341 की धारा (1) के अधीन एक नोटिस जारी न कर दिया हो जिसमें उस जवाबी रियासत के संबंध की पट्टी-दर्ज जातें बता दी गई हों;

(बी) किसी सूबे या रियासत में सारी पट्टी दर्ज जातों को एक समाज समझा जायगा.

(2) दफ्ता 382 या दफ्ता 385 के अधीन काम करने वाली किसी रियासत की कानून सभा के किसी सदन के मेम्बरों की सीटों में औसरी सूनियों को उन बंधानों के अनुसार भरा जायगा और ऐसी सूनियों को भरने के संबंध के सब मामलों की (जिनमें ऐसी सूनियों को भरने के चुनावों से पैदा होने वाली या उनके संबंध में शंकाओं और झगड़ों का फैसला शामिल है) कायदाबन्दी

उन बन्धानों के अनुसार की जायगी जिनके अधीन ऐसी सूनियां भरी जाती थीं और जिनसे ऐसे मामलों की क्रायदाबन्दी होती थी, और जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अमल में थे, पर उन अपवादों और अदल बदल का ध्यान रखते हुए जिनका राजपति हुक्म दे कर निर्देश कर दे.

डोमिनियन कानून सभा में और सुबों और देसी रियासतों की कानून सभाओं में पेश बिलों के बारे में बन्धान

389—कोई बिल जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन की कानून सभा में या किसी सूबे या देसी रियासत की कानून सभा में पेश था, इस बात के खिलाफ किसी ऐसे बन्धान का ध्यान रखते हुए जो इस विधान के अधीन राजपंचायत के या जवाबी रियासत की कानून सभा के बनाए नियमों में शामिल हो, राजपंचायत में या जवाबी रियासत की कानून सभा में, जैसी सूरत हो, उसी तरह चालू रह सकता है मानो हिन्द डोमिनियन की कानून सभा में या उस सूबे या उस देसी रियासत की कानून सभा में उस बिल के सम्बन्ध में जो कारबाइयां की गई थीं वह राजपंचायत में या जवाबी रियासत की कानून सभा में की गई हों.

विधान के आरंभ और 31 मार्च सन् 1950 के बीच जो रकमें मिलें या जुटाई जायं या जो खर्च किया जाय

390—इस विधान के जो बन्धान भारत के मूठकोश या किसी रियासत के मूठकोश से संबंध रखते हैं, और जो इनमें से किसी कोश से रकमों को खर्च की मदों में डालने से संबंध रखते हैं वह उन रकमों के या उस खर्च के संबंध में नहीं लागू होंगे जो रकमें भारत सरकार को या किसी रियासत की सरकार को इस विधान के आरंभ और मार्च सन् 1950 के इकतीसवें दिन के बीच, इन दोनों दिनों को लेकर, मिलें, या जिन्हें वह जुटावे, या जो खर्च बह करे, और इस अरसे में जो खर्च किया जायगा वह क्रायदे से अधिकारा हुआ समझा जायगा अगर वह खर्चा अधिकारे खर्च की किसी ऐसी पट्टी में दर्ज था जिसको हिन्द सरकार एक्ट, 1935, के बंधानों के अनुसार हिन्द डोमिनियन के गवरनर जनरल ने या जवाबी सूबे के गवरनर ने सही कर दिया था, या ऐसा खर्चा है जिसे उस रियासत के राजप्रमुख ने उन नियमों के अनुसार अधिकारा है जो नियम इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी देसी रियासत

की मालगुजारी में से खर्चा अधिकारे जाने पर लागू थे.

391—(1) अगर इस विधान के पास होने और उसके आरंभ होने के बीच किसी समय, हिन्द सरकार एक्ट, 1935, के बंधानों के अधीन कोई ऐसी कारवाई की जाय जिससे राजपति की राय में पहली पट्टी और चौथी पट्टी में कोई सुधार दरकार हो, तो राजपति, इस विधान में किसी बात के रहते भी, हुकुम देकर उन पट्टियों में इस तरह के सुधार कर सकता है जो उस कारवाई पर अमल कराने के लिये जरूरी हों, और ऐसे किसी हुकुम में ऐसे पूरक, प्रसंगी और परिनामी बंधान भी हो सकते हैं जिन्हें राजपति जरूरी समझे.

(2) जब पहली पट्टी या चौथी पट्टी में इस तरह सुधार हो जाय, तो इस विधान में उस पट्टी की जहां कहीं चरचा की गई है उससे यह मतलब लिया जायगा कि वह इस तरह सुधारी हुई पट्टी की ही चरचा है.

392—(1) राजपति किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के मतलब से, खासकर उन कठिनाइयों को जो हिन्द सरकार एक्ट 1935 के बन्धानों से इटकर इस विधान के बन्धानों तक आने से संबंध रखती हैं, हुकुम देकर निर्देश कर सकता है कि उस अरसे के दौरान में, जो उस हुकुम में बताया जाय, इस विधान पर उन अनुकूलनों के अधीन अमल होगा जिन्हें राजपति जरूरी या समयोचित समझे, चाहे उन अनुकूलनों के जरिये इस विधान में कुछ अदल बदल की गई हो, या जोड़ा गया हो, या छोड़ दिया गया हो:

शर्तें कि भाग पाँच के खंड दो के अधीन क़ायदे से बनी राजपंचायत की पहली मिलनी के बाद इस तरह का कोई हुकुम नहीं दिया जायगा.

(2) हर हुकुम जो धारा (1) के अधीन दिया जाय राज-पंचायत के सामने रखा जायगा.

(3) इस दफा से, दफा 324 से, दफा 367 की धारा (3) से और दफा 391 से जो शक्तियां राजपति को सौंपी गई हैं उनसे इस विधान के आरंभ से पहले हिन्द डोमिनियन का गवरनर जनरल काम ले सकेगा.

कुछ जोगाजोगों में राजपति को पहली और चौथी पट्टियों में सुधार करने की शक्ति

कठिनाइयों को दूर करने की राजपति को शक्ति

भाग बाईस

छोटा सरनामा, आरंभ, और रह

छोटा सरनामा

393—इस विधान को भारत का विधान कहा जाय.

आरम्भ

394—यह दफा और दफा 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 फौरन अमल में आ जायंगी, और इस विधान के बाक़ी बंधान जनवरी सन 1950 के छब्बीसवें दिन अमल में आयंगे; उस दिन की, इस विधान में, इस विधान का आरंभ कह कर चरचा की गई है.

रह

395—हिन्द आज़ादी एक्ट 1947, और हिन्द सरकार एक्ट 1935, उन सब क़ानूनों के साथ जो हिंद सरकार एक्ट 1935 में सुधार करते हैं, या उसके पूरक हैं, इस दफा से रह किये जाते हैं, पर उन क़ानूनों में प्रीवी कौंसिल अमलदारी अन्त एक्ट, 1949, शामिल नहीं है.

पहली पट्टी

(दफा 1, 4 और 391)

भारत की रियासतें और उसके भूभाग

भाग (ए)

रियासतों के नाम	जवाबी सूचों के नाम
1. आसाम	आसाम
2. बिहार	बिहार
3. बम्बई	बम्बई
4. मध्यप्रदेश	मध्य प्रान्त और बरार
5. मद्रास	मद्रास
6. उड़ीसा	उड़ीसा
7. पंजाब	पूरब पंजाब
8. युक्त प्रान्त*	युक्त प्रान्त
9. पच्छिम बंगाल	पच्छिम बंगाल

रियासतों के भूभाग

आसाम रियासत के भूभाग में वह भूभाग शामिल होंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले आसाम के सूबे, खासी रियासतों और आसाम कबायली क्षेत्रों में शामिल थे.

पच्छिम बंगाल की रियासत के भूभाग में वह भूभाग शामिल होगा जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले पच्छिम बंगाल के सूबे में शामिल था.

इस भाग की दूसरी रियासतों में से हर एक के भूभाग में वह भूभाग शामिल होंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी सूबे में और उन भूभागों में शामिल थे जिनका शासन हिन्द सरकार एक्ट 1935 की दफा 290 (प) के अधीन बने हुकुम की रू से विधान के आरंभ से ठीक पहले इस तरह किया जाता था मानो वह उस सूबे के भाग हैं.

भाग (बी)

रियासतों के नाम

1. हैदराबाद
2. जम्मू और काश्मीर
3. मध्य भारत
4. मैसूर
5. पटियाला और पूरब पंजाब रियासत यूनियन
6. राजस्थान
7. सौराष्ट्र
8. ट्रावनकोर - कोचीन
9. विन्ध्य प्रदेश

रियासतों के भूभाग

इस भाग की रियासतों में से हर एक के भूभाग में वह भूभाग शामिल होगा जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी देसी रियासत में शामिल था, और—

(ए) राजस्थान और सौराष्ट्र रियासतों में से हर एक की सूरत में उनमें वह भूभाग भी शामिल होंगे जिनका शासन विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी देसी रियासत की सरकार, चाहे सूबा-परे अमलदारी एक्ट 1947 के बन्धानों के अधीन, या दूसरी तरह, करती थी ; और

(बी) मध्यभारत रियासत की सूरत में उसमें वह भूभाग भी शामिल होगा जो विधान के आरंभ से ठीक पहले चीफ कमिशनर के सूबे पंथ पिपलोदा में शामिल था.

भाग (सी)

रियासतों के नाम

1. अजमेर
2. भोपाल
3. बिलासपुर

4. कूच बिहार
5. कुर्ग
6. दिल्ली
7. हिमाचल प्रदेश
8. कच्छ
9. मनीपुर
10. त्रिपुरा

रियासतों के भूभाग

अजमेर, कुर्ग और दिल्ली रियासतों में से हर एक के भूभाग में वह वह भूभाग शामिल होगा जो, इस विधान के आरंभ से ठीक पहले, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग और दिल्ली के चोफ कमिशनरी सूबों में अलग अलग शामिल था।

इस भाग की दूसरी रियासतों में से हर एक के भूभाग में वह वह भूभाग शामिल होंगे जिनका शासन, हिन्द सरकार एक्ट 1935 की क्सा 290 (ए) के अधीन बने हुकुम की रू से, इस विधान के आरंभ से ठीक पहले, इस तरह किया जाता था मानो वह भूभाग उसी नाम का चीफ कमिशनरी सूबा हैं।

भाग (डी)

अन्दमान और निकोबार टापू.

दूसरी पट्टी

[दफा 59 (3), 65 (3), 75 (6), 97, 125, 148 (3), 158 (3), 164 (5), 186 और 221]

भाग (ए)

राजपति के और पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज रियासतों के रियासतपतियों के बारे में बंधान

1—राजपति को और पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज रियासतों के रियासतपतियों को हर महीने नीचे लिखे वेतन दिये जायेंगे, यानी—

राजपति 10,000 रुपए

रियासत का रियासतपति 5,500 रुपए

2—राजपति को और इस तरह दर्ज रियासतों के रियासतपतियों को वह भत्ते भी दिये जायेंगे जो, इस विधान के आरंभ से ठीक पहले, हिन्द डोमिनियन के गवर्नर जनरल को और जवाबी सूबों के गवर्नरों को अलग अलग देने होते थे.

3—राजपति और ऐसी रियासतों के रियासतपति अपनी अपनी पद-मियाद भर में उन्हीं निजनियमों के हकदार होंगे जिनके गवर्नर जनरल और जवाबी सूबों के गवर्नर अलग अलग इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हकदार थे.

4—जब उप-राजपति या कोई दूसरा आदमी राजपति के कामों को निभार रहा हो, या राजपति की जगह काम कर रहा हो, या कोई आदमी रियासतपति के कामों को निभार रहा हो, तो वह उन्हीं वेतनों, भत्तों और निजनियमों का हकदार होगा जिनका वह राजपति या वह रियासतपति हकदार था जिसके कामों को वह निभार रहा है या जिसकी जगह वह काम कर रहा है, जैसी सूरत हो.

भाग (बी)

यूनियन के और पहली पट्टी के भाग (ए) और भाग (बी)

की रियासतों के वज्जोरों के बारे में बंधान

5—यूनियन के प्रधान वज्जोर को और दूसरे वज्जोरों में से हर एक को वह तनखाहें और भत्ते दिये जायंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन के प्रधान वज्जोर को और दूसरे वज्जोरों में से हर एक को अलग अलग देने होते थे.

6—पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज हर रियासत के वज्जोरों को वह तनखाहें और भत्ते दिये जायंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी सूबे या जवाबी देशी रियासत के वज्जोरों को, जैसी सूरत हो, देने होते थे.

भाग (सी)

लोक सदन के सभामुख और उप-सभामुख, रियासतसदन

के मसनदी और उप-मसनदी, पहली पट्टी के भाग

(ए) की हर रियासत के आमसदन के सभामुख और

उप-सभामुख, और ऐसी हर रियासत के खास सदन

के मसनदी और उप-मसनदी के बारे में बंधान

7—लोक सदन के सभामुख और रियासत सदन के मसनदी को वह तनखाहें और भत्ते दिये जायंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्दडोमिनियन की विधानसभा के सभामुख को देने होते थे, और लोक सदन के उप-सभामुख और रियासत सदन के उप-मसनदी को वह तनखाहें और भत्ते दिये जायंगे जो विधान आरंभ होने से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन की विधान सभा के उप-सभामुख को देने होते थे.

8—पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज हर रियासत के आम सदन के सभामुख और उप-सभामुख को और उस रियासत के खास सदन के मसनदी और उप-मसनदी को वह तनखाहें और भत्ते दिये जायंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी सूबे के आम सदन (लेजिस्लेटिव एसेम्बली) के सभामुख और उप-सभा-

मुख को और खाससदन (लेजिस्लेटिव कौंसिल) के सदर और नायब सदर को अलग अलग देने होते थे, और जहाँ विधान आरंभ होने से ठीक पहले जवाबी सूबे में लेजिस्लेटिव कौंसिल नहीं थी वहाँ उस रियासत के खास सदन के मसनदी और उप-मसनदी को वह तनखाहें और भत्ते दिये जायेंगे जो उस रियासत का रियासतपति तय करे.

भाग (डी)

आला अदालत के जजों के बारे में और पहली पट्टीके भाग (ए) की रियासतों की हाईकोर्टों के जजों के बारे में बंधान

9—(1) आला अदालत के जजों को, जितने दिनों वह असल नौकरी पर रहें उतने दिनों के बारे में, हर महीने नीचे लिखी दर से तनखाह दी जायगी, यानी —

सरजज 5, 000 रुपए

हर दूसरा जज 4, 000 रुपए

शर्तें कि अगर आला अदालत के किसी जज को उसके नियोजन के समय, हिन्द सरकार के अधीन, या उस जगह उससे पहले की सरकारों में से किसी के अधीन, या किसी रियासत की सरकार के अधीन, या उस जगह उससे पहले की सरकारों में से किसी के अधीन, किसी पहले की नौकरी के बारे में, (अपाहिजी पेनशन या घायल पेनशन को छोड़ कर) कोई पेनशन मिलती हो तो आला अदालत की नौकरी की उसकी तनखाह में से उस पेनशन की रकम के बराबर रकम कम कर दी जायगी.

(2) आला अदालत का हर जज, बिना किराया दिये, सरकारी मकान के इस्तेमाल का हकदार होगा.

(3) इस पैरा के उप-पैरा (2) की कोई बात किसी ऐसे जज पर, जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले,—

(ए) संघ अदालत के सरजज के पद पर था और विधान आरंभ होने पर दफ्ता 374 की धारा (1) के अधीन आला अदालत का सरजज हो गया है, या

(बी) संघ अदालत के किसी दूसरे जज की हैसियत से पद पर

था और विधान आरंभ होने पर उस धारा के अधीन आला अदालत का (सर जज को छोड़कर कोई दूसरा) जज हो गया है,

उस अरसे के दौरान में जब वह इस तरह के सरजज या दूसरे जज की हैसियत से पद पर रहे, लागू न होगी, और हर वह जज, जो इस तरह आला अदालत का सरजज या दूसरा जज हो जाय, उतने दिनों के बारे में जितने दिन वह सरजज या दूसरे जज की हैसियत से, जैसी सूरत हो, जितने दिन वह असल नौकरी पर रहे, इस पैरा के उप-पैरा (1) में बताई तनखाह के अलावा एक खास तनखाह के रूप में वह रकम पाने का हकदार होगा जो इस तरह बताई तनखाह और इस विधान के आरंभ से ठीक पहले उसे मिलने वाली तनखाह के फरक के बराबर है.

(4) आला अदालत का हर जज भारत के भूभाग के अन्दर सरकारी काम पर सफर करने में जो खर्च करेगा उसको पूरा करने के लिये उसे वह उचित भत्ते मिलेंगे और सफर के संबंध में उसे वह उचित सुविधाएँ दी जायेंगी जो राजपति समय समय पर तय करे.

(5) आला अदालत के जजों को छुट्टी (छुट्टी के भत्तों समेत) और पेनशन के बारे में अधिकार उन बंधानों के अधीन रहेंगे जो इस विधान के आरंभ होने से ठीक पहले संघ अदालत के जजों पर

10—(1) पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज हर रियासत की हाई-कोर्ट के जजों को जितने दिनों वह असल नौकरी पर रहें, उतने दिनों के बारे में हर महीने नीचे लिखी दर से तनखाहें दी जायेंगी यानी —

सरजज	4,000 रुपए
हर दूसरा जज	3,000 रुपए

(2) हर वह आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले—

(ए) किसी सूबे में किसी हाईकोर्ट के सरजज के

पद पर था और विधान आरंभ होने पर दफ्ता 376 की धारा (1) के अधीन जवाबी रियासत की हाईकोर्ट का सरजज हो गया है, या

(बी) किसी सूबे में किसी हाईकोर्ट के किसी दूसरे जज के पद पर था और विधान आरंभ होने पर उस धारा के अधीन जवाबी रियासत में हाईकोर्ट का (सरजज को छोड़कर) कोई जज हो गया है,

अगर विधान आरंभ होने से ठीक पहले वह इस पैरा के उप-पैरा (1) में बताई दर से अधिक तनखाह पा रहा था तो, सरजज की या किसी दूसरे जज की हैसियत से, जैसी सूरत हो, जितने दिनों वह असल नौकरी पर रहे उतने दिनों के बारे में, उस उप पैरा में बताई तनखाह के अलावा खास तनखाह के रूप में वह रकम पाने का हकदार होगा जो इस तरह बताई तनखाह और विधान आरंभ होने से ठीक पहले उसे मिलने वाली तनखाह के फ़रक के बराबर है.

(3) हाईकोर्ट का हर जज भारत के भूभाग के अन्दर सरकारी काम पर सफ़र करने में जो खर्च करेगा उसको पूरा करने के लिये उसे वह उचित भत्ते मिलेंगे और सफ़र के संबंध में उसे वह उचित सुविधाएँ दी जायेंगी जो राजपति समय समय पर तय करे.

(4) किसी रियासत की हाईकोर्ट के जजों को छुट्टी (छुट्टी के भत्तों समेत) और पेनशन के बारे में अधिकार उन बंधानों के अधीन रहेंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी सूबे में हाईकोर्ट के जजों पर लागू थे.

11—अगर प्रसंग से कुछ और दरकार न हो तो इस भाग में—

(ए) “सरजज” शब्द में कारकर सरजज, और “जज” में ज़रूरती जज शामिल हैं;

(बी) “असल नौकरी” में—

(एक) वह समय शामिल है जो किसी जज ने जज का फ़रज पूरा करने में या ऐसे दूसरे काम करने में बिताया हो जिन्हें निभारना राजपति की प्रार्थना पर उसने अपने ज़िम्मे ले लिया है;

(दो) तात्वीलों का समय शामिल है, उस समय को छोड़कर जिसमें जज ने छुट्टी ले रखी हो; और

(तीन) वह समय शामिल है जो किसी हाईकोर्ट से आला अदालत को या किसी एक हाईकोर्ट से दूसरी हाईकोर्ट को तबादला होने पर जाने और काम संभालने में खर्च हो.

भाग (ई)

भारत के दाब अफसर और सरपड़तालिया के बारे में बंधान

12—(1) भारत के दाब अफसर और सरपड़तालिया को चार हजार रुपए माहवार की दर से तनखाह दी जायगी.

(2) वह आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द के सरपड़तालिया के पद पर था और विधान आरंभ होने पर दफा 377 के अधीन भारत का दाब अफसर और सरपड़तालिया हो गया है, इस पैरा के उप-पैरा (1) में बताई तनखाह के अलावा खास तनखाह के रूप में वह रकम पाने का हकदार होगा जो इस तरह बताई तनखाह और विधान आरंभ होने से ठीक पहले उम्मे हिन्द के सरपड़तालिया की हैभियत से मिलने वाली तनखाह के फरक के बराबर है.

(3) भारत के दाब अफसर और सरपड़तालिया की छुट्टी और पेनशन के बारे में अधिकार और उसकी नौकरी की दूसरी शर्तें उन बंधानों के अधीन रहेंगी या अधीन जारी रहेंगी, जैसी सूरत हो, जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द के ऑडीटर-जनरल पर लागू थीं, और उन बंधानों में जहाँ जहाँ गवरनर जनरल की चरचा की गई है उस से यह मतलब लिया जायगा मानो वह राजपति की चरचा है.

तीसरी पट्टी

[दफा 75 (4), 99, 124 (6), 148 (2), 164 (3), 188 और 219]

हलफ़ या वचन के रूप

एक

यूनियन के बज़ीर के पद के हलफ़ का रूप :—

“मैं,.....(नाम).....ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के गंभीरता से वचन भरता हूँ

उस विधान का जो क़ानून से क़ायम हुआ है सचाई से वफ़ादार और भक्त रहूँगा, वफ़ादारी के साथ और अपनी अन्तरात्मा की आवाज़ पर चलते हुए यूनियन के एक बज़ीर की हैसियत से अपने फ़रज़ों को निभाऊँगा और विधान और क़ानून के अनुसार सब तरह के लोगों के साथ बिना डर या तरफ़दारी, बिना लगाव या बैर ठीक ठीक बरताव करूँगा.”

दो

यूनियन के बज़ीर के लिये राज़दारी के हलफ़ का रूप :—

“मैं,.....(नाम).....ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं, कोई गंभीरता से वचन भरता हूँ

मामला जो मेरे बिचार के लिये लाया जायगा, या जो यूनियन के बज़ीर की हैसियत से मुझे मालूम होगा, किसी आदमी या आदमियों तक, सीधे या नासीधे, न पहुँचाऊँगा न किसी को बताऊँगा, सिवाय जब कि बज़ीर की हैसियत से अपने फ़रज़ क़ायदे से निभारने के लिये मुझे ऐसा करना दरकार हो”.

तीन

राजपंचायत के मेम्बर के लिये हलफ़ या वचन का रूप :—

“मैं,.....(नाम)..... जो रियासत सदन (या लोक सदन) का मेम्बर

चुना गया हूँ (या नामजद किया गया हूँ), ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ
गंभीरता से वचन भरता हूँ

कि मैं भारत के उस विधान का जो कानून से कायम हुआ है सचाई से वफादार और भक्त रहूँगा, और जो फ़रज़ मैं अब संभालने वाला हूँ उसे वफादारी के साथ निभाऊँगा।”

चार

आला अदालत के जजों के लिये और भारत के दाव अफ़सर और सरपड़तालिया के लिये हलफ़ या वचन का रूप :—

“मैं,....(नाम), जो भारत की आला अदालत का सरजज (या जज) (या भारत का दाव अफ़सर और सरपड़तालिया) नियोजा गया हूँ, ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के उस विधान का जो गंभीरता से वचन भरता हूँ कानून से कायम हुआ है सचाई से वफादार और भक्त रहूँगा. अपनी पूरी सकत, जानकारी और विवेक से, बिना डर या तरफ़दारी, बिना लगाव या बैर, कायदे से और वफादारी के साथ, अपने पद के फ़रज़ पूरे करूँगा, और विधान और कानूनों की मान-मर्यादा को बनाए रखूँगा।

पाँच

रियासत के वज़ीर के लिये पद के हलफ़ का रूप :—

“मैं,.....(नाम)....., ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं भारत गंभीरता से वचन भरता हूँ

के उस विधान का जो कानून से कायम हुआ है सचाई से वफादार और भक्त रहूँगा, वफादारी के साथ और अपनी अन्तरात्मा की आवाज़ पर चलते हुए,.....रियासत के एक वज़ीर की हैसियत से, अपने फ़रज़ों को निभाऊँगा, और विधान और कानून के अनुसार, सब तरह के लोगों के साथ, बिना डर या तरफ़दारी, बिना लगाव या बैर, ठीक ठीक बरताव करूँगा।”

छे

रियासत के वज़ीर के लिये राजदारी के हलफ़ का रूप :—

“मैं,.....(नाम)....., ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं, कोई गंभीरता से वचन भरता हूँ

मामला जो मेरे विचार के लिये लाया जायगा, या जो.....रियासत के वजीर की हैसियत से मुझे मालूम होगा, किसी आदमी या आदमियों तक, सीधे या नासीधे, न पहुँचाऊँगा न किसी को बताऊँगा, सिवाय जब कि वजीर की हैसियत से अपने फरज क़ायदे से निभारने के लिये मुझे ऐसा करना दरकार हो.”

सात

रियासत की क़ानून सभा के मेम्बर के लिये हलफ़ या वचन का रूप:—

“मैं,...(नाम), जो आम सदन (या खास सदन) का मेम्बर चुना गया हूँ (या नामज़द किया गया हूँ), ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि गंभीरता से वचन भरता हूँ मैं भारत के उस विधान का जो क़ानून से क़ायम हुआ है सचार्इ से वफ़ादार और भक्त रहूँगा, और जो फ़रज मैं अब संभालने वाला हूँ उसे वफ़ादारी के साथ निभारूँगा.”

आठ

हाईकोर्ट के जजों के लिये हलफ़ या वचन का रूप:—

“मैं...(नाम)..., जो.....की हाईकोर्ट का सर जज (या जज) नियोजा गया हूँ, ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के उस विधान का जो क़ानून से क़ायम हुआ है सचार्इ से वफ़ादार और भक्त रहूँगा, अपनी पूरी सकत, जानकारी और विवेक से, बिना डर या तरफ़दारी, बिना लगाव या बैर, क़ायदे से और वफ़ादारी के साथ, अपने पद के फ़रज पूरे करूँगा, और विधान और क़ानूनों की मान-मर्यादा को बनाए रखूँगा.”

चौथी पट्टी

[इफ़ा 4 (1), 80(2), और 391]

रियासत सदन की सीटों का बटवारा

इस पट्टी के साथ दिये सीटों के नक्शे के पहले कालम में दर्ज हर रियासत या रियासत गुट को उतनी सीटें दी जायेंगी जितनी इस नक्शे के दूसरे कालम में उस रियासत या रियासत गुट के नाम के सामने, जैसी सूरत हो, दर्ज हैं।

सीटों का नक्शा

रियासत सदन

पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज रियासतों के प्रतिनिधि

1	2
रियासतें	कुल सीटें
1. आसाम	6
2. बिहार	21
3. बम्बई	17
4. मध्यप्रदेश	12
5. मद्रास	27
6. उड़ीसा	9
7. पंजाब	8
8. युक्तप्रान्त	31
9. पच्छिम बंगाल	14
<hr/>	
	कुल 145

पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज रियासतों के प्रतिनिधि

1	2
रियासतें	कुल सीटें
1. हैदराबाद	11
2. जम्मू और काश्मीर	4
3. मध्यभारत	6
4. मैसूर	6
5. पटियाला और पूरब पंजाब रियासत यूनियन	3
6. राजस्थान	9
7. सौराष्ट्र	4
8. ट्रावणकोर कोचीन	6
9. विन्ध्य-प्रदेश	4
	कुल 53

पहला पट्टी के भाग (सी) में दर्ज रियासतों के प्रतिनिधि

1	2
रियासत और रियासत गुट	कुल सीटें
1. अजमेर }	1
2. कुर्ग }	
3. भोपाल	1
4. बिलासपुर }	1
5. हिमाचल प्रदेश }	
6. कूच-बिहार	1
7. दिल्ली	1
8. कच्छ	1
9. मनीपुर }	1
10. त्रिपुरा }	
	कुल

पांचवी पट्टी

[दफा 244 (1)]

पट्टी-दर्ज क्षेत्रों और पट्टी-दर्ज कबीलों के शासन और दबान
के बारे में बंधान

भाग (ए)

आम

1—अर्थ—इस पट्टी में, जब तक प्रसंग से कुछ और दरकार न हो, “रियासत” शब्द के मानी हैं पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज कोई रियासत, पर इसमें आसाम की रियासत शामिल नहीं है.

2—पट्टी-दर्ज क्षेत्रों में रियासत की काजकारी शक्ति—
इस पट्टी के बंधानों के अधीन रहते हुए, हर रियासत की काजकारी शक्ति के फैलाव में उसके अन्दर के पट्टी-दर्ज क्षेत्र शामिल हैं.

3—पट्टी-दर्ज क्षेत्रों के शासन के बारे में रियासतपति या राजप्रमुख की राजपति को रिपोर्ट—हर ऐसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख जिसमें पट्टी-दर्ज क्षेत्र हैं, हर साल या जब कभी राजपति मांगे, उस रियासत के पट्टी-दर्ज क्षेत्रों के शासन के बारे में राजपति को रिपोर्ट देगा, और यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में उन क्षेत्रों के शासन के बारे में उस रियासत को निर्देश देना शामिल होगा.

भाग (बी)

पट्टी-दर्ज क्षेत्रों और पट्टी-दर्ज कबीलों का शासन
और दबान

4—कबीला सलाहकार मंडल—(1)हर उस रियासत में जिसमें पट्टी-दर्ज क्षेत्र हैं, और अगर राजपति इस तरह निर्देश करे तो किसी ऐसी रियासत में भी जिसमें पट्टी-दर्ज कबीले हैं पर पट्टी-

दर्ज क्षेत्र नहीं हैं, एक कबीला सलाहकार मंडल कायम किया जायगा, जिसमें बीस से अधिक मेम्बर नहीं होंगे जिनमें से तीन चौथाई के जितने करीब हो सके वह होंगे जो उस रियासत के आम सदन में पट्टी-दर्ज कबीलों के प्रतिनिधि हैं :

शर्तें कि अगर उस रियासत के आम सदन में पट्टी-दर्ज कबीलों के प्रतिनिधियों की गिनती, कबीला सलाहकार मंडल में जो सीटें ऐसे प्रतिनिधियों से भरी जानी हैं उन की गिनती से कम है तो बाक़ी सीटें उन कबीलों के दूसरे मेम्बरों से भरी जायंगी.

(2) कबीला सलाहकार मंडल का फ़रज होगा कि वह उन मामलों पर सलाह दे जिनका सम्बन्ध उस रियासत में पट्टी-दर्ज कबीलों की भलाई और बढ़ोतरी से है और जिन्हें रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, उसके पास राय के लिये भेजे.

(3) रियासतपति या राजप्रमुख—

(ए) मंडल के मेम्बरों की गिनती, उनके नियोजन का ढंग और मंडल के मसनदी और अफ़सरों और नौकरों के नियोजन का ढंग,

(बी) मंडल की मिलनियों का संचालन और उनका आम दस्तूर, और

(सी) प्रसंग से आए हुए दूसरे सब मामले, तय करने या उनकी कायदाबन्दी करने के लिये, जैसी सूरत हो, नियम बना सकता है.

5—पट्टी-दर्ज क्षेत्रों में लागू क़ानून—(1) इस विधान में किसी बात के रहते भी, रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, आम नोटिस निकाल कर निर्देश दे सकता है कि राजपंचायत का या उस रियासत की क़ानून सभा का कोई ख़ास एक्ट उस रियासत में किसी पट्टी-दर्ज क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा, या उस रियासत में किसी पट्टी-दर्ज क्षेत्र या उसके किसी भाग पर उन अपवादों और अदल बदल के अधीन लागू होगा जो वह उस नोटिस में बतावे, और इस उप-पैरा के अधीन जो निर्देश दिया जाय वह इस तरह दिया जा सकता है कि उसका पिछ-लगता असर हो.

(2) रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, रियासत के किसी ऐसे क्षेत्र की शान्ति और अच्छी हुकूमत के लिये, जो उस समय पट्टी-दर्ज क्षेत्र है, क़ायदे बना सकता है।

ऐसे क़ायदे, खास कर, और ऊपर-लिखी शक्ति की आमियत को कम किये बिना, —

(ए) उस क्षेत्र में पट्टी-दर्ज कबीलों के लोगों के, बाहर वालों को या एक दूसरे को, ज़मीन दे डालने पर रोक लगा सकते हैं या उसकी मनाही कर सकते हैं;

(बी) उस क्षेत्र में पट्टी दर्ज कबीलों के लोगों को ज़मीने बाँटे जाने की क़ायदाबन्दी कर सकते हैं;

(सी) उस क्षेत्र में पट्टी-दर्ज कबीलों के लोगों को जो लोग रुपया उधार देते हैं उनके इस साहूकारे के काम की क़ायदाबन्दी कर सकते हैं।

(3) ऐसा कोई क़ायदा बनाने में जिसकी चरचा इस पैरा के उप-पैरा (2) में की गई है रियासतपति या राजप्रमुख राजपंचायत के या उस रियासत की क़ानून सभा के किसी ऐसे एक्ट को या किसी ऐसे मौजूदा क़ानून को, जो उस क्षेत्र पर, जिसका सवाल है, उस समय लागू हो, रद्द कर सकता है या सुधार सकता है।

(4) इस पैरा के अधीन बने सब क़ायदे उसी समय राजपति के सामने रखे जायंगे और जब तक राजपति उन पर मंजूरी न दे दे उनका कोई असर नहीं होगा।

(5) इस पैरा के अधीन कोई क़ायदा नहीं बनाया जायगा जब तक उस क़ायदे को बनाने वाले रियासतपति या राजप्रमुख ने, उस सूरत में जब कि उस रियासत के लिये कोई कबीला सलाहकार मंडल है, उस मंडल से सलाह न करली हो।

भाग (सी)

पट्टी-दर्ज क्षेत्र

6—पट्टी-दर्ज क्षेत्र—(1) इस विधान में “पट्टी-दर्ज क्षेत्र” शब्दों के मानी हैं वह क्षेत्र जिन्हें राजपति हुकूम देकर पट्टी-दर्ज क्षेत्र ठहरावे।

(2) राजपति किसी भी समय हुकुम दे कर—

- (ए) यह निर्देश दे सकता है कि कोई पट्टी-दर्ज क्षेत्र पूरा या उसका कोई खास भाग, पट्टी-दर्ज क्षेत्र नहीं रहेगा या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा;
- (बी) किसी पट्टी-दर्ज क्षेत्र को बदल सकता है, पर केवल उसकी सीमाओं को ठीक करने के रूप में ही;
- (सी) किसी रियासत की सीमाओं के बदले जाने पर, या यूनि-यन में किसी नई रियासत के दाखिल किये जाने पर, या नई रियासत के क्रायम किये जाने पर, किसी ऐसे भूभाग को जो पहले किसी रियासत में शामिल नहीं था पट्टी-दर्ज क्षेत्र या किसी पट्टी-दर्ज क्षेत्र का भाग ऐलान कर सकता है;

और ऐसे किसी हुकुम में वह प्रसंगी और परिनामी बंधान रह सकते हैं जो राजपति को जरूरी और उचित मालूम हों, पर सिवाय जैसा ऊपर कहा गया है इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन दिये हुए हुकुम को किसी बाद के हुकुम से नहीं बदला जायगा.

भाग (डी)

इस पट्टी में सुधार

7—इस पट्टी में सुधार—(1) राजपंचायत समय समय पर क़ानून बना कर इस पट्टी के बंधानों में से किसी में कुछ जोड़ कर, अदल बदल कर, या रद्द कर के, पट्टी में सुधार कर सकती है, और जब किसी पट्टी में इस तरह सुधार हो जाय, तब इस विधान में इस पट्टी की चरचा का मतलब यह लिया जायगा मानो वह इस तरह सुधारी हुई पट्टी की चरचा है.

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) में जिस क़ानून की बात आई है उस को दफा 368 के मतलबों के लिये इस विधान का सुधार नहीं समझा जायगा.

छटी पट्टी

[दफा 244(2) और 275 (1)]

आसाम के कबाइली क्षेत्रों के शासन के बारे में बंधान

1—स्वाधीन जिले और स्वाधीन इलाके—(1) इस पट्टी के पैरा 20 के साथ जो नक्शा दिया गया है उसके भाग (ए) की हर मद के कबाइली क्षेत्र, इस पैरा के बंधानों का ध्यान रखते हुए, एक स्वाधीन जिला होंगे.

(2) अगर किसी स्वाधीन जिले में अलग अलग पट्टी दर्ज कबीले हैं तो रियासतपति आम नोटिस निकालकर उस क्षेत्र या उन क्षेत्रों को, जिनमें वह कबीले बसते हैं, स्वाधीन इलाकों में बांट सकता है.

(3) रियासतपति आम नोटिस निकाल कर—

(ए) किसी क्षेत्र को उस नक्शे के भाग (ए) में शामिल कर सकता है;

(बी) किसी क्षेत्र को उस नक्शे के भाग (ए) से अलग कर सकता है;

(सी) एक नया स्वाधीन जिला बना सकता है;

(डी) किसी स्वाधीन जिले का क्षेत्र बढ़ा सकता है;

(ई) किसी स्वाधीन जिले का क्षेत्र घटा सकता है;

(एफ) दो या अधिक स्वाधीन जिलों को या उनके भागों को मिलाकर एक स्वाधीन जिला बना सकता है;

(जी) किसी स्वाधीन जिले की सीमाएँ तय कर सकता है:

शर्तें कि इस उप-पैरा की धारा (सी), (डी), (ई), और (एफ) के अधीन रियासतपति कोई हुकुम नहीं देगा जब तक कि वह इस पट्टी के पैरा 14 के उप-पैरा (1) के अधीन नियोजित हुए कमीशन की रिपोर्ट पर विचार न कर चुका हो.

2—जिला मंडलों और इलाका मंडलों की बनावट—

(1) हर स्वाधीन जिले के लिये एक जिला मंडल होगा जिसमें अधिक

से अधिक चौबीस मेम्बर होंगे, जिनमें से कम से कम तीन चौथाई बालिग वोट के आधार पर चुने जायेंगे.

(2) इस पट्टी के पैरा 1 के उप-पैरा (2) के अधीन स्वाधीन इलाका बने हर क्षेत्र के लिये एक अलग इलाका मंडल होगा,

(3) हर जिला मंडल और हर इलाका मंडल एकतन संस्था होगा जो अलग अलग “... (जिले का नाम) का जिला मंडल” और “... (इलाके का नाम) का इलाका मंडल” कहलायगा, जो लगातार बनता और चलता रहेगा, जिसकी एक ही मोहर होगी, और जो इस नाम से नालिश कर सकेगा और उस पर नालिश की जा सकेगी.

(4) इस पट्टी के बंधानों के अधीन रहते हुए, हर स्वाधीन जिले का शासन, जहां तक वह इस पट्टी के अधीन उस जिले के अन्दर किसी इलाका मंडल के हाथ में नहीं दिया गया है, उस जिले के जिला मंडल के हाथ में रहेगा, और हर स्वाधीन इलाके का शासन उस इलाके के इलाका मंडल के हाथ में रहेगा.

(5) हर ऐसे स्वाधीन जिले में, जहाँ इलाका मंडल हैं, इलाका मंडल के अधिकार के अधीन क्षेत्रों के बारे में जिला मंडल को उन शक्तियों के अलावा जो उन क्षेत्रों के बारे में इस पट्टी में जिला मंडल को सौंपी गई हैं, केवल वह शक्तियां और होंगी जो इलाका मंडल उसे अपनी तरफ से दे दे.

(6) रियासतपति, जिला मंडलों और इलाका मंडलों के पहली बार बनाए जाने के लिये, जिन स्वाधीन जिलों या इलाकों से इस बात का सम्बन्ध होगा उनके मौजूदा कबाइली मंडलों से या कबीलों का प्रतिनिधान करने वाली दूसरी संस्थाओं से सलाह लेकर, नियम बनायगा और उन नियमों में नीचे लिखी बातों का बन्धान किया जायगा:—

(प) जिला मंडलों और इलाका मंडलों की रचना और उनमें सीटों का बटवारा;

(बी) इन मंडलों के चुनावों के मतलब के लिये भूभागी चुनाव इलाकों की हदबन्दी;

- (सी) ऐसे चुनावों में वोट देने वालों की जोगताएँ और उनके लिये चुनाव-चिट्ठों का तैयार किया जाना;
- (डी) उन चुनावों में उन मंडलों के मेम्बर चुने जाने वालों की जोगताएँ;
- (ई) उन मंडलों के मेम्बरों की पद-भियाद;
- (एफ) उन मंडलों के चुनावों या उनके लिये नामजदगी के बारे में या उन से सम्बन्ध रखने वाला कोई और मामला;
- (जी) जिला और इलाका मंडलों के दस्तूर और उनके काम का संचालन;
- (एच) जिला और इलाका मंडलों के अफसरों और अमलों का नियोजन.

(7) पहली बार बन जाने के बाद जिला या इलाका मंडल इस पैरा के उप-पैरा (6) में जो मामले दर्ज हैं, उनके लिये नियम बना सकते हैं; और नीचे लिखे मामलों की क्रायदाबन्दी करने के लिये भी नियम बना सकते हैं:—

- (ए) मातहत मुकामी मंडलों या बोर्डों का बनाना और उनके दस्तूर और उनके काम का संचालन;
- (बी) उस जिले या इलाके के, जैसी सूरत हो, शासन से सम्बन्ध रखने वाले काम चलाने के बारे में आम तौर पर सब मामले:

शर्तें कि जब तक जिला या इलाका मंडल इस उप-पैरा के अधीन नियम नहीं बनाता, तब तक हर ऐसे मंडल के चुनावों के बारे में, उसके अफसरों और अमल के बारे में, और उसके दस्तूर और काम के संचालन के बारे में, इस पैरा के उप-पैरा (6) के अधीन रियासत-पति के बनाए नियम अमल में रहेंगे:

और शर्तें कि उत्तर कछार पहाड़ियों और मिकिर पहाड़ियों का डिप्टी कमिश्नर या सब-डिविजनल अफसर, जैसी सूरत हो, अपने पद-नाते, इस पट्टी के पैरा 20 के साथ वाले नक्शे के भाग (ए) की मद 5 और मद 6 के अलग अलग भूभागों के लिये बने हुए जिला मंडल

का मसनदी होगी, और जिला मंडल के पहली बार बनने के बाद छै बरस के अरसे के लिये, उसको, रियासतपति के दबान के अधीन रहते हुए, यह शक्ति होगी कि वह जिला मंडल के किसी ठहराव या फ़ैसले को मंसूख कर दे, या उसमें अदल बदल कर दे, या जिला मंडल को ऐसी हिदायतें दे जो वह मुनासिब समझे, और जिला मंडल को हर इस तरह दी हुई हिदायत पर अमल करना होगा।

3—जिला मंडलों और इलाका मंडलों की कानून बनाने की शक्तियाँ—(1) हर स्वाधीन इलाके के इलाका मंडल को उस इलाके के अन्दर के सब छेत्रों के बारे में, और हर स्वाधीन जिले के जिला मंडल को उस जिले के अन्दर के सब छेत्रों के बारे में, सिवाय उस जिले के अन्दर के उन छेत्रों के जो इलाका मंडलों के अधिकार में हैं, अगर उस जिले में कोई इलाका मंडल हों तो, नीचे लिखे मामलों के बारे में कानून बनाने की शक्ति होगी:—

(ए) रखाए हुए जंगल की ज़मीन को छोड़ कर और कोई ज़मीन, खेती बाड़ी के या ढोर चराने के मतलबों के लिये, या रिहाइश के या दूसरे ग़ैर-खेती बाड़ी मतलबों के लिये, या किसी और ऐसे मतलब के लिये जिससे किसी गाँव या क़स्बे के रहने वालों के हितों के बढ़ने की संभावना हो, किसी के नाम कर देना, उस पर क़ब्ज़ा, उसका इस्तेमाल, या उसे अलग कर देना :

शर्त कि इन क़ानूनों की कोई बात आसाम की सरकार को, सरकारी मतलबों के लिये, किसी ऐसे क़ानून के अनुसार जो उस समय अमल में हो और जो ज़मीन को इस तरह हासिल करने का अधिकार देता हो, किसी ज़मीन को, चाहे उस पर किसी का क़ब्ज़ा हो या न हो, ज़बरन हासिल करने से नहीं रोक सकेगी;

(बी) किसी ऐसे जंगल का प्रबन्ध जो रखाया हुआ जंगल नहीं है;

(सी) खेती बाड़ी के मतलब के लिये किसी नहर या जल-मार्ग का इस्तेमाल;

- (डी) भूम के रिवाज या बदलती जुताई के दूसरे रूपों के लिये क़ायदाबन्दी;
- (ई) गाँव या क़स्बा कमेटियों या मंडलों का क़ायम करना और उनकी शक्तियाँ;
- (एफ) गाँव या क़स्बों के शासन के सम्बन्ध में कोई दूसरा मामला, जिसमें गाँव या क़स्बों की पुलिस, जन तन-दुरुस्ती और सफ़ाई शामिल है;
- (जी) सरदारों या मुखियों का नियोजन और उनके बाद उनका पदगाहन;
- (एच) जायदाद की विरासत;
- (आई) शादी-ब्याह;
- (जे) समाजी रीति-रिवाज.

(2) इस पैरा में “रखाए हुए जंगल” के मानी हैं कोई ऐसा क्षेत्र जो ‘आसाम जंगल क़ायदाबन्दी 1891’ के अधीन या किसी दूसरे क़ानून के अधीन, जो, जिस क्षेत्र का सवाल है उसमें उस समय अमल में हो, रखाया हुआ जंगल है.

(3) इस पैरा के अधीन बने सब क़ानून उसी समय रियासतपति के सामने रखे जायंगे और जब तक रियासतपति उन पर अपनी मंजूरी न दे दे उनका कोई असर नहीं होगा.

4—स्वाधीन जिलों और स्वाधीन इलाक़ों में न्याय शासन—

(1) हर स्वाधीन इलाक़े का इलाक़ा मंडल उस इलाक़े के अन्दर के क्षेत्रों के बारे में, और हर स्वाधीन ज़िले का ज़िला मंडल उस ज़िले के अन्दर के क्षेत्रों के बारे में, सिवाय उस ज़िले के अन्दर के उन क्षेत्रों के जो इलाक़ा मंडल के अधिकार में हैं, अगर उस ज़िले में कोई इलाक़ा मंडल हों तो, उन फ़रीकों के बीच नालिशों और मुक़दमों की जांच के लिये जो सबके सब उन क्षेत्रों के अन्दर पट्टी-दर्ज क़बीलों के आदमी हैं, पर उन नालिशों और मुक़दमों को छोड़ कर जिन पर इस पट्टी के पैरा 5 के उप-पैरा (1) के बन्धान लागू होते हैं, गाँव मंडल या गाँव अदालतें बना सकते हैं, जिनके अलावा रियासत की किसी और अदालतें बना सकते हैं,

तल में उन नालिशों या मुकदमों की जांच नहीं हो सकेगी, और उन गाँव मंडलों की मेम्बरी के लिये या उन गाँव अदालतों की सदरत के लिये उचित आदमियों का नियोजन कर सकते हैं, और इस पट्टी के पैरा 3 के अधीन बने कानूनों को अमल में लाने के लिये जरूरी अफसरों का भी नियोजन कर सकते हैं.

(2) इस विधान में किसी बात के रहते भी, किसी स्वाधीन इलाक़े के लिये इलाक़ा मंडल या कोई अदालत जो इस काम के लिये इलाक़ा मंडल ने बनाई हो, या अगर किसी स्वाधीन ज़िले के किसी क्षेत्र का कोई इलाक़ा मंडल नहीं है, तो उस ज़िले का ज़िला मंडल, या कोई अदालत जो इस काम के लिये ज़िला मंडल ने बनाई हो, उन सब नालिशों और मुकदमों के बारे में अपीली अदालत की शक्तियों से काम लेगी जो ऐसे इलाक़े या क्षेत्र के अन्दर, जैसी सूरत हो, इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन बने गाँव मंडल या गाँव अदालत के सामने सुने जा सकते हों, पर उन नालिशों और मुकदमों को छोड़ कर जिन पर इस पट्टी के पैरा 5 के उप-पैरा (1) के बन्धान लागू होते हैं, और ऐसी नालिशों और मुकदमों पर हाइकोर्ट या आला अदालत को छोड़ कर और किसी दूसरी अदालत की अमलदारी नहीं होगी.

(3) उन नालिशों और मुकदमों पर जिन पर इस पैरा के उप-पैरा (2) के बन्धान लागू होते हैं आसाम की हाईकोर्ट को वह अमलदारी हासिल होगी और वह उससे काम लेगी जो रियासत-पति समय समय पर हुकुम दे कर बताए.

(4) कोई इलाक़ा मंडल या ज़िला मंडल, जैसी सूरत हो, पहले से रियासतपति की रज़ामन्दी लेकर नीचे लिखे मामलों की क़ायदाबन्दी के लिये नियम बना सकता है:—

(ए) गाँव मंडलों और गाँव अदालतों की बनावट और वह शक्तियाँ जिनसे इस पैरा के अधीन गाँव मंडल और गाँव अदालत काम लेंगे;

(बी) इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन नालिशों और मुकदमों की जाँच करने में गाँव मंडलों या गाँव अदालतों को जिस दस्तूर पर चलना है वह दस्तूर;

(सी) इस पैरा के उप-पैरा (2) के अधीन अधीनों और दूसरी कारवाइयों में इलाका या जिला मंडल को या ऐसे मंडल की बनाई किसी अदालत को जिस दस्तूर पर चलना है वह दस्तूर;

(डी) ऐसे मंडलों और अदालतों के फैसलों और हुकुमों पर अमल कराना;

(ई) इस पैरा के उप-पैरा (1) और (2) के बन्धानों पर अमल कराने के लिये और सब सहायक मामले.

5—ज्वाब्ता दीवानी 1908 और ज्वाब्ता फौजदारी 1898 के अधीन, कुछ नालिशों, मुकदमों और जुमों की जांच के लिये इलाका और जिला मंडलों को, और कुछ अदालतों और अफसरों को शक्तियाँ सौंपना—(1) रियासतपति, ऐसी नालिशों या ऐसे मुकदमों की जांच के लिये, जो किसी ऐसे क़ानून से पैदा हों जो किसी स्वाधीन ज़िले या इलाके में अमल में हो और जिसको इस काम के लिये रियासतपति ने बताया हो, या ऐसे जुमों की जांच के लिये जिनकी सज़ा ताज़ीरात हिन्द के अधीन या किसी दूसरे क़ानून के अधीन जो उस समय उस ज़िले या इलाके पर लागू हो, मौत, आजीवन काला पानी या कम से कम पांच साल की कैद हो, उस ज़िला मंडल या उस इलाका मंडल को जिसका उस ज़िले या उस इलाके पर अधिकार है, या उन अदालतों को जिन्हें ऐसे किसी ज़िला मंडल ने बनाया है, या किसी अफसर को जिसको इस काम के लिये रियासतपति ने नियोजा हो, ज्वाब्ता दीवानी 1908 के या ज्वाब्ता फौजदारी 1898 के अधीन, जैसी सूरत हो, ऐसी शक्तियाँ सौंप सकता है जिन्हें वह मुनासिब समझे, और उसके ऐसा करने पर वह मंडल, अदालत या अफसर, उन शक्तियों से काम लेते हुए, जो इस तरह सौंपी जायं, उन नालिशों, मुकदमों या जुमों की जांच करेगा.

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन किसी ज़िला मंडल, इलाका मंडल, अदालत या अफसर को जो शक्तियाँ सौंपी

जायं उनमें से किसी को रियासतपति वापिस ले सकता है या उनमें अदल बदल कर सकता है.

(3) सिवाय इसके कि इस पैरा में कोई साफ़ साफ़ बन्धान किया गया हो, ज़ाबता दीवानी 1908 और ज़ाबता फ़ौजदारी 1898, किसी स्वाधीन ज़िले या किसी स्वाधीन इलाक़े में, जिन पर इस पैरा के बन्धान लागू होते हैं, किसी नालिश, मुक़दमें या जुर्म की जांच पर लागू नहीं होंगे.

6—ज़िला मंडल को प्राइमरी स्कूल वगैरा क़ायम करने की शक्तियाँ—किसी स्वाधीन ज़िले का ज़िला मंडल ज़िले में प्राइमरी स्कूल, दबाख़ाने, मंडियां, कांजी हौज़, चतराई घाट, मछिया-रियां, सड़कें और जल मार्ग क़ायम कर सकता है, बना सकता है या उनका प्रबन्ध कर सकता है और खास कर यह बता सकता है कि ज़िले के प्राइमरी स्कूलों में किस भाषा में और किस ढंग से प्राइमरी तालीम दी जायगी.

7—ज़िला और इलाक़ा कोश—(1) हर स्वाधीन ज़िले के लिये एक ज़िला कोश और हर स्वाधीन इलाक़े के लिये एक इलाक़ा कोश बनाया जायगा, जिसमें वह सब रक़में जमा की जायंगी, जो इस विधान के बन्धानों के अनुसार, उस ज़िले या जैसी सूरत हो उस इलाक़े के शासन के दौरान में उस ज़िले के लिये ज़िला मंडल को और उस इलाक़े के लिये उस इलाक़ा मंडल को मिलें.

(2) रियासतपति की रज़ामंदी से, ज़िला मंडल और इलाक़ा मंडल ज़िला कोश या, जैसी सूरत हो, इलाक़ा कोश के प्रबन्ध के लिये नियम बना सकते हैं, और जो नियम इस तरह बनाए जायं वह उस कोश में रक़में जमा कराने, उसमें से रक़में निकालने, उस में रक़मों की रखवाली करने, और इन मामलों से सम्बन्ध रखने वाले या इनके सहायक किसी और मामले, में जो दस्तूर बरता जायगा उसे तय कर सकते हैं.

8—ज़मीन की मालगुजारी तय करने और जमा करने और टैक्स लगाने की शक्तियाँ—(1) हर स्वाधीन इलाक़े के इलाक़ा

मंडल को उस इलाके के अन्दर की सब ज़मीनों के बारे में, और हर स्वाधीन ज़िले के ज़िला मंडल को उस ज़िले के अन्दर, ऐसी ज़मीनों को छोड़ कर जो उन छेत्रों के अन्दर हैं जो इलाका मंडलों के अधिकार में हैं, अगर वहाँ कोई इलाका मंडल हों तो, बाकी सब ज़मीनों के बारे में, शक्ति होगी कि वह उन सिद्धान्तों के अनुसार, उन ज़मीनों की मालगुजारी तय करें और जमा करें जिन सिद्धान्तों पर उस समय आसाम सरकार आसाम की रियासत में आम तौर पर मालगुजारी के मतलबों के लिये ज़मीनों को आंकने में चलती है.

(2) हर स्वाधीन इलाके के इलाका मंडल को उस इलाके के अन्दर के छेत्रों के बारे में, और हर स्वाधीन ज़िले के ज़िला मंडल को उस ज़िले के अन्दर, उन छेत्रों को छोड़ कर जो इलाका मंडलों के अधिकार में हों, अगर वहाँ कोई इलाका मंडल हों तो, बाकी सब छेत्रों के बारे में, ज़मीनों और इमारतों पर टैक्स लगाने और जमा करने, और उन छेत्रों में बसने वाले लोगों पर टोल टैक्स लगाने की शक्ति होगी.

(3) हर स्वाधीन ज़िले के ज़िला मंडल को उस ज़िले के अन्दर नीचे लिखे सब टैक्स या उन में से कोई टैक्स लगाने और जमा करने की शक्ति होगी, यानी—

(ए) पेशों, व्यापारों, रोज़गारों और कामगारियों पर टैक्स;

(बी) जानवरों, गाड़ियों और नावों पर टैक्स;

(सी) किसी मंडी में बिकरी के लिये माल आने पर टैक्स, और सवारियों और माल पर घाट उतराई टोल; और

(डी) स्कूलों, दवाखानों या सड़कों को बनाए रखने के लिये टैक्स.

(4) कोई इलाका मंडल या ज़िला मंडल, जैसी सूरत हो, इस पैरा के उप-पैरा (2) और (3) में जो टैक्स बताए गए हैं उनके लगाने और जमा करने का बंधान करने के लिये क़ायदे बना सकता है.

9—खनिजों की खोज करने या उनको निकालने के लिये लाइसेंस या पट्टे—(1) किसी स्वाधीन ज़िले के किसी

क्षेत्र में खनिजों की खोज करने या उनको निकालने के लिये आसाम सरकार जो लाइसेंस या पट्टे दे उनसे हर साल जो रायलटियां मिलें उनका वह हिस्सा जिस पर उस ज़िले का ज़िला मंडल और आसाम सरकार दोनों राज़ी हो जायं ज़िला मंडल को दे दिया जायगा.

(2) किसी ज़िला मंडल को ऐसी रायलटियों का जो हिस्सा दिया जाना है उसके बारे में अगर कोई झगड़ा उठे तो वह झगड़ा तय करने के लिये रियासतपति के पास भेज दिया जायगा, और रियासतपति अपनी समझ से जो रकम तय कर दे वह वह रकम समझी जायगी जो इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन ज़िला मंडल को दी जानी है, और रियासतपति का फैसला आख़री होगा.

10—गैर-क्रबाहली लोगों के रुपया उधार देने और ब्योपार करने पर दबान रखने के लिये कायदाबन्दी करने की ज़िला मंडल को शक्ति—(1) हर स्वाधीन ज़िले का ज़िला मंडल उस ज़िले में बसने वाले पट्टी-दर्ज क़बीलों को छोड़ कर उस ज़िले के अन्दर दूसरे लोगों के रुपया उधार देने या ब्योपार करने पर दबान रखने और इन कामों की कायदाबन्दी करने के लिये कायदे बना सकता है.

(2) ऐसे कायदों में, खास कर, और ऊपर लिखी शक्ति की आमियत को कम किये बिना—

- (ए) यह बताया जा सकता है कि रुपया उधार देने का कार-बार उस आदमी के सिवा जिसके पास इस काम के लिये जारी हुआ लाइसेंस है, और कोई आदमी नहीं करेगा;
- (बी) यह बताया जा सकता है कि साहूकार सूद की अधिक से अधिक क्या दर लगा सकता है या वसूल कर सकता है;
- (सी) साहूकारों के हिसाब रखने का, और ऐसे अफसरों से जिन्हें इस काम के लिये ज़िला मंडल नियोजे उस हिसाब की जांच कराने का, बंधान किया जा सकता है;

(डी) यह बताया जा सकता है कि कोई आदमी, जो उस ज़िले में बसने वाले पट्टी दर्ज कबीलों का मेम्बर नहीं है, किसी विजारती माल का थोक या फुटकर कारबार नहीं करेगा, सिवाय ऐसे लाइसेंस के अधीन जिसे इस काम के लिये ज़िला मंडल ने जारी किया हो:

शर्तें कि इस पैरा के अधीन कोई क्रायदे नहीं बनाए जा सकेंगे जब तक कि वह उस ज़िला मंडल के कुल मेम्बरों के कम से कम तीन चौथाई की बढ़ीयत से पास न हों :

और शर्तें कि ऐसे किन्हीं क्रायदों के अधीन किसी ऐसे साहूकार या ब्योपारी को जो उस ज़िले में उन क्रायदों के बनने के पहले से कारबार कर रहा है, लाइसेंस देने से इनकार नहीं किया जा सकेगा.

(3) इस पैरा के अधीन बने सब क्रायदे उसी समय रियासतपति के सामने रखे जायेंगे और, जब तक वह मंजूरी न दे, उन का कोई असर नहीं होगा.

11—इस पट्टी के अधीन बने कानूनों, नियमों और क्रायदों का निकालना—वह सब कानून, नियम और क्रायदे जो इस पट्टी के अधीन कोई ज़िला मंडल या इलाका मंडल बनाए उसी समय रियासत के दफ्तरी गज़ट में निकाले जायेंगे, और इस तरह निकलने पर वह कानून का असर रखेंगे.

12—स्वाधीन जिलों और स्वाधीन इलाकों पर राज-पंचायत के और उस रियासत की कानून सभा के एफ्टों का लागू होना—(1) इस बिधान में किसी बात के रहते भी—

(ए) इस पट्टी के पैरा 3 में जिन मामलों को ऐसे मामले बताया गया है जिनके बारे में कोई ज़िला मंडल या इलाका मंडल कानून बना सकता है, उनके बारे में उस रियासत की कानून सभा का कोई एक्ट और उस रियासत की कानून सभा का कोई ऐसा एक्ट जो किसी बिना-खिच्चे अलकोहोली तरल की खपत की मनाही

करता है या उस पर रुकावटें लगाता है, किसी स्वाधीन ज़िले या स्वाधीन इलाक़े पर लागू नहीं होगा जब तक कि, दोनों सूरतों में, उस ज़िले का या उस इलाक़े पर अमलदारी रखने वाला ज़िला मंडल आम नोटिस निकाल कर यह निर्देश न दे दे, और किसी एक्ट के बारे में इस तरह का निर्देश देने में ज़िला-मंडल यह भी निर्देश दे सकता है कि उस ज़िले या इलाक़े पर या उसके किसी भाग पर उस एक्ट का असर उन अपवादों और अदल बदल के अधीन होगा जिन्हें वह ज़िला मंडल ठीक समझे;

(बी) रियासतपति आम नोटिस निकाल कर यह निर्देश दे सकता है कि राजपंचायत का या उस रियासत की क़ानून सभा का कोई एक्ट, जिस पर इस उप-पैरा की धारा (ए) के बंधन लागू नहीं होते, किसी स्वाधीन ज़िले या स्वाधीन इलाक़े पर लागू नहीं होगा, या किसी ऐसे ज़िले या इलाक़े या उसके किसी भाग पर ऐसे अपवादों या अदल बदल के साथ लागू होगा जो रियासतपति उस नोटिस में बतावे.

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन कोई निर्देश इस तरह भी दिया जा सकता है कि उसका पिछ-लगता असर हो.

13—स्वाधीन ज़िलों की आमदनी और खर्च के तख़्मीनों का सालाना माली ब्योरे में अलग दिखाया जाना—
हर स्वाधीन ज़िले के सम्बन्ध की उस आमदनी के तख़्मीने को जो आसाम की रियासत के मूठकोश में जमा होनी है, और उस ज़िले के सम्बन्ध के उस खर्च के तख़्मीने को जो उस मूठकोश में से किया जाना है, पहले बहस के लिये ज़िला मंडल के सामने रखा जायगा, और उस बहस के बाद उन तख़्मीनों को रियासत के उस सालाना माली ब्योरे में अलग दिखाया जायगा जो दफ़ा 202 के अधीन रियासत की क़ानून सभा के सामने रखा जाना है.

14—स्वाधीन जिलों और स्वाधीन इलाकों के शासन की बाबत पूछताछ करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिये कमीशन का नियोजन—(1) रियासतपति किसी समय भी रियासत के स्वाधीन जिलों और स्वाधीन इलाकों के शासन के संबंध में किसी ऐसे मामले की जो वह बता दे, जिसमें इस पट्टी के पैरा 1 के उप-पैरा (3) की धारा (सी), (डी), (ई) और (एफ) में बताए मामले शामिल हैं, जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिये एक कमीशन का नियोजन कर सकता है, या रियासत के स्वाधीन जिलों और स्वाधीन इलाकों के आम शासन की और खास तौर पर नीचे लिखी बातों की समय समय पर पूछताछ करने और उन पर रिपोर्ट देने के लिये एक कमीशन का नियोजन कर सकता है :—

(ए) ऐसे जिलों और इलाकों में तालीम और दवादारु की सुविधाओं और आवाजाई का इंतजाम;

(बी) ऐसे जिलों और इलाकों के बारे में किसी नए या खास क़ानून के बनाने की ज़रूरत; और

(सी) जो क़ानून, नियम और क़ायदे ज़िला और इलाका मंडल बनाएं, उनको अमल में लाना;

और रियासतपति उस दस्तूर को तय कर सकता है जिस पर वह कमीशन चलेगा.

(2) ऐसे हर कमीशन की रिपोर्ट को, उसके बारे में रियासतपति की सिफ़ारिशों के साथ और एक ऐसे यादपत्र के साथ जिसमें यह समझाया गया हो कि आसाम सरकार उस पर क्या कारवाई करने की तजवीज़ करती है, उस महक़मे का वज़ीर रियासत की क़ानून सभा के सामने रखेगा.

(3) रियासतपति, रियासत की सरकार का काम अपने वज़ीरों में बांटते समय, अपने किसी वज़ीर को, खास तौर पर रियासत के स्वाधीन जिलों और स्वाधीन इलाकों की भलाई का काम सौंप सकता है.

15—जिला और इलाका मंडलों के कामों और ठहरावों को मंजूर करना या मुअत्तल करना—(1) अगर किसी समय रियासतपति को इस बात का इतमीनान हो जाय कि किसी जिला मंडल या इलाका मंडल के किसी काम या ठहराव से भारत की रक्षा को कोई खतरा पैदा हो सकता है तो वह ऐसे काम या ठहराव को मंजूर कर सकता है या मुअत्तल कर सकता है, और ऐसे कदम उठा सकता है (जिसमें उस मंडल का मुअत्तल किया जाना और मंडल को जो शक्तियां हासिल थीं या जिन से वह मंडल काम ले सकता था उन सबको या उनमें से किसी को अपने हाथ में ले लेना भी शामिल है) जिन्हें वह उस काम को न होने देने या उसके जारी न रहने देने, या उस ठहराव पर अमल न होने देने के लिये ज़रूरी समझे.

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन रियासतपति जो हुकुम देगा वह हुकुम और उसके दिये जाने के कारन जितनी जल्दी हो सकेगा रियासत की क़ानून सभा के सामने रखे जायेंगे, और जब तक उसे उस रियासत की क़ानून सभा मंजूर न कर दे तब तक वह हुकुम जिस तारीख को दिया गया था उससे बारह महीने के अरसे तक अमल में रहेगा :

शर्तें कि अगर और जितनी बार रियासत की क़ानून सभा ऐसे किसी हुकुम को अमल में रखने के लिये अपनी रज़ामन्दी का ठहराव पास कर दे, उतनी बार वह हुकुम, उस तारीख से लेकर जिस पर वह इस पैरा के अधीन ठहराव पास न होने की सूरत में अमल में न रहता, बारह महीने के एक और अरसे तक अमल में रहेगा, जब तक कि रियासतपति उसे रद्द न कर दे.

16—किसी जिला या इलाका मंडल का भंग किया जाना—रियासतपति, इस पट्टी के पैरा 14 के अधीन नियोजे हुए किसी कमीशन की सिफ़ारिश पर, आम नोटिस निकाल कर, किसी जिला या इलाका मंडल के भंग किये जाने का हुकुम दे सकता है, और—

- (ए) यह निर्देश दे सकता है कि मंडल के फिर बनाए जाने के लिये कौरन नया आम चुनाव किया जायगा, या
- (बी) रियासत की कानून सभा की पहले से राजामन्दी लेकर, अधिक से अधिक बारह महीने के अरसे के लिये उस मंडल के अधिकार के अधीन वाले क्षेत्र का शासन अपने हाथ में ले सकता है, या उस क्षेत्र का शासन उस पैरा के अधीन नियोजे हुए कमीशन के हाथों में, या किसी दूसरी संस्था के हाथों में जिसे वह ठीक समझे दे सकता है :

शर्ते कि जब इस पैरा की धारा (ए) के अधीन कोई हुकुम दिया जा चुका हो तो रियासतपति नया आम चुनाव होने पर मंडल के फिर से बनने तक, जिस क्षेत्र का सवाल है उसके शासन के संबंध में वह कारवाई कर सकता है जिसकी चरचा इस पैरा की धारा (बी) में की गई है :

और शर्ते कि, जिला मंडल या इलाका मंडल को, जैसी सूरत हो, रियासत की कानून सभा के सामने अपने विचार रखने का मौका दिये बिना, इस पैरा की धारा (बी) के अधीन कोई कारवाई नहीं की जायगी.

17—स्वाधीन जिलों में चुनाव हलके बनाने के लिये

उन जिलों में से क्षेत्रों का अलग करना—आसाम के आम सदन के चुनावों के मतलबों के लिये रियासतपति हुकुम देकर जाहिर कर सकता है कि किसी स्वाधीन जिले के अन्दर का कोई क्षेत्र आम सदन में उस जिले के लिये अलग रखी किसी सीट या सीटों को भरने के लिये बने किसी चुनाव हलके का भाग नहीं होगा, बल्कि किसी ऐसे चुनाव हलके का भाग होगा जो उस हुकुम में बता दिया जाय और जो उस सदन में किसी ऐसी सीट या सीटों को भरने के लिये हो, जो इस तरह अलग नहीं रखी गई हैं.

18—पैरा २० के साथ के नक्शे के भाग (बी) में दर्ज क्षेत्रों पर इस पट्टी के बंधानों का लागू होना—

(1) रियासतपति—

(ए) राजपति की पहले से रज़ामन्दी लेकर और आम नोटिस निकालकर इस पट्टी के ऊपर-लिखे सब बंधानों या उन में से किसी को, इस पट्टी के पैरा 20 के साथ के नक्शे के भाग (बी) में दर्ज किसी क़बाइली छेत्र पर या ऐसे छेत्र के किसी भाग पर लागू कर सकता है, और ऐसा होने पर उस छेत्र का या उस भाग का शासन उन बंधानों के अनुसार किया जायगा, और

(बी) इसी तरह की रज़ामन्दी लेकर और आम नोटिस निकालकर, ऊपर बताए नक्शे के भाग (बी) में दर्ज किसी क़बाइली छेत्र को या उस छेत्र के किसी भाग को उस नक्शे में से अलग कर सकता है.

(2) जब तक ऊपर बताए नक्शे के भाग (बी) में दिये हुए किसी क़बाइली छेत्र के बारे में या उस छेत्र के किसी भाग के बारे में इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन कोई नोटिस न निकाला जाय तबतक उस छेत्र का या उसके उस भाग का शासन, जैसी सूरत हो, राजपति आसाम के रियासतपति की मारफ़त उसे अपना एजेन्ट मान कर चलायगा, और भाग नौ के बंधान उस छेत्र या उसके उस भाग पर उसी तरह लागू होंगे मानो वह छेत्र या उसका वह भाग पहली पट्टी के भाग (डी) में दर्ज कोई भूभाग है.

(3) इस पैरा के उप-पैरा (2) के अधीन राजपति के एजेन्ट की हैसियत से अपने काम निभारने में रियासतपति अपनी समस्त से काम करेगा.

19—बिच-वक्ती बंधान—(1) इस विधान के आरंभ होने के बाद जितनी ज़रूरी हो सकेगा, रियासतपति इस पट्टी के अधीन रियासत के हर स्वाधीन ज़िले के लिये एक एक ज़िला मंडल बनाने के लिये क़दम उठायगा, और जब तक किसी स्वाधीन ज़िले के लिये इस तरह ज़िला मंडल न बन जाय तब तक उस ज़िले का शासन रियासतपति के हाथों में रहेगा, और उस ज़िले के अन्दर के छेत्रों के शासन पर, इस पट्टी में ऊपर-लिखे बंधानों की जगह नीचे लिखे बंधान लागू होंगे, यानी :—

(ए) राजपंचायत का या उस रियासत की कानून सभा का कोई एकट ऐसे किसी क्षेत्र पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि रियासतपति आम नोटिस निकाल कर इसका निर्देश न दे दे; और किसी एकट के बारे में ऐसा निर्देश देते समय रियासतपति यह निर्देश दे सकता है कि उस क्षेत्र पर या उसके किसी बताए हुए भाग पर लागू होने में उस एकट का असर उन अपवादों या अदल बदल के अधीन होगा जो रियासतपति ठीक समझे;

(बी) रियासतपति ऐसे किसी क्षेत्र की शान्ति और अच्छी हुकूमत के लिये क्रायदे बना सकता है और जो क्रायदे इस तरह बनाए जायं वह राजपंचायत के या रियासत की कानून सभा के ऐसे किसी एकट को या ऐसे किसी मौजूदा कानून को जो उस समय उस क्षेत्र पर लागू होता हो, रद्द कर सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं.

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) की धारा (ए) के अधीन रियासतपति जो निर्देश दे वह इस तरह दिया जा सकता है कि उसका पिक-लगतता असर हो.

(3) इस पैरा के उप-पैरा (1) की धारा (बी) के अधीन बने हुए सब क्रायदे उसी समय राजपति के सामने रखे जायंगे, और जब तक राजपति उन पर मंजूरी न दे दे उनका कोई असर नहीं होगा.

20—कबाइली क्षेत्र—(1) जो क्षेत्र नीचे दिये हुए नक्शे के भाग (ए) और (बी) में दर्ज हैं वह आसाम की रियासत के अन्दर कबाइली क्षेत्र होंगे.

(2) युक्त खासी-जैन्तिया पहाड़ी जिले में वह भूभाग शामिल होंगे जो इस बिधान के आरंभ से पहले खासी रियासतें और खासी और जैन्तिया पहाड़ी जिला कहलाते थे; इनमें वह क्षेत्र शामिल नहीं होंगे जो उस समय शिलांग की छावनी और नगरायत में शामिल हों,

पर शिलांग की नगरायत के अन्दर के क्षेत्र का उतना भाग शामिल होगा जो मिझिपम की खासी रियासत का भाग था :

शर्तें कि इस पट्टी के पैरा 3 के उप-पैरा (1) की धारा (ई) और (एफ), पैरा 4, पैरा 5, पैरा 6, पैरा 8 के उप-पैरा (2), उप-पैरा (3) की धारा (ए), (बी) और (डी), और उप-पैरा (4), और पैरा 10 के उप-पैरा (2) की धारा (डो) के मतलबों के लिये शिलांग की नगरायत के अन्दर के क्षेत्र का कोई भाग युक्त खासी जैन्तिया पहाड़ी जिले में नहीं समझा जायगा.

(3) नीचे दिये नक्शों में किसी जिले (युक्त खासी-जैन्तिया पहाड़ी जिले को छोड़ कर) या शासनी क्षेत्र की चरचा से उस जिले या क्षेत्र की चरचा समझी जायगी जैसा वह इस विधान के आरंभ के समय था :

शर्तें कि नीचे दिये नक्शों के भाग (बी) में दर्ज कबाइली क्षेत्रों में मैदानों के कोई ऐसे क्षेत्र शामिल नहीं होंगे जिनकी बाबत, पहले से राजपति की रजामंदी लेकर, आसाम का रियासतपति इस तरह का नोटिस निकाल दे.

नक्शा

भाग (ए)

1. युक्त खासी-जैन्तिया पहाड़ी जिला.
2. गारो पहाड़ी जिला.
3. लुसाई पहाड़ी जिला.
4. नागा पहाड़ी जिला.
5. उत्तर कछार पहाड़ियां.
6. मिफिर पहाड़ियां.

भाग (बी)

1. उत्तर पूरब सरहदी खिस्ता जिसमें बालीपारा सरहदी खिस्ता, तिराप सरहदी खिस्ता, अबोर पहाड़ी खिला और मिसिमी पहाड़ी खिला शामिल हैं.
2. नागा कबाइली क्षेत्र.

21—पट्टी में सुधार—(1) राजपंचायत समय समय पर क़ानून बना कर इस पट्टी के किन्हीं बंधानों में कुछ जोड़ कर, बदल कर या रद्द करके सुधार कर सकती है और जब इस पट्टी में इस तरह सुधार किया जाय तो इस विधान में इस पट्टी की जहाँ कहीं चरचा आई है उससे मतलब इस तरह सुधार की हुई पट्टी की चरचा से लिया जायगा.

(2) कोई ऐसा क़ानून जिसका इस पैरा के उप-पैरा (1) में ज़िक्र आया है, दफ़ा 368 के मतलबों के लिये इस विधान का सुधार नहीं समझा जायगा.



निकट

प्रभु प्रीति

१०१

सिद्धि

११

१२

१३

१४

सातवीं पट्टी

[दफा 246]

तालिका एक—यूनियन तालिका

1. भारत का और भारत के हर भाग का बचाव, जिसमें बचाव की तैयारी और वह सब काम शामिल हैं जिनसे जंग के समय जंग चलाने में और जंग खतम होने के बाद असरदार ढंग से लाम तोड़ने में मदद मिले.

2. समन्दरी, जमीनी और हवाई फौजें; यूनियन की कोई और हथियार-बन्द फौजें.

3. छावनी छेत्रों की हद्दबन्दी, उन छेत्रों में मुकामी स्वराज, उन छेत्रों में छावनी अधिकारियों की बनावट और शक्तियां, और उन छेत्रों में मकानी गुंजाइश की क्वायदाबन्दी (जिसमें किरायों पर दबान शामिल है).

4. समन्दरी, जमीनी और हवाई फौजों की इमारतें.

5. हथियार, आग-हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक.

6. ऐटम शक्ति और उसे पैदा करने के लिये जरूरी खनिज साधन.

7. वह उद्योग जिन्हें राजपंचायत कानून बना कर बचाव के मतलब के लिये या जंग चलाने के लिये जरूरी ठहरा दे.

8. जानकारी और जांच का मरकजी महकमा.

9. बचाव, बिदेशी मामलों, या भारत की सुरक्षा से संबंध रखने वाले कारनों से रोकथामी नज़रबन्दी, इस तरह नज़रबन्दी किये हुए लोग.

10. विदेशी मामले; वह सब मामले जिनसे यूनियन का किसी बिदेशी मुल्क से संबंध होता है.

11. राजदूती, बनिजदूती और ब्योपारी प्रतिनिधान.

12. संयुक्त कौमी संगठन (यू एन ओ)

13. अन्तर-कौमी कानफरेन्सों, सभाओं और दूसरी संस्थाओं में भाग लेना और वहाँ जो फैसले किये जाय उन पर काम कराना.

14. विदेशी मुल्कों के साथ संधिनामे और समझौते करना और विदेशी मुल्कों के साथ जो संधिनामे, समझौते और माने हुए रिवाज हों उन पर काम कराना.

15. जंग और सुलह.

16. विदेशी अमलदारी.

17. नागरता, देखीकरन और विदेशी लोग.

18. परसौंपनी.

19. भारत में दाखिल होना, और भारत से बाहर जा बसना और भारत से निकाला जाना; पासपोर्ट और बीसा.

20. भारत से बाहर जगहों की तीर्थ यात्रा.

21. समन्दरी डकैतियां और जुर्म जो बीच समन्दर पर या हवा में किये जायं; क्रौमी के क़ानून के खिलाफ़ जुर्म जो ज़मीन पर या बीच समन्दर पर या हवा में किये जायं.

22. रेलमार्ग.

23. थल मार्ग जिन्हें राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में या ऐसे किसी क़ानून के अधीन क्रौमी थल मार्ग ठहरा दिया गया है.

24. देश के अन्दर के उन जल मार्गों पर, जिन्हें राजपंचायत ने क़ानून बना कर क्रौमी जल मार्ग ठहरा दिया हो, मशीनों से चलने वाले जहाज़ों के जरिये जहाज़बानी और जहाज़रानी; ऐसे जल-मार्गों पर मार्ग नियम.

25. समन्दरी जहाज़बानी और जहाज़रानी, जिसमें उबार-जल पर की जहाज़बानी और जहाज़रानी शामिल हैं; तिजारती बेड़े के लिये तालीम और ट्रेनिंग का प्रबन्ध, और इस तरह की तालीम और ट्रेनिंग का रियासतें और दूसरी एजेन्सियां जो प्रबन्ध करें उसकी क़ायदाबन्दी.

26. दीप-घर, जिसमें दीप जहाज़, मार्ग-संकेत, और जहाज़ों और हवा जहाज़ों की सलाहमती के लिये दूसरे प्रबन्ध शामिल हैं.

27. वह बन्दरगाह जो राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में या किसी मौजूदा क़ानून में या उनके अधीन 'बड़े बन्दरगाह' ठहरा

दिये गए हैं, जिनमें उनकी हृदयबन्दी, और उन बन्दरगाहों के अधिकारियों का बनाना और उनकी शक्तियां शामिल हैं.

28. बन्दरगाह चालीसिया, जिसमें उस संबंध के अस्पताल शामिल हैं; मल्लाही और समन्दरी अस्पताल.

29. हवा मार्ग; हवा जहाज और हवा-जहाजरानी; हवाई अड्डों का प्रबन्ध; हवा व्योपार और हवाई अड्डों की क्रायदाबन्दी और संगठन; हवा विद्या की तालीम और ट्रेनिंग का प्रबन्ध, और इस तरह की तालीम और ट्रेनिंग का रियासतें और दूसरी एजेन्सियां जो प्रबन्ध करें उसकी क्रायदाबन्दी.

30. सवारियों और माल का रेल मार्ग, समन्दर या हवा के रास्ते, या मशीनों से चलने वाले जहाजों में क्रौमी जल मार्गों से लाना, ले जाना.

31. डाक और तार; टेलीफोन, बेतार, धुनपसार और आवा-जाई के ऐसे ही दूसरे रूप.

32. यूनियन की जायदाद और उससे मालगुजारी, पर जो जायदाद पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत में है उस के बारे में उस रियासत के कानूनों के अधीन रहते हुए, सिवाय जहाँ तक कि राजपंचायत कानून बना कर कुछ और बंधान कर दे.

33. यूनियन के मतलबों के लिये जायदाद का हासिल करना या मंगैनी ले लेना.

34. देसी रियासतों के शासकों की मिलकियतों के लिये कोर्ट-कचहरियां.

35. यूनियन का सरकारी क्ररजा.

36. शिक्षा चलन, शिक्षा-गढ़न और कानूनी शिक्षा; विदेशी शिक्षा-बदलाव.

37. विदेशी उधारियां.

38. भारत का रिज़र्व बैंक,

39. डाकघर बचत बैंक.

40. भारत सरकार की या रियासत की सरकार की चलाई जाटारियां.

41. विदेशी मुल्कों से ब्योपार और तिजारत; बिदेसनी महसूल की सीमा के पार आयासी और निकासी; बिदेसनी महसूल की सीमाओं की परिभाषा.

42. अन्तर-रियासती ब्योपार और तिजारत.

43. ब्योपारी एकतनियों को एकतन करना, उनकी क्रायदाबन्दी और उनका समेटना, इसमें बंकदारी, बीमा और माली एकतनियों शामिल हैं पर सहकारी समितियां शामिल नहीं हैं.

44. ऐसी एकतनियों को एकतन करना, उनकी क्रायदाबन्दी और उनका समेटना, चाहे वह ब्योपारी हों या न हों, जिनके उद्देश एक रियासत तक महदूद नहीं हैं, पर इनमें विद्यापीठें शामिल नहीं हैं.

45. बंकदारी.

46. बदलाव-हुंडियाँ, चेक, प्रामिसरी नोट और इसी तरह के दूसरे पट्टे.

47. बीमा.

48. शेयर बाजार और पेश बाजार.

49. पेटेंट, ईजादें और डिजाइन; कापी राइट; ब्योपार-छाप और सौदागरी-माल-छाप.

50. तोल और माप के मान क्रायम करना.

51. भारत से बाहर भेजे जाने वाले और एक रियासत से दूसरी रियासत में जाने वाले माल के गुन-मान क्रायम करना.

52. वह उद्योग जिन का यूनियन के दबान में रहना राजपंचायत ने कानून बना कर जनता के हित में समझोचित ठहरा दिया है.

53. तेल-छेत्रों और खनिज तेल के स्रोतों की क्रायदाबन्दी और उनका विकास; पेट्रोलेियम और पेट्रोलेियम से बनी चीजें; दूसरे वह तरल और वह चीजें जिन्हें राजपंचायत ने कानून बनाकर भयानक आग-बकड़ ठहरा दिया है.

54. उस हद तक खदानों की क्रायदाबन्दी और खनिजों का विकास जिस हद तक कि इस तरह की क्रायदाबन्दी और विकास को

यूनियन के दबान में रखना राजपंचायत ने कानून बना कर जनता के हित में समयोचित ठहरा दिया है.

55. खदानों और तेल-छेत्रों में मजदूरी की क्रायदाबन्दी और सलामती .

56. उस हद तक अन्तर-रियासती नदियों और नदी-घाटियों की क्रायदाबन्दी और विकास जिस हद तक कि इस तरह की क्रायदाबन्दी और विकास को यूनियन के दबान में रखना राज-पंचायत ने कानून बनाकर जनता के हित में समयोचित ठहरा दिया है.

57. भूभागी समन्दर से परे मछली पकड़ना और मछियारी.

58. यूनियन की एजेंसियों का नमक बनाना, मोहय्या करना और बांटना; दूसरी एजेंसियाँ जो नमक बनाएं, मोहय्या करें और बांटें उसकी क्रायदाबन्दी और उस पर दबान.

59. अफीम की खेती, उसका बनाना और देश-बाहर निर्यात के लिये उसकी बिक्री.

60. सिनेमा फिल्मों को दिखाने की मंजूरी.

61. यूनियन के कामगारों संबंधी उद्योगी मगड़े.

62. वह संस्थाएँ जो इस विधान के आरंभ के समय नेशनल लाइब्रेरी, इन्डियन म्यूजियम, इम्पीरियल वार म्यूजियम, विक्टोरिया मेमोरियल और इन्डियन वार मेमोरियल कहलाती थीं और ऐसी कोई और संस्था जिसमें कुल या कुछ रुपया हिन्द सरकार का लगा हो और जिसे राजपंचायत कानून बना कर क़ौमी महत्व की संस्था ठहरा दे.

63. वह संस्थाएँ जो इस विधान के आरंभ के समय बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुसलिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी कहलाती थीं और कोई और संस्था जिसे राजपंचायत कानून बनाकर क़ौमी महत्व की संस्था ठहरा दे.

64. साइंसी या तकनीकी तालीम के लिये वह संस्थाएँ जिन में कुल या कुछ रुपया हिन्द सरकार का लगा हो और जिन्हें राज-पंचायत कानून बना कर क़ौमी महत्व की संस्था ठहरा दे.

65. नीचे लिखे मामलों के लिये यूनियन की एजेंसियां और संस्थाएं:—

- (ए) पेशाई, रोजगारी या तकनीकी ट्रेनिंग, जिसमें पुलिस अफसरों की ट्रेनिंग शामिल है; या
- (बी) खास पढ़ाईयों या खोज को बढ़ाना; या
- (सी) जुर्म की जांच या पता लगाने में साइंसी या तकनीकी मदद.

66. ऊँची तालीम या खोज की संस्थाओं और साइंसी और तकनीकी संस्थाओं में स्तर तय करना और उनमें तालमेल.

67. प्राचीन और इतिहासी यादगारों और लेखे और पुरातत्त्वी स्थान और खंडहर जिन्हें राजपंचायत कानून बनाकर क्रीमी महत्व का ठहरा दे.

68. भारत की सरवे, भारत की भू-विद्या, वनस्पति-विद्या, जन्तु-विद्या और नर-विद्या संबंधी अलग अलग सरवे; खगोल-विद्या संबंधी संस्थाएं.

69. गिनाबा.

70. यूनियन सरकारी नौकरियां; कुल-भारत नौकरियां; यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन.

71. यूनियन पेनशनें, यानी वह पेनशनें जो भारत सरकार को देनी हैं या भारत के मूठकोश में से दी जानी हैं.

72. राजपंचायत के, रियासतों की कानून सभाओं के और राजपति और उप-राजपति के पदों के चुनाव; चुनाव कमीशन.

73. राजपंचायत के मेम्बरों की, रियासत सदन के मसनदी और उप-मसनदी की और लोक सदन के सभामुख और उप-सभामुख की तनखाहें और भत्ते.

74. राजपंचायत के हर सदन की और हर सदन के मेम्बरों और कमेटियों की शक्तियां, निजनियम और बरीयते; राजपंचायत की कमेटियों या राजपंचायत के नियोजे कमीशनों के सामने गवाही देने या दस्तावेज पेश करने के लिये लोगों की हाजिरी लाजमी कराना.

75. राजपति और रियासतपतियों के बेतन, भत्ते, निजनियम

और छुट्टी के बारे में अधिकार; यूनियन के वज्जीरों की तनखाहें और भत्ते; दाब अफसर और सरपड़तालिया की तनखाहें, भत्ते और छुट्टी के बारे में अधिकार और नौकरी की दूसरी शर्तें.

76. यूनियन के और रियासतों के हिसाब किताब की पड़ताल.

77. आला अदालत की बनावट, संगठन, अमलदारी और शक्तियां (जिसमें उस अदालत की तौहीन शामिल है), और उस अदालत में जो फीसें ली जायं; वह लोग जो आला अदालत में बकालत करने के हकदार हैं.

78. हाईकोर्टों के अफसरों और नौकरों के बारे में बंधानों को छोड़कर हाईकोर्टों की बनावट और संगठन; वह लोग जो हाईकोर्टों में बकालत करने के हकदार हैं.

79. किसी ऐसी हाईकोर्ट की अमलदारी को जिसकी खास जगह किसी रियासत में है उस रियासत से बाहर किसी क्षेत्र तक बढ़ा देना, और उस रियासत से बाहर के किसी क्षेत्र से ऐसी किसी हाईकोर्ट की अमलदारी को अलग कर देना.

80. किसी रियासत के पुलिस बल के मेम्बरों की शक्तियों और अमलदारी को उस रियासत से बाहर के किसी क्षेत्र तक बढ़ा देना, पर इस तरह नहीं कि एक रियासत की पुलिस उस रियासत से बाहर के किसी क्षेत्र में, उस रियासत की सरकार की अनुमति बिना जिसके अन्दर वह क्षेत्र है, अपनी शक्तियों और अमलदारी से काम ले सके; किसी रियासत के पुलिस बल के मेम्बरों की शक्तियों और अमलदारी को उस रियासत से बाहर के रेल मार्ग क्षेत्रों तक बढ़ा देना.

81. एक रियासत से दूसरी रियासत में जा बसना; अन्तर-रियासती आलीसिया.

82. खेती-बाड़ी की आमदनी को छोड़ दूसरी आमदनी पर टैक्स.

83. बिदेसनी महसूल जिनमें निकासी महसूल शामिल हैं.

84. तन्त्राकू पर और भारत में बने या पैदा हुए सिबाय नीचे लिखे मालों के, दूसरे माल पर निकासनी महसूल :-

(ए) लोगों में खपत के लिये अलकोहोली तरल;

(बी) अफ्रीम, गांजा और दूसरी पीनक वाली जड़ी-बूटियां
और पीनक वाली चीजें,

पर दवा और सिंगार की वह तैयार की हुई चीजें इसमें शामिल
हैं जिनमें अलकोहल या इस अन्तरी के उप-पैरा (बी) में आई
हुई कोई चीज है.

85. एकतनी टैक्स.

86. खेती बाड़ी की जमीन को छोड़कर, अलग अलग आदमियों
और कम्पनियों की लेनदारियों की कुल मालियत पर टैक्स;
कम्पनियों की पूंजी पर टैक्स.

87. खेती बाड़ी की जमीन को छोड़कर दूसरी जायदाद के बारे
में मिलकियत महसूल.

88. खेती बाड़ी की जमीन को छोड़ कर दूसरी जायदाद की
विरासत के बारे में महसूल.

89. रेल मार्ग, समन्दर या हवा से जाने वाले माल या सवारियों
पर हद्दबारी टैक्स; रेल मार्ग के किरायों और भाड़ों पर टैक्स.

90. शेयर बाजारों और पेश बाजारों के सौदों पर स्टाम्प
महसूल को छोड़कर दूसरे टैक्स.

91. बदलाव हुण्डियों, चेकों, प्रामिसरी नोटों, लदाई बिलटियों,
साख-पत्रों, बीमा पालिसियों, शेयरों के तबादलों, क्ररज-पत्रों,
एक्जिजियों और रसीदों के बारे में स्टाम्प-महसूल की दरें.

92. अखबारों की बिकरी या खरीद पर और उनमें निकलने
वाले जाहिरात पर टैक्स.

93. इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में कानूनों के
जिक्काफ़ जुर्म.

94. इस तालिका के मामलों में से किसी के मतलब के लिये
पूछताछ, सरवे और आंकड़े.

95. इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में आला-
अदालत को छोड़ कर और सब अदालतों की अमलदारी और
शक्तियां; समन्दरी विभाग की अमलदारी.

96. किसी अदालत में जो फीसें ली जाती हैं उनको शामिल न

करते हुए, इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में फ्रीसें.

97. कोई दूसरा मामला, जो तालिका दो या तालिका तीन में नहीं गिनाया गया, जिसमें ऐसा टैक्स शामिल है जिसका जिक्र उन तालिकाओं में से किसी में नहीं आया.

तालिका दो-रियासत तालिका

1. जन-व्यवस्था (लेकिन नागरी शक्ति की मदद के लिये यूनि-यन की समन्दरी, जमीनी या हवाई फौजों या और किसी हथियार-बंद फौजों का इस्तेमाल इसमें शामिल नहीं है).

2. पुलिस, जिसमें रेल मार्ग और गांव पुलिस शामिल है.

3. न्याय-शासन; आला अदालत और हाईकोर्ट के सिवा सब अदालतों की बनावट और उनका संगठन; हाईकोर्ट के अफसर और नौकर; लगान और मालगुजारी की अदालतों का दस्तूर; आला अदालत के सिवा सब अदालतों में ली जाने वाली फ्रीसें.

4. जेलखानें, सुधार-घर, बोरस्टली संस्थाएँ और इसी तरह की दूसरी संस्थाएँ, और वह लोग जो उनमें रोक कर रखे जायें; जेल-खानों और दूसरी संस्थाओं के इस्तेमाल के लिये दूसरी रियासतों के साथ प्रबन्ध.

5. मुकामी हकूमत, यानी नगर एकतनियों, नगर सुधार ट्रस्टों, जिला बोर्डों, खदान आबादी अधिकारियों, और मुकामी स्वराज या गांव शासन के मतलब के लिये दूसरे मुकामी अधिकारियों, की बनावट और उनकी शक्तियां.

6. जन-तन्दुरुस्ती और सफाई; अस्पताल और दवाखाने.

7. तीर्थ यात्राएँ, भारत से बाहर जगहों की तीर्थ यात्राओं को छोड़ कर.

8. नशीले तरल, यानी नशीले तरलों का पैदा करना, बनाना, रखना, लाना ले जाना, खरीदना और बेचना.

9. अपाहिजों और काम न कर सकने वालों की मदद.

10. दफन और दफन-भूमियां; दाह और दाह-भूमियां.

11. तालीम जिसमें विद्यापीठ शामिल हैं पर तालिका एक की अन्वरी 63, 64, 65 और 66 और तालिका तीन की

अन्तरी 25 के बंधानों का ध्यान रखते हुए.

12. वह किताबघर, अजायबघर, और इस तरह की दूसरी संस्थाएँ जो रियासत के दबान में हों या रियासत के रूप से चलती हों; प्राचीन और इतिहासी यादगारें और लेखे, उन्हें छोड़ कर जिन्हें राजपंचायत क्रानून बना कर कौमी महत्व का ठहरा दे.

13. आबा-जाई के साधन यानी सड़कें, पुल, उतराई घाट, और आबा-जाई के ऐसे दूसरे साधन जो तालिका एक में दर्ज नहीं हैं; नगर ट्राम मार्ग; रस्सा मार्ग; देश अन्दर के जल मार्ग और ऐसे जल मार्गों के बारे में तालिका एक और तालिका तीन के बंधानों का ध्यान रखते हुए उन पर का ब्यापार; मशीन से चलने वाली गाड़ियों को छोड़ कर दूसरी गाड़ियां.

14. खेती बाड़ी, जिसमें खेती बाड़ी की तालीम और खोज, महामारी से रक्षा और पौधों की बीमारियों की रोकथाम शामिल है.

15. मवेशियों को बनाए रखना, बचाए रखना, और उनकी नसल सुधारना, और जानवरों की बीमारियों की रोकथाम; पशु-इलाज की ट्रेनिंग और उसका ब्योहार.

16. कांजी हौज़ और मवेशियों के हृद लांचने की रोकथाम.

17. पानी, यानी पानी पहुँचाना, सिंचाई और नहरें, पानी का निकास और बांध, पानी इकट्ठा करना और पन-शक्ति, तालिका एक की अन्तरी 56 के बंधानों का ध्यान रखते हुए.

18. ज़मीन, यानी ज़मीन में या ज़मीन पर अधिकार, भूमि-दारियां जिनमें ज़मींदार और किसान का संबंध शामिल है, और लगान जमा करना; खेती बाड़ी की ज़मीन का दाखिल-खारिज और दूसरों को दे डालना; ज़मीन को सुधारना और खेती बाड़ी के लिये उधारियां; बस्तियां बसाना.

19. जंगलात.

20. जंगली जानवरों और परिन्दों की रक्षा.

21. मछियारियां.

22. तालिका एक की अन्तरी 34 के बंधानों का ध्यान रखते हुए कोर्ट कचहरियां; करजा-दबी और कुर्क मिलकियतें.

23. यूनियन के दबान में खदानों की क्रायदाबन्दी और खनिजों के विकास की बाबत तालिका एक के बंधानों का ध्यान रखते हुए खदानों की क्रायदाबन्दी और खनिजों का विकास.

24. तालिका एक की अन्तरी 52 के बंधानों का ध्यान रखते हुए उद्योग.

25. गैस और गैस के कारखाने.

26. रियासत के अन्दर व्यापार और तिजारत, तालिका तीन की अन्तरी 33 के बंधानों का ध्यान रखते हुए.

27. माल का पैदा करना, मोहय्या करना और बांटना, तालिका तीन की अन्तरी 33 के बंधानों का ध्यान रखते हुए.

28. मंडियां और मेले.

29. तोलने के बाट और माप, सिवाय उनके मान क्रायम करने के.

30. रुपया उधार देना और साहूकार; खेतिहरों की कर्जदारी को हल्का करना.

31. सराय और सराय रखने वाले.

32. तालिका एक में दर्ज एकतनियों को छोड़ कर एकतनियों और विद्यापीठों को एकतन करना, उनकी क्रायदाबन्दी, और उनको समेटना; ऐसी व्यापारी, अदबी, साइंसी, धार्मिक और दूसरी सोसाइटियां और सभाएँ जो एकतन नहीं हैं; सहकारी समितियां.

33. थेटर और नाटक के खेल; तालिका एक की अन्तरी 60 के बंधानों का ध्यान रखते हुए सिनेमा; खेल, मनोरंजन और तमाशे.

34. शर्त बदना और जुआ खेलना.

35. कारखाने, जमीनें और इमारतें जो रियासत को हासिल हैं या जो रियासत के कब्जे में हैं.

36. तालिका तीन की अन्तरी 42 के बंधानों का ध्यान रखते हुए, जायदाद का हासिल कर लेना या मंगैनी ले लेना, सिवाय यूनियन के मतलबों के लिये.

37. राजपंचायत के बनाये किसी क़ानून के बंधानों का ध्यान रखते हुए रियासत की क़ानून सभा के चुनाव.

38. रियासत की क़ानून सभा के मेम्बरों की, आम सदन के

सभामुख और उप-सभामुख की, और अगर खास सदन हो तो उसके मसनदी और उप-मसनदी की तनखाहें और भत्ते.

39. आम सदन की, और उसके मेम्बरों और उसकी कमेटियों की, और अगर खास सदन है तो उस सदन की और उसके मेम्बरों और उसकी कमेटियों की, शक्तियां, निजनियम और बरीयतें; रियासत की क़ानून सभा की कमेटियों के सामने गवाही देने या दस्तावेजों पेश करने के लिये लोगों की हाज़िरी लाज़मी कराना.

40. रियासत के वज़ीरों की तनखाहें और भत्ते.

41. रियासत सरकारी नौकरियां; रियासत सरकारी नौकरी कमीशन.

42. रियासत पेनशनें, यानी वह पेनशनें जो रियासत को देनी हैं या रियासत के मूठकोश में से दी जानी हैं.

43. रियासत का सरकारी करखा.

44. गड़े और लावारसी खज़ाने.

45. ज़मीन की मालगुज़ारी, जिसमें मालगुज़ारी का तय करना और जमा करना, ज़मीन के लेखे रखना, मालगुज़ारी के मतलबों के लिये सरवे और अधिकारों के लेखे, और मालगुज़ारी दूसरों के नाम करना, सब शामिल हैं.

46. खेती बाड़ी की आमदनी पर टैक्स.

47. खेती बाड़ी की ज़मीन की विरासत के बारे में महसूल.

48. खेती बाड़ी की ज़मीन के बारे में मिलकियत महसूल.

49. ज़मीनों और इमारतों पर टैक्स.

50. उन सीमाओं के अन्दर रहते हुए जो राजपंचायत क़ानून बना कर खनिजों के विकास के संबंध में तय कर दे, खनिजों के अधिकारों पर टैक्स.

51. नीचे लिखे मालों पर जो उस रियासत में बने हों या पैदा हुए हों निकासनी महसूल, और उसी तरह के मालों पर जो भारत में कहीं और बने हों या पैदा हुए हों उसी दर से या कम दर से पाखंगी महसूल :—

(ए) लोगों में खपत के लिये अलकोहोली तरल;

(बी) अफीम, गांजा और दूसरी पीनक वाली जड़ी बूटियां और पीनक वाली चीजें;
पर दबा और सिंगार की वह तैयार की हुई चीजें इनमें शामिल नहीं होंगी जिनमें अलकोहल या इस अन्तरी के उप-पैरा (बी) में आई हुई कोई चीज है.

52. किसी मुकामी क्षेत्र में खपत, इस्तेमाल या बिकरी के लिये माल की आमद पर टैक्स.

53. बिजली की खपत या बिकरी पर टैक्स.

54. अखबारों को छोड़ कर दूसरे मालों की बिकरी या खरीद पर टैक्स.

55. अखबारों में निकलने वाले जाहिरात को छोड़ कर दूसरे जाहिरात पर टैक्स.

56. सड़कों से या देश-अन्दर के जलमार्गों से जाने वाले माल और सवारियों पर टैक्स.

57. ऐसी गाड़ियों पर टैक्स, चाहे वह मशीन से चलती हों या नहीं, जो सड़कों पर इस्तेमाल के क्वालिफाई हों, जिनमें ट्राम-गाड़ियां शामिल हैं, पर तालिका चीन की अन्तरी 35 के बंधानों का ध्यान रखते हुए.

58. जानवरों और किशतियों पर टैक्स.

59. टोल टैक्स.

60. पेशों, व्यापारों, रोजगारों और कामगारियों पर टैक्स.

61. आदमीवार टैक्स.

62. ऐश की चीजों पर टैक्स, जिनमें मनोरंजनों, तमाशों, शर्त बटने और जूए पर टैक्स शामिल हैं.

63. स्टाम्प महसूल की दरों के बारे में तालिका एक के बंधानों में जो दस्तावेजों बताई गई हैं उनको छोड़कर दूसरी दस्तावेजों के बारे में स्टाम्प महसूल की दरें.

64. इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में कानूनों के खिलाफ जुर्म.

65. इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में आला-

अदालत के बिना सब अदालतों की अमलदारी और शक्तियां.

66. इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में फीसें, लेकिन किसी अदालत में ली जाने वाली फीसें इसमें शामिल नहीं हैं.

तालिका तीन—संगचारी तालिका

1. फौजदारी कानून, जिस में वह सब मामले शामिल हैं जो इस विधान के आरंभ के समय ताज्जिरात हिन्द में शामिल हों, पर तालिका एक या तालिका दो में दर्ज मामलों में से किसी के बारे में कानूनों के खिलाफ जुर्म इसमें शामिल नहीं है और न नागरी शक्ति की मदद के लिये यूनियन की समन्दरी, ज़मीनी या हवाई फौजों या दूसरी किसी हथियार-बन्द फौजों का इस्तेमाल इसमें शामिल है.

2. फौजदारी दस्तूर, जिसमें वह सब मामले शामिल हैं जो इस विधान के आरम्भ के समय ज़ाब्ता फौजदारी में शामिल हों.

3. किसी रियासत की सुरक्षा से, जन-व्यवस्था को बनाए रखने से, या समाज के लिये ज़रूरी रखद और नौकरियों को बनाए रखने से संबंध रखने वाले कारनों से रोकथामी नज़रबन्दी; वह लोग जो इस तरह नज़रबंद रखे जायें.

4. क़ैदियों का, मुलज़िमों का और इस तालिका की अन्तरी 3 में दर्ज कारनों से रोकथामी नज़रबन्दी में रखे लोगों का एक रियासत से दूसरी रियासत को हटाया जाना.

5. ब्याह-शादी और तलाक़; दुधमुँह बच्चे और नाबालिग़; गोद लेना; बसीयतें, बेवसीयती और विरासत; मिला-जुला परिवार और बटवारा; वह सब मामले जिनके बारे में इस विधान के आरंभ होने से ठीक पहले अदालती कारवाइयों के फ़रीक़ अपने अपने निजी कानून के अधीन थे.

6. खेती बाड़ी की ज़मीन को छोड़ कर दूसरी जायदाद का वबादला; तमसुकों और दस्तावेज़ों की रजिस्ट्री.

7. ठेके, जिसमें सामेदारी, एजेंसी, माल ढोने के ठेके, और ठेकों के दूसरे खास रूप शामिल हैं, पर जिनमें खेती बाड़ी की ज़मीन के बारे में ठेके शामिल नहीं हैं.

8. कानूनी कारवाई के क़ाबिल ग़लत काम.

9. नादार हो जाना और दिवाला.
10. ट्रस्ट और ट्रस्टी.
11. सर प्रबन्धक और सरकारी ट्रस्टी.
12. गवाही और हलफ; क़ानूनों, सरकारी कामों और सरकारी लेखों, और अदालती कारवाइयों का माना जाना.
13. दीबानी दस्तूर, जिसमें वह सब मामले शामिल हैं जो इस विधान के आरंभ के समय ज़ाबता दीबानी में शामिल हों, मियाद-बन्दी और पंचनामा.
14. अदालत की तौहीन, पर जिसमें आला अदालत की तौहीन शामिल नहीं है.
15. आबारागरदी; खानाबदोश और मौसमी क़बीले.
16. पागलपन और दिमागी कमी, जिसमें वह जगहें शामिल हैं जहां पागलों और दिमागी कमी वालों को लिया जाय या उनका इलाज किया जाय.
17. जानवरों पर बेरहमी की रोकथाम.
18. खाने की चीज़ों और दूसरे माल में मिलावट.
19. जड़ी बूटियां और जहर, अफ़ीम के बारे में तालिका एक की अन्तरी 59 के बंधानों का ध्यान रखते हुए.
20. आर्थिक और समाजी योजना.
21. तिजारती और उद्योगी इजारे, ब्योपारी गुट और ट्रस्ट.
22. ट्रेड यूनियनों; उद्योगी और मज़दूरी क़गड़े.
23. समाजी सुरक्षा और समाजी बीमा; कामगारी और बेकामगारी.
24. मज़दूरों की भलाई, जिसमें काम की शर्तें, प्राविडेन्ट फ़ण्ड, मालिकों की देनदारी, कामगारों की नुक़सान-भरपाई, निबल और बुढ़ापा पेनशनें और जापा रियायतें शामिल हैं.
25. मज़दूरों की रोज़गारी और तकनीकी ट्रेनिंग.
26. क़ानूनी, डाक्टरी और दूसरे पेशे.
27. हिन्दू और पाकिस्तान डोमिनियनों के क़ायम होने के कारन अपनी पहली रहने की जगह से उखड़े हुए लोगों की मदद और उनका फिर-बसाव.

28. खैरात और खैराती संस्थाएँ, खैराती और धार्मिक देन और धार्मिक संस्थाएँ.

29. उड़नी बीमारियों या छूत की बीमारियों या आक्रमियों, जानवरों या पौधों पर असर करने वाली महामारियों, के एक रियासत से दूसरी रियासत में फैलने की रोकथाम.

30. जीवन आंकड़े, जिसमें जनम और मौत की रजिस्ट्री शामिल है.

31. बन्दरगाह, उन बन्दरगाहों को छोड़ कर जिनको राज-पंचायत के बनाए क़ानून में या मौजूदा क़ानून में या उनके अधीन बड़े बन्दरगाह ठहरा दिया गया हो.

32. देश-अन्दर के जलमार्गों पर, जहाँ तक मशीन से चलने वाले जहाज़ों का सम्बन्ध है, जहाज़बानी और जहाज़रानी, ऐसे जलमार्गों पर मार्ग नियम, और क़ौमी जल मार्गों के बारे में तालिका एक के बंधानों का ध्यान रखते हुए, देश-अन्दर के जलमार्गों पर सवारियों और माल का लाना लेजाना.

33. जहाँ कुछ उद्योगों को यूनियन के दबान में रखना राज-पंचायत ने क़ानून बनाकर जनता के हित में समयोचित ठहरा दिया हो, वहाँ उन उद्योगों की पैदावार का ब्योपार और तिज़ारत, और उनका पैदा करना, मोह्य्या करना और बांटना.

34. दाम कंट्रोल.

35. मशीनों से चलने वाली गाड़ियाँ, जिसमें वह सिद्धान्त शामिल हैं जिनके अनुसार ऐसी गाड़ियों पर टैक्स लगाये जायेंगे.

36. फ़ैक्टरियाँ.

37. बायलर.

38. बिजली.

39. अख़बार, किताबें और छापेखाने.

40. पुरातत्त्वी स्थान और खंडहर, उनको छोड़ कर जिन्हें राज-पंचायत क़ानून बना कर क़ौमी महत्व का ठहरा दे.

41. उस जायदाद की रखवाली, प्रबन्ध और निपटारा (जिसमें खेती बाड़ी की ज़मीन शामिल है), जिसे क़ानून ने घर छुट-जायदाद ठहरा दिया हो.

42. वह सिद्धान्त जिन पर यूनियन के या किसी रियासत के मतलबों के लिये या किसी दूसरे सरकारी मतलब के लिये जो जायदाद हासिल कर ली जाय या मंगैनी ले ली जाय उसकी नुकसान भरपाई तय की जानी है, और जिस रूप में और जिस ढंग से वह भरपाई दी जानी है.

43. किसी रियासत में टैक्सों और दूसरी सरकारी मांगों के बारे में, जिनमें ज़मीन की मालगुजारी की बक्राया और ऐसी बक्राया के रूप में जो रक़मों वसूल करनी हैं वह शामिल हैं, उन दावों की वसूली जो उस रियासत के बाहर पैदा हुए हों.

44. अदालती स्टाम्पों से जो महसूल या फ़ीस जमा की जाय उनको छोड़ कर दूसरे स्टाम्प महसूल, पर इसमें स्टाम्प महसूल की दरें शामिल नहीं हैं.

45. तालिका दो या तालिका तीन में दर्ज मामलों में से किसी के मतलबों के लिये पूछताछ और आंकड़े.

46. इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में, आला अदालत के सिवा, सब अदालतों की अमलदारी और शक्तियां.

47. इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में फ़ीसें, लेकिन किसी अदालत में ली जाने वाली फ़ीसें इसमें शामिल नहीं हैं.

आठवीं पट्टी

[दफा 344 (1) और 351]

भाषाएँ

1. आसामी.
 2. बंगला.
 3. गुजराती.
 4. हिन्दी.
 5. कन्नड.
 6. कश्मीरी.
 7. मलयालम.
 8. मराठी.
 9. उड़िया.
 10. पंजाबी.
 11. संस्कृत.
 12. तामिल.
 13. तेलगू.
 14. उर्दू.
-

भारत के विधान
की
शब्द-माला

शब्दमाला

हिन्दी से अंगरेजी

हिन्दी के कुछ शब्द जो इस अनुवाद में बरते गए हैं और

उनके सामने मूल अंगरेजी के जवाबी शब्द

अ	अदालती फ़ैसला—Adjudication
अचल—Immoveable	अदालती स्टाम्प—Judicial stamp
अचानक माँग—Unexpected demand	अधिक अदालत—Additional court
अचानक—Emergency	अधिक खर्च—Excess expenditure
अचानकी का ऐलान—Proclamation of emergency	अधिक ज़िला जज—Additional District Judge
अचानकी बन्धान—Emergency provision	अधिक देनगी—Excess grant
अछूतपन—Untouchability	अधिक सेशन जज—Additional Sessions Judge
अजायबघर—Museum	अधिकार—Right
अयोग्यता—Disqualification	अधिकारना—To authorise
अदन साहित्य—Literature	अधिकारी—Authority
अदबी—Literary	अधिकारी अदालत—Competent Court
अदल बदल—Modification	अधिकारी क़ानून सभा—Competent Legislature
अदल बदल करना—To modify	अन-ओटी रुई—Unginned cotton
अदा करना—To make payment, to repay	अनकरी क़रूरत—Undeserved want
अदा करना, अपने को—To express oneself	अनधिकार—Incompetency
अदायगी—Payment	अनमिल फ़ैसला—Dissenting judgment
अदालत—Court	
अदालती कारवाई—Judicial proceeding	

भारत का विधान

अनमिल राय—Dissenting Opinion	अफसर—Office
अनसूझे खच—Unforeseen expenditure	अबरक—Mica
अनिश्चित रूप—Indefinite character	अमलदारी—Jurisdiction
अनुकूलन—Adaptation	अमला—Staff
अनुपात—Ratio	अमली—Practicable, practical
अनुमति—Consent	अमली तजुर्बा—Practical experience
अनुवाद—Translation	अरज़ी पत्र—Representation
अन्तरक्रौमी—International	अर्थ—Interpretation
अन्तरब्योहार—Intercourse	अर्थ व्यवस्था—Economic system
अन्तररियासती—Inter-state	अलकोहल—Alcohol
अन्तरात्मा—Conscience	अलकोहोली तरल—Alcoholic liquor
अन्तरी—Entry	अलग देनगी—Exceptional grant
अपनाना—To adopt	अलग रखना—Reservation
अपमानलेख—Libel	अलग रखी सोट—Reserved seat
अपमानवचन—Slander	अलावा—In addition to
अपवाद—Exception	असक्त—Disability
अपात्र—Ineligible	असर—Effect
अपाहज—Disabled	असरदार—Effective
अपाहजी पेनशन—Disability pension	असरदार ढंग से—Effectively
अपील—Appeal	असल कीमत—Principal value
अपील की बिना—Ground of appeal	असल नौकरी—Actual service
अपीली अदाकत—Court of appeal	असल वसुली—Net proceeds
अपीली अमलदारी—Appellate jurisdiction	आ
	आकड़ा—Figure
	आकड़े—Statistics
	आकना—To assess

आग-इधवार—Fire-arms	आर्थिक—Economic
आज़ादी—Liberty, freedom	आर्थिक सकत—Economic capacity
आजीवन काकापानी—Transportation for life	आर्थिक संगठन—Economic organisation
आदतन—Habitually	आर्थिक हित—Economic interest
आदमीवार टैक्स—Capitation tax	आला अदालत—Supreme Court
आधार—Basis	आला कमान—Supreme command
आम—General, public	आवाजआई—Communication
आम कानून—General law	आवाजआई के साधन—Means of communication
आम चुनाव—General election	आवारागरदी—Vagrancy
आम चुनाव चिट्ठा—General electoral roll	आवेदन पत्र—Memorial
आम टैक्स—General tax	आसाम जंगल कायदाबन्दी, 1891—Assam Forest Regulation, 1891
आमदनी टैक्स—Income tax	
आम दस्तूर—Procedure in general	
आम धारा एक्ट, 1897—General Clauses Act, 1897	
आम नोटिस—Public notification	
आम सदन—Legislative Assembly	
आम हुकुम—General order	
आमियत—Generality	
आयासी—Import	
आरज़ी—Temporary	
आरज़ी बन्वान—Temporary provision	
आरम्भ—Commencement	

भारत का शिक्षान

इलाका कोश—Regional fund	एकतनी—Corporation
इलाका भाषा—Regional language	एकतनी कम्पनी—Incorporated company
इलाका मंडल—Regional council	एकतनी टैक्स—Corporation tax
इस्तीफा—Resignation	एकता—Unity
ई	एकरूपता—Uniformity
ईजाद—Invention	एक्ट—Act
उ	एजेंट—Agent
उठावा—Issue	एजेंसी—Agency
उबनी बीमारी—Infectious disease	एटम शक्ति—Atomic energy
	एवजी—Proxy
	ऐ
उतराई घाट—Ferry	ऐलान—Proclamation
उद्योग—Industry	ऐलान करना—To proclaim, to declare
उद्योगी—Industrial	ऐलान निकालना—To issue proclamation
उद्योगी कारबार—Industrial undetraking	ऐश—Luxury
उद्योगी झगड़ा—Industrial dispute	ओ
उधार लेना—Borrowing	ओटी रुई—Ginned cotton
उधारी—Loan	ओहदा—Office
उधारी लेना—To raise loan	औ
उप-धारा—Sub-clause	औसत—Average
उप-राजपति—Vice-President	औसरी सुनी—Casual vacancy
उपराजप्रमुख—Uprajpramukh	क
उपाधि—Distinction	कषा उमर—Tender age
उम्मीदवार—Candidate	कषाईली क्षेत्र—Tribal area
ए	कषाईली मंडल—Tribal Council
एकतन करना—To incorporate	
एकतन संस्था—Body corporate	

क्राइली समाज—Tribal comm-	क्रान्तिकारी—Legislative
unity	क्रान्तिकारी काम—Legislative
कबीला—Tribe	function
कबीला सलाहकार मंडल—Tribes	क्रान्तिकारी शक्ति—Legislative
Advisory Council	power
कमीयत—Minority	क्रान्तिकारी संबंध—Legislative
कमीशन—Commission	relation
कमेटी—Committee	क्रान्तिकार्य—Violation of law
कम्पनी—Company	क्रान्तिकार्य बनाना—To legislate,
करजपत्र—Debenture	to enact
करजा—Debt	क्रान्तिकार्य शास्त्री—Jurist
करजा स्वर्च—Debt charges	क्रान्तिकार्यसभा—Legislature
करजा चुकाई कोश—Sinking fund	क्रान्तिकार्यसंगत—Lawful
करजा चुकाना, करजा भुक्तान—	क्रान्तिकार्यी कारवाही—Legal pro-
Redemption of debt	ceedings
करजादारी—Encumbered	क्रान्तिकार्यी सामला—Legal matter
कलचर—Culture	क्रान्तिकार्यी सवाल—Question of law
कलचरी—Cultural	क्रान्तिकार्यी सिक्का—Legal tender
कला—Art	कपीराइट—Copyright
कसबा कमेटी—Town com-	काम का संचालन—Conduct of
mittee	business
काजकारी—Executive	कामगार—Employee, work-
काजकारी काम—Executive	man, worker
action, executive function	कामगारी—Employment
काजकारी शक्ति—Executive	कामचलाक—Provisional
power	कामचलाक क्रान्तिकार्यसभा—Provisi-
कानग्रेंस—Conference	onal Legislature
क्रान्तिकार्य—Law	कामचलाक राजपंचायत—Provi-
क्रान्तिकार्य का ठोस सवाल—Substan-	sional Parliament
tial question of law	काम निभारना—To discharge
	function

भारत का विधान

क्रायदा, क्रायदाबन्दी—Regulation	खदान—Mine
क्रायदादारी—Discipline	खदान आबादी अधिकारी—Mining Settlement Authority
क्रायसी हुकुम—Standing order	खनिज—Mineral
कारकर—Acting	खनिज तेल—Mineral oil
कारकर सरजज—Acting Chief Justice	खनिज साधन—Mineral resources
कारबार—Business	खनिजों का विकास—Mineral development
कारवाई रोक देना—Stay of proceedings	खपत—Consumption
कालम—Column	खफ़ीफ़ा अदालत—Small Cause Court
कांजी हौज़ - Cattle pound, pound	खर्च—Expenditure, expense
किताब घर—Library	खर्च की मद में ढालना—To appropriate
की रु से—By virtue of	खानाबदोश—Nomadic
कुरकी—Attachment	खास चुनाव बिट्टा—Special electoral roll
कुल मालियत—Capital value	खास जानकारी—Special knowledge
कुल वसूली—Whole proceeds	खास टैक्स—Special tax
के इच्छाकाल तक—During the pleasure of	खास दस्तूर—Special procedure
कोर्ट कचहरी—Court of Wards	खास निर्देश—Special directive
कोरम—Quorum	खास पढ़ाई—Special study
क्रीम—Nation	खास प्रतिनिधान—Special representation
क्रीमी जलमार्ग—National waterway	खास बन्धान—Special provision
क्रीमी थलमार्ग—National highway	
क्रीमी हित—National interest	
क़ासिल समेत सम्राट—His Majesty in Council	
क्लर्क—Clerk	
ख	
खगोलविद्या—Meteorology	

खास रियायत—Special concession	गवर्नरी सूबा—Governor's province
खास रूप—Special form	गहरी अप्पानकी—Grave emergency
खास सदन—Legislative Council	गाँव अदालत—Village court
खास सरबचन—Special address	गाँव कमेटी—Village committee
खिताब—Title	गाँव पुलिस—Village police
खिता—Tract	गाँव पंचायत—Village panchayat
खुद-मालिक—Sovereign	गाँव मंडल—Village council
खुला इजलास—Open court	गाँव शासन—Village administration
खेतिहर—Agricultural worker	गारंटी—Guarantee
खेती बाड़ी—Agriculture	गिनावा—Census
खेती बाड़ी की आमदनी—Agricultural income	गुन मान—Standard of quality
खेती बाड़ी की जमीन—Agricultural land	गुना—Multiple
खैरान—Charity	घरकानूनी—Illegal
खरती संस्था—Charitable institution	घेर-हिन्दी-भाषी क्षेत्र—Non-Hindi speaking area
खोज—Research	गस—Gas
खोज निकालना—Discovery	गोद लेना—Adoption
खंड—Chapter	गोला बारूद—Ammunition
खंडहर—Remains	घ
ग	घरछुट—Evacuee
गम्भीरता के साथ—Solemnly	घरछुट जायदाद—Evacuee property
गवर्नर—Governor	घरेलू उद्योग—Cottage industry
गवर्नर जनरल—Governor General	घाटी—Valle

भारत का विधान

घायली पेनशन—Wound pension	छावनी अधिकारी—Cantonment authority
च	छावनी क्षेत्र—Cantonment area
चल—Moveable	छुट-क़ानून—Bye-law
चालीसिया—Quarantine	छुट्टी—Leave, leave of absence
चाहनी—Desirable	छूत की बीमारी—Contagious disease
चीफ़ कमिशनर—Chief Com- missioner	क्षेत्र—Area
चीफ़ कमिशनरी सूबा—Chief Commissioner's Province	छोटा सरनामा—Short title
चुनायत—Electorate	ज
चुनाव—Election	जज—Judge
चुनाव अदालत—Election tribunal	जड़ी बूटी—Drug
चुनाव अरज़ी—Election petition	जनक पुरुष—Male progenitor
चुनाव कमिशनर—Election Commissioner	जन-वन्दुस्ती—Public health
चुनाव कमीशन—Election Com- mission	जनता—Public
चुनाव का संचालन—Conduct of election	जनता की संस्था—Public insti- tution
चुनाव चिट्ठा—Electoral roll	जनराज—Republic
चुनाव मंडल—Electoral college	जन-व्यवस्था—Public order
चुनाव इल्का—Constituency	जन्तु विद्या—Zoology
चेक—Cheque	जन्मस्थान—Place of birth
छ	जबरन हासिल करना—Compul- sory acquisition
छांटना—To select	जबरी पज़बूरी—Forced labour
छापाख़ाना—Printing press	जबरी सेवा—Compulsory service
छावनी—Cantonment	ज़प्ती—Forfeiture
	ज़मानत—Security, bail

शब्दमाला

जमीन—Land	जायदाद—Property
जमीन का बटवारा—Allotment of land	जाहिरात—Advertisement
जमीनी श्रौज—Military force	बिताऊ वोट—Casting vote
जकरती जज—Ad hoc Judge	बिन्स—Sex
जलयान घर—Restaurant	ज़िला—District
जलमार्ग—Waterway	ज़िला अदालत—District Court
जवाबदेह—Answerable	ज़िला कोश—District fund
जवाबदेही करना—To defend	ज़िला जज—District Judge
जवाबी देसो रियासत—Corres- ponding Indian State	ज़िला बोर्ड—District Board
जवाबी रियासत—Correspond- ing State	ज़िला मंडल—District Council
जवाबी सूबा—Corresponding Province	जीवन आंकड़े—Vital Statistics
जहाज़—Vessel, shipping	जीवन स्तर—Standard of living
जहाज़बानी—Shipping	जुर्म लगाना—To accuse
जहाज़ रानी—Navigation	ख़तरा का काम—Hazardous employment
जात—Caste	जोग—Qualified
जानकारी और जाँच का मरकज़ी महकमा—Central Bureau of Intelligence and Investi- gation	जोगता—Qualification
जापा—Maternity	जोगाजोग—Contingency
जापा मदद—Maternity relief	जोगाजोग कोश—Contingency Fund
जापा रियायत—Maternity benefit	जंग ख़तम होना—Termination of war
जा बसना—Migration	जंग चलाना—Prosecution of war
ज़ान्दा दीवानी—Code of Civil Procedure	ज्वार जल—Tidal waters
ज़ान्दा फ़ौजदारी—Code of Criminal Procedure	झु —Tendency ट टापू—Island

भारत की विधान

द्रु—Fraction	त
टेलीफोन—Telephone	तकनीकी—Technical
टैक्स—Tax	तकनीकी तालीम—Technical education
टोल टैक्स—Tolls	तखमीना—Estimate
ट्रस्ट—Trust	तनखाह—Salary
ट्रस्टी—Trustee	तनपाऊन तल—Level of nutrition
ट्रामगाड़ी—Tramcar	तन्दुस्ती—Health
ट्राममार्ग—Tramway	तफ़सील—Detail
ट्रेड यूनियन—Trade Union	तबदीलना—To transfer
ट्रेनिंग—Training	तबादला—Transfer
ठ	तमसुक—Deed
ठहराव—Resolution	तमाशा—Amusement
ठहराव पेश करना—To move a resolution	तरक्की—Promotion
ठेका—Contract	तरजीह—Preference
ड	तरल—Liquid, liquor
डाक और तार—Posts and Telegraphs	तलाक़—Divorce
डाकघर—Post Office	तसदीक़ करना—To ratify
डाकघर बचत बैंक—Post Office Savings Bank	ताज़ीराय हिन्द—Indian Penal Code
डिग्री—Decree	तातील—Vacation
डिजाइन—Design	ताक़मेल—Co-ordination
डिप्टी कमिशनर—Deputy Commissioner	तालिका—List
डिवीज़न अदालत—Division Court	तालीम—Education
डोमिनियन कानूनसभा—Dominion Legislature	तालीमी देनगियां—Educational grants
	तालीमी संस्था—Educational institution

शब्दमाला

तिजारत—Commerce	दसखती सनद—Signed
तिजारती कारबार—Commercial	Certificate
undertaking	दस्तावेज—Document
तिजारती बेड़ा—Mercantile	दस्तूर—Procedure
marine	दस्तूरी मामला—Matter of
तिजारती माल—Commodity	Procedure
तिलहन—Oilseeds	दाखला—Admission
तीथयात्रा—Pilgrimage	दाखिल खारिज—Transfer
तेलक्षेत्र—Oil field	(of proprietary right in
तेनातो—Posting	land)
तोल—Weight	दाब अफसर—Comptroller
तोलने के षाट—Weights	दाब अफसर और सर पढ़तालिया—
तौहीन—Contempt	Comptroller and Auditor

थ

थल मार्ग—Highway	दाम कंट्रोल—Price control
थेटर—Theatre	दावा—Claim
थोक कारबार—Wholesale	दावा करना—To claim
business	दाह—Cremation

द

दफ़तर—Office	दाह भूमि—Cremation
दफ़तरी गज़ट—Official Gazette	ground
दफ़तरी भाषा—Official	दिमाग की कमजोरी—Infirmary
language	of mind
दफ़न—Burial	दिमागी कमी—Mental defi-
दफ़न भूमि—Burial ground	ciency
दफ़्ता—Article	दिवाळा—Insolvency
दबान—Control	दिवाळिया—Insolvent
दर—Rate	दीपघर—Lighthouse
दवाखाना—Dispensary	दीप जहाज़—Lightship
	दीवानी—Civil
	दीवानी अदालत—Civil court

भारत का विधान

दीवानी अमलदारी--Civil jurisdiction	धन का कीलना -- Concentration of wealth
दीवानी कारवाई--Civil proceeding	धन दौलती--Economic
दीवानी दस्तूर--Civil procedure	धरती--Land
दीवानी नालिश--Civil suit	धर्म--Religion
दीवानी पद्धत--Civil code	धारा--Clause
दुधारी बोर--Milch cattle	धार्मिक--Religious
दुबरी चुनाव--Biennial election	धार्मिक आज़ादी--Freedom of religion
दुसरकी स्कूल--Secondary school	धार्मिक देन--Religious endowment
देन--Endowment	धार्मिक फ़िरका - Religious denomination
देनगी--Grant	धार्मिक शिक्षा--Religious instruction
देनगी करना--To grant, to make a grant	धार्मिक संस्था--Religious institution
देनगी की मांग--Demand for a grant	धुनपसार--Broadcasting
देनगी को पूरा करना--To meet a grant	धंधा--Occupation
देनदार--Liable	न
देनदारी--Liability	नक़दी बिल--Money Bill
देनस्थान--Destination of grant	नक़ल--Copy
देसीकरण--Naturalisation	नक़शा--Table
देसी रियासत--Indian State	नगर एकतनी--Municipal Corporation
दोशलेखा--Charge	नगर ट्रामवार्ग--Municipal tramway
दंड--Penalty	नगर दीवानी अदालत--City Civil Court
ध	नगर सुधार ट्रस्ट--Improvement Trust
धन--Wealth	

नगरायत—Municipality	नायब सदर—Deputy President
नगरायत क्षेत्र—Municipal area	
नज़रबन्दी—Detention	नाख़िश—Suit
नज़रसानी—Review	नाख़िश करना—To sue
नदी-घाटी—River-valley	नासरदुख्त—Invalid
नरबिधा—Anthropology	नासरदुख्त ठहराना—To invalidate
नरेश—Prince	
नशीला तरल—Intoxicating liquor	निकासनी महसूल—Excise duty
नशीला पान—Intoxicating drink	निकासी—Export
नसल—Descent, race, breed	निकासी महसूल—Export duty
नागर—Citizen	निगरानी—Superintendence
नागरता—Citizenship	निजनियम—Privilege
नागरी जगह—Civil post	निजी—Personal
नागरी नौकरी—Civil service	निजी क़ानून—Personal law
नागरी शक्ति—Civil power	निजी थैली—Privy purse
नागरी हैसियत से—In civil capacity	निजी हैसियत से—In personal capacity
नाठीक दियाय—Unsound mind	निबल पेनशन—Invalidity pension
नादार हो जाना—Bankruptcy	नियम—Rule
ना-निवास—Non-residence	नियोजन—Appointment
नाबालिग—Minor	नियोजना—To appoint
नामज़द करना—To nominate	निर्देश करना, निर्देश देना—To direct
नामज़दगी—Nomination	निर्देशक सिद्धान्त—Directive principle
नामी क़ानूनशास्त्री—Distinguished jurist	निर्देशन—Direction
नायब रियासतपति—Lieutenant Governor	निवास—Domicile
	निवेदनी—Address
	निस्यत—Proportion

भारत का विधान

निसबती प्रतिनिधान—Proportio-	पट्टीदर्ज क्षेत्र—Scheduled area
nal representation	पट्टीदर्ज जाति—Scheduled
नीति—Policy	caste
नुकसान भरपाई—Compensation	पड़ताल की रिपोर्ट—Audit report
नैतिक आधारही—Moral abandon-	पड़तालना—To audit
ment	पड़ोसी रियासत—Neighbouring
नोटिस—Notice	State
नौकरी—Service	पत्तीपूँजी—Stock
नौकरी की शर्तें—Conditions	पद—Office
of service	पद का हलफ़—Oath of office
न्याय—Justice	पदगाहन—Succession
न्यायकार—Judiciary	पदगाही—Successor
न्याय शासन—Administration	पदनाते—Ex-officio
of justice	पद-मियाद—Term of office
न्यायी—Just, judicial	पद सूना करना—To vacate
न्यायी अधिकारी—Judicial	office
authority	पद संभालना—To enter upon
न्यायी काम—Judicial fun-	office
ction	पनशक्ति—Water power
न्यायी जगह—Judicial post	परमिट—Permit
न्यायी नौकरी—Judicial service	परवाना—Writ
न्यायी पद—Judicial office	परवाना अधिकारवताई—Quo
न्यूज़ प्रिंट—Newsprint	Warranto
प	परवाना तनतल्बी—Habeas
पक्की वापसी—Permanent	Corpus
return	परवाना मनाही—Prohibition
पटसन—Jute	परवाना मिसलमंगई—Certiorari
पट्टा—Instrument, lease	परवाना हुकुम—Mandamus
पट्टी—Schedule	परसौपनो—Extradition
पट्टीदर्ज कबीला—Scheduled	परिनामी—Consequential
tribe	

परिनामी बन्धान—Consequential provision	पूरक खच—Supplementary expenditure
परिभाषा—Definition	पूरक देनगी—Supplementary grant
परीक्षा—Examination	
पशु-इलाज की ट्रेनिंग—Veterinary training	पूरक बन्धान—Supplemental provision
पशुपालन—Animal husbandry	पूरक शक्ति—Supplemental power
पहली सुनवाई का अधिकार—Original jurisdiction	पूरब पंजाब रियासत यूनियन—East Punjab States Union
पात्र—Eligible	पेटेंट—Patent
पात्रता—Eligibility	पेट्रोलियम—Petroleum
पानी का निकास—Drainage	पेनशन—Pension
पानी पहुँचाना—Water supply	पेशगी—Advance
पासपोर्ट—Passport	पेशनगदी—Imprest
पासंगी मद्दत—Countervailing duty	पेश बाज़ार—Futures market
पिछड़ी हुई जमात—Backward class	पेशा—Profession
पिछलगत असर—Retrospective effect	पेशाई—Professional
	पैदावार—Product, production
पीनकवालो—Narcotic	पैमाना—Scale
पीनकवाली चीज़ें—Narcotics	पैरा—Paragraph
पुरातत्वी—Archaeological	पंच—Arbitrator
पुलिस—Police	पंचनामा—Arbitration
पुलिस बल—Police force	पंच क्रैसला—Arbitration, award
पूँजी—Capital	पंचायती अदालत—Arbitral tribunal
पूछताछ—Inquiry	
पूरक—Supplemental, supplementary	प्रतिनिधान—Representation
	प्रतिनिधि—Representative

प्रधान बजीर, भारत का—Prime Minister of India	फ
प्रमान लिखत—Authoritative text	फर .—Duty
प्रमुख चुनाव कमिशनर—Chief Election Commissioner	फरज निभारना—To discharge duty
प्रमुख जज—Chief Judge	फरीक—Party
प्रमुख प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट—Chief Presidency Magistrate	फिरका—Denomination
प्रसंग—Context	फिरकेवाराना—Denominational
प्रसंगी—Incidental	फिरबसाव—Rehabilitation
प्रसंगी बन्धान—Incidental provision	फिराती रकम—Recurring sum
प्रसंगी मामला—Incidental matter	फीस—Fee
प्रसंग से आया हुआ—Incidental	फुटकर—Miscellaneous
प्राइमरी तालीम—Primary education	फेल होना—To fail
प्राइमरी स्कूल—Primary school	फैक्टरी—Factory
प्राचीन—Ancient	फैलाव—Extent
प्रामिसरी नोट—Promissory note	फैसला—Decision, judgment
प्राविडेंट फंड—Provident fund	फैसला देना—To deliver judgment
प्रार्थना पत्र—Petition	फैसला सुनाना—To pronounce judgment
प्रिवी कौंसिल—Privy Council	फौजदारी—Criminal
प्रिवी कौंसिल अमलदारी अन्त एक्ट, 1949—Abolition of Privy Council Jurisdiction Act, 1949.	फौजदारी अमलदारी—Criminal jurisdiction
प्लीडर—Pleader	फौजदारी कानून—Criminal law
	फौजदारी कारवाई—Criminal proceedings
	फौजदारी दस्तूर—Criminal procedure
	फौजदारी नाक़िश—Criminal suit
	फौजदारी मामला—Criminal matter

फौजी—Military	बन्द परची—Secret ballot
फौजी अदालत—Court martial	बन्दरगाह—Port
फौजी कानून—Martial law	बन्धान—Provision
फौजी महत्व—Military importance	बन्धान करना—To make provision, to provide
फौलाद—Steel	बरखास्त करना—To prorogue
ब	बराबरी—Equality
बचाव—Defence	बरी—Immune, exempt
बचाव करना—To defend	बरीयत—Immunity
बचावबनो—Safeguard	बरी होना—Exemption
बचाव नौकरी—Defence service	बस्ती बसाना—Colonization
बचाव फौज—Defence force	बाध—Embankment
बचावा—Saving	बायलर—Boiler
बची शक्ति—Residuary power	बालिय वोट—Adult suffrage
बटवारा—Distribution,	बासी—Resident
partition	बाहरी हमला—External
बढ़ती नफ़ा टैक्स—Excess Profits Tax	aggression
बढ़ावा देना—To encourage	बिचवक्ती—Transitional
बढ़ोतरी—Advancement	बिचवक्ती बन्धान—
बड़ा बन्दरगाह—Major port	Transitional provision
बड़ा वज़ीर, किसी रियासत का—	बिजली—Electricity
Chief Minister of a State	बिदेसनी महसूल—Customs,
बड़ीयत—Majority	Customs duty
बदव्योहार—Misbehaviour	बिदेसनी महसूल की सीमा—
बदलती जुलाई—Shifting	Customs frontier
cultivation	बिना—Ground (as of
बदलाव हुंड़ी—Bill of exchange	appeal)
बनस्पति विद्या—Botany	बिनाखिंची—Non-distilled
बनिजदूती—Consular	बिल—Bill

भारत का विधान

बिल का रखा जाना—	भत्ता—Allowance
Introduction of a Bill	भयानक आगपकड़—
बिल की पृष्ठ करना—	Dangerously inflammable
To originate a Bill	भरती—Recruitment
बीमा—Insurance	भरपाई—Relief
बीमा पालिसी—Insurantee	भरपाई भत्ता—Compensatory
policy	allowance
बेकामगारी, बेकारी—Unempl-	भलमंसी—Decency
oyment	भलाई—Well-being,
बेकामदगी—Irregularity	welfare
बेघरबारगी—Material	भाईचारा—Fraternity
abandonment	भाग—Part
बेतार—Wireless	भाग देना—To divide
बेमेल—Inconsistent	भागफल—Quotient
बेवसोयती—Intestacy	भाड़ा, माछ का—Freight
बैठक—Sitting	भारत—India
बैठ बिठाव—Adjustment	भारत का गज़ट—Gazette
बोरस्टली संस्था—Borstal	of India
institution	भारत का मूठकोश—
बोर्ड—Board	Consolidated Fund of
बंकदारी—Banking	India
व्यापार—Traffic	भारत का रिज़र्व बैंक—Reserve
व्योपार—Trade	Bank of India
व्योपार छाप—Trade-mark	भारत का विधान—Constitution
व्योपारी—Trader	of India
व्योपारी एकतनी—Trading cor-	भारत की सर्वे—Survey of
poration	India
व्योरा—Description, state-	भारत पक़्ताल और हिसाब महक़्मा—
ment, return	Indian Audit and
म	Accounts Department
भक्ति—Allegiance	भारवाही डोर—Draught cattle

भाषा—Language	मह-वटवारा—Appropriation
भीतरी गड़बड़ी—Internal disturbance	मह-वटवारा बिल—Appropriation Bill
भुगतान खर्च—Redemption charges	मनाही—Prohibition
भूभाग—Territory	मनोरंजन—Entertainment
भूभागपरे—Extra-territorial	मसनदी—Chairman
भूभागपरे अमल—Extra-territorial operation	महसूल—Duty
भूभागपरे असर—Extra-territorial effect	महामारी—Pest
भूभागी—Territorial	मार्ग—Demand
भूभागी चुनाव इलक्का—Territorial constituency	मातहत—Subordinate
भूभागी समंदर—Territorial waters	मातहत अदालत—Subordinate court
भूमिदारी—Land tenure	माही साधन—Material resources
भूविद्या—Geology	मान—Standard
भेदभाव—Discrimination	मानहानि—Defamation
भंग करना—To dissolve	माप—Measure
भंग होना, सदन का—Dissolution of the House	माफ़ी देना, माफ़ कर देना—To grant pardon
म	माल—Finance, goods
मकानी गुंजाइश—House accommodation	माल कमीशन—Finance Commission
मछियारी—Fishery	माल की मिलकियत—Property in goods
मजदूरी कगड़ा—Labour dispute	मालगुजारी—Revenue
मतकब—Purpose	मालगुजारी खाते खर्च—Expenditure on revenue account
मद्—Item	मालामाल करना—Enrichment
	मालियत—Value
	माफ़ी—Financial

भारत का विधान

माली	अचानकी—Financial emergency	मिलनी—Meeting	मिल मजदूर—Industrial worker
माली	अमलदारी—Revenue jurisdiction	मिलजुला	कमीशन—Joint Commission
माली	एकतनी—Financial corporation	मिलजुला परिवार—Joint family	मिलजुला रियासत सरकारी नौकरी
माली	काम—Financial business	कमीशन—Joint State Public Service Commission	
माली	जिम्मेदारी—Financial obligation	मिलावट—Adulteration	
माली	टिकाव—Financial stability	मिलीजुली कलचर—Composite culture	
माली	बन्धान—Financial provision	मिलोजुली बैठक—Joint sitting	
माली	बिल—Financial Bill	मिलोजुली भरती—Joint recruitment	
माली	ब्योरा—Financial statement	मिलीजुली मिलनी—Joint meeting	
माली	मदद—Financial assistance	मुअत्तल करना—To suspend	
माली	मामला—Financial matter	मुआहिदा—Covenant	
		मुकदमा—Cause, case	
		मुकदमा उठा लेना—To withdraw a case	
माली	साल—Financial year	मुकदमा निपटाना—To dispose of a case	
मार्ग	Way		
मार्ग नियम	Rule of the road	मुकामी—Local	
मार्ग संकेत	Beacon	मुकामी अधिकारी—Local authority	
मियाद	Term		
मियादबन्दी	Limitation	मुकामी क्षेत्र—Local area	
मिळकियत	Estate, ownership	मुकामी टैक्स—Cess, local tax	
मिळकियत मरसूल	Estate duty	मुकामी बोर्ड—Local Board	
मिलन पट्टा	Instrument of Accession	मुकामी मतलब—Local purpose	
		मुकामी सीमा—Local limit	

मुकामी स्वराज—Local self-government	मंगैनी ले लेना—To requisition
मुकामी हुकूमत—Local government	मंडल—Council
	मंडो—Market
मुखतार—Attorney	मंत्रायत—Secretariat
मुखिया—Headman	मंत्रायती अमला—Secretarial staff
मुनाफ़ा—Profit	मंसूख करना—To revoke, to annul
मुनासिब क़ानूनसभा—Appropriate Legislature	य
मुनासिब कारवाई—Appropriate proceedings	यादगार—Monument
मुनासिब सुरतों में—In appropriate cases	यादपत्र, यादी—Memorandum
मुफ़्त और ज़बरी तालीम—Free and compulsory education	युक्त खासी जैन्तिया पहाड़ी ज़िला—The United Khasi and Jaintia Hills District
मुखतवी करना—To adjourn	यूनियन—Union
मुहय्या करना—To supply	यूनियन तालिका—Union List
मूठकोश—Consolidated Fund	यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन—Union Public Service Commission
मूल अधिकार—Fundamental right	योजना—Scheme, planning
मेम्बर—Member	र
मेम्बरी—Membership	रक़म जुटाना—To raise money
मेख बिठाना—To bring into accord	रक्षा—Protection
मेला—Fair	रखवाली—Custody
मेहनताना—Remuneration	रखाया हुआ जंगल—Reserved forest
मैजिस्ट्रेट—Magistrate	रचना—Composition
मोहर—Seal	रचाना पचाना—To assimilate
मोहक़्त देना—To grant respite	रज़ामंदी—Approval
मौसमी क़बीला—Migratory tribe	

भारत का विधान

रजिस्ट्री—Registration	रियासत का मूठकोश—Consolidated Fund of the State
रद्द—Void, repeal	रियासत तालिका—State List
रद्द करना—To repeal	रियासतपति—Governor
रसद—Supply	रियासत सदन—Council of States
रसीद—Receipt	रियासत सरकारी नौकरी कमिशन—State Public Service Commission
रस्ता मार्ग—Ropeway	रियासतों का गुट—Group of States
राज—The State (as defined in Part III)	रिहाइश—Residence
राजकाजी—Political	रिहाइश की जगह—Place of residence
राजदारी—Secrecy	रिहाइशी—Residential
राजदारी का हक़—Oath of secrecy	रीतरिवाज—Custom
राजदूती—Diplomatic	रुकावट—Restriction
राजपति—President	रुतबा घटाया जाना—Reduction in rank
राजपंचायत—Parliament	रुपया निकालना—Withdrawal of money
राजप्रमुख—Rajpramukh	रूप—Form
राजहुकुम—Ordinance	रूप देना—To formulate
राज्रीनामा—Agreement	रूपविगाह—Disfigurement
राय—Opinion	रेलमार्ग—Railway
रायल्टी—Royalty	रेलमार्ग कंपनी—Railway company
राहरीत पेशगी—Ways and means advance	रेलमार्ग क्षेत्र—Railway area
रिपोर्ट—Report	रेहन रखना—Mortgage
रियासत—Concession	रोक—Bar
रियासत—State	
रियासत का जोशजोग कोश—Contingency Fund of the State	
रियासत का मिलना—Accession of a State	

रोकथाम—Prevention	लोक सदन—House of the
रोकथामी नज़रबन्दी—Preventive detention	People
रोज़गार—Calling, avocation	व
रोज़गारी—Vocational	वचन भरना—To affirm, affirmation
रोज़गारी ट्रेनिंग—Vocational training	वज़ीर—Minister
रोज़ी—Livelihood	वज़ीर मंडल—Council of Ministers
ल	वज़ीरायती अधिकारी—Ministerial authority
लगातार—Consecutive, in succession	वफ़ादार रहना—To bear faith
लगान—Rent	वफ़ादारी से—Faithfully
लगाव—Adherence	वसीयत—Will
लज़र—Frivolous	वाक्याती सवाल—Question of fact
लदाई बिल्टी—Bill of lading	वारिस—Successor
लाइन—Line	विकास—Development
लाइसेंस—License	विचार करना—To consider
लागू—Applicable	विचार के लिये रख देना—To reserve for consideration
लागू होना—To apply	विदेशी अमलदारी—Foreign jurisdiction
लाटरी—Lottery	विदेशी उधारी—Foreign loan
लाभ—Profit	विदेशी मामला—Foreign affair
लाभबंटावा—Dividend	विदेशी राज—Foreign State
लाभ तोषना—Demobilisation	विदेशी सिक्का बदलाव—Foreign exchange
लावारसी, वारिस न रहना—Bona vacantia	विद्यापीठ—University
लेखे—Records	विधान—Constitution
लेनदारी—Asset	
लोक महत्व—Public importance	
लोकशाही—Democracy, democratic	

भारत का विधान

विधान तोड़ना—Violation of	शपथ लेना—To swear
the Constitution	शब्दावली—Vocabulary
विधान सभा—Constituent	शर्त बटना—Betting
Assembly	शर्तें कि—Provided that
विधानी मशीन—Constitutional	शांति—Peace
machinery	शामलाती—Common
विरासत—Succession, inhe-	शामलाती कुल-भारत नौकरियाँ—
ritence	Common All-India
विशेष कर—In particular	services
विशेष योगता—Special quali-	शासक—Ruler
fication	शासन—Administration
विस्फोटक—Explosive	शासन की कुशलता—Efficiency
वीसा—Visa	of administration
वेतन—Emolument	शासन तल—Level of admi-
वेतनी काम—Paid employ-	nistration
ment	शासन सम्बन्धी—Relating to
वोट—Vote	administration
वोटर—Voter	शासनी—Administrative
वंश—Descent	शासनी खर्च—Administrative
व्यवस्था—Order	expenses
व्यवस्था क्रायम करना—Resto-	शासनी क्षेत्र—Administrative
ration of order	area
व्यवस्था बनाए रखना—Mainte-	शासनी शक्ति—Administrative
nance of order	power
श	शासनी सम्बन्ध—Administra-
शक्ति—Power	tive relation
शक्ति से काम लेना—Exercise	शिकायत—Complaint
of power	शेयर बाज़ार—Stock exchange
शक्ति सौंपना—To confer	शेरिफ़—Sheriff
power	शैली—Style

शीशन—Exploitation	समन्दरी जहाज़रानी—Maritime
स	navigation
सकत—Ability	समन्दरी डकैती—Piracy
सज़ा—Punishment	समन्दरी फ़ौज—Naval force
सड़क—Road	समन्दरी विभाग—Admiralty
सत्ता—Authority	समय समय पर—From time to time
सदन—House	समयोचित—Expedient
सदन का बरखास्त होना—Prorogation of the House	समर्थन करना—To support
सदन का भंग होना—Dissolution of the House	समाज की भलाई—Social welfare
सदन को मुलतवी करना—To adjourn the House	समाज सेवा—Social service
सदर—President	समाज सुधार—Social reform
सदाचार—Morality	समाजी—Social
सदारत करना—To preside	समाजी अन्याय—Social injustice
सनद—Sanad, certificate	समाजी बीमा—Social insurance
सनद करना या देना—To certify	समाजी व्यवस्था—Social order
सन्धिनामा—Treaty	समेटना—To wind up
सन्धि बन्धन—Treaty obligation	सम्मान—Dignity
सब डिवीज़नल अफ़सर—Sub-Divisional Officer	सम्राट—Crown, His Majesty
सबसे पहली अदालत—Court of first instance	सरकार—Government
समा—Association	सरकारी करज़ा—Public debt
समासुल—Speaker	सरकारी ज़न्ती—Escheat
समझाव—Explanation	सरकारी ट्रस्टी—Official trustee
समझौता—Agreement	सरकारी नौकरी कमीशन—Public Service Commission
समन्दरी—Marine, maritime	सरकारी मकान—Official residence
समन्दरी जहाज़रानी—Maritime shipping	सरकारी हुंजी—Treasury Bill

भारत का विधान

सरजज—Chief Justice	सहायक बन्धान—Ancillary
सरदुस्त—Valid	provision
सरदुस्त ठहराना—To validate	सहायक सेशन जज—Assistant
सरदुस्ती—Validity	Sessions Judge
सरनामा—Title	सहायता—Aid
सरपञ्चालिया—Auditor-General	सहायती देनगी—Grant-in-aid
सरप्रबन्धक—Administrator-General	सहीकरण—Authentication
सरप्रबन्धक—Administrator-General	सही करना—To authenticate
सरबचन देना—To address	सही किया हुआ—Authenticated
सरमुख—Head	साइंस—Science
सरमुखतार—Attorney-General	साइंसी—Scientific
सरलेख—Preamble	साइंसी ताळीम—Scientific education
सरवकील—Advocate General	साइंसी रीत—Scientific line
सरवे—Survey	साख—Credit
सरहद्दी खित्ता—Frontier tract	साख पत्र—Letter of credit
सलामती—Safety	साझेदारी—Partnership
सलाहकार मंडल—Advisory Council, Council of Advisors	साधन—means, resources
सलाह देना—To advise	सायल—Suitor
सहकारी आधार—Co-operative basis	सारचारा—Concentrates
सहकारी आन्दोलन—Co-operative movement	सालाना माली ब्योरा—Annual financial statement
सहकारी समिति—Co-operative society	साहूकार—Money lender
सहमती—Concurrence	सिंजार—Toilet
सहायक—Ancillary, assistant	सिंचाई—Irrigation
सहायक जिला जज—Assistant District Judge	सिका गढ़न—Coinage
	सिका चलन—Currency
	सिद्धान्त—Principle
	सिनेमा—Cinema, cinematograph
	सिफारिश—Recommendation

सीट—Seat	सूबापरे—Extra-Provincial
सीट को सूनी ठहराना—To declare a seat vacant	सूबापरे अमलदारी एक्ट, 1947— Extra-Provincial Jurisdic-
सीटें अलग रखना—To reserve seats	tion Act, 1947
सीटों का बंटवारा—Allocation of seats	सूबे का गवर्नर—Governor of a Province
सीधा चुनाव—Direct election	सूबों का गुट—Group of Provinces
सीधे या नासीधे—Directly or indirectly	सेवामुक्त—Retired
सीमा—Limit	सेशन जज—Sessions Judge
सीमिताना—To limit	सोसाइटी—Society
सुझाव—Proposal	सौदागरी-माछ छाप—Merchandi- se mark
सुधार—Amendment	संगचारी तालिका—Concurrent List
सुधार करना—To amend, to make amendment	संगठन—Organisation
सुधारघर—Reformatory	संगठित क्रौमै—Organised peoples
सुधार पेश करना—To move an amendment	संगत—Relevant
सुधार सुझाना—To suggest an amendment	संगी जिला जज—Joint District Judge
सुनवाई—Hearing	संघ अदालत—Federal Court
सुनवाई का अधिकार—Right of audience	संचालन—Conduct
सुरक्षा—Security	संदेश—Message
सूचना—Information	संयुक्त क्रौमी संगठन—United Nations Organisation
सूझ, सूझ-ब्याज—Interest	संरक्षक—Guardian
सुनी—Vacancy	संस्था—Body, institution
सुनी करना—To vacate	स्कूल—School
सुनी भरना—To fill a vacancy	स्टाम्प महसूल—Stamp duty
सूबा—Province	स्टेट सेक्रेटरी—Secretary of State
	स्तर—Standard

भारत का विधान

स्नातक — Graduate	हाज़िरी तलब करना—To require attendance
स्वतंत्रता—Liberty	
स्वराज—Self-government	हित—Interest
स्वाधीन—Autonomous	हिदायत—Instruction
स्वाधीन इलाका—Autonomous region	हिन्द आज़ादी एक्ट, 1947— Indian Independence Act, 1947
स्वाधीन ज़िला—Autonomous district	हिन्द डोमिनियन—Dominion of India
ह	
हकदार—Entitled, Competent	हिन्द पुलिस नौकरी—Indian Police Service
हथियार—Arms	हिन्द शासनी नौकरी—Indian Administrative Service
हथियारबन्द फ़ौज—Armed force	हिन्द सम्राट—Crown in India
हदबन्दी—Delimitation	हिन्द सरकार एक्ट, 1935— Government of India Act, 1935
हद लांघना—Trespass	
हदवारी टैक्स—Terminal tax	
हदियाना—To limit	
हलफ़—Oath	हिन्दसे—Numerals
हवाई अड्डा—Aerodrome	हिन्दी निकास—Indian origin
हवाई जहाज़—Aeroplane	हिन्दुस्तानी हिन्दसे—Indian numerals
हवाई फ़ौज—Air force	हिरासत—Custody
हवा जहाज़—Aircraft	हिसाब—Account
हवा जहाज़रानी—Air navigation	हिसाब किताब —Accounts
हवा व्यापार—Air traffic	हिस्सा—Share
हवा मार्ग—Airways	हिस्सा लेना—To participate
हवा विद्या की तालीम—Aeronautical education	हिस्सेदारी—Contributory
हाईकोर्ट—High Court	हुकूम—Order
हाज़िरी—Attendance	हुकूमनामा—Process, warrant

शब्दमाला

अंगरेजी से हिन्दी

मूल अंगरेजी विधान के कुछ शब्द और उनके सामने

जवाबी हिन्दी शब्द जो इस अनुवाद में बरते गए हैं

A	Additional District Judge
Abolish—अन्त करना, तोष देना	—अधिक ज़िला जज
Abolition of Privy Council Jurisdiction Act, 1949—	Additional Sessions Judge
प्रिवी कौंसिल अमलदारी अन्त एक्ट, 1949	—अधिक सेशन जज
Abrogate—रद्द करना	Address— सरबचन, सरबचन देना,
Absence—नामौजूदगी	निवेदनी
Absent—नामौजूद	Adherence— लगाव
Absent on leave—छुट्टी पर	Ad hoc— ज़रूरती
Accession of a State—	Ad hoc Judge— ज़रूरती जज
रियासत का मिलना	Adjourn— मुलतवी करना
Account—हिसाब	Adjourn the House— सदन
Accounts—हिसाब किताब	को मुलतवी करना
Accused—मुलज़िम	Adjudication— अदालती फ़ सला
Act—एक्ट, काम	Adjustment— बैठबिठाव
Acting—कारकर	Administer— प्रबन्ध करना,
Acting Chief Justice—	शासन करना
कारकर सरजज	Administration— शासन
Actual service—असल नौकरी	Administration of justice—
Adaptation—अनुकूलन	न्याय शासन
Additional—अधिक	Administrative— शासनी
Additional Chief Presidency Magistrate—अधिक	Administrative area—
प्रमुख प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट	शासनी क्षेत्र
	Administrative expenses—
	शासनी खर्च

भारत का विधान

Administrative power— शासनी शक्ति	Agricultural income—खेती- बाड़ी की आमदनी
Administrator General— सरप्रबंधक	Agricultural land—खेती- बाड़ी की ज़मीन
Admiralty—समन्दरी विभाग	Agricultural worker— खेतिहर
Admission—दाखिला	Agriculture—खेतीबाड़ी
Adoption—अपनाना, गोद लेना	Aid—सहायता, सहायता देना
Adult—बालिय	Aircraft—हवा जहाज़
Adulteration—मिलावट	Air force—हवाई फ़ौज
Adult suffrage—बालिय वोट	Air navigation—हवा जहाज़रानी
Advance—पेशगी	Air traffic—हवा व्यापार
Advertisement—जाहिरात	Airways—हवा मार्ग
Advise—सलाह देना	Alcohol—अलकोहल
Advisory Board—सलाहकार बोर्ड	Alcoholic liquor—अलको- होली तरल
Advisory Council—सलाह- कार मंडल	Alien—विदेशी
Advocate—वकील	Allegiance—भक्ति
Advocate General— सरवकील	All-India service—कुल-भारत नौकरी
Aerodrome—हवाई अड्डा	Allocation of seats—सीटों का बंटवारा
Aeronautical education— हवा विद्या की तालीम	Allotment—बांटना, किसी के नाम कर देना
Affirm, affirmation—वचन भरना	Allotment of land—ज़मीन का बाँटा जाना
Aforesaid—ऊपर कहा	Allowance—भत्ता
Agency—एजेंसी	Amend—सुधार करना
Agent—एजेंट	Amendment—सुधार
Aggression—हमला	
Agreement—समझौता, राज़ीनामा	

Ammunition—गोला बारूद	Appropriate	Legisla-
Amount—रकम	ture—मुनासिब	क्रानूनसभा
Amusement—तमाशा	Appropriate	proceedi-
Ancient—प्राचीन	ngs—मुनासिब	कारवाई
Ancillary—सहायक	Appropriation—मद्-बटवारा	
Ancillary matter—सहायक मामला	Appropriation Bill—मद्- बटवारा बिल	
Ancillary power—सहायक शक्ति	Approval—रज़ामन्दी	
Ancillary provision— सहायक बन्धान	Arbitral tribunal—पंचायती अदालत	
Anglo Indian—एंग्लो इंडियन	Arbitration—पंच क्र सला, पंचनामा	
Animal husbandry—पशु- पालन	Arbitrator—पंच	
Annual admission—साळाना दाखला	Archaeological—पुरातत्वी	
Annual financial state- ment—सालाना माली न्योरा	Area—क्षेत्र	
Annuity—सालाना किस्त	Armed	force—हथियार बन्द फौज
Annul—मंसूख करना	Arms—हथियार	
Answerable—जवाबदेह	Arrears—बकाया	
Anthropology—नरविद्या	Arrest—गिरफ्तारी	
Appeal—अपील	Art—कला	
Appellate jurisdiction— अपीली अमलदारी	Article—वक्रा	
Applicable—लागू	Assam Forest Regulation, 1891—आसाम जंगल क़ायदाबन्दी, 1891	
Application—दरखास्त, अरज़ी	Assent—मंजूरी	
Appoint—नियोजन	Assess—आंकना	
Appointment—नियोजन	Assess land for revenue purposes—मालगुज़ारी के मत- लबों के लिए ज़मीन आंकना	
Appropriate—मुनासिब, खर्च की मद् में डालना		

भारत का विधान

A sessment of revenue—	Authorised—अधिकार हुआ
मालगुजारी तय करना	Authorised amount—
Asset—लेनदारी	अधिकारी हुई रकम
Assign—नाम कर देना	Authorised expenditure—
Assimilate—रचाना पचाना	अधिकार हुआ खच
Assistant—सहायक	Authoritative text—प्रमान
Assistant District Judge—	लिखत
सहायक ज़िला जज	Authority—अधिकारी, अधिकारी
Assistant Sessions Judge—	संस्था, सत्ता
सहायक सेशन जज	Autonomous—स्वाधीन
Association—सभा	Autonomous district —
Assurance—मरोसा	स्वाधीन ज़िला
As the case may be—जैसी	Autonomous region—स्वाधीन
सूत हो	इलाक़ा
Atomic energy—एटम शक्ति	Average—औसत
Attachment—कुरक्री	Avocation—रोज़गार
Attendance—हाज़िरी	Award—पंच क्रैसला
Attorney—मुखतार	B
Attorney-General—सरमुखतार	Backward class—पिछड़ी हुई
Audit—पड़तालना	जमात
Auditor-General—सरपड़ता-	Bail—ज़मानत
लिखा	Banking—बैंकदारी
Audit report—पड़ताल की	Bankruptcy—नादार हो जाना
रिपोर्ट	Basis—आधार
Authenticate—सही करना	Beacon—मार्ग संकेत
Authenticated—सही किया	Bear allegiance—भक्त रहना
हुआ	Bear faith—बफ़ादार रहना
Authentication—सहीकरण	Belief—विश्वास
Authorise—अधिकार देना,	Betting—शर्त बधना
अधिकारना	Biennial election—दुबरासी
	चुनाव

Bill—बिल	Canon—उसूल
Bill of exchange—बदलाव हुंड़ी	Cantonment—छावनी
Bill of lading—लदाई बिल्टी	Capital—पूंजी
Board—बोर्ड	Capital value—कुल मालियत
Body—संस्था	Capitation tax—आदमोवार टक्स
Body corporate—एकतन संस्था	Case—मुकदमा
Boiler—बायलर	Caste—जात
Bona vacantia—वारिस न रहना, छावारिसी	Casting vote—जिताऊ वोट
Borrowing—उधार लेना	Casual vacancy—औसरी सूनी
Borstal institution—बोर- स्टली संस्था	Cattle pound—कांजी दौड़ा
Botany—बनस्पति विद्या	Cause—मुकदमा, कारन
Breed—नसल	Census—गिनावा
Bring into accord—मेल बिठाना	Central Bureau of Inte- lligence and Investiga- tion—जानकारी और जाँच का मरकज़ी महकमा
Broadcasting—धुनपसार	Certificate—सनद
Burial—दफन	Certify, certification— सनद करना, सनद देना
Burial ground—दफन भूमि	Certiorari—परवाना मिसल मंगाई
Business—कारबार, काम	Cess—मुकामी टैक्स
Bye-law—छुटकानून	Chairman—मसनदी
By virtue of—की रू से	Chapter—खंड
C	
Calculation—हिसाब लगाना	Charge—जुर्म, दोषलेखा
Calling—रोज़गार	Charge on—खाते में ढालमा
Call in question—सवाल उठाना	Charitable and religious endowments—खैराती और धार्मिक देन
Cancel—रद्द करना	
Candidate—उम्मीदवार	

भारत का विधान

Charitable institution— खैराती संस्था	Civil procedure—दीवानी दस्तूर
Charity—खैरात	Civil proceeding—दीवानी कारवाई
Cheque—चेक	Civil service—नागरी नौकरी
Chief—सरदार, प्रमुख	Civil suit—दीवानी नालिश
Chief Commissioner— चीफ कमिशनर	Claim—दावा, दावा करना
Chief Election Commis- sioner—प्रमुख चुनाव कमिशनर	Class—जमात
Chief Judge—प्रमुख जज	Clause—धारा
Chief Justice—सर्वजज	Clerk—क्लर्क
Chief Minister (of a State)—बड़ा बज़ीर (रियासत का)	Code—पद्धत
Chief Presidency Magis- trate—प्रमुख प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट	Code of Civil Procedure —ज़ान्ता दीवानी
Cinema, cinematograph— सिनेमा	Code of Criminal Proce- dure—ज़ान्ता फ़ौजदारी
Circumstance—हालत, सूत	Code of procedure—ज़ान्ता
Circumstances exist— सूरतें ऐसी हैं	Coinage—सिक्का गढ़न
Citizen—नागर	Collect—जमा करना
Citizenship—नागरता	Colonization—बस्ती बसाना
City civil court—नगर दीवानी अदालत	Column—कालम
Civil—नागरी, दीवानी	Combine—गुट
Civil code—दीवानी पद्धत	Command—कमान
Civil court—दीवानी अदालत	Commencement—आरम्भ
Civil jurisdiction—दीवानी अयकदारी	Commerce—विचारत
Civil power—नागरी शक्ति	Commercial undertaking— विचारती कारबार
	Commission—कमीशन
	Committee—कमेटी
	Commodity—विचारती माल
	Common all-India services शामकाली कुल-भारत नौकरियाँ

शब्दमाला

Common interest—मिला- जुला हित	Compute—गिनना
Communication—आवाजाई, आपसी ब्योहार	Concentrates—सारबारा
Community—समाज	Concentration of wealth— धन का कीलना
Commute a sentence— सजा का रूप बदल देना	Concession—रियायत
Company—कम्पनी	Concurrence—सहमतो
Compensation—नुकसान भरपाई	Concurrent List—संगचारी तालिका
Compensatory allowance— भरपाई भत्ता	Condition—हालत, शर्त
Competent—अधिकारी, इकद्वार	Conditions of service— नौकरी की शर्तें
Competent authority— इकद्वार अधिकारी	Conduct—चलन, संचालन
Competent court—अधिकारी अदालत	Conduct of business— काम का संचालन
Competent Legislature— अधिकारी कानूनसभा	Confer—सौंपना
Composite—मिलीजुली	Conference—कानफ्ररेन्स
Composite culture—मिली- जुली कलचर	Conscience—अन्तरात्मा
Composition—रचना	Consecutive—लगातार
Comptroller and Auditor General—बाम अफसर और सरपञ्चाखिया	Consent—अनुमति
Compulsory acquisition— जबरन हासिल करना	Consequential—परिनामी
Compulsory service— जबरी सेवा	Consequential provision— परिनामी बन्धान
	Conserve—बनाए रखना
	Consolidated Fund—मूठकोश
	Constituency—चुनाव इल्का
	Constituent Assembly— विधान सभा
	Constitution—विधान, बनावट
	Constitutional—विधानी
	Constitutional machinery —विधानी मशीन

भारत का विधान

Constitution of India— भारत का विधान	Cottage industry—बरेल उद्योग
Construct—बनाना	Council—मंडल
Consular—बनिजदूती	Council of Advisors— सलाहकार मंडल
Consumption—खपत	Council of Ministers— बज़ीर मंडल
Contagious disease—छूत की बीमारी	Council of States—रियासत सदन
Contempt—तौहीन	Countervailing duty— पासंगी महसूल
Context—प्रसंग	Court—अदालत
Contingency—जोगाजोग	Court immediately below— ठीक निचली अदालत
Contingency Fund—जोगा- जोग कोश	Court Martial—फौजी अदालत
Contract—ठीका	Court of appeal—अपीली अदालत
Contributory—हिस्सेदारी	Court of first instance— सबसे पहली अदालत
Control—दबान, कंट्रोल	Court of record—नज़ीरो अदालत
Convention—माना हुआ रिवाज	Court of wards—कोर्ट कचहरी
Convict—दोषी ठहराना	Covenant—सुआहिदा
Co-operative—सहकारी	Credit—साख
Co-operative movement— सहकारी आन्दोलन	Cremation—दाह
Co-operative society—सह- कारी समिति	Cremation ground—दाहभूमि
Co-ordination—तालमेल	Crime—ज़ुर्म
Copy—नक़ल	Criminal—फ़ौजदारी
Copyright—कापीराइट	Criminal court—फ़ौजदारी अदालत
Corporation—एकतनी	
Corporation tax—एकतनी टैक्स	
Corresponding—बराबरी	
Corrupt practice—धूसखोरी	

Criminal jurisdiction—	Defamation—मानहानि
क्रौञ्चदारी अमलदारी	Defence—बचाव
Criminal law—क्रौञ्चदारी कानून	Defence force—बचाव फौज
Criminal procedure—क्रौञ्च-	Defence service—बचाव
दारी दस्तूर	नौकरी
Criminal proceedings—	Defend—जवाबदेही करना, बचाव
क्रौञ्चदारी कारवाई	करना
Crown in India—हिन्दु सम्राट	Definition—परिभाषा
Cruelty—बेरहमी	Delimitation—हदबन्दी
Cultural—कलचरी	Deliver judgment—फ़सला
Culture—कलचर	देना
Currency—सिक्का चलन	Demand—मांग
Current—चालू	Demand for grant—देनगो
Current service—चालू सेवा	की मांग
Custody—हिरासत, रखवाली	Demobilisation—लाम तोड़ना
Custom—रीतिरिवाज	Democracy, democratic—
Customs, custom duty—	लोकशाही
बिदेसनी महसूल	Denomination—फिरका
	Denominational — फिरके-
	बारानी
Debenture—करज़पत्र	Deputy Commissioner—
Debt—करज़ा	डिप्टी कमिशनर
Debt charges—करज़ा खर्च	Deputy President—नायब
Decency—मक़मसि	सदर
Decision—फ़सला	Descent—वंश, नसब
Declare—एकान करना, ठहरा देना,	Design—डिज़ाइन
ज़ाहिर करना	Designate—नामज़द करना
Declare law—कानून ठहराना	Desirable—चाहोती, चाहनी
Decree—डिगरी	Destination of grant—देन
Deed—तमसुक	स्थान

भारत का विधान

Destruction—बर्बादी	Discussion—बहस
Detail—तफ़सील	Disfigurement—रूप बिगाड़
Detention—नज़रबन्दी	Dismiss—बरखास्त करना
Development—विकास	Dispensary—दवाख़ाना
Devote oneself to—तन मन से लगना	Dispose of—निबटाना
Difference—फ़रक़	Disqualification—अयोगता
Difficulty—कठिनाई	Disqualify—अजोग ठहराना
Dignity—मान, सम्मान	Dissenting judgment— अनमिल क़ैसका
Diplomatic—राजदूती	Dissenting opinion— अनमिल राय
Direct—निर्देश देना	Dissolution of a House— सदन का भंग होना
Direct election—सीधा चुनाव	Dissolve—भंग करना
Direction—निर्देश, निर्देशन	Distinction—उपाधि
Directive—निर्देश	Distinguished jurist— नामी क़ानूनशास्त्री
Directive principle—निर्देशक सिद्धान्त	Distribution—बटवारा, बांटना
Directly or indirectly— सीधे या नासीधे	District—ज़िला
Disability—अपाह्वी, असकत	District Board—ज़िला बोर्ड
Disability pension—अपाह्वी पेंशन	District Council—ज़िला मंडल
Disabled—अपाह्व	District Court—ज़िला अदालत
Disablement—अंग भंग होना	District Judge—ज़िला जज
Disapprove—नापसन्द करना	Disturbance—गड़बड़ी
Discharge ones duty— अपना फ़रज़ निभारना	Divide—भाग देना
Discharge ones function— अपना काम निभारना	Dividend—लाभ बटावा
Discipline—क़ायदादारी	Division Court—डिविज़न अदालत
Discovery—खोज़ निकालना	Divorce—तलाक़
Discrimination—भेदभाव	Document—दस्तावेज़, कागज़ पत्र

Domicile—निवास	Effective—असरदार
Domiciled—निवासी	Effectively—असरदार ढंग से
Dominion Legislature— डोमिनियन कानूनसभा	Efficiency of administra- tion—शासन की कुशलता
Dominion of India—हिन्द डोमिनियन	Election—चुनाव
Draught cattle—भारवाही ढोर	Election Commission— चुनाव कमीशन
Drug—बड़ी दूदी	Election Commissioner— चुनाव कमिशनर
Duly—कायदे से	Election petition—चुनाव
Duration—सुदत	Election tribunal—चुनाव अर्जी
During the pleasure of— के इच्छाकाल तक	Election tribunal—चुनाव अदालत
Duty—महसूल, फरज	
E	Electoral college—चुनाव मंडल
East Punjab States Union —पूरब पंजाब रियासत यूनियन	Electoral roll—चुनाव चिट्ठा
Economic—आर्थिक, धनदौलती	Electorate—चुनायत
Economic capacity— आर्थिक सकत	Electricity—बिजली
Economic interest— आर्थिक हित	Element—अंग
Economic organisation— आर्थिक संगठन	Eligibility—पात्रता
Economic system—अर्थव्यवस्था	Eligible—पात्र
Education—तालीम	Embankment—बांध
Educational grants— तालीमी देनगियाँ	Emergency—अचानकी
Educational institution— तालीमी संस्था	Emergency provision— अचानकी बन्धन
Effect—असर	Emigration—बाहर जा बसना
	Emolument—वेतन
	Employ—काम पर लगाना
	Employee—कामगार
	Employment—कामगारी
	Empower—शक्ति देना

Encourage—बढ़ावा देना	Excess grant—अधिक देनगी
Encumbered—करजादबी	Excess Profits Tax—बढ़ती नफ़ा टक्स
Endowment—देन	Excise duty—निकासनी महसूल
Enforcement of attendance—हाज़िरी लाज़िमी करना	Executive—काजकारी
Engagement—इकरारनामा	Executive function—काजकारी काम
Enrichment—मालामाल करना	Executive power—काजकारी शक्ति
Enter appeal—अपील दाखिल करना	Exemption—बरी होना
Entertain appeal—अपील लेना	Exercise jurisdiction—अमलदारी से काम लेना
Entertainment—मनोरंजन	Exercise power—शक्ति से काम लेना
Enter upon office—पद संभालना	Existing law—मौजूदा क़ानून
Entitled—हक़दार	Ex-officio—पदनाते
Entrust—सौंपना	Expedient—समयोचित
Entry—दाखला, अन्तरी, आमद	Expenditure, expense—ख़च
Enumerate—गिनाना	Expenditure on revenue account—मालगुज़ारी खाते ख़र्च
Equality—बराबरी	Expire—बीतना
Escheat—सरकारी ज़ल्ती	Explanation—समझाव
Establish—क़ायम करना	Exploitation—शोशन
Estate—मिलकियत	Explosive—बिस्फोटक
Estate duty—मिलकियत महसूल	Export—निकासी
Estimate—तख़मीन	Export duty—निकासी महसूल
Evacuee—बरछुट	Expulsion—निकास जाना
Evacuee property—बरछुट जायदाद	Extent—फैलाव, हद
Evidence—गवाही	Extract minerals—खनिजों को निकालना
Examination—परीक्षा	Extradition—परसौंपनी
Exception—अपवाद	
Excess expenditure—अधिक ख़च	

Extra-Provincial—सूबापरे	Financial assistance—
Extra-Provincial Jurisdiction Act, 1947—सूबापरे	माळी मदद
अमलदारी एक्ट, 1947	Financial Bill—माळी बिल
Extra-territorial—भूभागपरे	Financial corporation—
Extra-territorial effect—	माळी एकतनी
भूभागपरे असर	Financial emergency—
Extra-territorial operation—भूभागपरे अमल	माळी अचानकी
	Financial obligation—
	माळी ज़िम्मेदारी
	Financial propriety—
	उचित माळी ब्योहार
F	Financial provision—
Facility—सुविधा	माळी बन्धान
Factory—फ़ैक्टरी	Financial stability—माळी
Fail—फ़ेल होना	टिकाव
Faith—विश्वास, बफ़ादारी	Financial statement—
Faithful—बफ़ादार	माळी ब्यौरा
Faithfully—बफ़ादारी से	Financial year—माळी साल
Fare—फ़िराया (सवारी का)	Fire-arms—आग हथियार
Favour—तरफ़दारी	Fishery—मछियारी
Federal Court—संघ अदालत	Fishing—मछली पकड़ना
Fee—फ़ीस	Forced labour—जबरी मज़दूरी
Ferry—उतराई घाट	Force of law—क़ानून का असर
Figure—आंकड़ा	Foregoing—ऊपरलिखे
Fill a vacancy—सूनी भरना	Foreign affairs—विदेशी मामले
Film—फ़िल्म	Foreign exchange—विदेशी
Final order—आखिरी हुकुम	सिक्का बदलाव
Finance—माळ, ख़या लगाना	Foreign jurisdiction—
Finance Commission—	विदेशी अमलदारी
माळ कमिशन	Foreign loan—विदेशी उधार
Financial—माळी	Foreign State—विदेशी राज

Forest—जंगल	Generality—आधिपत्य
Forfeiture—ज़बती	Generally—आम तौर पर
Form—रूप	General public—आम जनता
Formulate—रूप देना	Genius—आत्मा
Fraction—द्रुक	Geology—भूविद्या
Fraternity—भाईचारा	Ginned cotton—ओटी कई
Free and compulsory edu- cation—मुफ्त और जबरो तालीम	Give effect to—अमल में लाना
Freedom—आज़ादी	Goods—मााल
Freedom of religion— धार्मिक आज़ादी	Governing body—प्रबन्ध कमेटी
Freight—माड़ा (माल का)	Government—सरकार, हुकूमत
Frivolous—लचर	Government of India Act, 1935—हिन्दू सरकार एक्ट, 1935
From time to time—समय समय पर	Government of India (Scheduled Castes) Order, 1936—हिन्दू सरकार (पट्टी-ईर्ज जातों) हुकूम, 1936
Frontier—सरहद, सीमा	Governor—रिषासतपति, गवरनर
Frontier tract—सरहदी खिस्ता	Governor General—गवरनर जनरल
Function—काम	Governor's Province— गवरनरी सुबा
Fundamental right— मूल अधिकार	Graduate—स्नातक
Future market—पेश-बाज़ार	Grant—देनगी
G	Grant in-aid—सहायती देनगी
Gas—गैस	Grant pardon—माफ़ी देना, माफ़ कर देना
Gas works—गैस का कारखाना	Grant reprieve—सज़ा मुक़्तगी कर देना
Gazette of India—भारत का गज़ट	Grant respite—मुदक़्त देना
General Clauses Act, 1897—आम धारा एक्ट, 1897	
General election—आम चुनाव	
General electoral roll— आम चुनाव बिट्टा	

Gratuity—इनामी रकम	His Majesty in Council—
Grave emergency—गहरी	कौंसिल समेत सम्राट
अज्ञानकी	Historical—इतिहासी
Grazing—ढोर चराना	Honourable relation—
Ground—भूमि, बिना	सम्मानि रिश्ता
Ground of appeal—अपील	Hospital—अस्पताल
की बिना	House (of a Legislature)—
Group—गिरोह, गुट	सदन
Group of Provinces—सूबों	House accommodation—
का गुट	मकानी गुंजाइश
Group of States—रियासतों	House of the People—
का गुट	लोक सदन
Guarantee—गारंटी	I
Guardian—संरक्षक	Illegal—चैरकानूनी
	Illwill—बैर
H	Immediately before—ठीक
Habeas Corpus—परवाना	पहले
तनतलबी	Immoveable—अचल
Habitually—आदतन	Immunity—बरीयत
Hazardous employment—	Impeach—दोश लगाना
जोखम का काम	Implement a treaty—
Head—सरमुक	सन्धिनामे पर अमल कराना
Headman—मुखिया	Import—आयासी
Health—तन्दुस्ती	Impose duty—फरज लगाना
Hearing—सुनवाई	Impose fine—जुरमाना करना
High Court—हाईकोर्ट	Impose restriction—रुकावट
Higher education—ऊँची तालीम	लगाना
Highsea—बीच समन्दर	Impose tax—टैक्स लगाना
Highway—थक मार्ग	Imprest—पेशनगदी
His Majesty—सम्राट	Imprisonment—कैद

भारत का विधान

Improvement trust—नगर सुधार ट्रस्ट	Indian Hemp—गाँवा
In addition to—अलावा	Indian Independence Act 1947—हिन्द आज़ादी एक्ट, 1947
In appropriate cases—मुनासिब सूरतों में	Indian numerals—हिन्दु-स्तानी हिन्दसे
Incapacity—नाक़ाबिलियत	Indian origin—हिन्दी निकास
Incidental—प्रसंगी	Indian Penal Code—
Incidental matter—प्रसंगी मामला	ताज़ीरात हिन्द
Incidental provision—प्रसंगी बंधान	Indian State—देशी रियासत
In civil capacity—नागरी हैसियत से	Industrial dispute—उद्योगी
Income—आमदनी	Industrial undertaking—उद्योगी कारबार
Income tax—आमदनी टैक्स	Industrial worker—मिल मज़दूर
Incompetency—अनधिकार	Ineligible—अपात्र
Inconsistency—अनमेल होना	Infant—दुषर्मुह बच्चा
Inconsistent—बेमेल	Infectious disease—उड़नी बीमारी
Incorporate—एकतन करना	Infirmity of mind—दिमाग की कमज़ोरी
Incorporated company—एकतनी कंपनी	Inflammable—आगपकड़
Incur obligation—ज़िम्मेदारी लेना	In force, in operation—अमल में
Indefinite character—अनिश्चित रूप	Inheritance—विरासत
Indemnify—बरीयत देना	In his discretion—अपनी समझ से
India—भारत, हिन्द	Initiate—शुरूआत करना
Indian Audit and Accounts Department—भारत पड़ताल और हिसाब महकमा	Injury—आघात
	Inland—देश-अन्दर

Inn—सराय	Inter-State Council—
In part—कुछ हद तक	अन्तर-रियासती मंडल
In particular circumstances—खास हालतों में	Intestacy—वेवसीयती
In personal capacity—	Intoxicating drink—नशीलापान
निजी हैसियत से	Intoxicating liquor—नशीला
In pursuance of—की तामील में	तरल
Inquiry—पूछताछ	Introduction of a Bill—
Insolvency—दिवाला	बिल का रखा जाना
Insolvent—दिवालिया	Invalid—नासरदुरुस्त
Institute proceedings—	Invalidate—नासरदुरुस्त ठहराना
कारवाई शुरू करना	Invalidity pension—निबल
Institution—संस्था	पेनशन
Instruction—हिदायत	Invention—ईजाद
Instrument—पट्टा	Investigate—जांच करना
Instrument of Accession	Investigation—जांच
—मिलन पट्टा	Irregularity—वेक़ायदगी
In succession—लगातार	Irrigation—सिंचाई
In such cases—ऐसी सूरतों में	Island—टापू
Insurance—बीमा	Issue—उठावा, जारी करना, निकालना
Insurance policy—बीमा	Issue a Proclamation—
पालिसी	ऐलान निकालना
Intercourse—अन्तरव्योहार	Issue a Treasury Bill—
Interest—सूद, सूद-ब्याज, हित,	सरकारी हुंड़ी जारी करना
दिकचस्पी	Item—मद
Interfere—इच्छा देना	J
International—अन्तरक्रौमी	Joint Commission—मिला-
Interpretation—अर्थ	जुला कमीशन
Inter se—आपस में	Joint District Judge—
Inter-State—अन्तर-रियासती	संगी ज़िला जज
	Joint family—मिलाजुला परिवार

भारत का विधान

Joint recruitment—मिली- जुली भरती	Lawful—कानूनसंगत
Joint sitting—मिलीजुली बैठक	Lease—पट्टा
Joint State Public Service Commission—मिलीजुला रिया- सत सरकारी नौकरी कमीशन	Leave, leave of absence— छुट्टी
Judge—जज	Legal—कानूनी
Judgment—फ़ैसला, विवेक	Legal profession—कानूनी पेशा
Judicial—न्यायी, अदालती	Legal right—कानूनी अधिकार
Judicial authority—न्यायी अधिकारी	Legal tender—कानूनी सिक्का
Judicial proceeding—अदा- लती कारवाई	Legislate—कानून बनाना
Judicial stamp—अदालती स्टाम्प	Legislative—कानूनकारी
Judiciary—न्यायकारी	Legislative Assembly— आम सदन
Jurisdiction—अमलदारी	Legislative Council—खास सदन
Jurist—कानूनशास्त्री	Legislative function— कानूनकारी काम
Just—न्यायी	Legislative power—कानून- कारी शक्ति
Justice—इन्साफ़, न्याय	Legislative relation—कानून- कारी संबंध
Jute—पटसन	Legislature—कानूनसभा
L	Leisure—फ़ुरसत
Labour dispute—मज़दूरी झगड़ा	Lend—उधार देना
Landlord—ज़मींदार	Letter of credit—साख्त पत्र
Land tenure—भूमिदारी	Level of administration— शासन तक
Language—भाषा	Level of nutrition—तन- पाकन तक
Lapse—गिर जाना, हक़ ख़तम हो जाना	Levy duty—महसूल लगाना
Law—कानून	Liability—देनदारी
	Liable—देनदार

Libel—अपमान लेख

Liberty—आज़ादी, स्वतंत्रता

Library—किताबघर

License—लाइसेंस

Lieutenant-Governor—

नायब रियासतपति

Lighthouse—दीपघर

Lightship—दीपबहाज़

Limit—इदियाना, सीमियाना, सीमा

Limitation—मियादबन्दी, सीमा

Line—लाइन

Liquid, liquor—तरल

List—तालिका

Literary—अदबी

Literature—अदब साहित्य

Livelihood—रोज़ी

Loan—उधारी

Local—मुकामी

Local authority—मुकामी
अधिकारी

Local Board—मुकामी बोर्ड

Local government—मुकामी
हकुमत

Local self-government—
मुकामी स्वराज

Loss—घाटा

Lottery—लाटरी

Lunacy—पागलपन

Luxury—ऐश

M

Magistrate—मैजिस्ट्रेट

Maintain—रखना, बनाए रखना

Maintain account—हिसाब

रखना

Maintain order—व्यवस्था

बनाए रखना

Maintain record—लेखा रखना

Major port—बड़ा बन्दरगाह

Majority—बड़ीयत

Make a loan—उधारी देना

Make order—हुकुम देना

Make payment—अदा करना

Make representation—

अरज़ी पत्र देना

Male progenitor—जनक पुरुष

Mandamus—परवाना हुकुम

Manner—ढंग

Manufacture—बनाना

Manufactured goods—

बना माल

Marine, maritime—समन्दरी

Maritime navigation—

समन्दरी जहाज़रानी

Maritime shipping—

समन्दरी जहाज़बानी

- Market—मंडी

Martial law—फौजी क़ानून

Material abandonment—

बेघरबारगी

भारत का विधान

Material resources—माही साधन	Merchandise mark— सौदागरी माल छाप
Maternity benefit—जापा रियायत	Merit—क़ाबलियत
Maternity relief—जापा मदद	Message—संदेश
Matter—मामला	Meteorology—खगोल विद्या
Matter of procedure— दस्तूरी मामला	Mica—अबरक
Meaning—मानी	Migratory tribe—मौसमी क़बीला
Means—साधन	Milch cattle—दुधारी ढोर
Means of communication आवाजाई के साधन	Military—क़ौजी
Measure—माप, तरकीब	Military force—ज़मीनी क़ौज
Mechanically propelled— मशीनों से चलने वाले	Military importance— क़ौजी महत्व
Medical profession— डाक्टरी पेशा	Mine—खदान
Medicinal preparations— दवाई का सामान	Mineral—खनिज
Meet a grant—देनगी को पूरा करना	Mineral development— खनिज विकास
Meet an expenditure— खर्च को पूरा करना	Mineral oil—खनिज तेल
Meeting—मिलनी	Mineral resources—खनिज साधन
Member—मेम्बर	Mining settlement autho- rity—खदान आबादी अधिकारी
Membership—मेम्बरी	Minister—बज़ीर
Memorandum—यादो, यादपत्र	Ministerial authority— बज़ीरायती अधिकारी
Memorial—आवेदनपत्र	Ministry—बज़ीरायत
Mental deficiency—दिमागी कमी	Minor—नाबालिय
Mercantile marine— तिजाराती बेड़ा	Minority—कमीयत
	Misbehaviour—बदब्योहार
	Miscellaneous—फ़ुटकर

Misconduct—बुरा चलन	National importance—
Modification—अदल बदल	क्रौमी महत्व
Modify—अदल बदल करना	National interest—क्रौमी हित
Money Bill—नकदी बिल	National life—क्रौमी जीवन
Money lender—साहूकार	National waterway—
Monopoly—इजारा	क्रौमी जल मार्ग
Monument—यादगार	Naturalisation—देसीकरण
Moral abandonment—	Naval force—समन्दरी फौज
नैतिक आवारगी	Navigation—जहाज़रानी
Morality—सदाचार	Neighbouring State—पड़ोसी
Mortgage—रेहन रखना	रियासत
Moveable—चल	Net proceeds—असल वसूली
Move an amendment—	Newsprint—न्यूज़प्रिन्ट
सुधार पेश करना	Nomadic—खानाबदोश
Move a resolution—उद्हराव	Nominate—नामज़द करना
पेश करना	Nomination—नामज़दगी
Multiple—गुना	Non-distilled—बिनाखिचो
Municipal area—नगरायत क्षेत्र	Non-Hindi speaking area
Municipal corporation—	—गैर हिन्दीभाषी क्षेत्र
नगर एकतनी	Non-tribals—गैर क्रमाङ्की लोग
Municipality—नगरायत	Notice—नोटिस
Municipal tramway—	Notice in writing—लिखा
नगर ट्राम मार्ग	नोटिस
Museum—अभयधर	Notwithstanding—के रहते
N	Number—गिनती, तादाद
Narcotic—पीनक वाली	Numerals—हिन्दु
Narcotics—पीनक वाली चीज़ें	0
Nation—क्रौमी	Oath—हज़क
National highway—क्रौमी	Oath of office—पद का हज़क
थल मार्ग	

भारत का विधान

Oath of secrecy—राजदारी
का हलफ़

Obligation—ज़िम्मेदारी

Occupation—कब्ज़ा, धन्धा

Occurrence of vacancy—
सूनी होना

Office—पद, ओहदा, दफ़्तर

Officer—अफ़सर

Official Gazette—दफ़्तरी
गज़ट

Official language—दफ़्तरी
भाषा

Official residence—सरकारी
मकान

Official trustee—सरकारी ट्रस्टी

Oil field—तेल क्षेत्र

Oilseeds—तिलहन

Ommission—छोड़ना

On the ground—इस बिना पर

Open court—खुला इजलास

Operation—अमल, चलाना

Opinion—राय

Opportunity—मौका

Order—हुकुम, व्यवस्था

Order of acquittal—बेगुनाही
का हुकुम

Ordinance—राजहुकुम

Ordinarily—आम तौर पर

Organisation—संगठन

Organised peoples—संगठित
कौम

Original jurisdiction—
पहली सुनवाई का अधिकार

Originate a Bill—बिल की
पहल करना

Overthrow—उलट देना

P

Paid employment—बेतनी काम

Paragraph—पैरा

Parity—बराबरी

Parliament—राजपंचायत

Part—भाग

Participate—हिस्सा लेना, भाग
लेना

Partition—बटवारा

Partnership—साझेदारी

Party—फ़रीक़

Pass—पास करना, पास होना

Passenger—सवारी

Passport—पासपोर्ट

Patent—पेटेन्ट

Payment—अदायगी

Peace—शांति, सुलह

Penalty—दंड

Pending—पेश, चालू

Pension—पेंशन

People—लोग

Percentage—फ़ी सैकड़ा

Perform duty—फ़रज़ अदा
करना, फ़रज़ पूरा करना

Period—अरसा	Pound—कांजी हौज़
Permanent return—पक्की वापसी	Power—शक्ति
Per mensem—माहवार	Practicable, practical—अमली
Permission—इजाज़त	Practical experience—अमली तजुर्बा
Permit—इजाज़त देना, परमिट	Preamble—सरलेख
Personal—निजी	Prefer a charge—दोशलेखा पेश करना
Personal law—निजी क़ानून	Preference—तरजीह
Personally—निजी तौर पर	Preside—सदारत करना
Personal right—निजी अधिकार	President—राजपति, सदर
Pest—महामारी	Prevention—रोकथाम
Petition—प्रार्थना पत्र	Preventive detention—रोकथामी नज़रबन्दी
Petroleum—पेट्रोलियम	Previous sanction—पहले से मंजूरी
Pilgrimage—तीर्थ यात्रा	Previous service—पहले की नौकरी
Piracy—समन्दरी डकैती	Price control—दाम कंट्रोल
Place of birth—जन्मस्थान	Primary education—प्राइमरी ताज़ीम
Planning—योजना	Primary school—प्राइमरी
Plead—बकाऊत करना	Prime Minister of India) —प्रधान वज़ीर (भारत का)
Pleader—फ़ीडर	Prince—नरेश
Police—पुलिस	Principal seat—खास जगह
Police force—पुलिस बल	Principal value—असल क़ीमत
Policy—नीति	Principle—सिद्धान्त
Political—राजकाजी	Printing press—छापाखाना
Population—आबादी	
Port—बन्दरगाह	
Possession—कब्ज़ा	
Posting—तैनाती	
Post Office Savings Bank —डाकघर बचत बँक	
Posts and Telegraphs—डाक और तार	

भारत का विधान

Prison—जेलखाना	Proportion—निसबत, हिस्सा
Prisoner—कैदी	Proportional representation—निसबती प्रतिनिधान
Privilege—निजनियम	Proposal—सुझाव
Privy Council—प्रिवी कौंसिल	Prorogation of the House—सदन का बरखास्त होना
Privy purse—निजी थैली	Prorogue—बरखास्त करना
Procedure—दस्तूर	Prosecution of war—जंग चलायाना
Procedure in general—आम दस्तूर	Prospect for minerals—खनिजों की खोज
Proceeding—कारवाई	Protection—रक्षा
Proceeds—बसुली	Prove—साबित करना
Process—हुकुमनामा	Provide—प्रबन्ध करना, बताना, बन्धान करना
Proclamation—ऐलान	Provided that—शर्तें कि
Proclamation of emergency—अचानकी का ऐलान	Provident fund—प्राविडेन्ट फंड
Product—पैदावार	Province—सूबा
Profession—पेशा	Provision—इन्तज़ाम, प्रबन्ध, बन्धान
Professional—पेशाई	Provisional—कामचलाऊ
Prohibition—परवाना मनाही, मनाही	Provisional Legislature—कामचलाऊ क़ानूनसभा
Promissory note—प्रामिसरी नोट	Provisional Parliament—कामचलाऊ राजपंचायत
Promotion—तरक्की	Proviso—शर्त
Promulgate—जारी करना	Proxy—एजन्ती
Pronounce judgment—क़ैसला सुनाना	Public—जनता, सरकारी, आम
Proof—सबूत	Public debt—सरकारी कर्ज़ा
Propagate—प्रचार करना	Public health—जन-तन्दुस्ती
Property—जायदाद	
Property in goods—माल की मिल्कियत	

Public importance—लोक महत्व	Railway Company—रेलमार्ग
Public institution—जनसंस्था, जनता की संस्था	कंपनी Raise a loan—उधारी लेना
Public interest—जनहित, जनता का हित	Raise money—रकम जुटाना
Public notification—आम नोटिस	Rajpramukh—राजप्रमुख
Public order—जन-व्यवस्था	Rank—रुतबा
Public Service Commi- ssion—सरकारी नौकरी कमीशन	Rate—दर
Publish—निकालना	Ratify—तसदीक करना
Punishment—सज़ा	Ratio—अनुपात
Purchase—खरीद	Readjust—घटत बढ़त करना
Purpose—मतलब	Reasonable—उचित
	Receipt—रसीद, आमदनी
	Recess—छुट्टी के दिन
	Recognise—मान लेना
	Recognised institution— मानी हुई संस्था
	Recommendation—सिफारिश
	Reconsideration—फिर से विचार
	Records—लेखे
	Recurring sum—फिराती रकम
	Recruitment—भरती
	Redemption charges— भुगतान खर्च
	Redemption of debt—करजा चुकाना, करजा भुगतान
	Reformatory—सुधारघर
	Region—इलाका
	Regional Commissioner— इलाका कमिशनर

Q

Qualification—जोगता	
Qualified—जोग	
Quarantine—चाहीसिया	
Question—सवाल	
Question of fact—वाक्याती सवाल	
Question of law—कानूनी सवाल	
Quorum—कोरम	
Quotient—भागफल	
Quo Warranto—परवाना अधिकार- बताई	

R

Race—जसल	
Railway—रेलमार्ग	

भारत का विधान

Regional Council —इलाका मंडल	Remuneration —मेहनताना
Regional fund —इलाका कोश	Rent —लगान, किराया
Register —रजिस्टर करना	Repeal —रद्द, रद्द करना
Registration —रजिस्ट्री	Report —रिपोर्ट
Regulate —कायदाबन्दी करना	Representation —प्रतिनिधान, अरज़ी पत्र
Regulation —कायदा, कायदाबन्दी	Representative —प्रतिनिधि
Rehabilitation —फिरबसाव	Republic —जनराज
Reimburse a person for his expenses —किसी के खर्च को पूरा करना	Repugnant —खिलाफ़
Relevant —संगत	Require attendance —हाज़िरी तलब करना
Relief —मद्द, भरपाई	Requisition —मंगैनी ले लेना
Religion —धर्म	Research —खोज
Religious —धार्मिक	Reservation —अलग रखना
Religious denomination —धार्मिक फ़िरका	Reserve Bank of India —भारत का रिज़र्व बैंक
Religious endowment —धार्मिक देन	Reserved forest —रखाया हुआ जंगल
Religious institution —धार्मिक संस्था	Reserved seat —अलग रखी सीट
Religious instruction —धार्मिक शिक्षा	Reserve for consideration —विचार के लिए रख देना
Remainder —बाक़ी	Reserve seats —सीटें अलग रखना
Remains —खंडहर	Reside —बसना, रहना
Remedy —उपाय	Residence —रिहाइश
Remission of tax —टैक्स में	Resident —बासी, बसने वाले, रहने वाले
Remit a sentence —सज़ा को कम कर देना	Residential —रिहाइश
	Residuary power —बचने शक्ति

Resign—इस्तीफा देना	Sale—बिक्री
Resolution—ठहराव	Sanad—सनद
Responsible—जिम्मेदार	Sanction—मंजूरी
Restaurant—जलपान घर	Sanitation—सफाई
Restriction—रुकावट	Save—सिवाय
Retail business—फुटकर कारबार	Saving—बचाव
Retired—सेवामुक्त	Scale—पैमाना
Retrospective effect— पिछलगता असर	Scarcity of goods—माल की कमी
Return—व्यौरा	Schedule—पट्टी
Revenue—मालगुजारी	Scheduled—पट्टीदर्ज
Revenue jurisdiction— माली अमलदारी	Scheduled caste—पट्टीदर्ज जाति
Review—नज़रसानी	Scheduled tribe—पट्टीदर्ज कबीला
Revoke—मंसूख करना	Scheme—योजना
Right—अधिकार	School—स्कूल
Right of audience—सुनवाई का अधिकार	Science—साइंस
River valley—नदी घाटी	Scientific—साइंसो
Road—सड़क	Scientific education— साइंसो तालीम
Ropeway—रस्सा मार्ग	Scientific line—साइंसो रीति
Royalty—रायल्टी	Script—लिखावट
Rule—नियम	Seal—मोहर
Rule of the road—मार्ग नियम	Seaman—मल्लाह
Ruler—शासक	Seat—जगह
S	Secondary school—दूसरी
Safeguard—बचावनी	Secrecy—राजदारी
Safety—सलामती	Secretarial staff—मंत्रायती
Salary—तनखाह	

भारत का विधान

Secretariat—मंत्रायत	Site—स्थान
Secretary of State—स्टेट सेक्रेटरी	Sitting—बैठक
Secret ballot—बन्द परची	Situation—हालत
Section—टुकड़ी	Slander—अपमान वचन
Security—सुरक्षा, जमानत, हुंडी	Small Cause Court— खफ़ीफ़ा अदालत
Select—छांटना	Social—समाजी
Self-government—स्वराज	Social injustice—समाजी अन्याय
Sentence—सज़ा का हुकुम	Social insurance—समाजी बीमा
Service—सेवा, नौकरी	Socially—समाजी निगाह से
Service of debt—करज़ा जारी रखना	Social order—समाजी व्यवस्था
Session—इजलास	Social reform—समाज सुधार
Session of Legislature— क्रानूनसभा का इजलास	Social service—समाज सेवा
Sessions Judge—सेशन जज	Social welfare—समाज की भलाई
Settle—बस जाना	Society—सोसाइटी
Sex—जिन्स	Solemly—गंभीरता के साथ
Share—हिस्सा	Sovereign—खुदमालिक
Sheriff—शेरीफ़	Speaker—सभामुख
Shifting cultivation— बदलती जुताई	Special—खास, विशेष
Shipping—जहाज़, जहाज़बानी	Special address—खास सरबचन
Short title—छोटा सरनामा	Special directive—खास निर्देश
Signed certificate—दसखती सनद	Special electoral roll— खास चुनाव चिट्ठा
Single judge—अकेला जज	Special knowledge—खास जानकारी
Single transferable vote— इकहरा बदलता वोट	Special procedure—खास इस्तूर
Sinking fund—करज़ा चुकाई कोश	Special provision—खास बन्धान

Special qualification— खास योगता	Subordinate court—मानहत अदालत
Special representation— खास प्रतिनिधान	Substantial question of law—क्रानून का ठोस सवाल
Spoilation—छूट खसोट	Succession—पदगाहन, विरासत
Staff—अमला	Successor—पदगाही, वारिस
Stamp duty—स्टाम्प महसूल	Sue—नालिश करना
Standard—दर्जा, स्तर, मान	Suit—नालिश
Standard of living—जीवनस्तर	Suitor—सायल
Standard of quality—गुणमान	Superintendence—निगरानी
Standing order—क्रायमी हुकुम	Supplemental power—पूरक शक्ति
State—रियासत	Supplemental, suppleme- ntary—पूरक
State List—रियासत तालिका	Supplementary expendi- ture—पूरक खच
Statement—ज्यौरा	Supplementary grant— पूरक देनगी
State Public Service Com- mission—रियासत सरकारी नौकरी कमीशन	Supply—मुदय्या करना, रसद
Statistics—आंकड़े	Support—समर्थन करना
Status—दर्जा	Supreme Command—आळा कमान
Stay of proceedings—कार- वाई रोक देना	Supreme Court—आळा अदालत
Steel—फ़ौलाइ	Surcharge—अधिक टैक्स
Stock—पत्तीपूजी, नसल (मवेशियों की)	Survey—सरवे
Stock exchange—शेयर बाज़ार	Suspend—मुअतल करना, रोक देना
Style—शैली	Suspend a meeting—मिलनी को रोक देना
Sub-clause—उपधारा	Suspend a sentence—सज़ा के हुकुम को रोक देना
Sub-Divisional Officer— सबडिवीज़नल अफ़सर	
Subordinate—मातहत, अधीन	

Swear—शपथ लेना	Through—मार्फत
T	Tidal waters—उच्चार जल
Table—नक्शा	Title—खिताब, सरनामा
Take step—कदम उठाना	Toilet—सिंघार
Tax—टैक्स	Toilet preparation—सिंघार सामान
Tax on income—आमदनी पर टैक्स	Tolls—टोल टैक्स
Technical—तकनीकी	Town—क़सबा
Technical education— तकनीकी तालीम	Town Committee—क़सबा कमेटी
Telephone—टेलीफ़ोन	Tract—ख़िता
Temporary—आरज़ी	Trade—ब्योपार
Tenant—किसान	Trademark—ब्योपार छाप
Tendency—झुकाव	Trader—ब्योपारी
Tender age—कच्ची उमर	Trade Union—ट्रेड यूनियन
Term—शर्त, बंधन, मियाद	Trading corporation— ब्योपारी एकतनी
Terminal tax—हदवारी टैक्स	Traffic—ब्यापार
Terminate—खतम करना	Training—ट्रेनिंग
Term of office—पद-मियाद	Tramcar—ट्रामगाड़ी
Territorial—भूभागी	Tramway—ट्राममार्ग
Territorial constituency— भूभागी चुनाव हलका	Transaction—सौदा
Territorial waters—भूभागी जल, भूभागी समन्दर	Transfer—बदलो करना, तबादला, तबदीलना, दाखिल खारिज
Territory—भूभाग	Transitional—विशेषकी
The State (as defined in Part III)—राज	Transitional provision— विशेषकी बंधन
Things of value—कीमती चीज़ें	Translation—अनुबाद
Thought—विचार	Transport—जाना डे जाना
	Transporation for life— आजीवन काकापानी

Treasure trove—गढ़ा लावारिसी
खज़ाना

Treasury Bill—सरकारी हुंडी

Treaty—संधिनामा

Treaty obligations—संधि
बंधन

Trespass—हद लांघना

Trial—जांच

Tribal—क्रबाइली

Tribal Council—क्रबाइली मंडल

Tribals—क्रबाइली लोग

Tribe—कबीला

Tribes Advisory Council
कबीला सलाहकार मंडल

Tribunal—पंच अदालत, पंचायती
अदालत

Trust—ट्रस्ट, भरोसा

Trustee—ट्रस्टी

U

Undermine—जड़ खोखली करना

Undertaking—कारबार

Undeserved want—अनकरी
ज़रूरत

Unemployment—बेकारी,
बेकामगारी

Unexpected demand—अचा-
नक मांग

Unforeseen expenditure—
अनसूझा खर्च

Unginned cotton—अनओटी
रूई, कपास

Uniformity—एकरूपता

Union—यूनियन

Union List—यूनियन तालिका

Union Public Service

Commission—यूनियन सरकारी
नौकरी कमीशन

Unit—इकाई

United Khasi and Jaintia
Hills District—युक्त खासी
जैन्तिया पहाड़ी ज़िला

United Nations Organisa-
tion—संयुक्त कौम संगठन

Unity—एकता

University—विद्यापीठ

Unsound mind—नाठीक दिमाग

Unsoundness of mind—
दिमाग ठीक न होना

Untouchability—अछूतपन

Uprajpramukh—उपराजप्रमुख

Usage—रिवाज

Use—इस्तेमाल

V

Vacancy—सूनी

Vacate—सूना करना

Vacation—तालील

Vagrancy—आबारागरदी

Validate—सरदुरुस्त ठहराना

Validity—सरदुरुस्ती

Valley—घाटी

Vehicle—गाड़ी

Vessel—जहाज़	Waterway—जलमार्ग
Veterinary—पशु-इलाज	Ways and means advance—
Vice-President—उपराजपति	राष्ट्रपति पेशगी
Village administration—	Weaker section—निबल दुकड़ी
गांव शासन	Weight—तोल
Village committee—गांव	Weights—तोलने के षाट
कमेटी	Welfare—भरवाई, खुशहाली
Village council—गांव मंडल	Wholesale business—
Village court—गांव अदालत	थोक कारबार
Violation of Constitu-	Will—बचीयत
tion—विधान तोड़ना	Wind up—समेटना
Violation of law—कानून	Wireless—बेतार
तोड़ना	Withdraw a case—मुकदमा
Visa—वीसा	उठा लेना
Vital statistics—जीवन आंकड़े	Withdrawal of money—
Vocabulary—शब्दावली	रुपया निकालना
Vocation—रोज़गार	Worker—कामगार
Void—रद्द	Workmen's compensation
Voluntarily—अपनी मरज़ी से,	—कामगारों की मुकसान भरपाई
अपनी इच्छा से	Works—कारखाना, इमारत
Vote—वोट, वोट देना	Worship—पूजाबंदगी
Voter—वोटर	Wound pension—घायली
	पेनशन
W	Writ—परवाना
War—जंग	Writing under ones hand
Warrant—हुक्मनामा	—इसखती लिखत
Water power—पनशक्ति	Z
	Zoology—जन्तुबिद्या

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय
Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Library

मुससुरी
 MUSSOORIE

अवाप्ति सं०

Acc. No.....122-049.....

कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस कर दें।

Please return this book on or before the date last stamped below.

दिनांक Date	उधारकर्ता की संख्या Borrower's No.	दिनांक Date	उधारकर्ता की संख्या Borrower's No.

GL H 342.54
 BHA



122049
 BENIAA

